रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-73

REGISTERED NO. D. (D. N.)—73

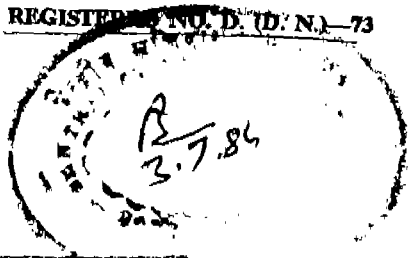

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 22] नई दिल्ली, शनिवार, जून 2, 1984/ज्येष्ठ 12, 1906

No. 22] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 2, 1984/JYAISTHA 12, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किये गये सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 16 मई, 1984

सूचना

का० आ० 1734.—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री के० जयप्रकाश शेट्टी, एडवोकेट, नं० 257, 14वां क्रास, 2 ब्लाक, आर०टी०नगर, बंगलौर-560032 ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे बंगलौर शहर में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्त किया जाए।

2. उक्त व्यक्ति की नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप में मेरे पास भेजा जाए।

[सं० 5 (24)/84-न्याय]

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

(Department of Legal Affairs)

New Delhi, the 16th May, 1984

NOTICE

S.O. 1734.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries Rules, 1956 that application has been made to the said Authority, under rule 4 of the said Rules, by Shri K. Jayaprakash Shetty, Advocate, No. 257, 14th Cross, II Block, R.T. Nagar, Bangalore-560032 for appointment as a Notary to practise in the City of Bangalore.

2. Any objection to that appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this Notice.

[No. F. 5(24)/84-Judl.]

नई दिल्ली, 17 मई, 1984

सूचना

का० आ० 1735.—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री बलराम, एडवोकेट, गांव व डाकखाना शहाबाद, मोहम्मदपुर, नई दिल्ली 45 ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे नई दिल्ली में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्त किया जाए।

2. उक्त व्यक्ति की नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप में मेरे पास भेजा जाए है।

[सं० एफ० 5(86)/83-न्या०]
एस० गुप्तु, सक्षम प्राधिकारी

New Delhi, the 17th May, 1984

NOTICE

S.O. 1735.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries Rules, 1956, that application has been made to the said Authority, under rule 4 of the said Rules, by Shri Bal Ram, Advocate, Village and P. O. Shahabad, Mohammadpur, New Delhi-45 for appointment as a Notary to practise in New Delhi.

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this Notice.

[No. F. 5(86)/83-Judl.]
S. GOOPTU, Competent Authority

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 11 मई, 1984

का० आ० 1736.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबन्ध) स्कीम 1970 के खंड 8 के उपखंड (1) के साथ पठित खंड 3 के उपखंड (क) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात श्री जे०एस० भटनागर को 11 मई, 1984 से आरम्भ होने वाली और 10 मई 1987 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त करती है।

[सं० एफ० 9/39/83-बी० ओ०-I-(1)]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

New Delhi, the 11th May, 1984

S.O. 1736.—In pursuance of sub-clause (a) of clause 3 read with sub-clause (1) of clause 8 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India, hereby appoints Shri J. S. Bhatnagar as the Managing Director of the Union Bank of India for a period commencing on May 11, 1984 and ending with May 10, 1987.

[No. F. 9/39/83-BO.I(1)]

का०आ० 1737.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबन्ध) स्कीम, 1970 के खंड 7 के साथ पठित खंड 5 के उपखंड (1) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात श्री जे० एस० भटनागर को जिन्हें 11 मई, 1984 से यूनियन बैंक आफ इंडिया के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है उस तारीख से यूनियन बैंक आफ इंडिया के निदेशक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करती है।

[संख्या एफ० 9/39/83-बी ओ०-I(2)]

S.O. 1737.—In pursuance of sub-clause (1) of clause 5, read with clause 7, of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government after consultation with the Reserve Bank of India, hereby, appoints Shri J. S. Bhatnagar who has been appointed as Managing Director of the Union Bank of India with effect from May 11, 1984 to be the Chairman of the Board of Directors of the Union Bank of India with effect from the same date.

[No. F. 9/39/83-BO. I(2)]

नई दिल्ली, 18 मई, 1984

का०आ० 1738.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध तथा प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 के खण्ड 3 के उपखण्ड (ग) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से एतद्द्वारा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग) की 5 [illegible] 1984 की अधिसूचना सं० एफ० 9/15/84-बी०ओ०-1 को [illegible] जाता है।

[सं० एफ 9/26/84-बी०ओ०I]
च० व० मीरचन्दानी, निदेशक

New Delhi, the 18th May, 1984

S.O. 1738.—In pursuance of sub-clause (c) of clause 3 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India, hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Banking Division) No. F. 9/15/84-B.O. I dated May 5, 1984.

[No. F. 9/26/84-BO. I]
C. W. MIRCHANDANI, Director

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 3 मई, 1984

प्रधान कार्यालय संस्थापन

का०आ० 1739.—केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 (1963 की संख्या 54) की धारा 3 की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारतीय राजस्व सेवा (आयकर) के अधिकारी श्री एस०एस० नारायणन को जो पिछले दिनों मुख्य आयुक्त (प्रशासन) तथा आयकर आयुक्त तमिलनाडु-1 मद्रास के पद पर तैनात थे, 26 अप्रैल, 1984 के पूर्वाह्न से केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त करती है।

[फा०सं०ए० 19011/4/84-प्रशा० I]

(Department of Revenue)

New Delhi, the 3rd May, 1984

HEADQUARTERS ESTABLISHMENT

S.O. 1739.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 3 of the Central Board of Revenue Act, 1963 (No. 54 of 1963), the Central Government hereby

appoints Shri M. S. Narayanan, an officer of the Indian Revenue Service (Income-tax) & lately posted as Chief Commissioner (Admn.) & Commissioner of Income-tax, Tamil Nadu-I, Madras, as Member of the Central Board of Direct Taxes with effect from the forenoon of the 26th April, 1984.

[F. No. A. 19011/4/84-Ad. I]

का०आ० 1740.—केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 (1963 की संख्या 54) की धारा 3 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारतीय राजस्व सेवा (आयकर) के अधिकारी श्री एस०बी० जैन को जो पिछले दिनों मुख्य आयुक्त (प्रशासन) तथा आयकर दिल्ली-1 नई दिल्ली के पद पर तैनात थे 30 अप्रैल, 1984 के अपराह्न से केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त करती है।

[फा०सं० ए० 19011/3/84-प्रशा० I]

S.O. 1740.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 3 of the Central Board of Revenue Act, 1963 (No. 54 of 1963), the Central Government hereby appoints Shri S. B. Jain, an officer of the Indian Revenue Service (Income-tax) and lately posted as Chief Commissioner (Admn.) and Commissioner of Income-tax, Delhi-I, New Delhi as Member of the Central Board of Direct Taxes with effect from the afternoon of the 30th April, 1984.

[F. No. A. 19011/3/84-Ad. I]

का०आ० 1741.—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (कारबार के संव्यवहार का विनियमन) नियमावली, 1964 के नियम 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के सदस्य तथा भारत सरकार के पदेन अपर सचिव श्री एन० सुब्रामनियन को 30 अप्रैल, 1984 के अपराह्न से अगला आदेश होने तक केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त करती है।

[फा०सं० ए० 19011/53/81-प्रशा-I]
जी०एस० मेहरा, उप सचिव

S.O. 1741.—In exercise of the powers conferred by Rule 3 of the Central Board of Direct Taxes (Regulation of Transaction of Business) Rules, 1964, the Central Government hereby appoints Shri N. Subramanian, Member, Central Board of Direct Taxes and ex-officio Additional Secretary to the Government of India, as Chairman of the Central Board of Direct Taxes with effect from the afternoon of the 30th April, 1984 and until further orders.

[F. No. A. 19011/53/81-Ad. I]
G. S. MEHRA, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 16 मई, 1984

स्टाम्प

का०आ० 1742.—भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (1899 का 2) की धारा 20 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 29 फरवरी, 1984 की अधिसूचना संख्या 17/84-स्टाम्प फा०सं० 33/2/83-वि०क० (अ०का०सं० 818) का अतिलंघन करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (3) में स्टाम्प शुल्क की संगणना के प्रयोजनार्थ उस सारणी के स्तम्भ (2) में तत्वनुरूपी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट विदेशी मुद्रा को भारतीय मुद्रा में संपरिवर्तित करने के लिए विनिमय की दर निर्धारित करती है।

सारणी

क्र०सं०	देश का नाम	विदेशी मुद्रा	100 रु० के समतुल्य विदेशी मुद्रा के विनिमय की दर
1	2	3	4
1.	आस्ट्रियन	शिलिंग	167.5
2.	आस्ट्रेलियन	डालर	9.820
3.	बेल्जियम	फ्रैंक	488.5
4.	कनाडियन	डालर	11.750
5.	डेनिश	क्रोनर	87.65
6.	डूच	मार्क	23.76
7.	डच	गिल्डर	26.71
8.	फ्रेंच	फ्रैंक	73.55
9.	हांग कांग	डालर	71.80
10.	इतालवी	लीरा	149.28
11.	जापानी	येन	2057
12	मलेशियन	डालर	21.09
13.	नार्वेजियन	क्रोनर	69.00
14.	पौंड	स्टर्लिंग	6.4050
15.	स्वीडिश	क्रोनर	71.05
16.	स्विस	फ्रैंक	19.775
17.	अमरीकी	डालर	9.250
18.	सिंगापुर	डालर	19.205

[सं० 33/84/स्टाम्प फा०सं० 33/2/83-वि०क०]

New Delhi, the 16th May, 1984

STAMPS

S.O. 1742.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 20 of the Indian Stamp Act, 1899(2 of 1899) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Dpartment of Revenue) No. 17/84-Stamps F.No. 33/2/83 ST (S.O. No. 818) dated the 29th February, 1984, the Central Government hereby perscribed in column 3 of the Table below the rate of exchange for the conversion of the foreign currency specified in the corespondin entry in column (2) thereof into the currency of India for the purposes of calculating stamp duty.

TABLE

S.No.	Foreign Currency		Rate of exchange of foreign currency equivalent to Rs. 100/-
1		2	3
1.	Austrian	Schillings	167.5
2.	Australian	Dollars	9.820
3.	Belgian	Francs	488.5
4.	Canadian	Dollars	11.750
5.	Danish	Kroners	87.65
6.	Deutsche	Marks	23.76
7.	Dutch	Guilders	26.71
8.	French	Francs	73.55
9.	Hong Kong	Dollars	71.80
10.	Italian	Lire	149.28
11.	Japanese	Yen	2057
12.	Malayasian	Dollars	21.09
13.	Norwegian	Korners	69.09
14.	Pound	Sterling	6.4050
15.	Swedish	Kroners	71.05
16.	Swiss	Francs	17.775
17.	U.S.A.	Dollars	9.250
18.	Singapore	Dollars	19.205

[No. 33/84-Stamps-F.No. 33/2//83-ST]

आदेश

नई दिल्ली, 17 मई, 1984

स्टाम्प

का०आ० 1743.—भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उस शुल्क को माफ करती है जो आवास और शहर विकास निगम लि० नई दिल्ली द्वारा सोलह करोड़ पचास लाख रुपये मूल्य के ऋण पत्रों के रूप में जारी किए जाने वाले बन्ध पत्रों पर उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रभार्य है।

[सं० 34/84-स्टाम्प-फा०सं० 33/25/84-वि०क०]

ORDER

New Delhi, the 17th May, 1984

STAMPS

S.O. 1743.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby remits the duty with which the bonds in the nature of debentures to the value of rupees sixteen crores and fifty lakhs to be issued by Housing and Urban Development Corporation Ltd., New Delhi are chargeable under the said Act.

[No. 34/84-Stamps-F. No. 33/25/84-ST]

आदेश

नई दिल्ली, 18 मई, 1984

स्टाम्प

का०आ० 1744.—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा मैसर्स ऊषा मार्टिन इंडस्ट्रीज लि०, कलकत्ता को केवल तिरासी हजार तीन सौ एक रुपये के उस समेकित स्टाम्प शुल्क की अदायगी करने की अनुमति देती है जो उक्त कम्पनी द्वारा जारी किए जाने वाले एक करोड़ ग्यारह लाख छः हजार आठ सौ रुपये के अंकित मूल्य के ऋण-पत्रों के रूप में बंधपत्रों पर प्रभार्य है।

[सं० 37/84-स्टाम्प-फा. सं० 33/29/84-वि०क०]

ORDER

New Delhi, the 18th May, 1984.

STAMPS

S.O. 1744.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby permits M/s. Usha Martin Industries Ltd, Calcutta to pay consolidated stamp duty of rupees eighty-three thousand three hundred and one only,, chargeable on account of the stamp duty on bonds in the form of debentures of the face value of rupees One crore eleven lakhs six thousand and eight hundred only to be issued by the said company.

[No. 37/84—Stamps-F. No. 33/29/84-ST]

आदेश

स्टाम्प

का०आ० 1745.—भारतीय, स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उस शुल्क को माफ करती है जो राष्ट्रीय लघु औद्योगिक निगम द्वारा मात्र चार करोड़ रुपये मूल्य के वचनपत्रों के रूप में जारी किए जाने वाले बंधपत्रों पर उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रभार्य है।

[सं० 36/84 स्टाम्प-फा सं 33/23/84-वि०क०]

भगवान दास, अवर सचिव

ORDER

STAMPS

S.O. 1745.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899) the Central Government hereby remits the duty with which the bonds in the nature of Promissory notes of the value of rupees four crores only to be issued by the National Small Industries Corporation are chargeable under the said Act.

[No. 36/84-Stamps/F. No. 33/23/84-ST]

BHAGWAN DAS, Under Secy.

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली 10 फरवरी, 1984

आयकर

का०आ० 1746.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 28-9-1983 की अधिसूचना संख्या 5412 (फा० सं० 203/35/83-आ० क० नि०-II) की सातवीं लाइन में आने वाले "अन्य प्राकृतिक और अनुप्रयुक्त विज्ञानों के क्षेत्र में" शब्दों का एतद्द्वारा लोप किया जाता है।

[संख्या 5619 /फा० सं० 203/24/84-आ० क० नि०-II]

CORRIGENDUM

New Delhi, the 10th February, 1984

INCOME TAX

S.O. 1746.—It is hereby notified for general information that the words, "in the area of other natural and applied sciences" occurring in seventh line of Ministry of Finance (Department of Revenue) Notification No. 5412 (F. No. 203/35/83-ITA. II) dated 28-9-1983, are hereby deleted.

[No. 5619/F. No. 203/24/84-ITA. II]

नई दिल्ली 16 फरवरी 1984

आय-कर

का० आ० 1747.—सर्वसाधारण की सूचना के लिए एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी अर्थात् विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम 1962 के नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के प्रयोजनार्थ "विश्वविद्यालय" प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है अर्थात् :—

(i) यह कि मंगलौर विश्वविद्यालय मंगलौर वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उसके द्वारा प्राप्त धनराशियों का एक पृथक लेखा रखेगा।

(ii) यह कि उक्त विश्वविद्यालय अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों की वार्षिक विवरणी विहित प्राधिकारी के प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रतिवर्ष 30 अप्रैल तक ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किया जाए और उसे सूचित किया जाए।

(iii) यह कि उक्त विश्वविद्यालय अपनी कुल आय तथा व्यय दर्शाते हुए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसंपत्तियां देनदारियां दर्शाते हुए तुलन-पत्र की एक-एक प्रति प्रतिवर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति संबंधित आयकर आयुक्त को भेजेगा।

संस्था

मंगलौर विश्वविद्यालय मंगलौर।

यह अधिसूचना 17-9-1983 से 16-9-1986 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी रहेगी।

[सं० 5640/फा० सं० 203/117/83-आ० क० नि०-II]

मदन गोपाल चंद गोयल, अवर सचिव

New Delhi, the 16th February, 1984

INCOME TAX

S.O. 1747.—It is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by Department of Science & Technology, New Delhi the prescribed authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category "University" subject to the following conditions :—

(i) That the Mangalore University, Mangalore will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.

(ii) That the said university will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 30th April each year.

(ii) That the said University will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and balance sheet showing its assets liabilities with a copy of each of these documents to the concerned Commissioner of Income-tax.

INSTITUTION

Mangalore University, Mangalore.

This notification is effective for a period of three years from 17-9-1983 to 16-9-1986.

[No. 5640/F. No. 203/117/83-ITA. II]

M. G. C GOYAL, Under Secy.

नई दिल्ली, 28 मार्च, 1984

आय-कर

का०आ० 1748.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80-ल की उपधारा (1) के खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ, इण्डस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन कार्पोरेशन आफ इण्डिया लि० द्वारा जनवरी, 1984 में जारी किए गए 4.5 करोड़ रुपये (अधिसूचित राशि) 8.25 प्रतिशत-12 वर्षीय आई०आर०सी०आई० बन्धपत्र विनिर्दिष्ट करती है।

[सं० 5727/फा० सं० 178/29/84-आ०क० (नि०-1)]
वी० बी० श्रीनिवासन, निदेशक

New Delhi, the 28th March, 1984.

INCOME-TAX

S.O. 1748.—In exercise of the powers conferred by clause (ii) of sub-section (1) of Section 80-L of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby specifies the 8.25% 12 years I. R. C. I. Bonds for 4.5 Crores (notified amount) issued by the Industrial Reconstruction Corporation of India Ltd. in January, 1984 for the purposes of the said clause.

[No. 5727/F. No. 178/29/84-IT(AI)]
V. B. SRINIVASAN, Director

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 17 मई, 1984

का०आ० 1749.—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 56 के साथ पठित धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर, एतद्द्वारा यह घोषणा करती है कि बैंककारी विनियमन (सहकारी समितियां) नियम 1966 के नियम 10 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 31 के प्रावधान को ऑपरेटिव सिटी बैंक लि०, गौहाटी को 30 जून 1983 को समाप्त वर्ष के लिए उसके लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट सहित तुलनपत्र और लाभ-हानि लेखा समाचार-पत्र में प्रकाशित होने के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे।

[सं०फा० 18-2/84-एसी]
अमर सिंह, अवर सचिव

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

New Delhi, the 17th May, 1984

S.O. 1749.—In exercise of the powers conferred by section 53 read with Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government on the recommendation of the Reserve Bank of India hereby declares that the provisions of Section 31 of the said Act, read with Rule 10 of the Banking Regulation (Co-operative Societies) Rules, 1966 shall not apply to the Co-operative City Bank Ltd., Gauhati so far as they relate to the publication of its balance-sheet and profit & loss account for the year ended the 30th June 1983 together with the auditor's report in the news papers.

[No. F. 18-2/84-AC]
AMAR SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 18 मई, 1984

का० आ० 1750—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री वी० एन० शर्मा को जम्मू रूरल बैंक जम्मू का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 31-3-1984 से प्रारम्भ होकर 31-1-1986 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान श्री वी० एन० शर्मा अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।

[संख्या 2/11/81 आर० आर० बी०]

New Delhi, the 18th May, 1984

S.O. 1750.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976) the Central Government hereby appoints Shri V. N. Sharma as the Chairman of the Jammu Rural Bank, Jammu and specifies the period commencing on the 31-1-84 and ending with the 31-1-1986 as the period for which the said Shri V.N. Sharma shall hold office as such Chairman.

[No. 2(11)/81-RRB]

का० आ० 1751.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री मुनीर खां को कानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कानपुर का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 1-3-1984 से प्रारम्भ होकर 31-3-1987 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान श्री मुनीर खां अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।

[संख्या एफ० 2/61/82 आर० आर० बी०]
एस० एस० हसूरकर, निदेशक

S.O. 1751.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976) the Central Government hereby appoints Shri Munir Khan as the Chairman of the Kanpur Kshetriya Gramin Bank, Kanpur and specifies the period commencing on the 1-3-1984 and ending with the 31-3-1987 as the period for which the said Shri Munir Khan shall hold office as such Chairman.

[No. 2(61)/82-RRB]
S.S. HASURKAR, Director

नई दिल्ली, 17 अप्रैल, 1984

का० आ० 1752.—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 53(2) के अनुसरण में केन्द्रीय निदेशक बोर्ड ने, भारत सरकार को 30 जून, 1983 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के कामकाज पर वार्षिक रिपोर्ट भेजी है जो नीचे उद्धृत की जाती है :—

पहली जुलाई 1982 से 30 जून 1983 तक के वर्ष के लिए

भारतीय रिजर्व बैंक के कामकाज पर वार्षिक रिपोर्ट

भाग—I आर्थिक स्थिति

1. वर्ष 1982-83 में, भयंकर सूखे के कारण कृषि उत्पादन में हुई भारी कमी तथा औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर में आई भारी गिरावट के कारण अर्थव्यवस्था को गंभीर आघात पहुंचा। फलतः राष्ट्रीय आय में केवल सीमान्त वृद्धि ही हुई। समग्र भुगतान संतुलन ने थोड़ा सुधार दर्शाया, भले ही उस पर अभी भी बराबर दबाव बना हुआ है। इन प्रतिकूल प्रवृत्तियों के बावजूद वर्ष के अधिकांश भाग में मूल्य काफी स्थित बने रहे।

2. कृषि उत्पादन—वर्ष के दौरान, भारी सूखे की वजह से कृषि उत्पादन में गिरावट आयी। दक्षिण-पश्चिमी मानसून के देर से आने, वर्षा ठीक से न होने और वह भी समय से पहले ही खत्म हो जाने की वजह से 15 राज्यों के 480 लाख हेक्टेयर से अधिक फसल-क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। यहां यह उल्लेखनीय है कि पिछले पांच वर्षों की अवधि में भारतीय कृषि को दूसरी बार भयंकर सूखे का सामना करना पड़ा है। 1979-80 में भी दक्षिण-पश्चिमी मानसून ने धोखा दिया था और 410 लाख हेक्टेयर फसल-क्षेत्र सूखे से ग्रस्त हो गया था। 1982-83 में खरीफ की फसलों के लिए मौसम की स्थिति सर्वथा प्रतिकूल थी। इसके कारण 1981-82 के 791 लाख टन के उत्पादन की तुलना में इस वर्ष यह लगभग 90 लाख टन की कमी के साथ 690 या 700 लाख टन के आसपास रहने का अनुमान है। फिर भी खरीफ के उत्पादन में हुई यह कमी, 1979-80 जितनी नहीं है क्योंकि उस समय 150 लाख टन की कमी हुई थी। इसका कारण यह है कि खाद्यान्न पैदा करने वाले प्रमुख राज्य 1979-80 में, इस वर्ष की अपेक्षा, सूखे से अधिक प्रभावित हुए थे। इसके अलावा, लघु सिंचाई सुविधाओं का रखरखाव और विस्तार करके और उर्वरकों तथा अन्य कृषि उत्पादों आदि को उपलब्ध करा कर मानसून की असफलता के विपरीत प्रभाव को कम करने के लिए जो प्रयास किये गये उनसे भी 1982-83 के दौरान फसल को बचाने में सहायता मिली। इस वर्ष के दौरान इन प्रयासों में काफी वृद्धि की गयी। अनुमान है कि पिछले वर्ष की अपेक्षा, 1982-83 में उर्वरकों का उपभोग लगभग 6 प्रतिशत बढ़ गया है। यद्यपि, उपभोग का जो लक्ष्य रखा गया था उससे यह बहुत कम है, फिर भी मौसम की प्रतिकूल स्थितियों वाले वर्ष में यह वृद्धि भी कम नहीं है। आशा है रबी की फसल के खाद्यान्नों का उत्पादन 580 लाख टन के रिकार्ड उत्पादन तक पहुंच जायेगा जो 1981-82 के रबी उत्पादन से लगभग 40 लाख टन अधिक है।

3. आशा है, 1982-83 में, खाद्यान्नों का कुल उत्पादन 1270-1280 लाख टन रहेगा। यह अधिकतम उत्पादन भी पिछले वर्ष के 1330 लाख टन के वास्तविक उत्पादन से 50 लाख टन कम बैठेगा। जहां तक खाद्येतर फसलों का संबंध है, जूट, मेस्ता और तिलहनों के उत्पादन में ज्यादा तेजी से गिरावट आयी है। जूट और मेस्ता का उत्पादन लगभग 72 लाख गांठ ही रहने का अनुमान है जबकि 1981-82 में 84 लाख गांठों का उत्पादन हुआ था। इसी प्रकार, तिलहन का उत्पादन पिछले वर्ष के 121 लाख टन की तुलना में इस वर्ष 110 लाख टन ही होगा। गन्ने का उत्पादन भी, पिछले मौसम के दौरान (गुड़ के रूप में) हुए लगभग 187 लाख टन की अपेक्षा कम, अर्थात् 177 लाख टन रहने की आशा है। कपास का उत्पादन 82 लाख गांठें रहने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के वास्तविक उत्पादन अर्थात्, 84 लाख गांठों के लगभग बराबर ही बैठेगा।

4. इस स्थिति का एक अनुकूल पहलू यह है कि 1982-83 के सूखे से सरकारी वसूली एजेंसियों के खाद्यान्न भंडारों पर कोई खास असर नहीं पड़ा। वसूली कार्यों में तेजी लायी गयी जिसकी वजह से इस विपणन मौसम में चावल और मोटे अनाज की वसूली (71 लाख टन) पिछले वर्ष की 73 लाख टन की अपेक्षा केवल सीमान्त रूप से कम थी। साथ ही, चालू रबी मौसम के दौरान गेहूं की वसूली 82 लाख टन के उच्च स्तर पर पहुंच गयी। इसके अलावा, अमेरिका से 40 लाख टन गेहूं आयात करने की व्यवस्था को भी अंतिम रूप दिया गया, जिसमें से फरवरी 1983 के अंत तक, 14.5 लाख टन गेहूं प्राप्त किया जा चुका था। यह आयात उस स्टाक स्तर पर को बनाये रखने के लिए जरूरी था जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से तेजी से किये जा रहे वितरण के कारण कम होता जा रहा था। 1982-83 (जुलाई-जून) में कुल 164 लाख टन खाद्यान्न उठाया गया जबकि 1981-82 की इसी अवधि में 118 लाख टन खाद्यान्न उठाया गया था। 1982-83 के दौरान उठाये गये खाद्यान्न का मासिक औसत, 1981-82 के 12 लाख टन से बढ़कर, 14 लाख टन हो गया। जून 1983 के अंत में, सरकारी एजेंसियों के पास खाद्यानों का भंडार 165 लाख टन का था जो पिछले वर्ष के 155 लाख टन के स्तर से ज्यादा था। 1981-82 मौसम में चीनी के उत्पादन में हुई तेज वृद्धि के कारण इस वर्ष के दौरान 5 लाख टन चीनी का एक "बफर स्टाक" बनाया गया।

5. औद्योगिक उत्पादन—कृषि-उत्पादन में मौसम की स्थिति में सुधार होने पर वृद्धि की आशा की जा सकती है, इसलिए कृषि उत्पादन में कमी होना उतना चिंताजनक नहीं है जितना कि औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि की गति में कमी आना है। जुलाई 1982 से मई 1983 के ग्यारह महीनों की अवधि के दौरान, पिछले वर्ष के इन्हीं महीनों के औद्योगिक उत्पादन के समग्र सूचकांक के मुकाबले केवल 3.2 प्रतिशत की ही वृद्धि हुई जबकि 1981-82 में यह वृद्धि 7.6 प्रतिशत की थी। कैलेण्डर वर्ष 1982 के प्रारंभ में भी उत्पादन में गिरावट की प्रवृत्ति स्पष्ट रूप में दिखायी पड़ रही थी। जनवरी-मार्च 1982 की तिमाही में औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक में औसत वृद्धि 6.4 प्रतिशत की रही जबकि 1981 की इसी तिमाही में 8.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। यद्यपि अप्रैल-जून 1982 की तिमाही में, सूचकांक में औसत-वृद्धि पिछली तिमाही के लगभग बराबर ही अर्थात् 6 प्रतिशत बनी रही, तथापि, पिछले वर्ष की तदनुरूप तिमाही की अपेक्षा यह वृद्धि बहुत कम थी क्योंकि तब 11.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी जुलाई-सितंबर 1982 में उत्पादन की वृद्धि की गति में कमी और भी ज्यादा दिखायी दी जब सूचकांक में औसत वृद्धि 2.1 प्रतिशत ही रह गयी। जुलाई-सितंबर 1981 में औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक में औसत वृद्धि 9.1 प्रतिशत की थी। 1982 में अक्तूबर-दिसंबर की तिमाही में 3.6 प्रतिशत की ही वृद्धि हुई जबकि 1981 में 8.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। औद्योगिक उत्पादन में यह गिरावट बराबर जारी है क्योंकि जनवरी से मई 1983 के ताजा आंकड़ों के अनुसार 3.6 प्रतिशत की ही औसत-वृद्धि हुई है जबकि पिछले वर्ष के इन्हीं महीनों में 6.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

6. औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के क्षेत्रवार वर्गीकरण के अनुसार, औद्योगिक वृद्धि में गिरावट मुख्य रूप से निर्माण क्षेत्र के कारण आयी है, जिसका हिस्सा इस सूचकांक में 81 प्रतिशत रहता है। जुलाई 1982 से मई 1983 के ग्यारह महीनों की अवधि में इस क्षेत्र में मात्र 1.7 प्रतिशत की ही वृद्धि दर्ज की गयी जबकि पिछले वर्ष यह वृद्धि

6.8 प्रतिशत की थी। खनन और उत्खनन (माइनिंग और क्वेरीइंग) में पिछले वर्ष 15.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी जबकि इस वर्ष 8.4 प्रतिशत की ही वृद्धि हुई। 1982-83 (जुलाई-मई) के दौरान बिजली के उत्पादन में 6.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह 1981-82 के इन्हीं महीनों में हुई 7.1 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में आंशिक रूप से कम थी।

7. सूचकांकों के उपयोग-आधारित वर्गीकरण के विश्लेषण से यह पता चलता है कि पूंजीगत वस्तुओं के उद्योगों के संबंध में सूचकांक में जुलाई 1982 –मार्च 1983 की अवधि के दौरान 3.9 प्रतिशत की पूर्ण कमी दर्ज की गयी जबकि 1981-82 की इसी अवधि के दौरान 7.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। उपभोक्ता वस्तुओं के संबंध में 0.6 प्रतिशत की सामान्त वृद्धि हुई जबकि 1981-82 में इसमें 10.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी थी। मध्यवर्ती वस्तु उद्योग में 3.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो 1981-82 में हुई 3.3 प्रतिशत के लगभग बराबर ही थी। मूल उद्योगों के संबंध मे, 1982-83 (जुलाई–मार्च) में 8.4 प्रतिशत की वृद्धि भी खासी रही, लेकिन पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह वृद्धि 11.0 प्रतिशत की रही थी।

8. पिछले वर्षों के औद्योगिक उत्पादन सूचकांकों को देखने से यह जाहिर होता है कि हर वर्ष इसमें तेजी से उतार-चढ़ाव आना एक सामान्य बात रही है। 1975-76 (जुलाई जून) में सूचकांक में वृद्धि की दर 10.5 प्रतिशत थी जो 1979–80 में 1.9 प्रतिशत ही रह गयी। 1971 -72 से लेकर 12 वर्षों की अवधि में केवल 3 वर्ष में सूचकांक में 7.0 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई, जबकि 3 वर्षों में यह वृद्धि 3.0 प्रतिशत से कम रही। लेकिन उद्योग की उत्पादन वृद्धि की दर के धीमेपन के अनेक वर्षों के दौरान, इस कमी का मुख्य कारण बिजली और अन्य मूलभूत सुविधाओं का अभाव रहा 1982 83 का वर्ष इस दृष्टि से उल्लेखनीय रहा कि इसमें मूलभूत सुविधाओं के क्षेत्र का कार्य निष्पादन कुल मिलाकर अच्छा रहा।

9. वित्तीय वर्ष 1982-83 में देश में बिजली का उत्पादन पिछले वर्ष की इस अवधि के उत्पादन की अपेक्षा 7.0 प्रतिशत अधिक रहा। ताप (थर्मल) और अणुशक्ति से बिजली के उत्पादन में 13.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई जिसने जल विद्युत में हुई 2.6 प्रतिशत की कमी को काफी हद तक पूरा कर दिया 1,31.6 बिलियन किलोवाट बिजली का कुल उत्पादन, वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य से 0.4 बिलियन किलो वाट कम था। इसके अतिरिक्त बिजली के उत्पादन में वृद्धि की दर देश भर में एक समान नहीं रही। दक्षिण और पूर्व जैसे कुछ क्षेत्र ऐसे थे जिनमें बिजली की कमी की समस्या गंभीर रही और इसने इन क्षेत्रों में स्थित उद्योगों के उत्पादन को गंभीर रूप से प्रभावित किया। इस वित्तीय वर्ष के दौरान, कोयले का उत्पादन 1304.0 लाख टन हुआ जो पिछले वर्ष के उत्पादन स्तर से 4.4 प्रतिशत अधिक था। लेकिन, उसी गति से कोयले का उठाव न होने की वजह से यह भंडारों में जमा पड़ा रहा बिक्री योग्य इस्पात के उत्पादन में 0.5 प्रतिशत की मामूली सी वृद्धि हुई। लेकिन यहां भी भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० के पास इसका स्टाक इकट्ठा हो गया यह दोनों ही बातें इस बात की सूचक हैं कि उपयोग करने वाले उद्योग की मांग में कमी हुई है। पैट्रोलियम रिफायनरी उत्पादों और कच्चे तेल दोनों के उत्पादन में क्रमशः 10.3 प्रतिशत और 30.1 प्रतिशत की पर्याप्त वृद्धि हुई। सीमेंट में 11.6 प्रतिशत की तथा नाईट्रोजनयुक्त और फास्फेटिक उर्वरकों के उत्पादन में क्रमः 8.9 प्रतिशत और 3.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 1982-83 में रेल के राजस्व अर्जित करने वाले यातायात में 3.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

10. औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर में कमी लाने वाले कारण औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि की नीची दर की व्यवस्था करते समय हमें यह बात ध्यान में रखनी होगी कि औद्योगिक उत्पादन में चालू सूचकांकों में भार, 1970 के लिए उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर प्राप्त विभिन्न उद्योगों द्वारा निर्माण के जरिये मूल्य में किये गये अंशदान से लिये जाते हैं। तदनुसार कुछ नये और तेजी से उभरते हुए उद्योगों जैसे कूड, पैट्रोलियम कूड तथा कतिपय इंजीनियरी उद्योगों के सूचकांक में कम भार है।

11. एक महत्वपूर्ण घटक, जिसने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान औद्योगिक उत्पादन को स्पष्टतः प्रभावित किया है, वह है भयंकर सूखे के कारण मांग पर पूर्णतः प्रतिकूल प्रभाव और उसके परिणामस्वरूप कृषि आय में कमी। उद्योग द्वारा पिछले वर्ष (जुलाई-जून) के दौरान, 7.6 प्रतिशत पर दर्ज की गयी वृद्धि दर काफी अच्छी थी। स्वभावतः कृषि की दृष्टि से कमजोर इस वर्ष में इस प्रवृत्ति को बनाये नहीं रखा जा सका। कृषि उत्पादन और आय में कमी से मांग पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले इस सामान्य घटक के अलावा कुछ और भी ऐसे कारण थे जिनकी वजह से उत्पादन में कमी आयी। ये मूलतः उद्योग–विशेष से संबंधित थे। बहुत बड़े निर्माण उद्योग सूती वस्त्र उद्योग के मामले में बम्बई मिलों में लंबी हड़ताल ने न केवल सूती वस्त्र के उत्पादन को प्रभावित किया, बल्कि रसायनों, टैक्सटाईल मशीनरी जैसे अन्य औद्योगिक समूहों के उत्पादों की मांग को भी प्रभावित किया। कुछ अन्य उद्योगों, को, उदाहरण के लिए वाणिज्यिक वाहन और कृषि के लिए ट्रैक्टरों आदि को, पिछले दो वर्षों के दौरान उत्पादन में काफी वृद्धि हो जाने के कारण वर्ष के दौरान अपने उत्पादन में कमी करनी पड़ी। इस मामलों में उत्पादन में धीमेपन का कारण रहा है मांग से पूर्ति का समायोजन। जैसाकि पहले बताया जा चुका है, बिजली उत्पादन में वृद्धि के बावजूद उपलब्धता और आवश्यकता के बीच अंतराल रहा जिसने विशेष रूप से दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्रों में उद्योगों को प्रभावित किया। निर्यात मांग में गिरावट ने उद्योगों उदाहरण के लिए जूट निर्माण में 17.5 प्रतिशत की गिरावट ने उत्पादन को धीमा कर दिया यह दावा किया जाता है कि उधार आयातों ने कुछ वस्तुओं के घरेलू उत्पादन पर प्रभाव डाला है। बार बार मोडा-आर का उदाहरण दिया जाता है जिसके मामले में 1979-80 और उसके बाद काफी मात्रा में आयात किया गया। हां, 1982-83 में आयात काफी कम हो गया अनुमान है कि समग्र रूप में वर्ष के दौरान उत्पादन पिछले वर्ष के स्तर पर ही पहुंचा है तथा वर्ष के अन्तर में स्टाक काफी कम थे।

12. राष्ट्रीय आय, बचत तथा निवेश—कृषि उत्पादन में कमी तथा औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर में गिरावट आने के कारण राष्ट्रीय आय पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। रिजर्व बैंक के अनुमानों के अनुसार 1982-83 में वास्तविक निवल राष्ट्रीय उत्पादन की वृद्धि दर एक और दो प्रतिशत के बीच रही जबकि 1981-82 और 80-81 में यह वृद्धि दर क्रमशः 5.0 प्रतिशत और 8.1 प्रतिशत थी। अनन्तिम अनुमान लगाया गया है कि 1982-83 में कुल शुद्ध घरेलू बचत चालू बाजार मूल्यों पर, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन के 16.8 प्रतिशत के बराबर रहेगी। 1981-82 में यह 16.5 प्रतिशत थी। इससे अनुमानित बचत में थोड़ी सी वृद्धि का पता चलता है। कुल बचत की दर में स्थिरता मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र की बचत में 0.8 प्रतिशत पाइंट की सामान्य गिरावट तथा घरेलू क्षेत्र की बचत में 1.1 प्रतिशत की वृद्धि के कारण आयी थी। हां, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन में घरेलू निजी निगमित क्षेत्र की बचत का हिस्सा लगातार तीसरे वर्ष में 0.6 प्रतिशत रहने का अनुमान है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन से प्रतिशतता के रूप में शुद्ध देशी बचत और निवेश के अनुमान आगे की सारणी में दिये गये हैं।

शुद्ध देशी बचत एवं निवेश के अनुमान-चालू बाजार कीमतों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन के प्रतिशत के रूप में

क्षेत्र/मद	राजकोषीय वर्ष		
	1980-81	1981-82	1982-83 (अनंतिम)
1	2	3	4
1. घरेलू क्षेत्र, जिसमें से	13.4	12.6	13.7
(क) वित्तीय परिसंपत्तियों में बचत	6.8	6.2	8.0

1	2	3	4
2. सार्वजनिक क्षेत्र	2.1	3.3	2.5
3. देशी निजी निगम क्षेत्र	0.6	0.6	0.6
4. कुल शुद्ध देशी बचत (1+2+3)	16.1	16.5	16.8
5. विदेशी स्रोतों का आगमन	1.9	2.6	2.0
6. कुल शुद्ध निवेश (4+5)	18.0	19.1	18.8

टिप्पणी : 1980-81 तथा 1981-82 के अनुपात पिछले वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट के अनुपात से मेल नहीं खाते क्योंकि राष्ट्रीय आय के अनुमानों में बाद में तथा और आंकड़े उपलब्ध होने पर बचत एवं निवेश में संशोधन किये गये।

13. वित्तीय आस्तियों के रूप में घरेलू क्षेत्र की बचत के अनुपात में उल्लेखनीय सुधार हुआ और यह 1981-82 के शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन के 6.2 प्रतिशत से बढ़कर, 1982-83 में 8.0 प्रतिशत हो गया। इसका श्रेय विशेष रूप से, मुद्रा और जमाराशियों में घरेलू क्षेत्र की बचत में वृद्धि को है। जमाराशियों में वृद्धि मुख्य रूप से वाणिज्य बैंकों के संबंध में हुई। मुद्रा के रूप में ऋण क्षेत्र की बचत 1981-82 में शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन के 0.7 प्रतिशत से बढ़कर, 1982-83 में, 1.3 प्रतिशत हो गयी जबकि जमाराशियों के रूप में बचत, 1981-82 के 4.3 की तुलना में, 1982-83 में अधिक अर्थात् 5.1 प्रतिशत रही। पिछले वर्ष विशेष वाहक बांडों में निवेश के कारण भारत सरकार पर जो दावे काफी बढ़ गये थे, उनमें 1982-83 में भारी गिरावट आयी। इसी तरह, घरेलू क्षेत्र की देयताएं पिछले वर्ष के 2.8 प्रतिशत से घट कर 1982-83 में, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन के 2.5 प्रतिशत के बराबर रह गयीं। यह गिरावट पूरी तरह से वाणिज्य बैंकों के ऋणों में गिरावट के कारण थी।

14. हालांकि, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने अपने कार्य निष्पादन में सुधार किया, लेकिन केन्द्रीय सरकार के प्रशासन में बचत न होने और राज्य सरकारों तथा उनके विभागीय उपक्रमों में बचत में गिरावट के कारण वर्ष के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की अनुमानित बचतों में कमी आयी।

15. शुद्ध देशी बचतों में सीमांतिक वृद्धि के बावजूद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन के रूप में शुद्ध निवेश 1981-82 के 19.1 प्रतिशत से घटकर, 1982-83 में 18.8 प्रतिशत रह गये। यह गिरावट विदेशों से संसाधनों की प्राप्ति में कुछ कमी के कारण आयी।

16. ऋण नीति विषयक गतिविधियां—1982-83 के अधिकांश भाग में ऋण नीति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना रहा कि ऋण वृद्धि की गति इतनी बनी रहे कि उत्पादन की मौजूदा रफ्तार में तेजी आये और यह बराबर बनी रहे और साथ ही-साथ मुद्रास्फीतिगत संभावनाओं की वृद्धि पर रोक लगायी जा सके। उद्योगों के चुने हुए क्षेत्रों, जैसे कि पूंजीगत-वस्तु क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया जो कि मांग की कमी के कारण पीड़ित थे। सामान्य मूल्य स्तर में सापेक्ष स्थिरता को देखते हुए वाणिज्य बैंकों की उधार ब्याज-दर में कमी की गयी। अलबत्ता, कृषि उत्पादन में गिरावट तथा मूल्यों में तीव्र वृद्धि को देखते हुए ऋण-नीति में, हाल ही में, परिवर्तन आया है और अब सावधानी और संयम से काम लिया जा रहा है। कम काम के मौसम के लिए निर्धारित नीति इस समय चालू है। इसका लक्ष्य यह है कि नकदी प्रारक्षित अनुपात को बढ़ा कर बैंकिंग प्रणाली में उपलब्ध अतिरिक्त नकदी को निष्क्रिय किया जाय तथा वर्ष के दौरान ऋण प्रवाह को ज्यादा से ज्यादा सुचारू बनाया जाये।

17. नीति विषयक उपाय, जुलाई 1982—पिछले वर्ष की रिपोर्ट में उल्लेख के अनुसार अप्रैल और जुलाई 1982 के बीच ऋण नीति में इस बात पर बल दिया गया था कि ऋण संबंधी कार्यों में सामान्य स्थिति फिर से स्थापित हो। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए तथा बैंकों द्वारा अनुभव किये जा रहे नकदी के दबाव को कम करने की दृष्टि से नकदी प्रारक्षित अनुपात को घटाया गया तथा 1981-82 के उत्तरार्ध में पुनर्वित्त फार्मूलों को उदार बनाया गया। वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए जुलाई 1982 में जारी किये गये ऋण-विस्तार विषयक मार्गदर्शी सिद्धांतों में बताया गया कि खाद्येतर ऋण के विस्तार में लगभग 16.8 प्रतिशत की वही वृद्धि दर बनी रहे जो 1981-82 में थी। इसका अर्थ यह हुआ कि समस्त प्रणाली के लिए यह वृद्धि लगभग 4,600 करोड़ रुपये होगी जबकि पिछले वर्ष वास्तविक वृद्धि 3,943 करोड़ रुपये की थी। उस स्तर पर यह अनुमान लगाया गया था कि 1982-83 में समस्त बैंकिंग प्रणाली की कुल जमाराशियां 6,600 करोड़ रुपये से 7,000 करोड़ रुपये के बीच होंगी। ऐसा प्रतीत हुआ कि 1982-83 के व्यस्त मौसम के दौरान धन की कुछ कमी पड़ सकती है। रिज़र्व बैंक ने यह संकेत दिया कि वास्तविक ऋण आवश्यकताओं की सीमा तक वह इस कमी को पूरा करने और बैंकों के साधनों में सहायता करने को तैयार है।

18. नीति विषयक उपाय, अक्तूबर 1982—व्यस्त मौसम के दौरान अक्तूबर 1982 में की गयी पुनरीक्षा से यह पता चला कि, अर्थव्यवस्था की विकास की दर में कमी आ रही है। अतः इस संबंध में विशेष रूप से प्राथमिक मुद्रा सृजन के संबंध में, निरंतर सावधानी बरतने की आवश्यकता महसूस की गयी। साथ ही, अर्थव्यवस्था के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को भी प्रोत्साहन देने की आवश्यकता थी जो मांग में कमी की समस्या से पीड़ित थे। ऐसी स्थिति में ऋण नीति को इस प्रकार निर्धारित करना आवश्यक हो गया कि वह मुद्रा-प्रसार को फिर से बढ़ावा दिये बिना उपलब्ध क्षमताओं के पूर्ण उपयोग में सहायता कर सके। एक ओर अर्थ-व्यवस्था की वास्तविक उत्पादन आवश्यकताओं के लिए बैंक ऋण के विस्तार की आवश्यकता थी तो दूसरी ओर मुद्रा प्रसार प्रवृत्तियों को रोकने के लिए ऋण विस्तार पर सावधानीपूर्वक नियंत्रण करना आवश्यक था। इस तरह, 25 अक्तूबर, 1982 को घोषित ऋण विषयक नीति उपाय, बचत को बढ़ावा देने, संभावित मुद्रा प्रसार को रोकने और मौद्रिक विस्तार पर इस प्रकार नियंत्रण रखने की आवश्यकताओं पर आधारित थे कि कुछ क्षेत्रों की गतिविधियों के प्रोत्साहन के लिए अधिक ऋण उपलब्ध हो जाये।

19. जमाराशियों का नया वर्ग—26 अक्तूबर, 1982 से, पांच वर्ष और उससे अधिक की मियादी जमाराशियों के वर्ग को फिर से प्रारंभ किया गया और उन पर 11 प्रतिशत की दर से ब्याज देने की अनुमति प्रदान की गयी। यह कदम बैंक जमाराशियों विषय कार्यकारी दल की सिफारिशों के अनुसरण में उठाया गया। यह स्मरणीय है कि पांच वर्ष और उससे अधिक अवधि की मीयादी जमाराशियों के वर्ग को मार्च 1981 में समाप्त कर दिया गया था और तीन वर्ष तथा उससे अधिक की अवधि की मीयादी जमाराशियों पर अधिकतम ब्याज की दर 10 प्रतिशत रखी गयी थी। अधिक ब्याज दर पर दीर्घावधि मियादी जमाराशियों के वर्ग को पुनः प्रारंभ करने का उद्देश्य अधिक अवधि की बैंक जमाराशियों के रूप में बचतों पर अधिक लाभ देना तथा जमाराशि जुटाने के बैंकों के प्रयासों में सहायता पहुंचाना था। इस समय उधार की ब्याज दर में कोई परिवर्तन नहीं किया गया लेकिन यह संकेत दिया गया कि उधार की ब्याज दर में कमी करने के प्रश्न पर बाद में विचार किया जायेगा।

20. पुनर्वित्त समायोजन—बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक से अधिक वित्तीय सहायता मिल सके, इस दृष्टि से पुनर्वित्त फार्मूलों में कुछ समायोजन किये गये। 26 अक्तूबर, 1982 के अंत तक बैंकों को खाद्यान्न ऋण में 2,200 करोड़ रुपये के स्तर से ऊपर की वृद्धि के लिए 50 प्रतिशत की सीमा तक और 2600 करोड़ रुपये के खाद्यान्न ऋण के बकाया स्तर के ऊपर की बकाया के लिए 100 प्रतिशत पुनर्वित्त उपलब्ध कराया गया था। पहली नवम्बर 1982 से 2,200 करोड़ रुपये के स्तर से अधिक की राशि पर आंशिक पुनर्वित्त समाप्त कर दिया गया और बैंकों को 2,500 करोड़ रुपये के बकाया स्तर के ऊपर पूर्ण (100 प्रतिशत)

पुनर्वित्त उपलब्ध कराया गया। निर्यात पुनर्वित्त के संबंध में, पात्रता (वृद्धि का 50 प्रतिशत) की गणना के लिए आधार स्तर को वार्षिक रूप से आगे लाये जाने की सामान्य पद्धति में संशोधन किया गया। संशोधित पद्धति के अनुसार अब बैंक निर्यात-ऋण के 1960 के मासिक औसत स्तर में 1981 के मासिक औसत स्तर तक वृद्धि हुई के 50 प्रतिशत तक और निर्यात ऋण के मासिक औसत स्तर में हुई वृद्धि के शत प्रतिशत तक के पुनर्वित्त के लिए पात्र हो गये। आशा है कि इससे निर्यात ऋण क्षमता में बिना किसी बाधा के वृद्धि हो सकेगी।

21. निवेश को प्रोत्साहन—निवेश के प्रोत्साहन के लिए जो उपाय किये गये वे चयनात्मक रूप से लागू किये गये और उनका लक्ष्य पूंजीगत और मध्यवर्ती वस्तुओं में निवेश को प्रोत्साहन देना था। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को यह वचन दिया गया कि साधनों और नियोजन के बीच असंतुलन की दशा में उसे वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाएगी ताकि राज्य बिजली बोर्डों और राज्य सड़क परिवहन निगमों को अतिरिक्त सीमा की मंजूरी को सुनिश्चित किया जा सके। राज्य सड़क परिवहन निगमों के मियादी ऋण में बैंकों के हिस्से की अधिकतम सीमा को परियोजना लागत के मियादी ऋण घटक के 25-30 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दिया गया। ट्रैक्टर और ट्रक खरीदने के लिए बैंक ऋणों के संबंध में लागू मार्जिन को 25 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया। निजी क्षेत्र की ऐसी पार्टियों के मामले में जो ऋण प्राधिकरण योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं (तीन वर्ष से अधिक वाले) मियादी ऋणों के लिए ऐसी अधिकतम सीमा को, जिसके लिए रिजर्व बैंक का पूर्व प्राधिकरण आवश्यक होता है, 25 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दिया गया। ऋण प्राधिकरण योजना में न आनेवाली निर्यात अभिमुख बड़ी निर्माण इकाइयों के मामले में, जिनका वार्षिक औसत निर्यात पण्यावर्त पिछले तीन वर्षों में कुल पण्यावर्त का 25 प्रतिशत से अधिक रहा हो, ऐसे मियादी ऋणों (तीन वर्ष से अधिक) की अधिकतम सीमा को, जिसके लिए रिजर्व बैंक का पूर्व प्राधिकरण आवश्यक है, 25 लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये कर दिया गया।

22. ऋण प्राधिकरण योजना की क्रियाविधि में परिवर्तन—निर्यात ऋण सीमाओं की अधिक तेजी से मंजूरी की दृष्टि से ऋण प्राधिकरण योजना की क्रियाविधियों को भी और उदार बनाया गया। ऐसी बड़ी निर्यात अभिमुख निर्माण इकाइयों के मामले में, जिनका निर्यात अंश कुल पण्यावर्त का 25 प्रतिशत से अधिक था, ऋण प्राधिकरण योजना के लिए अधिकतम सीमा को 3 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये कर दिया गया साथ ही, ऐसी अतिरिक्त पैकिंग ऋण सीमाओं की मंजूरी के संबंध में भी ढील दी गयी जिनके लिए पूर्व प्राधिकरण आवश्यक था।

23. अन्य रियायती उपाय—इस समय जो अन्य उपाय घोषित किये गये वे प्राथमिकता वाले अथवा वरीयता वाले क्षेत्रों को ऋण से संबंधित थे। राज्यों द्वारा प्रायोजित अनुसूचित जातों/अनुसूचित जनजातियों के संगठनों को अग्रिमों के मामले में 13.5 प्रतिशत की रियायती दर की घोषणा की गयी। कुल बैंक ऋणों में आवास हेतु वित्त के लिए निर्धारित राशि को 100 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 150 करोड़ रुपये कर दिया गया।

24. उधार की ब्याज दरों में कमी—मुद्रा-प्रसार की कम दर को देखते हुए यह महसूस किया गया कि ब्याज की वास्तविक दरें काफी ऊंची हैं। अतः यह निर्णय किया गया कि पहली अप्रैल 1983 से ब्याज-दरों में कमी लायी जाये। सरकार ने भी पहली अप्रैल, 1983 से, ब्याज से अर्जित आय पर कर की दर को घटाकर, आधा करके इस संबंध में अपना योगदान दिया।

25. ब्याज दरों में कमी—0.25 प्रतिशत पाईंट से 1.5 प्रतिशत पाईंटों के बीच की गयी और अधिकतम कमी 19.5 प्रतिशत से 18.0 प्रतिशत के बीच की गयी।

इन परिवर्तनों की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित हैं —

(1) ऐसी ब्याज दरों के मामले में, जो 17.5 प्रतिशत और 19.5 प्रतिशत अथवा 17.5 प्रतिशत से अनधिक और 19.5 प्रतिशत से 'अनधिक' पर निर्धारित की गयी थीं, निम्न प्रकार से अनुदिक कमी की गयी है :—

ब्याज दर (प्रतिशत वार्षिक)	
31 मार्च 1983 तक प्रभावी	1 अप्रैल 1983 से प्रभावी
17.5	16.5
17.5 से अनधिक	16.5 से अनधिक
19.5	18.0
19.5 से अनधिक	18.0 से अनधिक

(2) कृषि के लिए अल्पावधि ऋणों के मामले में 1.0 प्रतिशत बिंदु की अनुदिक कमी की गयी।

(3) लघु उद्योगों को अल्पावधि ऋणों के मामले में जो उपर्युक्त (1) में की गयी कमी में शामिल नहीं हैं, की गयी कमी 0.25 प्रतिशत पाईंट से 1.0 प्रतिशत पाईंट के बीच रही।

(4) निर्यातों के लिए अल्पावधि ऋणों के मामले में 0.5 प्रतिशत पाईंट की कमी की गयी।

(5) कारीगरों, ग्रामीण और कुटीर उद्योगों को सहायता देने वाले राज्यस्तरीय निगमों तथा राज्यों द्वारा प्रयोजित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विकास निगमों के मामले में 1.0 प्रतिशत पाईंट की कमी की गयी।

26. ब्याज दरों में कमी का उद्देश्य बड़े और मध्यम आकार के उद्योगों, कृषि, लघु उद्योगों और निर्यातकों सहित ऋणकर्ताओं के एक बड़े वर्ग को राहत पहुंचाना था। ऐसे वर्गों की ब्याज दरों में, जिनमें सितंबर 1979 से सबसे अधिक वृद्धि हुई थी, अन्य ऐसे वर्गों की अपेक्षा कुछ अधिक कमी की गयी जिनमें, सितंबर 1979 से, अपेक्षाकृत बहुत कम वृद्धि हुई थी और जिनमें पहले ही रियायत का महत्वपूर्ण अंश मौजूद था। यह आशा की जाती है कि उधार के संशोधित ब्याज-दर ढांचे से वास्तविक उत्पादन की वृद्धि को प्रोत्साहन मिलेगा।

27. नीति विषयक उपाय—अप्रैल 1983—अप्रैल 1983 के अंतिम सप्ताह में जब ऋण नीति की पुनरीक्षा की गयी तो यह दिख रहा था कि वास्तविक वृद्धि में गिरावट आ रही है। दूसरी मुख्य बात थी प्राथमिक मुद्रा में उल्लेखनीय वृद्धि तथा वाणिज्यिक ऋण की मांग में कमी। इन परिस्थितियों के कारण बैंकिंग तंत्र में बड़ी मात्रा में अतिरिक्त नकदी जमा हो गयी। यह भी अनुभव किया गया कि अतिरिक्त नकदी की समस्या कुछ ही समय रहेगी क्योंकि कृषि और औद्योगिक उत्पादन में

वृद्धि के कारण ऋण की मांग में वृद्धि अपेक्षित थी। लेकिन, मांग में यह वृद्धि 1983-84 के वित्तीय वर्ष के उत्तरार्द्ध में ही दिखायी देने की संभावना थी। इस बीच अतिरिक्त नकदी के कारण उत्पन्न होनेवाले संभावित मुद्रा-प्रसार पर नियंत्रण करना आवश्यक था और यह नियंत्रण इस प्रकार से किया जाना था कि उत्पादन की आवश्यक प्रक्रियाओं पर इनका कोई बुरा प्रभाव न पड़े। अतः स्थिति की मांग यह थी कि नकदी के संतुलित उपयोग को सुनिश्चित किया जाये ताकि वास्तविक उत्पादक आवश्यकताओं को पूरे वर्षभर, पर्याप्त रूप से पूरा किया जा सके।

28. वित्तीय वर्ष 1983-84 में ऋण विस्तार से संबंधित मार्गदर्शी सिद्धांत कुछ विस्तृत रूप में जारी किये गये। कार्यकारी अनुमानों के अनुसार 1983-84 में जमाराशियों की वृद्धि 8,000 करोड़ रुपये आंकी गयी जो 1982-83 में 7,100 करोड़ रुपये से थोड़ी अधिक थी बैंकों से यह कहा गया कि वे 1983-84 की प्रथम तिमाही तथा प्रथम छिमाहीं में प्रारंभिक रूप से अधिक ध्यान दें क्योंकि उस समय बैंकिंग तंत्र में समग्र नकदी की स्थिति में सुधार की आशा की गयी थी, हालांकि यह नकदी बैंकों के बीच असमान रूप से वितरित होगी। फिर भी, अनुमान यह था कि बैंक 1,500 करोड़ रुपये का ऋण विस्तार कर सकेंगे जो विद्यमान परिस्थितियों में पर्याप्त समझा गया।

29. अतिरिक्त नकदी का प्रबंध—यह अनुमान लगाया गया कि बैंक उपर्युक्त ऋण विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक से पुनर्वित्त सहायता लिये बिना, अपने स्वयं के साधनों से कर सकेंगे और साथ ही लगभग 1,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त नकदी का सृजन कर सकेंगे। अतः यह विवेक सम्मत समझा गया कि वर्ष की प्रथम छमाही में नकदी को बचा कर रखा जाए और उसका उपयोग केवल वास्तविक उत्पादक ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही किया जाये। अतः घोषित किये गये मुख्य नीति विषयक उपाय में जो निवेश दिये गये उनका उद्देश्य नकदी को बचाये रखने में सहायता पहुंचाना था। नकदी प्रारक्षित अनुपात को शुद्ध मांग और समय देयताओं के 7 प्रतिशत से बढ़ाकर 8 प्रतिशत कर दिया गया। यह वृद्धि दो चरणों में प्रभावी की जानी थी: मई 1983 से 0.50 प्रतिशत पाईंट की वृद्धि से 7.50 प्रतिशत और 29 जुलाई 1983 से 0.50 प्रतिशत की दूसरी ऐसी वृद्धि जो प्रारक्षित नकदी अनुपात को 8 प्रतिशत तक पहुंचा दे। इस बात पर जोर दिया गया कि नकदी प्रारक्षित अनुपात में यह वृद्धि अस्थायी नकदी को उस समय तक समाहित करने के लिए की गयी है जब तक कि उत्पादक ऋण के रूप में निधियों के नियोजन के लिए उपयुक्त परिस्थितियां तैयार नहीं हो जाती। इसके साथ ही, रिज़र्व बैंक के पास न्यूनतम 3 प्रतिशत से अधिक मात्रा में रहनेवाले बैंकों के जमाशेषों पर दिये जानेवाले ब्याज की दर भी पहली मई 1983 से 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 9 प्रतिशत कर दी गयी*। इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि अतिरिक्त नकदी बैंकिंग-तंत्र में असमान रूप से वितरित है, ऐसे बैंकों को जो प्रारक्षित नकदी के बढ़ाये गये अनुपात को पूरा करने में कठिनाइयां महसूस कर रहे थे, यह आश्वासन दिया गया कि उन्हें मामले के गुणदोषों के आधार पर, अल्पावधि के लिए, विवेकाधीन पुनर्वित्त उपलब्ध कराया जायेगा। खाद्य पुनर्वित्त फार्मूले के संबंध में बकाया खाद्य ऋणों की उस अधिकतम सीमा को जिस पर बैंकों को शत प्रतिशत पुनर्वित्त उपलब्ध था, पहली जुलाई 1983 से 2,500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2,800 करोड़ रुपये कर दिया गया।

30. अन्य उपाय —अन्य उपाय कुछ चुने हुए क्षेत्रों को प्रोत्साहन देने के लिए किये गये। अक्तूबर 1982 में राज्य बिजली बोर्डों और राज्य सड़क परिवहन निगमों को अतिरिक्त सीमाओं की मंजूरी के लिए, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के साधनों में वृद्धि की जो व्यवस्था की गयी थी उसे चालू रखा गया। ऋण नीति की पुनर्वितरण की वरीयताओं को सुदृढ़ करने की दृष्टि से अनुसूचित जातियों/जनजातियों के स्वनियोजित लोगों तथा महिलाओं को दिये जानेवाले बैंक ऋणों पर ब्याज की दरों में कमी की गयी। उर्वरकों के खुदरा व्यापार और बीज के उत्पादन और वितरण के संबंध में लागू ब्याज दरों में भी कमी लायी गयी। बैंकों को सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से निर्यात पुनर्वित्त के लिए बैंकों की पात्रता के संबंध में अपनाये जा रहे वर्तमान आधार में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। यह सुनिश्चित करने के लिए कि छोटे पैमाने के पूर्तिकर्ताओं को अपने बिलों का भुगतान बड़े पैमाने के उत्पादकों से शीघ्रतापूर्वक मिल सके, पहले से निर्धारित कुछ ऋण-मानदंडों पर फिर से जोर दिया गया ताकि उन्हें और अधिक प्रभावी रूप से लागू किया जा सके।

31. नकदी की बड़ी मात्रा में उपलब्धता में मुद्रा प्रसार की आशंका निहित है। अतः वर्तमान ऋण नीति विषयक उपायों का उद्देश्य इस अल्पकालीन अतिरिक्त नकदी को बैंकिंग प्रणाली में समाहित करना है। लेकिन, साथ ही, यह स्पष्ट कर दिया गया है कि परिस्थितियों की मांग के अनुसार नीति में परिवर्तन किये जा सकते हैं। ऋण नीति के लचीलेपन को तथा आर्थिक स्थिति के अल्पकालीन परिवर्तन के बारे में त्वरित प्रतिक्रिया कर सकने की इसकी क्षमता को अतीत काल में पूरी तरह से प्रदर्शित किया जा चुका है। वर्तमान परिस्थितियों में यह अपरिहार्य है कि ऋणनीति का जोर सावधानी पर रहे।

32. मुद्रा, ऋण तथा मूल्यों की प्रवृत्तियां—समीक्षाधीन वर्ष के दौरान मुद्रा पूर्ति में वृद्धि की दर पिछले वर्ष की तुलना में ऊंची थी सारणी 1 देखने से पता चलेगा कि 1982-83 (जुलाई-जून) में एम[1] में 12.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि पिछले वर्ष 10.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। एम[3] (एम[1]+मीयादी जमाराशियों) के रूप में वृद्धि 12.9 प्रतिशत की तुलना में 15.3 प्रतिशत रही।

*प्रारक्षित नकदी अनुपात 27 अगस्त, 1983 से आधा प्रतिशत पाइंट और बढ़ाकर 8.5 प्रतिशत कर दिया गया था।

सारणी 1—मुद्रा स्टॉक (एम 3) में घट-बढ़

(करोड़ रुपये)

	(जून 1981 के अंत से जून 1982 तक)		जून 1982 के अंत से जून 1983 तक + @	
	पूर्ण	प्रतिशत	पूर्ण	प्रतिशत
	1	2	3	4
1. एम3 (क+ख+ग):				
	+7,556	+12.9	+10,108	+15.3
(क) जनता के पास मुद्रा	+1,662	+12.0	+2,378	+15.3
(ख) बैंकों के पास कुल जमा-राशियां (I+II)				
	+6,021	+13.6	+7,683	+15.2

	1	2	3	4
(I) मांग जमाराशियां	+972	+9.8	+835	+7.7
(II) मीयादी जमाराशियां	+5,049	+14.6	+6,848	+17.3
(ग) रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाराशियां	—127	—51.8	+47	+39.8
I. एम1 (क+ख(i)+ग)	+2,507	+10.4	+3,260	+12.3
III. मुद्रा स्टॉक के स्त्रोत (एम3) (1+2+3+4—5)				
1. सरकार को शुद्ध बैंक ऋण (अ+आ)	+6,284	+22.2	+4,933	+14.2
(अ) सरकार को रिजर्व बैंक का शुद्ध ऋण (I-II)	+4,615	+25.6	+3,044	+13.4
(I) सरकार पर दावे (क+ख)	+4,716	+25.7	+3,397	+15.7
(क) केन्द्र सरकार	+4,836	+26.7	+3,184	+13.9
(ख) राज्य सरकारें	—120	—49.0	+213	+170.4
(II) रिजर्व बैंक के पास सरकारी जमाराशियां (क+ख)	+100	+33.3	+353	+88.3
(क) केन्द्र सरकार	—61	—28.5	+400	+261.4
(ख) राज्य सरकारें	+161	+187.2	+47	+19.4
(आ) सरकार को अन्य बैंकों का ऋण	+1,665	+16.2	+1,869	+15.7
2. वाणिज्य क्षेत्र को बैंक ऋण (अ+आ)	+6,402	+16.9	+7,745	+17.5
(अ) वाणिज्य क्षेत्र को रिजर्व बैंक का ऋण	+417	+23.6	+291	+13.3
(आ) वाणिज्य क्षेत्र को अन्य बैंक ऋण (I+III+1)	+5,985	+16.6	+7,454	+17.7
(i) वाणिज्य बैंकों द्वारा बैंक ऋण	+3,630	+13.7	+5,750	+19.9
(ii) सहकारी बैंकों द्वारा बैंक ऋण	+1,230	+25.4	+564	+9.3
(iii) वाणिज्य एवं सहकारी बैंकों द्वारा अन्य प्रतिभूतियों में निवेश	+1,125	+24.3	+1,140	+19.8
3. बैंकिंग क्षेत्र की शुद्ध विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां (अ+आ)	—1,955	—46.2	—381	—16.7
(अ) रिजर्व बैंक की शुद्ध विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां (i—ii)	—1,955	—45.7	—381	—16.4
(i) सकल विदेशी परिसंपत्तियां	—1,053	—23.1	+1,531	+43.7
(ii) मुद्रेतर विदेशी देयताएं	+902	+330.4	+1,912	+162.7
(आ) दूसरे बैंक की शुद्ध विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां	—	—	—	—
4. जनता को सरकार की मुद्रा देयतायें	+36	+5.7	+7	+1.0

	1	2	3	4
5. मीयादी जमाराशियों के अलावा बैंकिंग क्षेत्र की शुद्ध मुद्रेतर देयतायें (अ+आ)	+3,211	+25.9	+2,176	+13.9
(अ) रिजर्व बैंक की शुद्ध मुद्रेतर देयतायें	+1,371	+27.7	+119	+1.9
(आ) अन्य बैंकों की शुद्ध मुद्रेतर देयतायें (गृहीत)	+1,840	+24.7	+2,057	+22.1

+अनन्तिम

@नाबार्ड की स्थापना के कारण अपेक्षित कुल राशियों के पुनर्वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ये घट-बढ़ 12 जुलाई, 1982 के स्तोत के घटकों में परिवर्तनों से मेल नहीं खाती ।

*नाबार्ड की स्थापना के बाद से बैंकों का इसके द्वारा दिया गया पुनर्वित्त शामिल नहीं है ।

टिप्पणी : (1) चूंकि अलग-अलग मदों के आंकड़े पूर्णांकित किये गये हैं, इसलिये जोड़ों में वे वृद्धि नहीं कर सकते ।
(2) रिजर्व बैंक के आंकड़े जून के अंतिम दिन के हैं ।अन्य आंकड़े जून के अंतिम शुक्रवार के हैं ।

33. मुद्रा आपूर्ति—जिन कारणों से यह परिवर्तन हुआ, वे कुछ खास लक्षण बताते हैं । 1982-83 में सरकार को दिये गये शुद्ध बैंक-ऋण में वृद्धि, पिछले वर्ष की तुलना में काफी कम रही । प्रतिशतता की दृष्टि से यह वृद्धि 22.2 प्रतिशत की तुलना में मात्र 14.2 प्रतिशत थी । हालांकि 1982-83 (जुलाई-जून) में वाणिज्य क्षेत्र में बैंक-ऋण में वृद्धि 1,343 करोड़ रुपये के आसपास रही, प्रतिशतता की दृष्टि से इस वृद्धि में 1981-82 की वृद्धि से कोई विशेष अंतर नहीं हुआ । आलू वर्ष के दौरान मुद्रा विस्तार के पीछे एक प्रमुख कारण यह था कि विदेशी मुद्रा आस्तियों में गिरावट के प्रतिकूल प्रभाव मे कमी आयी थी । शुद्ध रूप में 1982-83 में बैंकिंग क्षेत्र की शुद्ध विदेशी मुद्रा आस्तियों में आयी गिरावट मात्र 381 करोड़ रुपये के आसपास रही जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में 1,955 करोड़ रुपये की गिरावट आयी थी ।

34. प्रारक्षित निधियां.—वर्ष के दौरान प्रारक्षित मुद्रा में हुई 13.8 प्रतिशत की वृद्धि 1981-82 की इसी अवधि के दौरान दर्ज की गयी 9.7 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में अधिक है (सारणी 2) । सरकार पर रिजर्व बैंक के दावे पिछले वर्ष के 25.6 प्रतिशत की तुलना में काफी धीमी गति से अर्थात् 13.4 प्रतिशत की दर से बढ़े, जबकि वाणिज्य और सहकारी बैंकों पर दावों में काफी गिरावट देखने में आयी । विदेशी मुद्रा की गिरावट में उल्लेखनीय कमी आयी और वह 1981-82 के 1,955 करोड़ रुपये अथवा 43.7 प्रतिशत से घटकर 1982-83 में 381 करोड़ रुपये अथवा 16.4 प्रतिशत रह गयी ।

35. बैंकिंग चल राशियों में घटबढ़.—सारणी 3 में दिये गये बैंकिंग चल राशियों के आंकड़ों से पता चलता है कि वर्ष के दौरान जमराशियों और ऋणों दोनों ही में हुई वृद्धि 1981-82 की तुलना में अधिक रही और यह भी कि ऋणों में हुई वृद्धि अधिक उल्लेखनीय थी । हालांकि पिछले वर्ष खाद्यान्न ऋणों में अधिक विस्तार हुआ, यह असमानता, मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों सहित वाणिज्य क्षेत्र को गैर-खाद्यान्न ऋणों के कारण रही । गैर खाद्यान्न ऋण में 1981-82 में 3,007 करोड़ रुपये अथवा 12.4 प्रतिशत की तुलना में 1982-83 में 4,987 करोड़ रुपये अथवा 18.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई । रिजर्व बैंक से लिये गये बैंकों के ऋणों में पिछले वर्ष की थोड़ी-सी वृद्धि की तुलना में इस वर्ष 63 करोड़ रुपये की गिरावट आयी । निवेशों में वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में 218 करोड़ रुपये अधिक रही जिससे इस बात का पता चलता है कि अधिक ऋण विस्तार के दबाव के बावजूद बैंकों की नकदी निधि स्थिति काफी अच्छी रही ।

सारणी 2—प्रारक्षित मुद्रा में उतार-चढ़ाव

(करोड़ रुपये)

	(जून 1981 के अंत से जून 1982 के अंत तक)		(जून 1982 के अंत से जून, 1983 के अंत तक)@+	
	पूर्ण	प्रतिशत	पूर्ण	प्रतिशत
I. प्रारक्षित मुद्रा (1+2+3+4)	+2,022	+9.7	+3,142	+13.8
1. जनता के पास मुद्रा	+1,662	+12.0	+2,378	+15.3
2. रिजर्व बैंक के पास अन्य जमा राशियां	—127	—51.8	+47	+39.8
3. बैंकों के पास नकदी	+26	+2.4	—23	—2.1
4. रिजर्व बैंक के पास बैंकों की जमा राशियां	+461	+8.3	+740	+12.2
II. प्रारक्षित मुद्रा के स्त्रोत (1+2+3+4+5+6)				
निम्नलिखित पर रिजर्व बैंक के दावे :				
1. सरकार (शुद्ध)	+4,615	+25.6	+3,044	13.4

	1 पूर्ण	2 प्रतिशत	3 पूर्ण	4 प्रतिशत
2. वाणिज्य एवं सहकारी बैंक	+279	+26.9	—720	—54.7
3. नाबार्ड	—	—	+1,020	—
4. वाणिज्य क्षेत्र*	+417	+23.6	+291	+13.3
5. रिजर्व बैंक की शुद्ध विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां	—1,955	—45.7	—381	—16.4
6. जनता को सरकारी मुद्रा देयतायें	+36	+5.7	+7	+1.0
7. रिजर्व बैंक की शुद्ध मुद्रेतर देयतायें	+1,371	+27.7	+119	+1.9

†अनन्तिम

@नाबार्ड की स्थापना के कारण अपेक्षित कुल राशियों के पुनर्वर्गीकरण के कारण परिणामस्वरूप ये घट-बढ़ 12 जुलाई 1982 के बीच के घटकों में परिवर्तनों से मेल नहीं खाती।

*इस में वित्तीय संस्थाओं तथा भूमि बंधक बैंकों के शेयरों/बांडों में निवेश और उन्हें दिये गये ऋण तथा खरीदे एवं भुनाये गये आतरिक बिलों का धारण करना शामिल है। नाबार्ड की स्थापना के बाद से बैंकों को इसके द्वारा दिया गया पुनर्वित्त शामिल नहीं है।

टिप्पणी : 1. चूंकि अलग-अलग मदों के आंकड़े पूर्णांकित किये हैं, इसलिए जोड़ों में वृद्धि नहीं कर सकते।

2. बैंकों के पास नकदी के आंकड़े अंतिम शुक्रवार से संबंधित हैं। रिजर्व बैंक के आंकड़े जून के अंतिम दिन के हैं।

36. क्षेत्रवार वितरण—सकल बैंक ऋण के मार्च 1983 के अंत तक उपलब्ध क्षेत्रवार वितरण के आंकड़े सारणी 4@ में दर्शाये गये हैं। जुलाई 1982-मार्च 1983 की अवधि के दौरान बैंक ऋणों ने 1981-82 की इसी अवधि के दौरान हुए 3,274 करोड़ रुपये (12.6 प्रतिशत) के विस्तार की तुलना में 4,295 करोड़ रुपये (14.4 प्रतिशत) का अपेक्षाकृत अधिक विस्तार दिखलाया। खाद्यान्न वसूली ऋणों में 217 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 75 करोड़ रुपये की गिरावट आयी थी। गैर-खाद्यान्न ऋणों में 4,078 करोड़ रुपये (15.1 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जबकि 1981-82 की इसी अवधि के दौरान 3,349 करोड़ रुपये (14.1 प्रतिशत) की वृद्धि हुई थी। उपलब्ध आंकड़ों से यह पता चलता है कि गैर-खाद्यान्न ऋणों में अधिक वृद्धि मुख्य रूप से मझौले और बड़े औद्योगिक क्षेत्र को दिये जाने वाले वृद्धिशील ऋणों में पर्याप्त वृद्धि के कारण हुई थी। इस वृद्धि का एक बहुत बड़ा हिस्सा केवल सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के ऋणों में वृद्धि के कारण था। लोहा और इस्पात उद्योग द्वारा, जो कमोबेश पूरी तरह से सार्वजनिक क्षेत्र का है, उपभोग में लाया गया अतिरिक्त ऋण, मझौले तथा बड़े उद्योगों को दिये गये ऋणों में हुई कुल वृद्धि का लगभग तिहाई हिस्सा था। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिये गये ऋणों में वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में काफी कम रही।

37. जुलाई 1982-मार्च 1983 के दौरान मझौले और बड़े उद्योगों को दिये गये वृद्धिशील ऋण पिछले वर्ष की इसी अवधि के 1,172 करोड़ रुपये की तुलना में 1,856 करोड़ रुपये रहे। कुल वृद्धिशील गैर-खाद्यान्न सकल ऋणों में बड़े और मझौले उद्योगों का हिस्सा पिछले वर्ष की इसी अवधि के 35.0 प्रतिशत की तुलना में 45.5 प्रतिशत रहा। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को अधिक मात्रा में ऋणों की उपलब्धता इसका एक प्रमुख कारण रही। मार्च 1983 के अंत में मझौले और बड़े उद्योगों पर बकाया ऋण 13,048 करोड़ रुपये थे जो कुल सकल बैंक ऋण का 38.3 प्रतिशत बैठते हैं।

38. लघु उद्योग सहित औद्योगिक ऋणों का वितरण सारणी 5 में दिया गया है। वे प्रमुख उद्योग, जिनके कारण वृद्धि हुई, ये थे, लोहा और इस्पात (575 करोड़ रुपये), इंजीनियरी ग्रुप (572 करोड़ रुपये), सूती वस्त्र (142 करोड़ रुपये), रसायन और संबंधित उद्योग (140 करोड़ रुपये)।

39. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों की अग्रिमों में जुलाई 1982-मार्च 1983 के दौरान हुई, 1,543 करोड़ रुपये की वृद्धि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान हुई, 1,710 करोड़ रुपये की वृद्धि के मुकाबले कम रही। यह कमी वाणिज्यिक क्षेत्र को, विशेषकर, दिसंबर 1982 से सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को बैंक ऋण में तीव्र वृद्धि के कारण हुई, लेकिन पिछले कुछ महीनों में सभी बैंकों ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिये जाने वाले अग्रिमों में वृद्धि की है। अलग-अलग बैंकों के साथ किये गये ऋण बजट विषयक विचार-विमर्श से यह पता चलता है कि प्राथमिकता प्राप्त अग्रिमों के संबंध में वे अपने लिए निर्धारित लक्ष्यों को पूरा कर सकेंगे। मार्च 1983 के अंत में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिये गये अग्रिम शुद्ध बैंकों का 37.0 प्रतिशत थे। एक वर्ष पहले ये अग्रिम शुद्ध बैंक ऋणों का 37.7 प्रतिशत थे।

सारणी 3—महत्वपूर्ण बैंकिंग निर्देशकों में उतार-चढ़ाव (अनुसूचित वाणिज्य बैंक)

(करोड़ रुपये)

मदें	निम्नलिखित तारीखों को बकाया राशि			वित्तीय वर्षों में उतार-चढ़ाव	
	26 जून 1981	25 जून 1982	24 जून 1983*	1981-82	1982-83
	1	2	3	4	5
कुल मांग एवं मीयादी देयताएं (इसमें रिजर्व बैंक/भा० औ० वि० बैंक तथा नाबार्ड से लिये गये उधार शामिल नहीं हैं)	44,482	50,009	57,748	+5,527	+7,739
कुल जमाराशियां	40,549	46,128	53,566	+5,579	+7,438
				+(13.8)	+(16.1)

@आंकड़े उन 50 बैंकों से संबंधित हैं, जिन्होंने विवरणी प्रस्तुत की है। कृपया सारणी 4 की पाद टिप्पणियां देखें।

	1	2	3	4	5
रिजर्व बैंक से उधार	564@	572@	509	+8	—63
बैंक ऋण शुद्ध	26,551	30,180	35,929	+3,629 (+13.7)	+5,749 (+19.1)
रिजर्व बैंक के पास पुनर्भुनाये गये बिल	3	—	—	—3	—
खाद्यान्न ऋण	2,202	2,825	3,587	+623	+762
गैर-खाद्यान्न सकल बैंक ऋण	24,348	27,355	32,342	+3,007 (+12.4)	+4,987 (+18.2)
निवेश	14,222	16,945	19,886	+2,723 (+19.1)	+2,941 (+17.4)
(क) सरकारी प्रतिभूतियाँ	9,975	11,617	13,460	+1,642	+1,843
(ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	4,247	5,328	6,426	+1,081	+1,098
हाथ में नकदी	985	999	983	+14	—16
रिजर्व बैंक के पास शेष राशियां	4,517	4,771	5,413	+254	+372
सकल ऋण जमा अनुपात (प्रतिशत)	65.5	65.4	67.1		
गैर-खाद्यान्न सकल ऋण-जमा अनुपात (प्रतिशत)	60.0	59.5	60.4		

*अंशतः संशोधित।

@12 जुलाई, 1982 को नाबार्ड को दिये गये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के उधार इसमें शामिल हैं।

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े प्रतिशत घट-बढ़ को दर्शाते हैं।

सारणी 4—सकल बैंक ऋण का क्षेत्रवार नियोजन

(करोड़ रुपये)

क्षेत्र	बकाया		घट-बढ़	बकाया		घट-बढ़
	जून 1981	मार्च 1982	जून 1981 से मार्च 1982 के बीच	जून 1982@	जून 1983@	जून 1982 से मार्च 1983 के बीच
	1	2	3	4	5	6
I. सार्वजनिक खाद्यान्न वसूली	2,202	2,127	—75	2,824	3,041	217
II. (क) प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र	8,966	10,676	+1,710 (51.1)	10,683	12,226	+1,543 (37.8)
(i) कृषि	3,783	4,615	+832 (24.8)	4,588	5,239	+651 (16.8)
(ii) लघु उद्योग	3,406	3,901	+495 (14.8)	3,921	4,447	+526 (12.9)
(iii) अन्य प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र	1,777	2,160	+383 (11.5)	2,174	2,540	+366 (8.9)
(ख) उद्योग (मझौले और बड़े)	9,983	11,155	+1,172 (35.0)	11,192	13,048	+1,856 (45.5)
(ग) थोक व्यापार (खाद्यान्न वसूली के अतिरिक्त)	2,000	2,198	+198 (5.9)	2,152	2,324	172 (4.2)
(i) भारतीय कपास निगम	232	255	+23 (0.7)	271	287	+16 (0.4)
(ii) भारतीय खाद्य निगम (उर्वरक ऋण)	313	411	+98 (2.9)	454	431	—23 (—0.6)
(iii) भारतीय जूट निगम	70	115	+45 (1.3)	102	74	—28 (—0.7)
(iv) अन्य व्यापार	1,385	1,417	+32 (1.0)	1,325	1,582	+207 (5.1)
(घ) अन्य क्षेत्र	2,737	3,006	+269 (8.0)	2,918	3,425	+507 (12.5)

	1	2	3	4	5	6
III गैर-खाद्यान्न सकल बैंक ऋण (क+ख+ग+घ)	23,686	27,035	+3,349 (100.0)	26,945	31,023	+4,078 (100.0)
उसमें से :						
निर्यात ऋण	1,728	1,796	68	1,735	1,738	+3
IV सकल बैंक ऋण (I+II)	25,888	29,162	+3,274	29,769	34,064	+4,295

@ अनंतिम ।

टिप्पणी— 1. आंकड़ों का संबंध उन 50 बैंकों से है जो सकल बैंक ऋण का लगभग 96 प्रतिशत प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त, इन आंकड़ों में रिजर्व बैंक के पास पुनर्भुनाए गए बिलों को शामिल करने के अलावा वे बिल भी शामिल हैं जो भा. औ. वि. बैंक तथा अन्य अनुमोदित संस्थाओं के पास पुनर्भुनाए जाते हैं और इसमें सहभागिता प्रमाणपत्र शामिल हैं।

2. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े गैर-खाद्यान्न वर्धमान ऋण के अनुपात के अनुसार हैं।

40. अवधि के दौरान प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों का अंश अग्रिमों में हुई 1,543 करोड़ रुपये की वृद्धि में कृषि और लघु उद्योगों का क्रमशः 651 करोड़ रुपये तथा 526 करोड़ रुपये रहा जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान यह वृद्धि क्रमशः 832 करोड़ रुपये तथा 495 करोड़ रुपये रही। कृषि क्षेत्र को दिये गये अग्रिम मार्च 1983 के अंत की स्थिति के मुताबिक 5,229 करोड़ रुपये थे। ये प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों को दिये गये कुल अग्रिमों के 42.9 प्रतिशत थे। एक वर्ष पहले यह प्रतिशत 43.2 था। लघु उद्योगों को दिये गये अग्रिम, जो 4,447 करोड़ रुपये थे, कुल ऋण के 36.4 प्रतिशत रहे। एक वर्ष पहले यह प्रतिशत 33.5 था।

41. थोक व्यापार (खाद्यान्न वसूली को छोड़कर) को अग्रिमों में 172 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई जबकि वर्ष के दौरान 198 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी। यह वृद्धि मुख्यतः "अन्य व्यापार" को (207 करोड़ रुपये) तथा अंशतः भारतीय कपास निगम को (16 करोड़ रुपये) दिये गये ऋणों के कारण हुई। हां, भारतीय जूट निगम को दिये गये अग्रिमों में 28 करोड़ रुपये की गिरावट आई। अन्य 20 क्षेत्रों को, ऋणों में, जो बाकी क्षेत्रों के द्योतक हैं और जिनमें वित्तीय संस्थाओं और किराया खरीद एजेंसियों को अग्रिम तथा व्यक्तिगत ऋण आदि शामिल हैं, जुलाई-मार्च 1982-83 के दौरान 507 करोड़ रुपये की उल्लेखनीय वृद्धि हुई जबकि 1981-82 की इसी अवधि में केवल 269 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी।

42. चीनी के बफर स्टॉक.—पण्य-विपणन के संबंध में एक महत्वपूर्ण गतिविधि यह रही कि सरकार ने 1981-82 चीनी वर्ष के उत्पादन के खुली बिक्री कोटे में से 5 लाख टन चीनी का बफर स्टाक बनाने का निर्णय किया। यह बफर स्टाक चीनी मिलों द्वारा यथानुपात आधार पर बनाए रखे गये स्टाक के रूप में रखा जाता है। बैंकों को मार्जिन अपेक्षाएं समाप्त करके बफर स्टाक का पूरा वित्तपोषण करना है। बफर को जाने वाली ब्याज दरों के संबंध में कोई रियायत नहीं है। बफर स्टाक रखने में आई लागतों और ब्याज प्रभारों के लिए भारत सरकार मिलों को प्रतिपूर्ति करेगी। इस योजना को अपना वित्तपोषण स्वयं करने में सक्षम बनाने के लिए नवंबर 1982 से चीनी पर उपकर प्रभार 5 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 14 रुपये प्रति क्विंटल कर दिये गये थे। 1981-82 के मौसम के दौरान चीनी उद्योग को बैंक ऋण जून 1982 में 527 करोड़ रुपये के सर्वोच्च स्तर तक पहुंच गया। यह अप्रैल 1981 के पिछले वर्ष के 348 करोड़ रुपये के सर्वोच्च स्तर से काफी ऊंचा था।

43. बैंकों को रिजर्व बैंक की सहायता.—वर्ष के दौरान अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के लिए रिजर्व बैंक की वित्तीय सहायता नीति के मूल ढांचे के भीतर ही पुनर्वित सुविधाओं में कतिपय संशोधन किये गये। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, खाद्यान्न और निर्यात ऋण के वास्ते पुनर्वित्त की सुविधाओं के संबंध में ये परिवर्तन किये गये थे ताकि बैंक उन क्षेत्रों में अपने वचनों को संसाधन विषयक अवांछित कठिनाइयों के बिना ही पूरा कर सकें। बैंकों को उनके संसाधनों की व्यवस्था में सहायता करने की दृष्टि से सहवर्ती (स्टैण्डबाई) पुनर्वित्त सुविधा को भी उपलब्ध बनाया गया। वर्ष के दौरान रिजर्व बैंक द्वारा उपलब्ध कराई गयी वित्तीय सुविधाओं की प्रवृत्तियों की चर्चा नीचे की जा रही है :

सारणी 5—सकल बैंक ऋण का उद्योगवार नियोजन

(करोड़ रुपये)

उद्योग	बकाया राशि		घटबढ़	बकाया राशि		घटबढ़
	जून 1981	मार्च 1982	जून 1981 से मार्च 1982 तक	जून 1982@	मार्च 1983@	जून 1982 से मार्च 1983 तक
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उद्योग (लघु, मझोले एवं बड़े उद्योगों का योग)	13,389	15,056	+1,667	15,113	17,495	+2,382
1. कोयला	55	53	—2	72	59	—13
2. लोहा और इस्पात	648	856	+208	942	1517	+575
3. अन्य धातुएं एवं उनके उत्पाद	462	527	+65	524	601	+77

1	2	3	4	5	6	7
4. सभी इंजीनियरी	3,266	3,817	+551	3,831	4,403	+572
5. विद्युत (निर्माण एवं ट्रान्समिशन)	181	259	+78	227	249	+22
6. सूती वस्त्र उद्योग	1,174	1,281	+107	1,200	1,342	+142
7. जूट वस्त्र उद्योग	168	187	+19	181	202	+21
8. अन्य वस्त्र उद्योग	723	842	+119	842	944	+102
9. चीनी	278	403	+125	527	570	+43
10. चाय	232	265	+33	272	277	+5
11. वनस्पति तेल (वनस्पति सहित)	188	215	+27	208	234	+26
12. तम्बाकू एवं तम्बाकू के उत्पाद	138	133	—5	146	143	—3
13. कागज एवं कागज के उत्पाद	298	357	+59	360	398	+38
14. रबड़ एवं रबड़ के उत्पाद	264	280	+16	275	306	+31
15. रसायन, रंजक, रंग, दवाइयां एवं औषधियां	1,529	1,672	+143	1,711	1,851	+140
उनमें से : उर्वरक	(299)	(329)	(+30)	(360)	(336)	(—24)
16. सीमेंट	135	158	+23	157	192	+35
17. चमड़ा एवं चमड़े के उत्पाद	188	220	+32	220	262	+42
18. निर्माण	125	143	+18	151	192	+41
19. नयी योजना के अंतर्गत विदेशों से प्राप्त जहाज	303	307	+4	309	327	+18
20. पेट्रोलियम	687	431	—256	299	102	—197
21. शेष उद्योग	2,347	2,650	+303	2,659	3,324	+665

@अनंतिम

44. खाद्यान्न ऋण पुनर्वित्त.—जून 1982 के अंतिम शुक्रवार को बैंक 347 करोड़ रुपये की खाद्यान्न पुनर्वित्त सीमा के पात्र थे, जिसमें से उन्होंने केवल 29 करोड़ रुपये का उपभोग किया । यह पात्रता 17 जून 1982 को 1,094 करोड़ रुपये के उच्चतम स्तर पर पहुंच गयी । बकाया राशियां दिसंबर 1982 में 389 करोड़ रुपये के उच्चतम स्तर तक पहुंच गयीं । इसके बाद बकाया राशियां जून 1983 के अंतिम शुक्रवार तक, 1,087 करोड़ रुपये की पात्रता की तुलना में घट कर 113 करोड़ रुपये रह गयी ।

45. निर्यात ऋण पुनर्वित्त—बैंकों की निर्यात पुनर्वित्त पात्रता जून 1982 के अंतिम शुक्रवार को 163 करोड़ रुपये की थी । इसके बाद बैंकों की निर्यात पुनर्वित्त पात्रता में क्रमशः गिरावट आयी और वे 3 दिसंबर 1982 को 57 करोड़ रुपये के न्यूनतम स्तर तक पहुंच गयी। इसके बाद इसमें धीमी वृद्धि देखने में आयी और जून 1983 की स्थिति के अनुसार बैंक 161 करोड़ रुपये के निर्यात पुनर्वित्त के पात्र हो गये । यह स्तर एक वर्ष पहले के 163 करोड़ रुपये के स्तर से थोड़ा-सा नीचे था । बैंकों द्वारा निर्यात पुनर्वित्त पात्रता का उपभोग 10 दिसंबर 1982 के 7 करोड़ रुपये के न्यून और अप्रैल 1983 में 99 करोड़ रुपये के उच्च स्तर के बीच चढ़ता उतरता रहा । जून 1983 के अंतिम शुक्रवार को बकाया राशियां 33 करोड़ रुपये थी ।

46. सहवर्ती पुनर्वित्त.—जून 1982 के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार कोई भी सहवर्ती (स्टैण्डबाइ) ऋण बकाया नहीं था । जुलाई 1982 से जून 1983 के दौरान बैंकों को मंजूर की गयी विवेकाधीन पुनर्वित्त सीमा का उच्चतम स्तर अप्रैल के अंत में 24 करोड़ रुपये था, जिसमें से 15 करोड़ रुपये बकाया थे । इसकी तुलना में अप्रैल 1982 में इसकी उच्चतम सीमा 97 करोड़ रुपये थी जिसके विरुद्ध 6.7 करोड़ रुपये की राशि बकाया थी । जून 1983 के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार, मंजूर की गयी सीमाएं 20 करोड़ रुपये थीं और इसमें से कोई राशि बकाया नहीं थी ।

47. विवेकाधीन पुनर्वित्त.—बैंकों को मंजूर की गयी विवेकाधीन पुनर्वित्त सीमाओं में वर्ष के दौरान तेज गिरावट आयी, 1982-83 के दौरान बैंकों को मंजूर की गयी सीमाओं का उच्चतम स्तर 24 करोड़ रुपये रहा जबकि पिछले वर्ष के दौरान यह राशि 121 करोड़ रुपये थी । 1982-83 के दौरान विवेकाधीन पुनर्वित्त सीमा के उपभोग का उच्चतम स्तर 1981-82 के 82 करोड़ रुपये के स्तर से काफी कम अर्थात् 8 करोड़ रुपये था ।

48. समग्र स्थिति.—अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के लिए (जहाजरानी ऋणों के लिए विशेष पुनर्वित्त और शुल्क वापसी को छोड़कर) रिजर्व बैंक की विभिन्न पुनर्वित्त सुविधाओं के अन्तर्गत उपलब्ध सीमाओं की कुल राशि में इस वर्ष के दौरान 777 करोड़ रुपये की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई जबकि पिछले वर्ष 309 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्ज की गयी थी । 1982-83 के दौरान बैंकों को मंजूर की गयी विभिन्न सीमाओं की कुल राशि 17 जून 1983 को 1,298 करोड़ रुपये की उच्चतम स्तर तक पहुंच गयी और इसके बाद 24 जून 1983 को यह सीमान्त रूप से घटकर 1,288 करोड़ रुपये रह गयी । इन सीमाओं की तुलना में बकाया राशियां जुलाई 1982—जून 1983 के दौरान 86 करोड़ रुपये की वृद्धि के साथ 146 करोड़ रुपये हो गयीं जबकि पिछले वर्ष 4 करोड़ रुपये की मामूली वृद्धि दर्ज की गयी थी । 1982-83 के दौरान विभिन्न सीमाओं में बकाया राशियों का उच्चतम स्तर मार्च 1983 को 457 करोड़ रुपये रहा, जबकि 1981-82 में यह स्तर 336 करोड़ रुपये का था ।

49. सरकारी वित्तपोषण.—भारत सरकार के 1983-84 के बजट में 1982-83 के कराधान स्तर पर कुल 2,250 करोड़ रुपये के घाटे की व्यवस्था की गयी थी। हां, यदि 1983-84 के दौरान अतिरिक्त स्रोत जुटाने के लिए किये गये प्रयासों के फलस्वरूप केन्द्र के पास जमा होने वाले 695* करोड़ रुपये के शुद्ध अतिरिक्त राजस्व की हिसाब में लिया जाये तो बजटीय घाटा 1982-83 के लिए संशोधित अनुमानों के 1,935 करोड़ रुपये की तुलना में 1,555 करोड़ रुपये रह जायेगा। राज्य सरकारों की मिली-जुली समग्र बजटीय स्थिति @1983-84 के लिए कुल 969 करोड़ रुपये का घाटा दर्शाती है जबकि 1982-83 के लिए संशोधित अनुमानों में 806 करोड़ रुपये के घाटे का अनुमान लगाया गया था। 1982-83 के लिए केन्द्र तथा साथ ही साथ राज्यों के बजटीय घाटे में, राज्यों द्वारा 31 मार्च 1982 की स्थिति अपने घाटे पूरे करने के लिए, उनके द्वारा प्राप्त की गयी 1,743 रुपये की ऋण सहायता शामिल नहीं है। वर्ष के दौरान राज्यों द्वारा 315 करोड़ रुपये के अतिरिक्त स्रोत जुटाने और केन्द्र के अतिरिक्त कराधान में राज्यों के 101 करोड़ रुपये के अंशदान के फलस्वरूप राज्यों का समग्र घाटा काफी कम हो कर 553 करोड़ रुपये रह जाने का अनुमान है।

50. समेकित स्थिति : केन्द्र और राज्य.—केन्द्र तथा राज्य सरकारों की प्राप्तियों और वितरणों की संयुक्त स्थिति सारणी 6 में दर्शायी गयी है। 1983-84 के बजट में कुल प्राप्तियां 52,593 करोड़ रुपये होने का अनुमान रखा गया है जबकि 1982-83 में बजट अनुमानों में यह राशि 44,886 करोड़ रुपये थी। इस तरह ये पिछले वर्ष के 19 प्रतिशत की तुलना मे 17.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है (संशोधित अनुमानों से बजट अनुमानों की वृद्धि)† 1983-84 में सकल वितरण पिछले वर्ष के बजट अनुमानों के 46,278 करोड़ रुपये पर 1982-83 में 19.4 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 18.2 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 54,701 करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया गया है। 1983-84 में विकासीय व्यय में 17.1 प्रतिशत की वृद्धि, 1982-83 में 19.5 प्रतिशत की वृद्धि दर से थोड़ी-सी गिरावट दर्शाती है। गैर-विकासीय व्यय की शुद्ध दर भी 1982-83 के 21.2 प्रतिशत से गिरकर 20.6 प्रतिशत रह जाने का अनुमान है।‡

*27 अप्रैल 1983 को घोषित बजटोत्तर कर रियायतें इसमें शामिल नहीं है।

@इसमें जम्मू और कश्मीर तथा त्रिपुरा शामिल नहीं हैं, क्योंकि उनसे आंकड़े प्राप्त नहीं हुए हैं।

†यदि 1983-84 के बजट अनुमानों की पिछले वर्ष के संशोधित अनुमानों के साथ तुलना की जाय तो कुल प्राप्तियों में वृद्धि 8.1 प्रतिशत और कुल व्यय में 6.4 प्रतिशत आती है। इसी तरह यदि 1982-83 के संशोधित अनुमानों की 1981-82 के लेखों से तुलना की जाय तो प्राप्तियों में वृद्धि, 17.6 प्रतिशत और व्यय में वृद्धि 17.4 प्रतिशत होगी।

‡यदि 1983-84 के बजट अनुमानों की पिछले वर्ष के संशोधित अनुमानों से तुलना की जाय तो विकासीय व्यय में वृद्धि 2.4 प्रतिशत और गैर विकासीय व्यय में वृद्धि 17.6 प्रतिशत आती है। इसी तरह यदि 1982-83 के संशोधित अनुमानों की 1981-82 के लेखों से तुलना की जाय तो विकासीय व्यय में वृद्धि 19.3 प्रतिशत और गैर-विकासीय व्यय में वृद्धि 21.6 प्रतिशत बैठेगी।

51. बाजार ऋण.—3,200 करोड़ रुपये के बजट अनुमानों की तुलना मे 1982-83 में केन्द्र सरकार के शुद्ध बाजार ऋण 3,800 करोड़ रुपये रहे जो 1981-82 के ऋण से 897 करोड़ रुपये अधिक है। दूसरी ओर राज्य सरकारों के शुद्ध बाजार ऋण, पिछले वर्ष की 130 करोड़ रुपये की वृद्धि की तुलना में 63 करोड़ रुपये की अल्प वृद्धि के साथ, 399 करोड़ रुपये रहे। केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा प्राधिकृत स्थानीय प्राधिकरणों और संस्थाओं के शुद्ध ऋण 1982-83 में 145 करोड़ रुपये की वृद्धि के साथ 1,503 करोड़ रुपये रहे। पिछले वर्ष ये 359 करोड़ रुपये की वृद्धि के साथ 1,358 करोड़ रुपये रहे थे। इनके ब्यौरे सारणी 6क में दिये गये है।

52. इस वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार ने 6 बार बाजार से उधार लिया तथा निवेशकर्ताओं को निर्मंत्रित करने के लिए एक बार रिजर्व बैंक को भी बांड बेचे।

53. 1982-83 के दौरान राज्य सरकारों के कुल ऋण 556 करोड़ रुपये रहे, जिसमें से 490 करोड़ रुपये नकद आधार पर तथा 66 करोड़ रुपये ऋणों की अवधि समाप्ति पर परिवर्तन के रूप में थे। 157 करोड़ रुपये की राशि को हिसाब में लेने पर राज्यों के शुद्ध ऋण 399 करोड़ रुपये रह जाते हैं। सकल देशीय उत्पाद (चालू बाजार मूल्यों पर) के अनुपात के रूप में कुल शुद्ध बाजार ऋण (केन्द्र तथा राज्य) 1981-82 के 2.20 प्रतिशत से थोड़ा-सा बढ़कर 1982-83 में 2.70 प्रतिशत हो गया।

54. केन्द्रीय ऋण—1983-84.—1983-84 के लिए केन्द्र सरकार ने 4,000 करोड़ रुपये के शुद्ध बाजार ऋणों का बजट रखा है। केन्द्र सरकार ने 30 मई 1983 को ऋणों की अपनी पहली श्रृंखला के साथ बाजार में प्रवेश किया और पूरी तरह नकद आधार पर 500 करोड़ रुपये की पूर्ण राशि के 10 प्रतिशत वाले 2,014 ऋण का प्रस्ताव रखा। इसमें कुल 550 करोड़ रुपये की राशि जमा हुई और सभी अभिदाताओं को पूरा आवंटन मिला। केन्द्र सरकार ने दूसरी बार बाजार में दो ऋणों के साथ 15 जुलाई 1983 को प्रवेश किया। ये ऋण थे—नकद सह-परिवर्तन आधार पर 7.75 प्रतिशत ऋण 1,991 तथा 10 प्रतिशत ऋण 2,014 (दूसरा निर्गम)। इनके द्वारा कुल 625 करोड़ रुपये जुटाये गये। इनमें से 602 करोड़ रुपये नकद रूप में थे और शेष परिवर्तन के रूप में। इन दो श्रृंखलाओं के साथ केन्द्र सरकार ने बाजार से शुद्ध 1,031 करोड़ रुपये की राशि जुटाई, जो 1983-84 के लिये कुल बजटीय बाजार ऋणों (शुद्ध) के 25.8 प्रतिशत के बराबर थी।

55. केन्द्रीय ऋणों को रिजर्व बैंक की सहायता.—सरकारी वित्त की एक महत्वपूर्ण विशेषता केन्द्रीय सरकार के उधार कार्यक्रम में वृद्धि और रिजर्व बैंक से अपेक्षित सहायता की सीमा है। 1981-82 की वार्षिक रिपोर्ट में भारत सरकार की वित्तीय स्थिति में बढ़ते हुए संरचनात्मक असंतुलन की ओर ध्यान दिलाया गया था। यह मुख्यतया राजस्व खातों में घाटे, बाजार उधारों पर निर्भर रहने की वृत्ति और बाजार में खपत की पर्याप्त क्षमता की कमी के कारण, सरकारी ऋणों में रिजर्व बैंक के बढ़ते हुए हिस्से से प्रकट होता था। पिछले दो वर्षों के आंकड़ों से इसमें कुछ सुधार परिलक्षित हुआ है। हालांकि राजस्व खाते में घाटे की प्रवृत्ति अब भी बनी हुई है, किन्तु कुल प्राप्तियों के अनुपात के रूप में समग्र घाटा 1980-81 (लेखे) में 11.6 प्रतिशत से घटकर 1983-84 (बजट अनुमान) में 4.6 प्रतिशत ही रह गया है। कुल प्राप्तियों में सकल बाजार ऋणों की मात्रा में कोई खास परिवर्तन नहीं आया है किन्तु सरकारी ऋणों के रिजर्व बैंक द्वारा धारित दिनांकित

सारणी 6—केन्द्र तथा राज्य सरकारों की संयुक्त प्राप्तियां एवं संवितरण
(1981-82—1983-84)

(करोड़ रुपये)

	1981-82 (संशोधित अनुमान)	1981-82 (लेखा)	1982-83 (बजट अनुमान)	1982-83 (संशोधित अनुमान)		1983-84 (बजट अनुमान)	
	राशि	राशि	राशि	राशि	पिछले वर्ष के तदनुरूपी संशोधित अनुमानों की तुलना में प्रतिशत का अंतर	राशि	पिछले वर्ष के तदनुरूपी बजट अनुमानों की तुलना में प्रतिशत का अंतर
	1	2	3	4	5	6	7
I. कुल प्राप्तियां (अ+आ)	40,727	41,360	44,886	48,660	+19.5	52,593	+17.2
अ. राजस्व प्राप्तियां	29,702	30,033	33,641	34,488	+16.1	38,505	+14.5
उनमें से कर प्राप्तियां	26,741	23,962	27,717	27,376	+15.3	31,419	+13.4
आ० पूंजीगत प्राप्तियां	11,025	11,327	11,245	14,172	+28.5	14,088	+25.3
II. कुल संवितरण (अ+आ+इ)	43,065	43,773	46,278	51,401	19.4	54,701	+18.2
अ. विकासात्मक व्यय (क+ख+ग)	28,292	28,333	29,552	33,802	+19.5	34,603	+17.1
(क) राजस्व	16,010	16,060	17,348	19,582	+22.3	20,788	+19.8
(ख) पूंजीगत	7,186	7,129	7,388	7,733	+7.6	7,820	+5.8
(ग) ऋण एवं अग्रिम	5,096	5,144@	4,816	6,487	+27.3	5,995	+24.5
आ. गैर विकासात्मक व्यय (क+ख+ग)	13,558	13,509	16,019	16,428	+21.2	19,316	+20.6
(क) राजस्व	12,779	12,691	14,956	15,314	+19.8	18,149	+21.3
(ख) पूंजीगत	522	596	786	807	+54.6	871	+10.8
(ग) ऋण एवं अग्रिम	257	222	277	307	+19.5	296	+6.9
इ. अन्य	1,215	1,931	707	1,171	—3.6	782	+10.6
III. समग्र अधिशेष (+) या घाटा (-) (I-II)	—2,338	—2,413	—1,392	—2,741		—2,108	—

टिप्पणी: 1. इन आंकड़ों में विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र नहीं आते। राज्यों के संबंध में आंकड़े 20 राज्यों से संबंधित हैं (अर्थात जम्मू और कश्मीर तथा त्रिपुरा को छोड़कर)। असम और आंध्र प्रदेश के आंकड़े लेखानुदान बजट से संबंधित हैं।

2. अन्य संवितरणों में देशी एवं विदेशी ऋण देना, स्थानीय निकायों तथा पंचायत राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति एवं सुपूर्दगी, आकस्मिकता निधियों, प्रेषणों (शुद्ध) के विनियोजन शामिल है और राज्य सरकारों ने अपने अपने बजटों में केन्द्र सरकार को ऋणों की जो चुकौती की है उनके आंकड़ों के अंतर समायोजित किये गये हैं।

इसमें भारत सरकार के बजट के संबंध में 27 अप्रैल 1982 को घोषित बजट के बाद कर रियायतों के आंकड़े शामिल नहीं है। लेकिन बजट प्रस्तावों के आंकड़े शामिल हैं।

@ चूंकि असम राज्य द्वारा दिये गये आंकड़ों में विकासात्मक तथा गैर विकासात्मक ऋण और अग्रिमों के ब्यौरे अलग अलग नहीं दिये गये है अतः सम्पूर्ण राशि को विकासात्मक प्रयोजनों के लिए ऋण और अग्रिम मान लिया गया है।

सारणी 6(क) केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों, स्थानीय प्राधिकरणों एवं केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित संस्थाओं को बाजार ऋण : 1981-82 और 1982-83

(करोड़ रुपये)

	सकल बाजार ऋण		चुकौती		शुद्ध बाजार ऋण	
	1981-82	1982-83	1981-82	1982-83	1981-82	1982-83
केन्द्र सरकार	3190	4166	287	360	2903	3800
राज्य सरकारें	506	556	170	157	336	399
स्थानीय प्राधिकरण तथा केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित संस्थायें @	1,601	1721	243	218	1,358	1503
जोड़	5,297	6443	700	741	4597	5702

टिप्पणी : आंकड़ों का संबंध राजकोषीय वर्ष से है।

@इसमें केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, नाबार्ड भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, आवास और शहरी विकास निगम, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम, दामोदर घाटी निगम जैसी संस्थायें और राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित राज्य बिजली बोर्ड, आवास बोर्ड, औद्योगिक निवेश निगम, औद्योगिक विकास निगम, राज्य वित्त निगम, नगरपालिकाएं, भूमि विकास बैंक तथा अन्य संस्थायें शामिल हैं।

प्रतिभूतियों की वृद्धि का जो अनुपात है वह प्रति वर्ष घटता हुआ 1980-81 में 43.1 प्रतिशत के असाधारणतः उच्च स्तर से घटकर 1981-82 (लेखे) में 38.6 प्रतिशत और 1982-83 (संशोधित अनुमान) में 25 प्रतिशत रह गया (सारणी 7)। यद्यपि प्रवृत्ति गिरावट की है फिर भी भारतीय रिजर्व बैंक से सहायता की मात्रा काफी अधिक है। यहां यह याद दिलाना उचित होगा कि हाल ही में 1978-79 में यह अनुपात केवल 1.6 प्रतिशत था और 1979-80 में भी, काफी कम, अर्थात् 18.1 प्रतिशत था। हां, रिजर्व बैंक की सहायता में वृद्धि, कुछ हद तक अन्तर राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा उपलब्ध करायी गयी विस्तारित निधि सुविधाओं के सरकार द्वारा इस्तेमाल की द्योतक है।

96. तीन वर्षीय राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बांड इस समय कोई भी निर्धारिती उस समय पूंजीगत लाभ कर से छूट की सुविधा ले सकता है जब पूंजीगत आस्ति के अन्तरण पर प्राप्त शुद्ध प्रतिफल का सात वर्षीय राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बांडों में निवेश किया गया हो। चूंकि 7 वर्षों की यह समाप्ति अवधि काफी लंबी थी अतः सरकार ने ये तीन वर्षीय राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बांड (दूसरा निर्गम जारी करने का निर्णय किया। ये 7 जुलाई 1983 से उपलब्ध होंगे और इन पर 7.5 प्रतिशत वार्षिक की दर पर ब्याज मिलेगा। इन बांडों पर 28 फरवरी 1983 के बाद होने वाले दीर्घावधि पूंजीगत लाभों के संबंध में शुद्ध प्रतिफल के निवेश पर निवेशकर्ता पूंजीगत लाभ कर से छूट की सुविधा का पात्र होगा।

सारणी 7 : बजट घाटा, बाजार ऋण तथा केन्द्र सरकार के बाजार ऋणों को रिजर्व बैंक द्वारा सहायता
(1980-81 से 1983-84)

(करोड़ रुपये)

मदें	1980-81 (लेखा)	1981-82 (लेखा)	1982-83 (बजट अनुमान)	1982-83 (संशोधित अनुमान)	1983-84(क) (बजट अनुमान)
1. राजस्व खाता					
(क) राजस्व	12,828.6	15,574.2	17,595.3	18,117.0	20,625.4
(ख) व्यय	14,543.6 (ख)	15,867.7	18,227.3	19,415.0	22,418.9
(ग) अधिशेष (+) घाटा (—)	−1,715.0	—293.5	−632.0	—1,298.0	−1,793.5
2. पूंजीगत लेखा					
(क) प्राप्ति या	9,432.3(ख)(ग)	10,155.7@	11,068.2	13,253.3	13,451.5
(ख) संवितरण	10,294.6(ग)	11,254.1	11,810.8	13,890.2(घ)	13,212.7
(ग) अधिशेष(+) घाटा(—)	−862.3	−1,098.4	−742.6	−636.9	+238.8
3. कुल प्राप्तियां [1(क)+2(क)]	22,260.9	25,729.9	28,663.5	31,370.3	34,076.9
4. समग्र अधिशेष (+)घाटा(—)	−2,577.3	−1,391.9	−1,374.6	−1,934.9	−1,554.7
5. (3) के प्रतिशत के अनुसार(4)	11.6	5.4	4.8	6.2	4.6
6. समग्र बाजार ऋण	2,848.5	3,198.3	3,566.0	4,166.0	4,344.0
7. (3) के प्रतिशत के अनुसार (6)	12.8	12.4	12.4	13.3	12.7
8. रिजर्व बैंक की विनाकित प्रतिभूतियों की धारिताएं*	1,229	1,236@	1,041	1,041	—
9. (6) के प्रतिशत के अनुसार(8)	43.1	38.6	29.2	25.0	

ये आंकड़े राजकोषीय वर्ष से संबंधित हैं।

(क) इसमें बजट प्रस्ताव से संबंधित आंकड़े शामिल है तथा 27 अप्रैल 1983 को घोषित बजटेतर कर रियायतें इस में शामिल नहीं है।

(ख) सातवें वित्तीय आयोग की सिफारिशों के अनुसार 1979-80 से पूर्व राज्य सरकारों को दिये गये 938.3 करोड़ रुपयों को बट्टे खाते डालने के संबंध में किये गये लेखा समायोजन शामिल हैं।

(ग) विशेष आहरण अधिकारों और प्रतिभूतियों के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक निधि में दिये गये 588.2 करोड़ रुपये का राष्ट्रीय प्राप्ति/व्यय शामिल है।

(घ) 31 मार्च 1982 को राज्य सरकारों के घाटों को पूरा करने के लिए दिया गया 1734.4 करोड़ रुपये का ऋण इस में शामिल नहीं है।

*बही-मूल्य के आधार पर।

@अस्थायी खजाना बिलों के बदले में भारतीय रिजर्व बैंक के पक्ष में जारी की गयी 3,500 करोड़ रुपये की विशेष प्रतिभूतियां इसमें शामिल नहीं है।

57. सात वर्षीय राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बांड.—9 जुलाई 1979 को जारी किये गये सात वर्षीय राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बांडों में वर्ष के दौरान भी धन प्राप्त होता रहा। इनके जारी किये जाने की तारीख से लेकर 30, जून 1983 तक कुल 178.40 करोड़ रुपये जुटाये जा चुके थे।

58. सामाजिक सुरक्षा प्रमाणपत्र.—पहली जुलाई 1982 से शुरू किये गये सामाजिक सुरक्षा प्रमाणपत्रों से अप्रैल 1983 के अंत तक 11.96 करोड़ रुपये के बराबर अभिदान जमा हुए।

59. पूंजीगत निवेश बांड.—पूंजीगत निवेश बांडों में 28 जून, 1982 से उनके निर्गम से लेकर 30 जून, 1983 तक 88.93 करोड़ रुपये के अभिदान हुए थे, जबकि 1982-83 के लिए 250 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया गया था और बाद में उसे घटाकर 170 करोड़ रुपये कर दिया गया। वर्ष 1983-84 के लिए बजट में 200 करोड़ रुपये के अभिदान का अनुमान लगाया गया है।

60. अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट.—पिछले वर्ष की रिपोर्ट में केन्द्र द्वारा एक मुश्त उपाय किये जाने के बारे में उल्लेख किया गया था ताकि राज्य, मार्च 1982 के अंत तक रिजर्व बैंक के साथ अपने बकाया ओवरड्राफ्टों को निपटा सकें। 18 राज्यों को कुल 1,743.46 करोड़ रुपये के मध्यावधि ऋण प्रदान किये गये ताकि वे 1981-82 के अंत तक अपने इति घाटे निपटा सकें। 1982-83 की पहली तिमाही के दौरान हुए घाटे को भी 787 करोड़ रुपये की अतिरिक्त अल्पावधि सहायता के जरिये पूरा किया गया। साथ ही, राज्य सरकारों को रिजर्व बैंक से प्राप्य अर्थोपाय सीमा भी दुगुनी कर दी गयी जो कि पहली जुलाई, 1982 से प्रभावी हुई। इन सब उपायों के बावजूद जुलाई, 1982 में ओवरड्राफ्ट फिर से अस्तित्व में आ गये। 26 मार्च 1982 को 18 राज्यों के 1,450.88 करोड़ रुपये के ओवरड्राफ्टों की तुलना में 25 मार्च, 1983 को 11 राज्य सरकारों के ओवरड्राफ्ट कुल 212.27 करोड़ रुपये के थे। ओवरड्राफ्टों की संख्या, ओवरड्राफ्ट लेने वाले राज्यों की कुल संख्या तथा साथ ही, ओवरड्राफ्ट जारी रहने के दिवसों की संख्या, (जिनके लिए ओवरड्राफ्ट बकाया रहे) के संबंध में स्थिति और बिगड़ी है। रिजर्व बैंक में जिन 20 राज्य सरकारों का खाता है उनमें से 12 ने 24 जून, 1983 तक कुल 579.22 करोड़ रुपये के ओवरड्राफ्ट लिये थे। केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गयी सहायता से संबंधित राज्य सरकार के ओवरड्राफ्ट चुका दिये गये और जून, 1983 के अंत की स्थिति के अनुसार कोई भी ओवरड्राफ्ट बकाया नहीं रहा। अर्थोपाय अग्रिमों के दुगुना कर दिये जाने के बाद भी, बहुत बड़ी मात्रा में, ओवरड्राफ्ट का बार-बार सहारा लेना राज्यों की चिंताजनक वित्तीय स्थिति की ओर इंगित करता है।

61. पूंजीगत बाजार की गतिविधियां.—निजी कंपनी क्षेत्र द्वारा बाजार से सीधे निधि जुटाने के सम्मिलित प्रयास जारी रहे। 1982-83 (अप्रैल-मार्च) के दौरान ईक्विटी और अधिमान शेयरों के जरिए जुटायी गयी 705.30 करोड़ रुपये की पूंजी के अनन्तिम आंकड़े, 1981-82 में जुटायी गयी 529.36 करोड़ रुपये की पूंजी से 33.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हैं। पिछले वर्ष की तरह 1982-83 में भी डिबेंचरों की प्रमुखता जारी रही और जुटाई गयी पूंजी में 1981-82 में डिबेंचरों के 52.6 प्रतिशत भाग की तुलना में 1982-83 के दौरान उनका हिस्सा 63.3 प्रतिशत था। आंकड़ों से यह पता चलता है कि जनता द्वारा परिवर्तनीय डिबेंचरों को वरीयता दिये जाने के बावजूद कम्पनियों ने अपरिवर्तनीय डिबेंचरों के निर्गम का सहारा लिया है। वित्तीय वर्ष 1982-83 के दौरान जारी किये गये कुल डिबेंचरों में अपरिवर्तनीय डिबेंचरों का प्रतिशत, 1981-82 के 22.6 से बढ़कर 36.5 हो गया। अप्रैल 1982 से ब्याज की उच्चतम सीमा में वृद्धि और प्रीमियम कर छूट के लिए प्रावधान के साथ-साथ सरकार ने अपरिवर्तनीय डिबेंचरों को बढ़ावा देने के कुछ अन्य उपाय भी किये। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त, डिबेंचरों के माध्यमिक बाजार विषयक कार्यकारी दल की सिफारिश पर अपरिवर्तनीय डिबेंचरों में निवेश के लिए नकदी निधि देने के उद्देश्य से, इस प्रकार के डिबेंचर जारी करने वाली सभी कंपनियों को पुनः खरीद व्यवस्था की अनुमति दी गयी है। इस योजना के अंतर्गत, कंपनियां किसी भी ऐसे डिबेंचर धारक से, जिसकी धारित राशि 40,000 रुपये से अनधिक हो, और जिसने कम से कम एक वर्ष तक डिबेंचर अपने पास रखे हों, सममूल्य पर अपरिवर्तनीय डिबेंचर पुनः खरीद सकती है। इसके बदले कम्पनियां ये डिबेंचर सामान्य बीमा निगम, जीवन बीमा निगम, यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया, आदि इस योजना में हिस्सा लेनेवाली संस्थाओं के पास रख सकती हैं। ये डिबेंचर इन संस्थाओं द्वारा 2½ प्रतिशत के बट्टे पर खरीदे जायेंगे जो वचनबद्ध प्रभार के रूप में वसूल किया जायेगा। सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं पर एफ० ई० आर० ए०/एम० आर० टी० पी० कंपनियों के निर्गमित डिबेंचरों में अभिदान करने और हामीदार बनने पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया गया है। इससे डिबेंचरों के निर्गम में सहायता मिली है। सरकार ने वित्तीय संस्थाओं को, एम० आर० टी० पी०, एफ० ई० आर० ए० कंपनियों द्वारा किसी भी निर्गमित डिबेंचर में, आपस में मिल-जुलकर 50 प्रतिशत तक अभिदान करने/हामीदार बनने की अनुमति दी है।

62. वित्तीय संस्थाओं द्वारा सहायता.—वर्ष 1982-83 (अप्रैल-मार्च) के दौरान अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं अर्थात् भा० औ० वि० बैं०, भा० औ० वि० नि०, भा० औ० ऋ० नि० नि०, भा० औ० पु० नि०, जी० बी० नि०, भा० यू० ट्रस्ट और सा० बी० नि० तथा उनकी सहयोगी संस्थाएं) द्वारा स्वीकृत और वितरित कुल सहायता की राशि क्रमशः 3053.3 करोड़ रुपये और 2193.3 करोड़ रुपये है। यह मंजूरी के संबंध 1981-82 के 19.8 प्रतिशत की तुलना में 22.3 प्रतिशत की वृद्धि में दर्शाती है। वितरणों में वृद्धि दर पिछले वर्ष के 28.8 प्रतिशत की तुलना में 18.2 प्रतिशत रही।

63. अनिवासियों द्वारा निवेश.—पूंजीगत बाजार पर प्रभाव डालने वाली दूसरी महत्वपूर्ण गतिविधि थी—भारतीय राष्ट्रिकत/मूल के अनिवासियों (विदेशी कंपनियों, भागीदारी फर्मों, समितियों तथा भारतीय राष्ट्रिकता/मूल के अनिवासियों के 60 प्रतिशत की सीमा तक स्वामित्व वाले अन्य नैगमिक निकायों तथा ऐसे व्यक्तियों के अपरिहार्य रूप से हिताधिकारी लाभ के कम से कम 60 प्रतिशत वाले विदेशी न्यासों सहित, (द्वारा निवेश तथा ऐसे निवेशों पर) विदेशी आयों के प्रत्यावर्जन से संबंधित कार्यविधियों को सरल बना दिया जाता। अनिवासी भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के लोगों तथा इन निवेशकर्ताओं के संबंध में कर राहतों के बारे में और अधिक उदार प्रवृत्ति अपनाई गयी। अनिवासी भारतीय निवेशकर्ताओं को, उनके विदेशी मुद्रा प्रेषण के माध्यम से अर्जित भारतीय कम्पनियों के शेयरों और डिबेंचरों सहित उनके निवेशों से प्राप्त होने वाली आय पर अब अधिभार सहित 20 प्रतिशत की एक समान दर पर कर लगेगा। इन निवेशों के अन्तरण से उत्पन्न दीर्घावधि पूंजीगत लाभ पर भी उसी एक समान दर पर कर लगेगा। इसके अलावा, ऐसे निवेशों पर सम्पत्ति कर से छूट दी जायेगी और विदेशों में बसे भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के व्यक्तियों द्वारा भारत में रह रहे उनके संबंधियों को इन परिसंपत्तियों के उपहारों पर भी कोई कर नहीं लगेगा। इसके अलावा, हाल ही में सरकार ने अनिवासियों द्वारा किसी कंपनी में कुल पोर्टफोलियो निवेशों पर शेयरों और परिवर्तनीय डिबेंचरों के चुकता पूंजी के पांच प्रतिशत को अधिकतम सीमा लागू कर दी। पांच प्रतिशत की इस सीमा से अधिक निवेश के लिए रिजर्व बैंक की अनुमति लेनी होगी।

64. विदेश व्यापार.—भारतीय अर्थव्यवस्था में विदेशी व्यापार का महत्व बढ़ रहा है। चालू बाजार मूल्यों पर कुल विदेशी व्यापार का शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में जो अनुपात 1970-71 में 8.4 प्रतिशत था, वह 1982-83 में बढ़कर 15.7 प्रतिशत हो गया। विश्व की आर्थिक स्थिति व्यापार संभावनाओं के प्रतिकूल बनी रही। 1980 और 1981 दोनों

में सीमान्त वृद्धियां दर्ज करने के बाद औद्योगिक देशों के वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद में 1982 में थोड़ी-सी गिरावट आयी । विश्व व्यापार की मात्रा में, जो 1981 में गतिहीन बनी रही थी, 1982 में 2 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आ गयी और वह विश्व व्यापार के 1979 के स्तर पर पहुंच गयी । विश्व व्यापार में गिरावट के पीछे प्रमुख कारण रहे—विश्व व्यापी मंदी और कई औद्योगिक देशों द्वारा संरक्षणवादी उपायों का तेज किया जाना । इन गतिविधियों के बावजूद विदेश व्यापार के उपलब्ध अनंतिम आंकड़ों से पता चलता है कि देश के व्यापार संतुलन के संबंध में सुधार आया । अप्रैल-मार्च 1982-83 में कुल निर्यात 8,638 करोड़ रुपये और आयात 14,047 करोड़ रुपये हुआ जो 5,409 करोड़ रुपये का प्रतिकूल व्यापार संतुलन दर्शाता है और जो 1981-82 के 5,752 करोड़ रुपये (अनंतिम) के घाटे से काफी कम है । हां, निर्यात के वर्गीकरण से यह पता चलता है कि निर्यातों में वृद्धि मुख्यतः कच्चे तेल के निर्यात के कारण हुई ।

65. परोक्ष वस्तुएं.—उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि वित्तीय वर्ष 1982-83 के दौरान शुद्ध अदृश्य खाते में अधिशेष का स्तर लगभग पिछले वर्ष के बराबर ही रहेगा । बैंक की विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों से हुई निवेश आय, पिछले वर्ष से, पांचवां हिस्सा कम थी । दूसरी तरफ, बढ़े हुए वाणिज्य उधार और अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष आहरणों पर ब्याज के भुगतान में वृद्धि हुई । 1982-83 में निजी अन्तरण प्राप्तियों में उतना प्रभाव नहीं पड़ा जितने का अनुमान लगाया गया था । समग्र रूप से, इस वर्ष के दौरान, चालू खाते के घाटे में, पिछले राजकोषीय वर्ष की तुलना में, बहुत अधिक अंतर नहीं होगा ।

66. विदेशी सहायता.—सकल विदेशी सहायता में वृद्धि की जो प्रवृत्ति वर्ष 1979-80 से देखी जा रही है वह वर्ष 1982-83 (अप्रैल-मार्च) के दौरान भी जारी रही । 1982-83 के दौरान सकल विदेशी सहायता 2,145 करोड़ रुपये थी, जिसमें 1981-82 के दौरान 177 करोड़ रुपये की वृद्धि परिलक्षित हुई । इसके परिणामस्वरूप 1982-83 के दौरान 1,192 करोड़ रुपयों की कुल विदेशी सहायता प्राप्त होने का अनुमान है, जो 1981-82 के 1,053 करोड़ रुपये (संशोधित) से 139 करोड़ रुपये अधिक है । 1982-83 के राजकोषीय वर्ष के दौरान भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से उसकी विस्तारित निधि सुविधा के अधीन 1,893 करोड़ रुपये आहरित किये । 1981-82 के दौरान ऐसे आहरणों की राशि केवल 637 करोड़ रुपये थी ।

67. विदेशी मुद्रा आस्तियां.—वर्ष 1982-83 के दौरान (जुलाई 1982 से जून 1983) भारतीय रिजर्व बैंक की विदेशी मुद्रा आस्तियों में 1,531 करोड़ रुपयों की बढ़ोतरी हुई, और वह बढ़कर 4,805 करोड़ रुपये हो गयी ।

68. 1982-83 (जुलाई-जून) के दौरान विस्तारित निधि सुविधा के अधीन भारत ने इस कोष से किये गये आहरणों से 1,908 करोड़ रुपये प्राप्त किये यदि इन प्राप्तियों को शामिल न किया जाए तो बैंक की विदेशी मुद्रागत आस्तियों में 377 करोड़ रुपयों की गिरावट देखने में आयेगी । इस वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रागत आस्तियों में आयी गिरावट की मात्रा 1981-82 की तदनुरूप अवधि में हुई 2,001 करोड़ रुपयों की गिरावट का लगभग पांचवां भाग रही । इसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से किये गये आहरण (948 करोड़ रुपये) शामिल नहीं हैं ।

69. विशेष आहरण अधिकार.—1982-83 के दौरान धारित विशेष आहरण अधिकारों (एस. डी. आर.) में 1,790 लाख विशेष आहरण अधिकारों की गिरावट आयी और वे 2,210 लाख रह गये जबकि 1981-82 की तदनुरूप अवधि में 820 लाख विशेष आहरण अधिकारों की गिरावट आयी थी । आलोच्य अवधि के दौरान धारित विशेष आहरण अधिकारों में आयी तीव्र गिरावट का मुख्य कारण यह था कि कोष से किये गये विभिन्न आहरणों पर 1,740 लाख विशेष आहरण अधिकारों के प्रभारों की अदायगी के वास्ते (विशेष आहरण अधिकारों की शुद्ध धारिताओं पर अर्जित ब्याज तथा निधि से प्राप्त लाभों के लिए) विशेष आहरण अधिकारों का उपयोग किया गया और देशों को 45 लाख विशेष आहरण अधिकार बेचे गये । 1981-82 में 340 लाख विशेष आहरण अधिकार पिछली निधि देयताओं के भुगतान के लिए तथा 480 लाख विशेष आहरण अधिकार प्रभारों के भुगतान के लिए (विशेष आहरण अधिकार धारिताओं पर शुद्ध ब्याज निधि से प्राप्त लाभ के वास्ते) उपयोग में लाये गये थे ।

70. स्वर्ण.—रिजर्व बैंक की स्वर्ण की धारिताएं बिना किसी परिवर्तन के 226 करोड़ रुपये (प्रति 10 ग्राम 84.39 रुपयों के सांविधिक धारण मूल्य पर आंकी गयी) ही बनी रही । पिछले वर्ष भी स्वर्ण धारिताओं में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था ।

71. विदेशी मुद्रा अनिवासी खाते और अनिवासी विदेशी रुपया खातों में घट-बढ़.—विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियों में सुधार लानेवाला एक महत्वपूर्ण तत्व रहा—विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता योजना (एफ. सी. एन. आर.) और अनिवासी विदेशी रुपया खाता (एन. आर. ई.) योजना के अधीन-विदेशी मुद्रा जमाराशियों में वृद्धि होना 1 मार्च 1982 से इन दो योजनाओं के अधीन एक वर्ष और उससे अधिक अवधि की मीयादी जमाराशियों पर देय ब्याज दर को इसी पुगाई अवधि की देशी जमाराशियों पर देय दर से दो प्रतिशत अंक अधिक कर दिया गया । विदेशों में जमा दरों में गिरावट आने के कारण ब्याज दर में यह वृद्धि कारगर सिद्ध हुई है । वर्ष 1982-83 के दौरान विदेशी मुद्रा अनिवासी खातों की बकाया जमाराशियों में 231 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई जबकि 1981-82 में उनमें 13 करोड़ रुपयों की गिरावट आयी थी । अनिवासी रुपया खातों में भी इसी प्रकार की प्रवृत्ति पायी गयी और वर्ष 1982-83 के दौरान उनमें 435 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई जबकि पिछले वर्ष उनमें 265 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई थी ।

72. अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संबंध.—बिना तेल वाले विकासशील देशों को विशेष रूप से प्रभावित करने वाले विश्व की आर्थिक स्थिति के तनाव इस वर्ष के दौरान भी बने रहे । औद्योगिक देशों की स्थिति में सुधार भी स्पष्ट नहीं है और उनके द्वारा अपनायी जानेवाली नीतियां अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग की प्रगति की दिशा में सहायक नहीं है । स्थिति में किसी भी सुधार के लिए और गरीबतर देशों की विशेष कठिनाइयों को दूर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा निश्चित रूप से विशेष प्रयास किये जाने की जरूरत है । विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को विकासशील देशों के भुगतान संतुलनों की सहायता के लिए तथा समायोजन की प्रक्रिया में मदद करने के लिए पर्याप्त वित्त जुटाने के वास्ते केन्द्रीय भूमिका निभानी होगी । अंतर्राष्ट्रीय प्रारक्षित निधियों की वृद्धि की गति में कमी आने के परिणाम स्वरूप विशेष आहरण अधिकार (एस. डी. आर.) के नवीकृत आबंटन के जरिये बिना शर्त साधन जुटाने की आवश्यकता और भी प्रबल हो गयी है । हालांकि इस निधि के कोटे में वृद्धि करने के लिए हाल ही में किये गये करार का स्वागत है; किन्तु यह करार सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति में प्रभावशाली भूमिका निभाने में इस निधि के लिए साधनों की जरूरत पूरी नहीं कर पाता । इसके अतिरिक्त "प्राप्ति सीमा" अथवा निधि की विभिन्न सुविधाओं के अंतर्गत सदस्यों द्वारा प्राप्त की जाने वाली सहायता की सीमाओं में कमी करने का सुझाव कोटे में किसी भी वृद्धि की प्रभावशीलता नष्ट कर देगा । इसके साथ ही, चूंकि निधि के स्रोतों

की प्राप्ति शर्तों के अधीन निर्धारित की जाती है, अतः इस निधि के ऋणों से विकासशील देशों को लाभ पहुंचाना है, तो उसे लचीलेपन के साथ लागू करना होगा।

73. विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव.—इस वर्ष के दौरान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में उतार-चढ़ाव की विशेष बात रही ऊंची उठानें और दिन-प्रति-दिन की अस्थिरता का ऊंचा स्तर। उदाहरण के लिए इस बात की गणना की गयी है कि 1982 में येन/डालर की हाजिर दर में अस्थिरता जो दिन प्रतिदिन के प्रतिशतता परिवर्तनों के औसत निरपेक्ष मूल्य के रूप में मापी गयी थी, 0.6 प्रतिशत से अधिक थी। यह 1973 में चल दरों में परिवर्तन के बाद से सब वर्षों से अधिक थी, अस्थिरता के अलावा विनिमय दर के उतार-चढ़ावों की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता यह थी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में चालू खाता शेष में गिरावट के बावजूद, अमरीकी डालर का निरंतर मजबूत बना रहना। पौंड स्टर्लिंग जो 1982 की दूसरी छमाही और 1983 की शुरुआत में तेल के मूल्यों में गिरावट के कारण काफी नीचे आ गया था, मार्च 1983 के बाद कुछ संभल गया।

74. रुपये की विनिमय दर में परिवर्तन.—रुपये का विनिमय मूल्य पौंड-स्टर्लिंग को मध्यवर्ती मुद्रा मानते हुए एक मुद्रा समूह के संबंध में निर्धारित किया जाता रहा। रुपये की विनिमय दर में वर्ष के दौरान 113 बार परिवर्तन हुए। 1982 के अंत की 16 रु० 50 पैसे प्रति पौंड स्टर्लिंग की मध्य दर से जून 1983 के अंत में 15 रु० 45 पैसे के स्तर तक गिरने के बाद इस वर्ष के दौरान पौंड-स्टर्लिंग के संदर्भ में रुपये का मूल्य 6.8 प्रतिशत बढ़ा। सितंबर 1975 में रुपये को मुद्रा समूह के साथ जोड़े जाने के बाद से पौंड के संबंध में रुपये की विनिमय दर में अधिकतम वृद्धि इस वर्ष के दौरान तब हुई जब उसकी मध्य दर 24 मार्च 1983 को बढ़कर 14.65 रुपये हो गयी। फ्रेंच फ्रांक (5.7 प्रतिशत), बेल्जियन फ्रांक (2.6 प्रतिशत) तथा इटली लीरा (2.9 प्रतिशत) की तुलना में रुपये का मूल्य बढ़ा। लेकिन कतिपय अन्य मुद्रा में गिरावट आयी, जैसे अमरीकी डालर (5.7 प्रतिशत), ड्यूश मार्क (2.5 प्रतिशत), तथा जापानी येन (11.5 प्रतिशत) की। रुपया विशेष आहरण अधिकार (एस. डी. आर.) दर में भी 3.8 प्रतिशत की गिरावट आयी।

75. मूल्य संबंधी स्थिति.—कृषि उत्पादन में आयी कमी, औद्योगिक विकास में आयी मंदी और अधिक तीव्र मुद्रा विस्तार के परिप्रेक्ष्य में आलोच्य वर्ष के अधिकांश हिस्से के दौरान मूल्यों की स्थिति अपेक्षाकृत अधिक स्थिर प्रतीत होती है। यदि बारीकी से देखा जाए तो जून 1982 के अंत में और जून 1983 के अंत की अवधि के बीच थोक मूल्यों के "सभी पण्यों" के सूचकांक में 7.0 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई जबकि 1981-82 में उसमें 2.5 प्रतिशत की गिरावट आयी थी। हां, साप्ताहिक औसत आधार पर देखने पर 1982-83 में हुई 4.2 प्रतिशत की वृद्धि 1981-82 की 5.8 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में कम थी।

76. सूचकांक के तीनों प्रमुख समूहों अर्थात प्राथमिक वस्तुओं; ईंधन, पावर, बिजली और चिकनाई पदार्थों तथा निर्मित उत्पादों में आलोच्य अवधि के दौरान नीचे दी गयी सारणी में दर्शाये गये अनुसार वृद्धि हुई:

कीमत विस्तार तथा थोक कीमत सूचकांक में प्रमुख पण्य समूहों का भारित अंशदान
(1970-71=100)

	भार	घट-बढ़ प्रतिशत में		भारित अंशदान (लगभग)	
		जून 1981 के अंत की तुलना में जून 1982 के अंत में	जून 1982 के अंत की तुलना में जून 1983* के अंत में	1981-82	1982-83
सभी पण्य	1000.00	+2.5	+7.0	+100.0	+1.00.0
प्रमुख वस्तुएं	416.67	+4.7	+8.9	+74.0	+50.1
ईंधन, पावर, बिजली तथा चिकनाई के पदार्थ	84.59	+11.7	+6.5	+56.0	+12.2
विनिर्मित उत्पाद	498.74	—1.6	+5.6	—30.0	+37.7

*अनंतिम

77. प्राथमिक वस्तुओं के समूह में सर्वाधिक वृद्धि पायी गयी अर्थात् इसने सूचकांक में हुई समग्र वृद्धि में 50 प्रतिशत का योगदान दिया। निर्मित उत्पाद समूह का 38 प्रतिशत पर भारित अंशदान काफी अधिक था। प्राथमिक वस्तुओं में मोटे अनाजों के सूचकांकों में हुई 16.3 प्रतिशत की वृद्धि विशेष उल्लेखनीय थी। निर्मित उत्पादों में चीनी के समूह में पिछले वर्ष हुई भारी गिरावट की तुलना में थोड़ी सी वृद्धि हुई। खाद्य तेलों में पिछले वर्ष की गिरावट की अपेक्षा काफी वृद्धि हुई। वर्ष 1982-83 तथा 1981-82 में जिन अन्य निर्मित उत्पादों में वृद्धि देखने में आयी उनमें वस्त्र, कागज और कागज से बनी वस्तुएं, सीमेंट, रसायन और रासायनिक उत्पाद, मूल धातु, मशीनें और मिश्र धातुएं तथा धातु उत्पाद तथा परिवहन उपकरण शामिल है। (देखिये सारणी 8)।

78. 1982-83 के दौरान थोक मूल्य सूचकांक में तीन स्पष्ट दौर देखे जा सकते हैं। इस अवधि के पहले आठ सप्ताहों में (21 अगस्त तक), मूल्यों में काफी तीव्र बढ़ोतरी की प्रवृत्ति पायी गयी जबकि समस्त पण्यों के सूचकांक में 2.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। दूध और दूध से बनी वस्तुओं, मछली और मांस जैसे प्राथमिक पण्यों के कुछ घटकों के अलावा मोटे अनाजों और दालों ने इस वृद्धि में काफी योगदान दिया। निर्मित उत्पादों में से वो० खाद्य उत्पादों के उप समूहों चीनी, खांडसारी और गुड़ तथा खाद्य तेलों में वृद्धि पायी गयी। 17 सप्ताहों के दूसरे चरण में (18 दिसंबर तक) सूचकांक में 2.7 प्रतिशत की गिरावट आयी जो पिछले चरण में हुई वृद्धि की मात्रा के लगभग समान ही थी। पूर्ववर्ती अवधि में जिन पण्यों के कारण बढ़ोतरी हुई थी, उनके मूल्यों में गिरावट आयी। तथापि मोटे अनाजों के मामले में यह गिरावट केवल मामूली थी। चीनी का समूह तथा फल और सब्जियां गिरावट लानेवाले प्रमुख तत्व थे।

79. दिसंबर 1982 के अंत में थोक मूल्य सूचकांक लगभग ठीक उसी स्तर पर था जिस पर वह छः महीने पहले था। सब से जून 1983 के अंत तक सूचकांक में 7.3 प्रतिशत की वृद्धि पायी गयी। इस दौर में फल और सब्जियां तथा चीनी समूह ने जिन्हें मौसमी प्रभावों के रूप में माना जा सकता है मूल्य वृद्धि में सर्वाधिक योगदान दिया। मोटे अनाजों, दालों और खाद्य तेलों के संदर्भ में भी सूचकांक में बढ़ोतरी हुई और साधारण मूल्य स्तर पर इन पण्यों का दीर्घकालीन प्रभाव रहेगा। यही वह तथ्य है, जो मूल्यों के तत्काल निर्धारण में महत्व रखता है।

80. प्रबंधित मूल्यों में परिवर्तन:— विभिन्न पण्यों के प्रबंधित मूल्यों में किये गये परिवर्तनों ने आलोच्य वर्ष के दौरान मूल्य वृद्धि में योगदान दिया। प्राथमिक वस्तुओं में धान और गेहूं के वसूली मूल्यों में प्रति क्विंटल क्रमशः 7 रुपये और 9 रुपये की वृद्धि की गयी। मोटे अनाजों के खरीद मूल्य में भी प्रति क्विंटल 2 रुपये की वृद्धि की गयी और चने के लिए प्रति क्विंटल 235 रुपये का खरीद मूल्य घोषित किया गया। वसूली के मूल्यों में हुई बढ़ोतरी के परिणामस्वरूप चीनी की साधारण, उत्तम और अति उत्तम किस्मों के विक्रय मूल्य में 1 अक्तूबर 1982 से प्रति क्विंटल 13 रुपये की एक समान वृद्धि-कर दी गयी। गेहूं के मामले में 15 अप्रैल 1983 से विक्रय मूल्य में वृद्धि की गयी और वह सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से तथा रोलर आटा मिलों के लिए की जाने वाली बिक्री के लिए प्रति क्विंटल क्रमशः 12 रुपये और 23 रुपये थी यह उल्लेखनीय है कि खाद्यान्नों के निर्गम मूल्यों में वृद्धियां उनके वसूली मूल्यों की वृद्धियों की तुलना में अधिक थीं। इस प्रकार निर्गम मूल्यों को चाल, बाजार मूल्यों के नजदीक लाया जा सकता है, जिनका सार्वजनिक वितरण प्रणाली से खाद्यान्न उठाये जाने पर कुछ प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। कुछ प्रमुख तिलहनों के समर्थनों मूल्यों में भी बढ़ोतरी की गयी, बिना छिली मूंगफली के मूल्यों में वृद्धि की मात्रा प्रति क्विंटल 25 रुपये थी। सरसों के दानों के लिए तीन वर्षों के अंतराल के बाद प्रति क्विंटल 355 रुपयों का समर्थन मूल्य घोषित किया गया।

81. विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों (पेट्रोल से इतर) के विक्रय मूल्यों में फरवरी 1983 से वृद्धि की गयी। संयुक्त संयंत्र समिति ने निर्मित उत्पादों में ढलवां लोहे और अन्य इस्पाती मदों के मूल्यों में अक्तूबर 1982 में संशोधन कर के, उसमें वृद्धि की। ढलवां लोहे के मूल्य में प्रति टन 100 रुपयों की वृद्धि की। प्लेटों और चादरों के प्लेटों में 250 रुपये प्रति मी. टन, संरचनात्मक सामग्री में 100 रुपये प्रति मी. टन, पहियों में 800 रुपये प्रति मी. टन और कोनिया लौह में 1000 रुपये प्रति मी. टन की वृद्धि की गयी। रेलवे भाड़ा दरों में बढ़ोतरी और समायोजन के परिणामस्वरूप संयुक्त संयंत्र समिति ने पहली अप्रैल 1983 से ढलवां लोहे के मूल्य में 105 रुपये प्रति मी. टन और इस्पात की वस्तुओं में

सारणी 8—थोक कीमतों के सूचकांक में घट-बढ़

(आधार 1970-71=100)

प्रमुख समूह/समूह/उप-समूह/पण्य	भार	जून 1981 के अन्त में	जून 1982 के अंत में	जून 1983 के अंत में	प्रतिशत बढ़ोतरी 1981-82 (2 से 3)	प्रतिशत बढ़ोतरी 1982-83 (3 से 4)
	1	2	3	4	5	6
सभी पण्य	1000	280.7	287.8	308.0	+2.5	+7.0
I. प्रमुख वस्तुएं	417	260.9	273.5	297.8	+4.8	+8.9
2. खाद्य वस्तुएं	298	229.6	250.4	279.2	+9.1	+11.5
(क)+(ख)	129	234.1	236.5	269.0	+1.0	+13.7
(क) अनाज	107	212.1	223.6	260.1	+5.1	+16.3
(i) चावल	51	220.8	243.2	296.6	+10.1	+22.0
(ii) गेहूं	34	184.8	191.3	210.0	+3.5	+9.8
(ख) दालें	22	339.9	300.2	313.3	—11.7	+4.4
(ग) फल और सब्जियां	61	238.1	275.1	305.8	+15.5	+11.2
(घ) दूध एवं दूध के उत्पादन	62	202.3	230.5	238.3	+13.9	+3.4
(ङ) अन्य खाद्यान्न वस्तुएं	16	244.0	261.5	384.9	+7.2	+47.2
(च) चाय	11	263.7	282.4	446.7	+7.2	+58.2
II. गैर खाद्यान्न वस्तुएं	106	241.1	239.7	268.6	+0.6	+12.1
रेशे	32	218.1	206.3	224.9	—5.4	+9.0
कपास	24	234.2	209.2	219.5	—10.7	—1.7
तिलहन	42	263.4	246.6	279.6	—6.4	+13.4
खनिज	13	1175.7	1112.8	989.3	—5.4	—11.1
पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस	6	2162.3	2006.4	1739.5	—7.2	—13.3
II. ईंधन, पावर, बिजली तथा चिकनाई के पदार्थ	84	401.0	447.9	477.1	+11.7	+6.5
कोयला	10	432.1	502.3	512.7	+16.2	+2.1
खनिज तेल	49	468.0	513.9	534.7	+9.8	+4.0
III. विनिर्मित उत्पादन	499	276.8	272.5	287.8	—1.6	+5.6

	1	2	3	4	5	6
1. खाद्य उत्पाद	133	336.1	270.7	288.5	−19.6	+6.6
(क) चीनी, खांडसारी तथा गुड़	72	403.5	283.4	293.0	−29.8	+3.4
(i) चीनी	22	276.5	238.5	233.8	−13.3	−2.8
(ii) गुड़	46	462.3	306.2	323.4	−33.8	+5.6
(ख) विविध खाद्य उत्पाद	49	261.7	256.8	284.8	−1.9	+10.9
खाद्य तेल	37	262.8	259.0	285.1	−1.4	+10.2
2. सूती वस्त्र उद्योग	110	223.2	229.6	241.6	+2.9	+5.2
3. कागज तथा कागज के उत्पाद	9	270.9	302.4	314.6	+11.6	+4.0
4. सीमेंट	7	231.7	357.2	399.7	+54.2	+11.9
5. रसायन तथा रासायनिक उत्पाद	56	254.7	265.5	277.7	+4.2	+4.6
6. मूल धातुएं, लौह मिश्रित धातुएं तथा लौह उत्पाद	60	305.7	349.2	375.4	+14.2	+7.5
7. मशीनरी तथा परिवहन उपकरण	67	259.0	275.5	288.3	+6.4	+4.6

*अनंतिम

160 रु० प्रति मी. टन की वृद्धि की। लेवी चीनी के विक्रय मूल्य में दिसंबर 1982 में प्रति किलोग्राम 10 पैसे की बढ़ोतरी की गयी। छपाई के सफेद कागज के प्रबंधित मूल्य में अप्रैल 1983 में प्रति टन 1,200 रु. की वृद्धि की गयी। सरकार ने 29 जून 1983 से सभी प्रकार के उर्वरकों के मूल्यों में 7.5 प्रतिशत की कमी की। 1983-84 के रेल बजट में प्रभावी भाड़ा दरों में वृद्धियां विभिन्न वस्तुओं पर लागू होती हैं तथा एक पैसे से 3.6 पैसे प्रति टन कि. मी. के बीच हैं। कृषि से इतर वस्तुओं का जिनके लिए प्रबंधित मूल्य वर्ष के दौरान बढ़ाये गये थे, थोक मूल्य सूचकांक में कुल वजन 8 प्रतिशत के आसपास है। चूंकि ये मुख्यतः माध्यमिक उत्पाद है, अतः विनिर्मित वस्तुओं के मूल्यों पर और प्रभाव पड़ेगा।

82. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक: औद्योगिक कामगारों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में (1960=100) 1982-83 में बिन्दु-वार आधार पर 10.9 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि हुई मगर वर्ष 1981-82 में उसमें 7.1 प्रतिशत की अल्प वृद्धि हुई थी। तथापि 1982-83 में हुई 9.0 प्रतिशत की औसत वृद्धि पिछले वर्ष की उसी अवधि में हुई 10.8 प्रतिशत की वृद्धि के मुकाबले कम थी। जैसा कि पिछले वर्ष की रिपोर्ट में चर्चा की गयी थी कि थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के स्वरूप और विन्यास में अंतर होने के कारण छोटी-सी अवधि के लिए उनकी गतिविधियों में असमानताएं पायी जाती हैं, परंतु लम्बी अवधि की दृष्टि से उनकी गतिविधियों में अपेक्षाकृत अधिक समानताएं पायी जाती है।

मूल्यांकन और सम्भावनाएं

83. कृषि उत्पादन में गिरावट और औद्योगिक वृद्धि में मन्दी इन, दोनों का राष्ट्रीय आय पर गंभीर प्रभाव पड़ा और वास्तविक राष्ट्रीय आय में 1982-83 में बहुत थोड़ी-सी वृद्धि हो पायी। यह अर्थव्यवस्था के बढ़े हुए लचीलेपन तथा आपूर्ति और मांग संबंधी नीतियों की प्रभाविष्णुता कारण ही है कि वर्ष के दौरान मूल्यों में सापेक्षित रूप से स्थिरता बनी रही। भयंकर सूखे तथा सहायता और व्यापार के लिए बिगड़े हुए विदेशी वातावरण के परिप्रेक्ष्य में मूल्य स्थिति और देश के विदेशी भुगतानों, दोनों की कुल व्यवस्था हो पाना, 1982-83 के दौरान आर्थिक कार्य निष्पादन की वस्तुतः एक बड़ी ही उत्साहजनक विशेषता रही।

84. वर्ष 1983-84 के लिए आर्थिक सम्भावनायें कृषि क्षेत्र में स्पष्ट सुधार की द्योतक है। कृषि उत्पादन में वृद्धि के परिणामस्वरूप मांग और आपूर्ति के असामंजस्य जैसी अल्पावधिक समस्याएं स्वयं हल हो जाने की वजह से औद्योगिक उत्पादन में बढ़ोतरी तीव्र पड़ने की सम्भावना है। फिर भी यह सुनिश्चित करने के वास्ते सावधानी बरतने की जरूरत है कि मूलभूत ढांचे की अपर्याप्तता उत्पादन में बाधक न बन जाय। कुल मिलाकर 1983-84 का वर्ष काफी सुधार का वर्ष होने की सम्भावना व्यक्त करता है। इसके साथ ही मूल्यों के मोर्चे पर सावधानी के साथ नजर रखनी होगी। जहां तक हाल के महीनों में कीमतों में वृद्धि पर मौसमी तत्वों के प्रभाव का सवाल है, अच्छी मानसून से निश्चय ही आपूर्ति में सुधार आयेगा और मुद्रास्फीति की सम्भावनाओं पर भी रोक लगेगी। साथ ही, गत वर्ष सामान्य-मूल्य-स्तर पर चीनी-समूह का जो नकारात्मक प्रभाव पड़ा था वह भी जारी रहने की सम्भावना नहीं है। पेट्रोलियम वस्तुओं, इस्पात और कोयले के मूल्यों में पहले की गयी वृद्धि के प्रभाव से विनिर्माण की लागतों और मूल्यों में आनेवाली और बढ़ोतरी को भी ध्यान में रखना होगा।

85. यद्यपि निकट भविष्य के लिए सम्भावनाएं उत्साहवर्धक हैं, अर्थ-व्यवस्था के लिए मध्यावधि संभावनाओं से उत्पन्न कुछ मुद्दों पर जोर देना जरूरी है जो नीति निर्माण को प्रभावित करते हैं।

86. इनमें से पहला मुद्दा कृषि से संबंधित है। कृषि के उत्पादन में धीमी वृद्धि के बारे में हाल ही में चिंता प्रकट की गयी है और यह विचार व्यक्त किया गया है कि विशेष रूप से अनाजों के उत्पादन के संबंध में एक गतिरोधक की स्थिति बन गयी है। इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि अब तक अधिकतम अन्न उत्पादन 1981-82 में 1330 लाख टन का रहा है जो कि 3 साल पहले अर्थात 1978-79 में हुए सर्वाधिक उत्पादन के केवल 10 लाख टन अधिक है। यद्यपि यह सत्य है किन्तु यह ध्यान में रखना होगा कि 1978-79 के बाद जो मानसून की दृष्टि से इस शताब्दी का सबसे अच्छा वर्ष माना जाता है मौसम कभी बहुत अनुकूल नहीं रहा है। 1979-80 में भारी सूखा पड़ा लेकिन उसके बाद के दो वर्षों में मानसून की समग्र स्थिति के बारे में ज्यादा से ज्यादा यह कहा जा सकता है कि वह "प्रतिकूल नहीं थी" 1982-83 का सूखा 1979-80 के सूखे से भी खराब माना जाता है। इस तरह पिछले चार वर्षों में मौसम की दृष्टि से सचमुच कोई अच्छा वर्ष नहीं रहा है। हां यहां इस बात का उल्लेख करना उचित है कि खाद्यान्न उत्पादन में गतिहीनता की इस प्रकार स्थितियां असामान्य नहीं है। उदाहरण के के लिए 1970-71 में उत्पादन 1084 लाख टन के उच्च शिखर पर पहुंच कर 1974-75 तक कमोबेश 970 से 1,050 लाख टन के बीच उतरता चढ़ता रहा। अगले वर्ष में उत्पादन एक नये स्तर तक जा पहुंचा। छठे और सातवें दशक में भी तेज उछालों के बाद उत्पादन के

गतिहीन हो जाने की इस प्रकार की घटनाएं होती रही हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि खाद्यान्न उत्पादन कमोबेश सीढ़ीनुमा तरीके से बढ़ता है। आठवें दशक के लिए समग्र और फसलवार दोनों वृष्टिकोणों से खाद्यान्न उत्पादन के आंकड़ों के विवेचनात्मक विश्लेषण से वृद्धि दर में कोई मंद गति दृष्टिगोचर नहीं होती। इसके साथ ही अगर प्रति व्यक्ति खाद्यान्नों की उपलब्धता को लगभग अपरिवर्तित मान लिया जाए तो पिछले दशक में प्राप्त की गई 2.50 प्रतिशत की वृद्धि दर जनसंख्या में वृद्धि की दर से केवल मामूली सी ही अधिक है। पिछले कुछ समय से यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि कृषि के लिए आवश्यक है कि नई फसलों और नए क्षेत्रों के लिए औद्योगिकी के इस्तेमाल को विकसित किया जाए। सिंचाई की स्थापित क्षमता का भरपूर उपयोग सूखे का सामना कर सकने वाली बीजों की किस्मों पर अनुसंधान गुणक खेती का विकास तथा छोटे किसानों तक पहुंचने के लिए अधिक प्रभावशाली सघन कार्य आदि कुछ तात्कालिक आवश्यकताएं हैं।

87. यद्यपि अगले कुछ वर्षों में भुगतान संतुलन नियंत्रित और व्यवस्थित रह सकता है, मगर देश के विदेशी भुगतानों की निरंतर अर्थ-क्षमता सुनिश्चित करने के लिए सावधानीपूर्वक योजना बनाने की जरूरत है। हाल ही के वर्षों में लिए गए काफी अधिक विदेशी ऋणों के शोधन और अदायगी का बोझ नौवें दशक के उत्तरार्ध में और भी बढ़ेगा। तेल मूल्यों में परिवर्तनों के संदर्भ में निजी खातों में प्रेषणों के भावी प्रवाह के बारे में अनिश्चितताओं को भी ध्यान में रखना होगा। बाहरी सहायता के आसार भी बहुत उत्साहवर्धक नहीं हैं। ऐसी स्थिति का सामना करने के लिये शुरुआत के तौर पर व्यापार घाटे को काफी कम करना होगा। इस स्थिति में यह तर्कसंगत है कि निर्यात संवर्धन और आयात विकल्प पर नए सिरे से ध्यान दिया जाये। वर्तमान प्रतिकूल अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में विशेष रूप से सबसे पहले निर्यात संवर्धन में लागतें घटाने और क्वालिटी में सुधार करने की जरूरत है। आयातों के क्षेत्र में सबसे अधिक उत्साहजनक स्थिति कच्चे तेल के संबंध में है। इधर कच्चे तेल के देशी उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है जिससे कुल उपलब्धता के प्रतिशत के रूप में आयात कम हुए हैं। इसके बावजूद ऊर्जा-उपभोग की वृद्धि की वर्तमान दर में कमी लाकर ऊर्जा के आयातित स्रोतों पर अपनी निर्भरता कम करने की जरूरत है। कच्चे तेल के अतिरिक्त कुछ और भी ऐसी वस्तुएं हैं जिनके बारे में आयात पर निर्भरता काफी तेजी से बढ़ी है उदाहरण के लिए वनस्पति तेल है। खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि पर अधिकतम जोर दिए जाने की जरूरत है ताकि अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या की जरूरत के लिए देश को आयातों पर निर्भर न रहना पड़े। इस तरह से भुगतान संतुलनों में घाटों को कम करने के लिए भी कृषि में तीव्र वृद्धि दर जरूरी हो जाती है।

88. इसी से जुड़ी दूसरी चिंता जो न केवल निकट भविष्य की है बल्कि आने वाले कई वर्षों के लिए हो सकती है वह है मुद्रास्फीति और उसके नियंत्रण से संबंधित समस्या की। अब यह बात भली प्रकार मान ली गई है कि मुद्रास्फीति की स्थिति आर्थिक वृद्धि के लिए मार्ग प्रशस्त नहीं करती। मुद्रास्फीति को जीवन का अंग मान लेने का विकल्प अब कोई विकल्प नहीं रह गया है। यदि हमारे भुगतान संतुलनों की अर्थक्षमता और विशेष रूप से हमारे निर्यातों की प्रतियोगिता-त्मकता को बनाये रखना है तो उसके लिए भी मुद्रास्फीति का नियंत्रण आवश्यक हो जाता है। इसलिए अब प्रासंगिक सवाल है मुद्रास्फीति विरोधी नीति के सही आयामों, मुद्रास्फीति के स्वरूप पर ध्यान दिये बिना कि यह प्राथमिक रूप से मांग प्रेरित अथवा उसमें लागतें बढ़ाने वाले घटक अधिक महत्वपूर्ण है नीति का एक महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि मुद्रा विस्तार का नियंत्रण हो यदि प्राप्त किया जाने वाला लक्ष्य मूल्य स्थिरता का है तो मुद्रा तथा ऋण की वृद्धि दर किसी भी समय वास्तविक उत्पादन में वृद्धि के प्रतिकूल नहीं रह सकती। हां व्यावहारिक नीति यह है कि न केवल वास्तविक उत्पादन की वृद्धि को बल्कि मूल्य स्तर में वृद्धि की किसी स्वीकार्य मात्रा को भी ध्यान में रखते हुए समग्र विस्तार की वांछित मात्रा पर भी विचार किया जाय। चूंकि मुद्रा सृजन की प्रक्रिया ऋण सृजन की प्रक्रिया भी है अतः केवल यही तय करना काफी नहीं है कि मुद्रा आपूर्ति कितनी बढ़ सकती है यह तय करना भी उतना ही जरूरी है कि विभिन्न इस्तेमाल करने वालों के बीच ऋण किस प्रकार आवंटित किये जाएंगे। अतएव, एक बार वांछित विस्तार पर विचार कर लिये जाने के बाद सरकार तथा वाणिज्य क्षेत्र दोनों ही में ऋण में इस्तेमाल करनेवालों को ऋण में वृद्धि को न्यूनतम रखने और कुल विस्तार को तय सीमाओं के भीतर ही रखने के अपरिहार्य अनुशासन के अधीन रहना होगा। ऐसी स्थिति में ही यह संभव है कि मुद्रा आपूर्ति वस्तुतः पूरी तरह से मौद्रिक प्राधिकरण के नियंत्रण में वास्तव में आ जाये।

89. हां इसका यह अभिप्राय नहीं है कि मूल्यों में वृद्धि की सभी स्थितियों में मौद्रिक विनियमन कारगर होगा। मूल्य नियंत्रण करने के लिए मूल भूत मुद्दों जैसे उत्पादकता की उपेक्षा नहीं की जा सकती। यदि मूल्य वृद्धि उत्पादन की इकाई लागत बढ़ने के फलस्वरूप हुई हो तो मौद्रिक नियंत्रण को लागू करना सही नीतिगत उपाय नहीं होगा। ऐसी परिस्थि-तियों में दीर्घकालीन नीति निवेश वस्तुओं के उपयोग में कुशलता बढ़ाने पर केन्द्रित होनी चाहिए। भारतीय परिस्थिति में स्थिर लगान की स्थितियों में बढ़ते हुए उत्पादन के लिए बचत दर बढ़ाने और पूंजी के इस्तेमाल की क्षमता में सुधार लाने की जरूरत होगी। यहां तक कि यदि निवेश दर को वर्तमान स्तर पर बनाये रखना है तो भी घरेलू बचत दर में वृद्धि की जरूरत पड़ेगी ताकि विदेशी बचतों की गिरावट की क्षति-पूर्ति की जा सके जो कि भुगतान संतुलन अंतराल को कम करने के लिए अपेक्षित संरचनात्मक समायोजन की प्रक्रिया का अंग है। बचत दर में वृद्धि भी किसी फायदे की नहीं होगी अगर इसके साथ साथ पूंजी का बेहतर इस्तेमाल नहीं किया जाता।

90. निकट भविष्य में लिए ऋण नीति का उद्देश्य कृषि और औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन में होने वाली संभावित वृद्धि को आधार प्रदान करना होना चाहिए। इसके लिए मूल्य वृद्धि की प्रवृत्ति पर नियंत्रण को जरूरत को ध्यान में रखना होगा बदलती हुई स्थितियों का सामना करने के लिए ऋण और मुद्रा की वृद्धि के अनुकूल ढालने में लक्ष्य यह होना चाहिए कि तंत्र में नकदी की मात्रा को नियमित किया जाये ताकि अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता के समग्र उपयोग को गुंजाइश के साथ-साथ मुद्रागत संभावनाओं को नियंत्रण में रखा जा सके।

भाग II—बैंकिंग एवं अन्य गतिविधियां

91. वर्ष के दौरान प्रमुख मौद्रिक एवं ऋण नीति संबंधी गतिविधियों की चर्चा पहले भाग में की गयी थी। रिपोर्ट के इस भाग में न केवल बैंकिंग एवं मौद्रिक क्षेत्रों की अन्य प्रमुख गतिविधियों की, बल्कि रिजर्व बैंक के कार्य के विभिन्न क्षेत्रों की भी चर्चा की गयी है। वर्ष 1982-83 (जुलाई-जून) के लिए बैंक का तुलन-पत्र एवं लेखे इसके अंत में दिये गये है।

बैंकिंग गतिविधियां

92. 1982-83 के लिए शाखा विस्तार नीति जैसा कि पिछले वर्ष की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था, अप्रैल 1982 से मार्च 1985 तक की तीन वर्ष की अवधि के लिए बैंक द्वारा तैयार की गयी शाखा लाईसेंस नीति का प्रमुख ध्येय यही बना रहा कि ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं में सुधार हो और ऐसी सुविधाओं के विस्तार में अन्तर्क्षेत्रीय विषमताएं कम की जायें। इस नीति का उद्देश्य ग्रामीण तथा अर्धशहरी क्षेत्रों में 1981 की जनगणना के आधार पर औसतन प्रति 17,000 की जनसंख्या के लिए एक बैंक कार्यालय का लक्ष्य प्राप्त करना है। राज्य सरकारों से ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे बैंकरहित स्थान निर्धारित करने के लिए कहा गया जहां नये बैंक कार्यालय स्थापित किये जा सकें। संबंधित राज्य सरकारों की सिफारिशों के आधार पर 18 राज्यों और 5 संघशासित क्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए शाखा विस्तार कार्यक्रमों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। शेष राज्यों संघशासित क्षेत्रों संबंधी कार्यक्रम इस समय अंतिम रूप दिये जाने के विभिन्न चरणों में है ग्रामीण अंचलों में नये बैंक

कार्यालय खोलने के लिए निर्धारित स्थानों के संबंध में राज्य सरकारों के सुझावों के आधार पर अब तक 5,100 स्थान बैंकों को आवंटित किये जा चुके हैं। अप्रैल 1983 के अंत की स्थिति के अनुसार 5,946 स्थानों में कार्यालय खोलने के लिए बैंकों के पास प्राधिकरण/लाईसेंस थे।

93. जुलाई 1982 से अप्रैल 1983 की अवधि के बीच वाणिज्य बैंकों द्वारा 2,278 कार्यालय खोले गये जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 3,115 कार्यालय खोले गये थे। इनमें से 363 कार्यालय भारतीय स्टेट बैंक और उसके सहयोगी बैंकों द्वारा 750 राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा तथा 99 निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा खोले गये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने 1,066 कार्यालय खोले। 1,720 कार्यालय अथवा नयी शाखाओं की कुल संख्या में से 75.5 प्रतिशत कार्यालय बैंक रहित क्षेत्रों में खोले गये। प्रति बैंक कार्यालय औसत जनसंख्या जून 1982 के अंत के 18,000 से घटकर अप्रैल 1983 के अंत में 17,000 रह गयी। जून 1969 के लिए यह औसत 65,000 के उच्च स्तर पर था। कुल बैंक कार्यालय में ग्रामीण क्षेत्र के कार्यालयों का अनुपात जो जून 1982 के अंत में 52.0 प्रतिशत था, बढ़कर अप्रैल 1983 में 53.5 प्रतिशत हो गया। जून 1969 में यह प्रतिशत 22.1 था।

94. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान केवल एक भारतीय बैंक, अर्थात इंडियन ओवरसीज बैंक की एक शाखा श्रीलंका में खोली गयी। जून 1983 के अंत में 25 देशों में 12 भारतीय वाणिज्य बैंकों की 138 शाखाएं कार्यरत थीं। इनमें पाकिस्तान में 17 तथा बंगला देश में स्थित 22 निष्क्रिय कार्यालय शामिल नहीं हैं। वर्ष के दौरान भारतीय स्टेट बैंक ने मास्को (रूस) तथा मिलान (इटली) में एक-एक प्रतिनिधि कार्यालय खोला। वर्ष के दौरान टोरन्टो (कनाडा) में सहायक बैंक तथा नाईजीरिया में संयुक्त तत्वावधान मर्चेंट बैंक की स्थापना के कारण, टोरन्टो (कनाडा) तथा लागोस (नाईजीरिया) में इसके प्रतिनिधि कार्यालय बंद कर दिये गये थे। वर्ष के दौरान दार-अस्सलाम (तंजानिया) में बैंक का प्रतिनिधि कार्यालय बंद कर दिया गया। इन कार्यालयों के बंद होने के साथ विदेशों में भारतीय बैंकों के प्रतिनिधि कार्यालयों की संख्या 12 रह गयी।

95 भारतीय स्टेट बैंक ने एक लास एंजेल्स (अमरीका) में स्टेट बैंक आफ इंडिया (कैलिफोर्निया) लि०, तथा कनाडा में स्टेट बैंक आफ इंडिया (कनाडा) नामक दो सम्पूर्ण स्वामित्व वाले सहायक बैंक स्थापित किये। इसने लागोस (नाईजीरिया) में एक संयुक्त तत्वावधान मर्चेंट बैंक में 40 प्रतिशत की ईक्विटी सहभागिता भी ली और उसके साथ प्रबंधकीय करार किया।

96 एक विदेशी बैंक अर्थात बैंक क्रैडिट एण्ड कामर्स इन्टरनेशनल (ओवरसीज) लि० केमान, आईलैण्ड ने भारत में अपने वर्तमान प्रतिनिधि कार्यालय का दर्जा बढ़ाकर, बम्बई में अपनी पहली शाखा खोली। इसके साथ जून 1983 के अंत की स्थिति के अनुसार, भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों की संख्या 17 और शाखाओं की कुल संख्या 131 हो गयी। ओमान अरब अफ्रीकन बैंक (ओमान) तथा बैंक आफ नोवास्कोशिया (कनाडा) को भी भारत में बैंकिंग कारोबार शुरू करने के लिए लाईसेंस जारी किये गये हैं। बैंक आफ नोवास्कोशिया अपने वर्तमान प्रतिनिधि कार्यालय का दर्जा बढ़ा कर कारोबार करेगा "द बैंक आफ फारेन" ट्रेड आफ द यू० एस० एस० आर० ने बम्बई में अपना प्रतिनिधि कार्यालय खोला जून 1983 के अन्त की स्थिति के अनुसार देश में 11 विदेशी बैंकों के एक एक प्रतिनिधि कार्यालय थे।

97. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक—समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 21 नए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किए गए। इसके साथ जून 1983 के अंत की स्थिति के अनुसार 245 जिलों को व्याप्त करते हुए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कुल संख्या 142 हो गई, जबकि छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, मार्च 1985 तक, 270 जिलों के लिए 170 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित करने का लक्ष्य है। जून 1983 के अंत की स्थिति के अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की जमाराशियां तथा अग्रिम क्रमशः 517.9 करोड़ रुपए तथा 623.7 करोड़ रुपए थे। एक वर्ष पहले ये राशियां क्रमशः 390.7 करोड़ रुपए तथा 465.6 करोड़ रुपए थीं।

98 नए शहरी सहकारी बैंकों का पंजीकरण—वर्ष के दौरान रिजर्व बैंक ने नए शहरी सहकारी बैंकों के प्रवर्तकों को सचेत किया कि वे सदस्य बनाना और उनसे शेयर पूंजी एकत्र करना शुरू न करें जब तक कि सम्बद्ध प्रस्तावों की जांच पूरी न हो जाए और उन्हें पंजीकरण के लिए स्वीकृत न कर लिया जाए। उन्हें प्रस्तावों के साथ, प्रारंभिक सर्वेक्षण रिपोर्ट तथा प्रस्तावित सदस्यता का विस्तृत व्यवसायवार वर्गीकरण भी प्रस्तुत करने के लिए कहा गया ताकि रिजर्व बैंक, अन्य बातों के साथ-साथ, उस क्षेत्र में प्रस्तावित बैंक की स्थापना की वास्तविक जरूरत का मूल्यांकन कर सके और साथ ही यह भी देख सके कि ये उस क्षेत्र में कमजोर वर्गों की जरूरतों को किस सीमा तक पूरा कर सकेंगे। यह कदम इसलिए उठाना पड़ा कि कई मामलों में इस बात के बावजूद कि उनके प्रस्ताव, कार्यक्षेत्र, उस क्षेत्र में प्रति बैंक कार्यालय औसतन जनसंख्या की सीमा आदि के मानदण्डों के अनुरूप नहीं थे, संचालकों ने सदस्यता अभियान और शेयर पूंजी एकत्र करने के लिए प्रयास शुरू कर दिए। रिजर्व बैंक को ये प्रस्ताव निरस्त करने पड़े, तथा संचालकों को उनके द्वारा पहले ही बना लिए गए सदस्यों की सदस्यता खारिज करनी पड़ी।

99. नया बीस-सूत्री कार्यक्रम लागू करने में बैंकों की भूमिका विषयक कार्यकारी दल—नया बीस सूत्री कार्यक्रम लागू करने में बैंकों की भूमिका विषयक कार्यकारी दल की सिफारिशों को भारत सरकार तथा रिजर्व बैंक द्वारा कतिपय संशोधनों के साथ मान लिया गया। रिजर्व बैंक ने बैंकों को 7 फरवरी 1983 को इस कार्यक्रम को लागू करने और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों, विशेष रूप से कमजोर वर्ग को ऋण प्रदान करने के विभिन्न लक्ष्यों और उप लक्ष्यों को प्राप्त करने के संबंध में अनुदेश जारी किये। यह बात सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का सारा ध्यान छोटे उधारकर्ताओं के वित्तपोषण की ओर हो, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के कुछ घटकों की परिभाषाओं में संशोधन किये गये। हालांकि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों के लिए निर्धारित बैंक ऋण के 40 प्रतिशत के समग्र लक्ष्य में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, लेकिन कृषि और कमजोर वर्गों के लिए ऋणों के उपलक्ष्यों में संशोधन कर दिये गये। बैंकों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि वे कृषि और संबंधित सेवाओं के लिए प्रत्यक्ष तथा परोक्ष दोनों प्रकार के वित्त के लिए 16 प्रतिशत के वर्तमान उपलक्ष्यों के स्थान पर सिर्फ कृषि (संबंधित सेवाओं सहित) के लिए प्रत्यक्ष वित्त का स्तर मार्च 1985 तक, कुल ऋण के कम से कम 15 प्रतिशत तक और मार्च 1987 तक कुल ऋण के कम से कम 16 प्रतिशत तक पहुंच जाये। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में कमजोर वर्गों की परिभाषा में 20-सूत्री कार्यक्रम के हिताधिकारियों के अनुरूप संशोधन किया गया। इसका लक्ष्य यह है कि समाज के कमजोर वर्गों के रहन सहन के स्तर में सुधार लाया जा सके। तदनुसार अब प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अन्तर्गत कमजोर वर्गों में निम्नलिखित शामिल होंगे—(क) 5 एकड़ अथवा कम की जोत की जमीन वाले छोटे एवं सीमांत कृषक, भूमिहीन मजदूर, काश्तकारी किसान तथा बटाईदार (ख) कारीगर, ग्राम तथा कुटीर उद्योग (ग) समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के हिताधिकारी (घ) अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियां (अनु०जा० अनु०ज०जा०) तथा विभेदक ब्याज दर योजना के हिताधिकारी। यह भी तय किया गया है कि मार्च 1985 के अन्त तक कमजोर वर्गों को दिये जाने वाले अग्रिम, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के कुल अग्रिमों के 25 प्रतिशत अथवा कुल बैंक ऋणों के 10 प्रतिशत के स्तर तक अवश्य पहुंच जाने चाहिए।

100 बैंक तथा समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम—इस समय भारत के सभी खण्डों में चल रहे समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (स०ग्रा० वि०का०) का उद्देश्य है सरकारी सहायता तथा संस्थागत वित्त की मदद से बिल्कुल ही गरीब लोगों, छोटे और सीमांत कृषकों, बटाईदारों, खेतिहर

मजदूरों, ग्रामीण कारीगरों, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा कमजोर वर्गों के जीवन स्तर सुधारना। हालांकि बैंकों को दिसम्बर 1981 में विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये गये थे जिनमें उन्हें स०ग्रा०वि०का० के अन्तर्गत ऋण प्रदान करने की गति बढ़ाने के उद्देश्य के वास्ते उनके द्वारा की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में बताया गया था, फिर भी प्रगति आशा के अनुरूप नहीं थी। फरवरी 1983 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कार्यपालकों के साथ हुई अपनी बैठक में गवर्नर ने उनका ध्यान इस ओर दिलाया और उनसे यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के हिताधिकारियों को ऋण प्रदान करने में और प्रगति करने के लिए प्रभावशाली कार्रवाई की जाये। इसके अतिरिक्त, निधियों का अंतिम उपयोग सही हो, इसकी भी देखरेख की जानी है ताकि उक्त कार्यक्रम के मुख्य लक्ष्य प्राप्त किये जा सकें।

101. विभेदक ब्याज दर योजना—विभेदक ब्याज दर योजना के अन्तर्गत ऋण प्रदान करने के संबंध में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने और प्रगति की। उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, उधार खातों की संख्या जो दिसम्बर 1980 के अन्त में 25.10 लाख थी वह बढ़कर दिसम्बर 1981 के अन्त में 29.25 लाख हो गयी। इन खातों में बकाया राशियों में 63 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई और वे 194 करोड़ रुपये से बढ़कर 257 करोड़ रुपये हो गयी। अनुपात के रूप में दिसम्बर 1981 के अन्त में विभेदक ब्याज पर अग्रिम (दिसम्बर 1980 के अन्त में) कुल अग्रिमों के 1.17 प्रतिशत तक पहुंच गये जबकि एक वर्ष पहले यह प्रतिशत 1.04 था। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उधारकर्ताओं की स्थिति में भी सुधार हुआ। उनके उधार खातों की संख्या दिसम्बर 1980 के अन्त के 11.18 लाख से बढ़कर, दिसम्बर 1981 के अन्त में, 13.76 लाख हो गयी तथा उनके ऋण की बकाया राशियां 88 करोड़ रुपये से बढ़कर 123 करोड़ रुपये हो गयी। इस योजना के अन्तर्गत कुल अग्रिमों के अनुपात के रूप में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के बकाया अग्रिम, दिसम्बर 1980 के 45.4 प्रतिशत से बढ़कर, दिसम्बर 1981 में, 47.9 प्रतिशत हो गये।

102 अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को ऋण सुविधाएं—अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को मिलने वाले संस्थागत ऋण की मात्रा को बढ़ाने की दृष्टि से सितम्बर 1982 में बैंकों से कहा गया था कि वे यह सुनिश्चित करें कि बैंक स्टाफ गरीब उधारकर्ताओं के फार्म आदि भरने और दूसरी खानापूरियां करने में मदद करें ताकि वे बिना किसी विलंब के ऋण सुविधाएं प्राप्त कर सकें। साथ ही उनका फील्ड स्टाफ अनपढ़ उधारकर्ताओं से संपर्क करें और उन्हें योजना की खास खास बातों और उनसे होने वाले लाभों के बारे में बताये। नवम्बर 1982 में उनसे यह भी कहा गया था कि वे इस वर्ग के वास्ते राज्य प्रायोजित विकास संगठनों को, इन संगठनों के हिताधिकारियों के लिए निवेश वस्तुओं की खरीद और आपूर्ति या विशिष्ट प्रयोजन और/अथवा उनके उत्पादनों के विपणन के लिए मंजूर किये गये अग्रिमों को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिया गया अग्रिम माने और उन पर कुछ शर्तों के अधीन 13.5 प्रतिशत वार्षिक रियायती दर पर ब्याज लिया जाना चाहिए। अप्रैल 1983 से इस दर को घटाकर 12.5 प्रतिशत कर दिया गया।

103 ऋण प्राधिकरण योजना—पिछले वर्ष की रिपोर्ट में निजी क्षेत्र के उधारकर्ताओं के लिए कार्यकारी पूंजी सीमाओं के वास्ते 17 जुलाई 1982 को घोषित विभाजन रेखा (कट आफ पाइंट) दो करोड़ रुपये से बढ़कर तीन करोड़ रुपये किये जाने का उल्लेख किया गया था। ऋण प्राधिकरण योजना से संबंधित नीति विषयक मार्गदर्शी सिद्धान्तों में इस वर्ष के दौरान किये गये कुछ और परिवर्तनों का उल्लेख आगे किया जा रहा है।

104. ऐसी, निर्यातोन्मुखी विनिर्माण इकाइयों के संबंध में, जिनका पिछले तीन वर्षों के दौरान वार्षिक औसत निर्यात पण्यावर्त उनके द्वारा निर्मित माल के कुल पण्यावर्त के 25 प्रतिशत से अधिक था और जिनका निर्यात पण्यावर्त आगे के वर्षों में उनके कुल पण्यावर्त के 25 प्रतिशत से कम नहीं होगा, कार्यकारी पूंजी सीमाओं के लिए कट आफ पाइंट बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये कर दिया गया। निजी क्षेत्र में गैर ऋण प्राधिकृत योजना पार्टियों को बैंकों द्वारा अकेले अथवा अन्य बैंकों के साथ संयुक्त रूप में मंजूर किये गये एकल मीयादी ऋणों के लिए कट आफ पाइंट, 25 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दिया गया। इसके अतिरिक्त, ऊपर बतायी गयी किस्म की निर्यातोन्मुखी विनिर्माण इकाइयों के लिए मीयादी ऋणों के लिए कट आफ पाइंट एक करोड़ रुपये निर्धारित किया गया।

105. कतिपय ऋण सुविधाओं को ऋण प्राधिकरण योजना के अन्तर्गत पूर्व प्राधिकरण से छूट दे दी गयी। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं: तीन माह से अनधिक अवधि के लिए वर्तमान पैकिंग ऋण सीमाओं के 25 प्रतिशत तक अतिरिक्त पैकिंग ऋण सुविधाएं अथवा 50 लाख रुपये जो भी कम हो, तीसरी पार्टी के दूसरे स्टेशन के चेकों/बैंक ड्राफ्टों की खरीद, उधारकर्ताओं के नाम पर सावधि जमाराशियों पर अग्रिम, तीन महीने से अनधिक की अवधि के लिए ऐसी वर्तमान सुविधाओं के 10 प्रतिशत तक अस्थायी कार्यशील पूंजी सीमाएं अथवा 40 लाख रुपये, जो भी कम हो तथा जहां बैंक द्वारा मंजूर की गयी उच्च सुविधाओं जारी करने का मामला रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकरण के लिए अनिर्णीत हो, वहां 25 लाख रुपये अन्तरिम कार्यशील पूंजी सीमाएं।

106 कट आफ पाइन्टों में वृद्धि किये जाने के फलस्वरूप ऋण प्राधिकरण योजना के अन्तर्गत आने वाली पार्टियों की संख्या जून 1982 के अन्त की 1,251 (सार्वजनिक क्षेत्र के 204 उपक्रमों सहित) से घटकर, जून 1983 के अंत में, 897 (सार्वजनिक क्षेत्र के 188 उपक्रमों सहित) रह गयी। हां, उक्त योजना के अंतर्गत आने वाली कुल चालू कार्यकारी पूंजी सीमाएं 15,906 करोड़ रुपये से बढ़कर 17,051 करोड़ रुपये हो गयी। सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों के 10,380 करोड़ रुपये के हिस्से में 2,010 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई जबकि निजी क्षेत्र के 6,671 करोड़ रुपये के हिस्से में 865 करोड़ रुपये की कमी आयी।

ऋण प्राधिकरण योजना के कार्यचालन की समीक्षा के लिए समिति—ऋण प्राधिकरण योजना के परिचालनगत पहलुओं के दृष्टिकोण से उसके कार्यचालन की समीक्षा के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने नवम्बर 1982 में एक समिति नियुक्त की। समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार थे:—

(1) योजना के लक्ष्यों, दायरों और विषयवस्तु की जांच करना और बदलती हुई आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उसमें यदि कोई संशोधन आवश्यक हों तो उनके लिए सुझाव देना।

(2) वाणिज्य बैंकों में मूल्यांकन मशीनरी प्रणालियों की पर्याप्तता अथवा अपर्याप्तता की जांच करना और उसके आधार पर, तत्संबंधी पद्धतियों में कोई सुधार आवश्यक हों तो उन्हें सुझाना।

(3) वाणिज्य बैंकों के भीतर प्रधान कार्यालय तथा उनके क्षेत्रीय कार्यालय, दोनों स्तरों पर इस योजना की अपेक्षाओं के अनुपालन के वर्तमान ढांचे का अध्ययन करना तथा सही मूल्यांकन तथा आवेदनों के शीघ्र निपटान और उनके अनुवर्तन की सुविधा के लिए यदि कोई संशोधन आवश्यक समझे जाएं तो उन्हें सुझाना।

(4) किसी पार्टी विशेष के लिए ऋण के विशेष स्तर के प्राधिकरण के लिए बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को सिफारिशें करने की वर्तमान आंकड़ा आधार की जांच करना और इस संबंध में कोई संशोधन/सरलीकरण आवश्यक हों तो सुझाना।

(5) प्राधिकरण मांगने के संबंध में बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदनपत्र के वर्तमान फार्मेट की जांच करना और उसमें यथावश्यक संशोधन सुझाना ।

(6) आवेदनपत्रों की जांच (प्रोसेसिंग) और निपटान में तेजी लाने के लिए, वाणिज्य बैंकों और रिजर्व बैंक के भीतर अपनाये जाने वाले समयबद्ध मार्गदर्शी सिद्धान्त शुरू करने की वांछनीयता का अध्ययन करना ।

(7) ऐसी अन्य सिफारिशें करना, जो योजना से संबंधित हों ।

107. समिति ने अपनी रिपोर्ट जून 1983 में रिजर्व बैंक को प्रस्तुत कर दी है और उसकी जांच चल रही है ।

108. रुग्ण औद्योगिक इकाइयां—बैंकिंग क्षेत्र से एक करोड़ रुपये अथवा अधिक की ऋण सीमाओं वाली रुग्ण इकाइयों के संबंध में बैंकों द्वारा दिसम्बर 1981 तक अन्तिम करायें गये आंकड़े दिखलाते हैं कि इस श्रेणी के अन्तर्गत जून 1982 के अंत में रुग्ण इकाइयों की संख्या 439 थी जिन पर कुल 1728.40 करोड़ रुपये के बैंक ऋण बकाया थे, जबकि जून 1981 के अंत में 422 इकाइयों पर 1453.29 करोड़ रुपये के बैंक ऋण बकाया थे । बैंकों द्वारा निर्धारित की गयी 439 बड़ी रुग्ण इकाइयों में से 374 के संबंध में व्यावहार्यता अध्ययन पूरे किये जा चुके हैं; इनमें से 320 में अर्थक्षमता की संभावना पायी गयी है और 235 इकाइयों को पोषण कार्यक्रम के अन्तर्गत रखा गया है ।

109. इसके अतिरिक्त, जून 1982 की स्थिति के अनुसार बैंकों ने 26,973 लघु रुग्ण इकाइयों को निर्धारित किया था, जिन पर कुल 393.67 करोड़ रुपये का बैंक बिल लगा हुआ था, जबकि जून 1981 के अंत में 22,360 रुग्ण इकाइयों के मामले में 321.52 करोड़ रुपये लगे हुए थे । बैंकों द्वारा इनमें से 5,316 इकाइयां अर्थक्षमता की संभावना वाली और 14,576 इकाइयां अक्षम समझी गयी थी । बैंकों ने 1982 अर्थक्षम इकाइयों को पोषण कार्यक्रम के अन्तर्गत रखा है ।

110. नाबार्ड के लिए सामान्य ऋण की व्यवस्था— जैसाकि पिछले वर्ष की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने 12 जुलाई, 1982 से कार्य करना प्रारंभ कर दिया । राज्य सहकारी बैंकों (एस सी बी) तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आर आर बी) को अल्पावधि पुनर्वित्त उपलब्ध करा सकने के लिए नाबार्ड को निधियां उपलब्ध कराने के वास्ते नाबार्ड के लिए एक सामान्य ऋण प्रणाली शुरू की गयी । भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 17(4) के अन्तर्गत इसे 1,200 करोड़ रुपये की अल्पावधि ऋण सीमा मंजूर की गयी है । इस समय इस सुविधा पर जो ब्याज लिया जा रहा है वह बैंक दर से 4.75 प्रतिशत कम है ।

111. मीयादी ऋण देने वाली संस्थाओं को सहायता—रिजर्व केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित वित्तीय संस्थाओं को दीर्घावधि ऋणदेक और साथ ही साथ अल्पावधि उधार सुविधाएं प्रदान करता है । भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को 1982-83 के दौरान राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि में से 245 करोड़ रुपये के दीर्घावधि ऋण मंजूर किये गये जबकि 1981-82 के दौरान इनकी राशि 265 करोड़ रुपये थी । भा०औ०वि० बैंक ने 245 करोड़ रुपये की पूरी राशि का उपभोग किया । भा०औ०वि० बैंक द्वारा राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घ-कालीन प्रवर्तन) निधि में से लिये गये कुल ऋण तथा बकाया की राशियां 30 जून, 1983 को 1,828 करोड़ रुपये हो गयी थीं ।

112. 1982-83 के दौरान भारतीय निर्यात आयात बैंक (एक्सिम बैंक) को राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि प्रवर्तन) निधि में से मंजूर किये गये दीर्घावधि ऋणों की राशि 45 करोड़ रुपये रही । इसकी तुलना में 1981-82 में यह राशि 25 करोड़ रु० थी । एक्सिम बैंक ने संपूर्ण ऋण सीमा का उपयोग कर लिया । एक्सिम बैंक द्वारा राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि प्रवर्तन) निधि से उधार ली गयी और बकाया राशि 30 जून, 1983 की स्थिति के मुताबिक 70 करोड़ रुपये थी ।

113. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को, उसके द्वारा 1982-83 में पुनर्भुनाये गये पात्र बिलों की जमानत पर मंजूर की गयी अल्पावधि ऋण सीमाएं 225 करोड़ रुपये रही जबकि 1981-82 में 190 करोड़ रुपये की सीमाएं मंजूर की गयी थीं । भा०औ०वि० बैंक को ये अल्पावधि सीमाएं इसलिए मंजूर की गयी थीं कि वह साधन जुटाने में अस्थायी अड़चनों को दूर कर सके और साथ ही, उसके द्वारा, राज्य सड़क परिवहन निगमों और राज्य विद्युत बोर्डों के वित्त पोषण के लिए निवेश संस्थाओं, जैसे, जीवन बीमा निगम तथा भारतीय यूनिट ट्रस्ट आदि से प्राप्त निधियों और भा०औ०वि० बैंक द्वारा इन निकायों के वास्तविक वितरणों के बीच के अंतराल को पार सके । भा०औ०वि० बैंक ने उपर्युक्त सीमा में से अल्पावधियों के लिए कई बार कुल 41.29 करोड़ रुपये की राशि के ऋण लिये तथा 30 जून 1983 को कुल बकाया राशि 1.95 करोड़ रुपये थी ।

114. भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को मंजूर की गयी 3 करोड़ रुपये की अल्पावधि ऋण सीमा को रिजर्व बैंक द्वारा दिसम्बर 1982 को समाप्त हुए एक और वर्ष के लिए बढ़ाया गया था । जून 1982 में भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम लि० (आई सी आई सी आई) को मंजूर की गयी 10 करोड़ रुपये की सीमा अगस्त 1983 में समाप्त हो जायेगी । निगम ने कई बार बहुत छोटी-छोटी अवधियों के लिए ऋण सीमा का उपभोग किया ।

115. बैंक ने 1983-84 के दौरान आठ राज्य वित्तीय निगमों को उनके तदर्थ बांडों के बदले कुल 16.75 करोड़ की नयी ऋण सीमा मंजूर की और 3 राज्य वित्तीय निगमों के संबंध में 9.20 करोड़ रुपये की ऋण सीमा अवधि बढ़ायी ।

116. जून 1983 के अंत में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम तथा भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम को मंजूर की गयी अल्पावधि सीमाओं में कोई राशि बकाया नहीं थी । राज्य वित्तीय निगमों की मंजूर की गयी सीमाओं के संबंध में 30 जून 1983 को बकाया राशियां 12 करोड़ रुपये थीं ।

117. चीनी मिलों के लिए वित्त—1981-82 के विस्तारित पेराई मौसम और 1982-83 के मौसम के पेराई कार्यों के शुरू होने से पहले मौसमेतर मरम्मतों के लिए बेजमानती ऋणों की तत्काल आवश्यकता को देखते हुए अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को 5 नवम्बर 1982 को सूचित किया गया था कि ऐसे प्रयोजनों के लिए चीनी मिलों को 25 लाख रुपये तक के बेजमानती ऋण मंजूर करने के लिए रिजर्व बैंक के पूर्व प्राधिकरण की जरूरत नहीं है । हां, ये ऋण 1982-83 का पेराई मौसम शुरू होने के बाद जितनी जल्दी हो सके, लेकिन हर हालत में 31 मार्च 1983 तक वापस अदा किये जाने थे । चूंकि इस उद्योग की अधिकतर इकाइयों द्वारा महसूस की जा रही तात्कालिक वित्तीय समस्या अनके खातों में मार्जिन घाटे को पूरा करने में उनकी असमर्थता थी, अतः बैंकों से यह कहा गया था कि वे अलग अलग मामलों की समीक्षा करें और गुणावगुण के आधार पर राहत प्रदान करें ।

118. अनसूचित वाणिज्य बैंकों को 6 नवम्बर 1982 को सूचित किया गया था कि वे 1982-83 के मौसम (जिसके दौरान उत्पादन 80 लाख टन के आसपास रहेंगे का अनुमान लगाया गया था) के लिए ऋण सीमाओं पर विचार करते समय सरकार द्वारा निर्धारित किये गये न्यूनतम गन्ना मूल्य को ध्यान में रखें तथा उन्हें, अलग अलग इकाइयों के चीनी उत्पादन के अनुमानों के अधीन, रिजर्व बैंक का पूर्व प्राधिकरण प्राप्त किये बिना वर्ष 1981-82 मौसम के दौरान ली गयी अधिकतम राशि (अस्थायी अतिरिक्त आहरणों को छोड़कर) के 125 प्रतिशत तक सीमाएं मंजूर करने की अनुमति दे दी गयी थी । उधारकर्ता खातों में

वास्तविक आहरण, मिलों के मासिक नकदी बजटों में दिखलाये गये आटे के आधार पर नियमित किये जाने थे। बैंकों से यह भी कहा गया कि वे गन्ना उत्पादकों को, चीनी मिलों द्वारा गन्ने के मूल्य की बकाया राशियों के भुगतान की देख रेख की प्रथा को और उधारकर्त्ताओं के परामर्श से, गन्ना उत्पादकों को भुगतान के लिए चीनी की गिरवी/दृष्टि-बंधक पर अग्रिमों में से निधियों को उद्दिष्ट करने की प्रणाली को यथावत जारी रखें।

119. जूट, चाय, चीनी और उर्वरकों के विषय में स्थायी समितियां—इन उद्योगों की वित्तीय समस्याओं के निरन्तर आधार अध्ययन के लिए रिजर्व बैंक द्वारा संस्थागत वित्त के समन्वयन के लिए जूट और चाय के वास्ते नवम्बर 1982 में तथा चीनी और उर्वरकों के लिए जनवरी 1982 में स्थायी समितियां गठित की गयी। इन समितियों के सदस्य भारतीय रिजर्व बैंक, मीयादी ऋणदात्री संस्थाओं, संबंधित उद्योगों, केन्द्र सरकार तथा विशेषज्ञों/प्रौद्योगिकीविदों में से चुने गये हैं।

120. चयनात्मक ऋण नियंत्रण—मूल्यों में घट-बढ़ वाली वस्तुओं के लिए ऋणों के संबंध में वर्तमान चयनात्मक ऋण नियंत्रण उपाय, कुछ वस्तुओं के लिए मार्जिन की अपेक्षाओं में समायोजनों और मार्जिन से छूट प्राप्त ऋणों के वर्गों में कुछ वृद्धियों के साथ, इस वर्ष के दौरान जारी रहे।

121. 1981-82 के मौसम में चीनी के काफी अधिक उत्पादन और मिलों के पास बड़े स्टाकों को देखते हुए चीनी के "न जारी किये गये" स्टाकों पर अग्रिमों की मार्जिन अपेक्षाओं को, 13 सितम्बर, 1982 से प्रभावी, 25 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया। इसी तरह गुड़ और खांडसारी के निर्माताओं को इन वस्तुओं के स्टाकों पर दिये जाने वाले अग्रिमों पर मार्जिन 65 प्रतिशत से घटाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया। चीनी के "न जारी किये गये" स्टाकों (बफर स्टाकों को छोड़कर) पर मार्जिन को 18 नवम्बर, 1982 से प्रभावी, 20 प्रतिशत से भी और घटाकर 17.5 प्रतिशत कर दिया गया था। बैंकों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि इस आधार पर चीनी इकाइयों के पास उपलब्ध होने वाली अतिरिक्त राशि का उपयोग जहां कहीं गन्ने का मूल्य बकाया हो, वहां उसका भुगतान करने तथा मुनाफाती व्यय पूरे करने के लिए किया जाये।

122. रोजगार के अवसर जुटाने के लिए संस्थागत आधार उपलब्ध कराने में खादी और ग्रामोद्योग आयोग की भूमिका की समीक्षा के पश्चात खादी और ग्रामोद्योग आयोग और उसकी सहयोगी संस्थाओं को मूल्यों में घट-बढ़वाली वस्तुओं के बदले दिये गये अग्रिमों को 26 अक्तूबर, 1982 से, लागू चयनात्मक ऋण नियंत्रणों के सीमा क्षेत्र से पूरी छूट दे दी गयी।

123. बम्बई में लम्बे अरसे से चली आ रही हड़ताल से प्रभावित सूती वस्त्र मिलों को सहायता उपलब्ध कराने और उनके तेजी से पुनर्वास में सहायता करने की दृष्टि से रिजर्व बैंक ने 1 दिसम्बर, 1982 से, रुई और कपास के स्टाकों पर सूत मिलों और साथ ही साथ नेशनल टैक्सटाईल कार्पोरेशन की बम्बई स्थित मिलों को अग्रिमों पर मार्जिन में, 3 जून, 1983 तक के 6 महीनों के लिए, 10 प्रतिशत पाईंटों की कमी कर दी।

124. पहली अप्रैल 1983 से प्रभावी बैंकों की ऋण दरों में कटौती के बारे में इस रिपोर्ट के भाग 1 में उल्लेख किया गया है। चयनात्मक ऋण नियंत्रण (चीनी मिलों को अग्रिमों के अतिरिक्त) के अधीन पण्यों पर लागू ब्याज की न्यूनतम दरों को भी 19.5 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया। सभी स्टाकों के संबंध में चीनी मिलों को दिये जाने वाले अग्रिमों के मामले में ब्याज की न्यूनतम दर 16.5 प्रतिशत पर तय की गयी और बैंकों को ऐसी दर वसूल करने की इजाजत दी गयी जो इस दर और अग्रिमों पर सामान्य न्यूनतम दर अर्थात् 18 प्रतिशत के बीच हो।

125. बैंकों को ऐसे निर्यातकों को पैकिंग ऋण मंजूर करने की अनुमति दी जाती है, जो आवश्यक कच्चे माल की सीमा तक संबंधित कच्चे माल (अर्थात् मूंगफली, बिनौले तथा चावल की भूसी) की जमानत पर तेल निकली हुई तथा खरदीरहित खली का निर्यात करते हैं चाहे मंजूर की गयी राशि निर्यात आदेश के मूल्य से अधिक ही क्यों न हो। लेकिन यह सुविधा इस शर्त पर दी जाती है कि निर्यात के मूल्य से अधिक राशि का समायोजन तेल निकालने के तुरंत बाद उसके सह उत्पाद के विक्रय द्वारा अथवा नकद रूप में समायोजित किया जाये, लेकिन यह समायोजन अग्रिम की तारीख से 15 दिन की अवधि में हो जाना आवश्यक है। निर्यातकों-उधारकर्त्ताओं द्वारा अतिरिक्त पैकिंग ऋण के समायोजन में अनुभव की जानेवाली कठिनाइयों को दृष्टि में रखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने पहली जुलाई 1983 को अथवा उसके बाद मंजूर किये गए पैकिंग ऋण के लिए समायोजन की अवधि को 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दिया है।

126 बैंकों का निरीक्षण—समीक्षाधीन वर्ष के दौरान वार्षिक मूल्यांकन के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों के निरीक्षण का दूसरा दौर लगभग पूरा कर लिया गया। तीसरे दौर के अंतर्गत 17 बैंकों के निरीक्षण का कार्य शुरू किया गया। इसके अतिरिक्त 24 बैंकों का द्वितीय निरीक्षण एवं भारतीय बैंकों की इंग्लैण्ड स्थित 13 विदेशी शाखाओं का निरीक्षण किया गया था। इनके अलावा, बहुत-सी छानबीन भी की गयी। ये अदा किये गये वाले और छोटे उधारकर्त्ताओं के संबंध में आवेदनों के संबंध में सत्यापन तथा साथ ही साथ निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम द्वारा जारी गारंटियों के अन्तर्गत आनेवाले (लघु उद्योग) अग्रिमों की परीक्षा जांच, विभिन्न शिकायतों/धोखाधड़ियों तथा बैंकों/उनके कर्मचारियों के खिलाफ आरोपों और चयनात्मक ऋण नियंत्रण निदेशों के उपबंधों के अनुपालन की जांच से संबंधित थे।

127 बैंकों में धोखाधड़ी—गवर्नर ने 25 फरवरी, 1983 को सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कार्यपालकों के साथ हुई अपनी बैठक में बैंकिंग तंत्र की बिगड़ती हुई छवि, असंतोषजनक ग्राहक सेवा के बारे में बढ़ती हुई शिकायतों, बैंकों में व्याप्त भ्रष्टाचार/दुराचार, धोखाधड़ियों की बढ़ती हुई संख्या पर चिंता व्यक्त की। अतएव बैंकों से कहा गया कि वे सतर्कता मशीनरी की समीक्षा करें और उसका पुनर्गठन करें नियंत्रण और पर्यवेक्षण को बेहतर बनाने के लिए तत्काल कदम उठायें, प्रबंध सूचना प्रणाली अनुवर्तन और निरीक्षण/लेखा-परीक्षा व्यवस्थाओं को मजबूत करें और बहियों के तुलना और अंतरशाखा तथा अन्य खातों के समाशोधन के बकाया काम को निपटाने के लिए, समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करें। धोखाधड़ियों की रोकथाम के लिए अप्रैल 1983 में उन्हें विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धांत भी जारी किए गये। बैंक में एक विशेष आसूचना कक्ष स्थापित किया गया है जो अन्य बातों के साथ-साथ बैंक की जानकारी में आने वाली प्रमुख धोखाधड़ियों की विशेष रूप से जांच करेगा और साथ ही साथ धोखाधड़ियां रोकने की दृष्टि से जारी किये गये विभिन्न मार्गदर्शी सिद्धांतों के लागू किये जाने पर कड़ी नजर रखेगा।

128. बैंकों में ग्राहक सेवा—रिजर्व बैंक ने राष्ट्रीयकृत बैंकों, भारतीय स्टेट बैंक और भारतीय बैंक संघ (आइबीए) के साथ बैंकिंग सेवा के ऐसे कतिपय नाजुक क्षेत्रों के बारे में चर्चा करने के लिये, जहां ग्राहक सेवा सुधारने के लिए समन्वित प्रयास किये जा सकते हैं, एक बैठक आयोजित की। बैंकों से निम्नलिखित क्षेत्रों पर और अधिक ध्यान देने के लिए कहा गया है:—टैलर प्रणाली, बैंक ड्राफ्ट जारी करना/उनका भुगतान, यात्री चेकों के भुगतान की व्यवस्थायें, बाहरी चेकों की उगाही, उगाही के लिये अग्रे 2,500 रुपये तक की राशि के बाहरी चेकों के प्रस्तुत किये जाने पर तुरंत जमा लिखना, ग्राहकों को खातों का विवरण सही समय पर भेजना, स्टाफ का व्यवहार और सामान्य अनुशासन, बैंकों का इस्तेमाल करने वालों की शिकायतों/सुझावों पर अनुवर्ती कार्रवाई तथा ग्राहक सेवाओं विषयक कार्यकारी दल की सिफारिशों के बैंकों के स्तर पर कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण एवं देखरेख। बैंक से कहा गया है कि अपनी प्रगति रिपोर्ट रिजर्व बैंक को भेजें।

129. बैंकों का पूंजीगत आधार—पिछले वर्ष की रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया गया था कि भारतीय बैंकों की अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर बढ़ती हुई स्थिति और विदेशों में उनकी छवि बनाने की जरूरत को देखते हुए बैंकों का पूंजीगत आधार बढ़ाने का निर्णय किया गया। भारत सरकार ने 1981-82 में 8 राष्ट्रीयकृत बैंकों की अतिरिक्त पूंजी के लिए 25 करोड़ रुपये प्रदान किये थे। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 3 और राष्ट्रीयकृत बैंकों की अतिरिक्त शेयर पूंजी के लिए 5 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये गये। इसके अतिरिक्त, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 में संशोधन किया गया है जिसके द्वारा सरकार द्वारा अभिसूचित किये जाने वाले बैंक अपनी कुल आय के 40 प्रतिशत से अनधिक राशियों के भाग को "विशेष प्रारक्षित खाते" में अन्तरित करने की स्थिति में हो सकेंगे। यह आयकर के प्रयोजन के लिए आय की गणना करते समय छूट की पात्र होगी।

130. बैंक जमाराशियों विषयक कार्यकारी दल : सिफारिशें—जैसा कि इस रिपोर्ट के भाग I में उल्लेख किया गया है रिजर्व बैंक ने पांच वर्ष और उससे अधिक की मीयादी जमाराशियों की श्रेणी फिर से शुरू करने और उस पर 11 प्रतिशत ब्याज दर की अनुमति देने की बैंक जमाराशियों विषयक कार्यकारी दल की सिफारिश को मान लिया है। बैंक ने रिपोर्ट में की गयी कतिपय अन्य सिफारिशों पर कार्रवाई शुरू की और बैंक जमाराशियों पर लागू होने वाले उपबंधों में कुछ संशोधन किये। अवधि समाप्ति से पहले पैसा वापस लेने पर दण्ड की दर दो प्रतिशत से घटाकर एक प्रतिशत कर दी गयी है। अवधि समाप्ति से पहले आहरण पर अथवा पुनर्निवेश योजना के अन्तर्गत जमाराशि के नवीकरण पर देय ब्याज चक्रवृद्धि दर पर होगा न कि साधारण दर पर। दैनिक जमा योजना तथा आवर्ती जमा योजना की राशियां अवधि समाप्ति से पहले बिना किसी दण्ड के सावधि जमाराशियों में परिवर्तित की जा सकती हैं। किसी मृत जमाकर्ता के नाम के चालू खाते में पड़ी शेष राशि पर तब तक बचत जमा की दर पर ब्याज देय होगा जब तक जमाराशि कानूनी उत्तराधिकारी को चुका नहीं दी जाती। पहले ही पात्र घोषित किये जा चुके कतिपय संगठनों के अतिरिक्त जो संस्थायें आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत आयकर चुकाने के लिए बाध्य नहीं हैं, वे भी बैंकों में अपने बचत बैंक खातों पर ब्याज अर्जित करने की पात्र होंगी। रिपोर्ट में की गयी कतिपय अन्य सिफारिशों पर रिजर्व बैंक सक्रियता से विचार कर रहा है।

131. बैंकिंग विधि (संशोधन) विधेयक—बैंकिंग विधि (संशोधन) विधेयक, जिसमें कतिपय महत्वपूर्ण उपलब्ध हैं, 10 मई 1983 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। बिल में अन्य बातों के अलावा निम्नलिखित की व्यवस्था की गयी है : बैंक खातों के संबंध में नामांकन सुविधायें प्रदान करना, अलग-अलग व्यक्तियों, फर्मों आदि द्वारा इस बिल में विहित संख्या से अधिक जमाकर्ताओं से जमाराशियां स्वीकार करने पर रोक लगाना, रिजर्व बैंक को यह शक्ति प्रदान करना कि वह अधिसूचना जारी करके सांविधिक नकदी अनुपात को 25 प्रतिशत से 40 प्रतिशत के बीच घटा-बढ़ा सके, बैंकों को यह सुविधा देना कि वे पट्टे पर लेने/देने के काम जैसे नवोन्मेष उपाय कर सकें तथा निजी क्षेत्र के बैंकों के ऐसे निदेशकों की कार्यावधि सीमित करना जो आठ वर्ष से अधिक की अवधि तक पद पर लगातार बने रहते हैं।

132. मौद्रिक प्रणाली की कार्य-विधि की समीक्षा के लिए समिति—रिजर्व बैंक ने दिसम्बर 1982 में, मौद्रिक प्रणाली की कार्यविधि का गहराई से अध्ययन करने के लिए एक पांच सदस्यीय समिति की नियुक्ति की। इस समिति को निम्नलिखित कार्य सौंपे गये हैं :—

(i) योजनाबद्ध विकास के मूल उद्देश्यों के संदर्भ में मौद्रिक प्रणाली के ढांचे और परिचालन की विवेचनात्मक समीक्षा करना।

(ii) मौद्रिक नीति और अन्य नीतियों, विशेष रूप से राजकोषीय नीति और लोक ऋण प्रबंध के बीच उस सीमा तक परस्पर प्रभाव का मूल्यांकन करना जिस सीमा तक वे मौद्रिक नीति की प्रभविष्णुता को प्रभावित करती हैं।

(iii) मौद्रिक तथा ऋण नीति के विभिन्न उपायों का ऋण प्रणाली और अर्थ व्यवस्था पर उनके प्रभाव के संदर्भ में मूल्यांकन करना। इसी संदर्भ में, बैंकिंग क्षेत्र, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं और असंगठित क्षेत्रों के बीच संबंधों का भी मूल्यांकन किया जा सकेगा;

(iv) मौद्रिक तथा ऋण नीतियों के ढांचे और परिचालन में सुधार के लिए उपायों की सिफारिश करना तथा ऐसे विशिष्ट क्षेत्रों के बारे में सुझाव देना जहां विभिन्न नीति संबंधी उपायों को मजबूत करने की जरूरत है; तथा

(v) ऐसी अन्य सिफारिशें करना जिन्हें समिति मौद्रिक तथा ऋण नीति के प्रभावशाली परिचालन के संबंध में उचित समझे।

133. समिति से जून 1984 के अन्त तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देने के लिए कहा गया है।

134. अर्थशास्त्रियों के पैनल—अकादमिक समुदाय से निकट का संपर्क स्थापित करने की दृष्टि से रिजर्व बैंक ने इस वर्ष के दौरान अर्थशास्त्रियों के 4 पैनल बनाये जो समय-समय पर मिलकर निम्नलिखित से संबंधित मामलों पर चर्चा कर सकेंगे : (1) समष्टि अर्थशास्त्रीय प्रणाली (2) उद्योग और औद्योगिक वित्त (3) कृषि और ग्रामीण विकास तथा (4) भुगतान संतुलन।

135. पूर्वी भारत में कृषि संबंधी उत्पादन और उत्पादकता की प्रवृत्तियों के अध्ययन के लिए समिति—चूंकि पूर्वी भारत में कृषि संबंधी उत्पादन और उत्पादकता की हाल ही की प्रवृत्तियां चिंता उत्पन्न कर रही थी, अतः भारतीय रिजर्व बैंक तथा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने मार्च 1983 में इन प्रवृत्तियों का अध्ययन करने तथा विशेष रूप से कृषि ऋण के क्षेत्र में ऐसे उपाय सुझाने के लिए समिति नियुक्त की थी जिन्हें नवें दशक की समाप्ति से पूर्व, जहां तक संभव हो सके, उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के लिए अपनाया जा सके।

136. इस समिति को जो कार्य सौंपे गये थे, उनमें बिहार, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में कृषि संबंधी उत्पादन की हाल ही के वर्षों की प्रवृत्तियों की समीक्षा करना तथा क्षेत्र की क्षमताओं तथा देश के शेष भागों की प्रवृत्तियों के साथ उनकी तुलना करना; ऊपर गिनाये गये राज्यों में उत्पादन के संभावित स्तर प्राप्त करने में आने वाली विभिन्न अड़चनों का पता लगाना और नवें दशक अर्थात् 1990 की समाप्ति तक यथासंभव सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए आवश्यक ऋण तथा निवेश पर विशेष ध्यान देते हुए उपाय सुझाना।

137. समिति को अपनी रिपोर्ट 6 माह के भीतर प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

विदेशी मुद्रा नियंत्रण तथा अन्य मामलों से संबंधित गतिविधियां

138. भारतीय राष्ट्रिकता अथवा मूल के अनिवासियों द्वारा निवेश—भाग I में भारतीय राष्ट्रिकता अथवा मूल के अनिवासियों द्वारा निवेश और ऐसे निवेश की बिक्री-आयों की वापसी से संबंधित कार्यविधियों के सरलीकरण के बारे में संक्षेप में उल्लेख किया गया है। अधिक ब्यौरे नीचे दिये जा रहे हैं :—

139. भारतीय राष्ट्रिकता अथवा मूल के अनिवासियों (ऐसे विदेशी निकायों सहित जिनमें इस प्रकार के व्यक्तियों का कम से कम 60 प्रतिशत हिस्सा है) को भारतीय कंपनियों के ईक्विटी शेयरों में पोर्टफोलियो अथवा प्रत्यक्ष निवेश के लिए उपलब्ध सुविधा को अब अधिमान शेयरों और डिबेंचरों (परिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय) में निवेशों के लिए भी बढ़ा दिया गया है।

140. भारतीय अनिवासियों के लिए पोर्टफोलियो निवेश योजना को भी, उसके परिचालन के दौरान हुए अनुभवों के प्रकाश में संशोधित किया

गया है। संशोधित योजना के अंतर्गत नामित बैंक हर मामले के लिए रिजर्व बैंक के विशिष्ट अनुमोदन के बिना निवेशिती कंपनी की कुल चुकता ईक्विटी पूंजी के 5 प्रतिशत तथा कंपनी द्वारा जारी किये गये परिवर्तनीय डिबेंचरों की प्रत्येक सिरीज के कुल चुकता मूल्य के 5 प्रतिशत की समग्र सीमा के अधीन एक प्रतिशत प्रति अनिवासी निवेशकर्ता की सीमा तक, ईक्विटी शेयर तथा परिवर्तनीय डिबेंचर खरीद सकते हैं। 5 प्रतिशत की सीमा प्रत्यावर्तन तथा गैर-प्रत्यावर्तन दोनों आधारों पर शेयर बाजार के जरिये ईक्विटी शेयरों और परिवर्तनीय शेयरों की खरीदियों पर लागू होगी। ऐसे ईक्विटी शेयर जो अनिवासी निवेशकर्ता, डिबेंचरों के परिवर्तन पर प्राप्त कर सकते हैं, 5 प्रतिशत की उच्चतम सीमा की गणना करने के प्रयोजन के लिए शामिल नहीं किये जायेंगे। कुल ऊपरी सीमा पर भारतीय रिजर्व बैंक के बम्बई स्थित केन्द्रीय कार्यालय द्वारा नजर रखी जायेगी। निवासी भारतीयों की ओर से स्टाफ एक्सचेंज के माध्यम से 5 प्रतिशत की सीमा से अधिक के ईक्विटी शेयर और परिवर्तनीय ऋणपत्रों की खरीद के लिए रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति आवश्यक होगी।

141. साथ ही, 40 प्रतिशत और 74 प्रतिशत वाली योजनाओं के अंतर्गत, पूर्ण प्रत्यावर्तन के लाभ सहित नये निर्गमों में सीधे निवेश की सुविधा जो पहले निर्माण कार्यों में संलग्न कंपनियों और विनिर्दिष्ट प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों के नये निर्गमों के संबंध में उपलब्ध थी, उसे अब अस्पतालों तथा "थ्री स्टार", "फोर स्टार", "फाइव स्टार" होटलों के संबंध में भी लागू कर दिया गया है।

142. भारतीय राष्ट्रिकता अथवा मूल के अनिवासी और कम से कम 60 प्रतिशत की सीमा तक उनके स्वामित्व वाले विदेशी निकायों को अब यह अनुमति दे दी गयी है कि वे "पब्लिक लिमिटेड कंपनियों" (सीमित दायित्व वाले सरकारी उपक्रमों सहित) में, पूर्ण प्रत्यावर्तन के लाभ सहित, 3 वर्षीय जमाराशियों के रूप में अपनी निधियां नियोजित कर सकते हैं बशर्ते कि जमाराशियां विदेश से प्रेषण के माध्यम से अथवा एन०आर० (ई०) रुपया खातों/एफ०सी०एन०आर० खातों/प्रेषणों से उपलब्ध करायी जायें और कि वे पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा ऐसी जमाराशियां स्वीकार किये जाने से संबंधित विद्यमान नियमों के अनुसार हों।

143. प्रत्यावर्तन के आधार पर स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से अनिवासियों द्वारा प्राप्त किये गये शेयरों की बिक्री से प्राप्त आय के प्रत्यावर्तन की सुविधा केवल तभी उपलब्ध होगी जब धारक, अथवा उसके बैंक, अथवा बैंक द्वारा नामित व्यक्ति के नाम में, शेयरों के पंजीकरण की तारीख से कम से कम एक वर्ष के लिए, निवेश को जारी रखा गया हो। ऐसे मामलों में, पूंजी निवेश की प्राप्ति की लागत की सीमा तक बिक्री से प्राप्त आय, अथवा वास्तविक बिक्री आय जो भी कम हो, आयकर प्राधिकारियों का "अनापत्ति प्रमाणपत्र" अथवा कर भुगतान प्रमाणपत्र प्रस्तुत किये बिना, प्रत्यावर्तित की जा सकती है। पूंजीगत लाभ की राशि का प्रत्यावर्तन आयकर प्राधिकारियों का कर भुगतान प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर किया जा सकता है।

144. शेयरों और ऋणपत्रों के नये निर्गमों में सीधे निवेश को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से रिजर्व बैंक भारतीय कंपनियों को विदेशों में अपने एजेंट नियुक्त करने तथा उनकी सहायता से प्राप्त वास्तविक निवेश की मात्रा के आधार पर, उन्हें उचित सीमा तक मेहनताने के भुगतान की अनुमति प्रदान करेगा।

145. आयात-निर्यात विषयक विशेषज्ञ समिति—रिजर्व बैंक ने नवंबर 1982 में निर्यात और आयात से संबंधित विदेशी मुद्रा नियंत्रण विनियमों की जांच तथा दस्तावेज-क्रियाविधियों को सरल और सुगम बनाने के लिए उपाय सुझाने के वास्ते एक विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति की। यह समिति, भारतीय फर्मों/कंपनियों द्वारा विदेशों में अपने कार्यालय खोलने, व्यापारिक प्रतिनिधियों को कमीशन का भुगतान करने, रायल्टी और लाइसेंस शुल्कों के प्रेषण भारतीय कार्मिकों की विदेशों में प्रतिनियुक्ति करने, विदेशी मुद्रा के प्राधिकृत डीलरों को अधिकारों के प्रत्यायोजन की वर्तमान प्रणाली का अध्ययन करने, जहां और अधिकारों का प्रत्यायोजन किया जा सकता है उन क्षेत्रों का सुझाव देने तथा विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों के कार्यों में और अधिक विकेन्द्रीकरण की संभावना की जांच करने जैसे अन्य संबंधित मामलों के बारे में विदेशी मुद्रा नियंत्रण विनियमों की समीक्षा भी करेगी। आशा है, यह समिति दिसंबर 1983 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी।

146. क्रियाविधियों में छूट/उनका सरलीकरण—भारत में स्थायी तौर से बसे व्यक्तियों द्वारा पूर्णतः अथवा मुख्यतः स्वर्ण से बने व्यक्तिगत आभूषण भारत से बाहर ले जाने से संबंधित 5,000 रुपये तक की प्रति व्यक्ति सीमा को बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है। अफगानिस्तान, ईरान और खाड़ी के देशों को छोड़कर किसी भी अन्य देश में जाने वाले किसी भी यात्री के लिए, पूर्णतः अथवा मुख्यतः स्वर्ण से बने आभूषणों को छोड़कर अन्य जवाहरात और आभूषणों के भारत से बाहर ले जाने से संबंधित प्रति व्यक्ति सीमा को भी 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है।

147. निवेश को छोड़कर अन्य प्रयोजनों के लिए एन०आर० (ई) रुपया तथा एफ०सी०एन०आर० जमाराशियों की जमानत पर अनिवासियों को मंजूर किये जाने वाले ऋणों की सीमा को 25,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया है।

148. विदेशी मुद्रा के प्राधिकृत डीलरों को यह अनुमति दे दी गई है कि वे भारत में स्थायी रूप से ऐसे विदेशियों को, जिन्होंने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 30 के अन्तर्गत रिजर्व बैंक से अनुमति प्राप्त कर ली हो, उनकी शुद्ध मासिक आय के 50 प्रतिशत तक की राशि के उनके परिवारों के भरण पोषण आदि के लिए आवर्ती प्रेषण की सुविधा दे सकते हैं। 2,500 रु० प्रतिमाह वाली पिछली मैट्रिक सीमा को समाप्त कर दिया गया है।

149. विदेश यात्रा योजना—अब "विदेश यात्रा योजना" के अंतर्गत यात्रा को, निर्यात संवर्धन अथवा व्यापारिक दौरों, हज तथा "पड़ौसी देशों की यात्रा योजना" के अंतर्गत आने वाली यात्राओं को छोड़कर, किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए की जाने वाली विदेश यात्रा के साथ जोड़ा जा सकता है।

150. विदेशी कंपनियों का भारतीयकरण तथा विदेशी ईक्विटी को कम करना—जून 1983 के अन्त में ऐसे मामलों की संख्या 365 थी जिनमें विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 29(2) (ए) के अंतर्गत यह अंतिम निर्णय दिये गये थे कि विनिर्दिष्ट स्तर तक कंपनियों का भारतीयकरण किया जाये अथवा उनकी ईक्विटी में कमी की जाये। इस वर्ष के दौरान 15 और कंपनियों ने निदेशों का अनुपालन कर लिया और इस प्रकार ऐसी कंपनियों की कुल संख्या 332 हो गयी। शेष 33 कंपनियां भी अनुपालन के विभिन्न चरणों में हैं।

151. निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डी०आइ०सी०जी०सी०)—निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम ने गैर औद्योगिक तथा लघु उद्योग क्षेत्रों के लिए अपनी एक जमा बीमा योजना और 4 ऋण गारंटी योजनाओं के अलावा 1 जनवरी 1983 से सहकारी क्षेत्र से संबंधित एक और गारंटी योजना अर्थात् सहकारी क्षेत्र (लघु ऋण सहकारी ऋण समितियां) गारंटी योजना, 1982, प्रारंभ की।

152. जमा बीमा योजना के अंतर्गत बीमाकृत बैंकों की कुल संख्या जून 1982 के 1,661 से बढ़कर जून 1983 के अंत में 1,718 हो गयी। इसमें 83 वाणिज्य बैंक, 140 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और 1,495 सहकारी बैंक शामिल थे। अब इस योजना में 14 राज्यों और 3 संघ-शासित क्षेत्रों के सहकारी बैंकों की जमाराशियां शामिल हैं। 30 जून 1918 को बीमाकृत खातों की संख्या 1,377 लाख थी जिसमें लगभग 35,004 करोड़ रुपये की कुल निर्धारणीय जमाराशियां आती थीं। यह संख्या 30 जून 1982 को बढ़कर 1,598 लाख खाते और लगभग 42,360 करोड़ रुपये हो गयी।

153. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 19 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक लघु ऋण गारंटी योजना 1971 में, तथा और 9 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सेवा सहकारी समितियां गारंटी योजना, 1971 में शामिल हुए। इसके साथ ही इन दो योजनाओं में भाग लेने वाली ऋण संस्थाओं की संख्या बढ़कर क्रमश: 188 (75 वाणिज्य बैंक और 113 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक) तथा 149 (61 वाणिज्य बैंक, 51 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा 37 सहकारी बैंक) हो गयी। वित्त निगम गारंटी योजना 1971 में भाग लेनेवाली संस्थाओं की संख्या 18 ही बनी रहीं। गैर औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित इन तीनों गारंटी योजनाओं के अंतर्गत कुल गारंटीकृत अग्रिमों की राशि जून 1982 के अंत के 4,840 करोड़ रुपये से बढ़कर दिसम्बर 1982 के अंत में 5,025 करोड़ रुपये हो गयी। यह वृद्धि 3.9 प्रतिशत की थी।

154. निगम की लघु ऋण गारंटी योजना 1981 में भाग लेने वाली संस्थाओं की संख्या जून 1983 के अन्त में बढ़कर 339 हो गयी जिसमें 71 वाणिज्य बैंक, 88 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, 15 राज्य वित्त निगम, 5 अन्य राज्य विकास एजेंसियां और 160 सहकारी बैंक शामिल थे। 2 राज्य वित्त निगमों, 1 राज्य विकास एजेंसी और 4 सहकारी बैंकों ने इस योजना में शामिल होने की अपनी इच्छा व्यक्त की लेकिन उन्होंने अभी तक करार का निष्पादन नहीं किया है। 31 दिसम्बर 1982 को लघु उद्योगों की गारंटीकृत अग्रिमों की राशि 4,087 करोड़ रुपये थी।

155. गैर बैंकिंग कंपनियों की जमाराशियां.—वित्तीय कंपनी विभाग द्वारा गैर बैंकिंग कम्पनियों की जमाराशियों के बारे में किये गये सर्वे से यह स्पष्ट होता है कि जमाराशियों में वृद्धि की प्रवृत्ति निरंतर बनी हुई है। मार्च 1982 को समाप्त वर्ष के दौरान कम्पनियों की कुल जमाराशियां 1,304.8 करोड़ रुपये (छूट प्राप्त जमाराशियों सहित) बढ़कर 5,492.8 करोड़ रुपये हो गयी। 5,420 रिपोर्टिंग कम्पनियों में से 2,750 गैर वित्तीय कम्पनियों, 2,129 वित्तीय कम्पनियों और 541 विविध गैर बैंकिंग कम्पनियों (चिट फंड कंपनियां) की बकाया जमाराशियां क्रमश: 3,746 करोड़ रु० (68.2 प्रतिशत) 1,535.9 करोड़ रुपये (28.0 प्रतिशत) और 211.0 करोड़ रु० (3.8 प्रतिशत) थी।

156. करेंसी चेस्ट.—देश में जून 1983 के अंत में कुल 4327 करेंसी चेस्ट थे, जिन में से 593 कोषागार (रिपोजिटरी) थे। इनमें से, रिज़र्व बैंक के पास 5, स्टेट बैंक समूह के पास 3,095 राष्ट्रीयकृत बैंकों के पास 352, सरकारी कोषागारों/उपकोषागारों के पास 268 तथा जम्मू और कश्मीर बैंक लि०, के पास 4 करेंसी चेस्ट थे।

157. सर्वेक्षण/संगोष्ठियां.—वर्ष के दौरान "अखिल भारतीय ऋण और निवेश सर्वेक्षण 1981-82" के लिए आंकड़ों के अभिसंस्करण तथा सांख्यिकीय सारणियों के बनाने के काम में प्रगति हुई। भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुरोध पर यह सर्वेक्षण, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संस्थान द्वारा आयोजित किया गया।

158. "भारत की विदेशी देयताएं और आस्तियां, 1981 और 1982" की गणना शुरू की गयी। इस गणना के लिए मुख्य रूप से विदेशी देयताओं और अस्तियों से संबंधित सूचनाएं एकत्रित की जा रही है; जिसमें शेयर और ऋण पत्र, आयात और निर्यातों से संबंधित आस्थगित ऋण जमाराशियां और अग्रिम जैसी मदें शामिल है।

159. वर्ष 1983-84 के दौरान वाणिज्य बैंकों से सहायता प्राप्त लघु औद्योगिक इकाइयों के संबंध में वैसा ही एक सर्वेक्षण करने का प्रस्ताव है जैसाकि 1977 में रिज़र्व बैंक द्वारा किया गया था।

160. "भारत सरकार द्वारा नियुक्त बचतों विषयक कार्यकारी दल" की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए मार्च 1983 में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में बचत और पूंजी निर्माण की अवधारणाओं, परिभाषाओं, पद्धतियों, आंकड़ों के स्रोतों तथा निर्वचनों और नीति के कार्यान्वयन पर विचार विमर्श किया गया।

161. सी० डी० देशमुख स्मारक व्याख्यान माला.—स्वर्गीय डॉ० सी० डी० देशमुख द्वारा की गयी रिज़र्व बैंक और देश की उल्लेखनीय सेवाओं को मान्यता प्रदान करने तथा उनकी स्मृति को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह निर्णय किया है कि डॉ० सी० डी० देशमुख स्मारक व्याख्यानमाला के अंतर्गत किसी प्रख्यात भारतीय अथवा विदेशी व्यक्ति से आर्थिक विकास, मुद्रा और केन्द्रीय बैंकिंग से संबंधित किसी भी विषय पर साल में एक बार व्याख्यान कराया जाये।

216GI/84—5

बैंक के संगठनात्मक मामले और लेखे

162. संगठनात्मक सुधार रिज़र्व बैंक के कुछ कार्य राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को सौंपे जाने के फलस्वरूप 12 जुलाई 1982 से "ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग" के नाम से एक नया विभाग बनाया गया। शहरी बैंक कक्ष जो अब तक कृषि ऋण विभाग जो अब नाबार्ड का हिस्सा बन चुका है, का हिस्सा था, रिज़र्व बैंक के बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग को अंतरित कर दिया गया है तथा इसका नाम बदल कर शहरी बैंक प्रभाग कर दिया गया। ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग ये कार्य करता है; जिला ऋण आयोजना सहित अग्रणी बैंक योजना, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों को अग्रिम, विशेष कार्यक्रमों और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत कमजोर वर्गों को ऋण, राज्य सहकारी बैंकों मध्यवर्ती सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से संबंधित भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 तथा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की विभिन्न धाराओं का अनुपालन तथा इन बैंकों द्वारा सांविधिक विवरणियों का प्रस्तुतीकरण, राज्य सहकारी बैंकों और उनकी शाखाओं को जमाराशियों तथा अग्रिमों पर ब्याज के संबंध में निदेश जारी करना, नाबार्ड को विशेषज्ञ मार्गदर्शन/सहायता तथा ऋण उपलब्ध करना, समन्वित ग्रामीण विकास के संवर्धन के लिए विशेष अध्ययन करना तथा ग्रामीण विकास के संबंध में रिज़र्व बैंक की नीति निर्धारित करने का काम करता है। शहरी बैंक प्रभाग शहरी बैंकों से संबंधित सभी मामले देखता है जिनमें बैंकों को लाइसेंस देना तथा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम और बैंककारी विनियमन अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों का अनुपालन शामिल है।

163. मशीनीकरण/कम्प्यूटरीकरण.—उत्पादकता तथा ग्राहक सेवा में सुधार की दृष्टि से इस वर्ष के दौरान जमा लेखा विभाग में चालू लेखे रखने तथा बंबई, मद्रास तथा नई दिल्ली के समाशोधनगृहों में समाशोधन तथा तुलन के लिए मशीनीकरण तथा कम्प्यूटरीकरण किया गया। 7 प्रतिशत पूंजी निवेश बांडों के जारी करने और तत्संबंधी सेवाएं उपलब्ध करने तथा बंबई में वेतन रोल के कार्य का भी कम्प्यूटरीकरण कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय लेखा अनुभाग, नागपुर में रिज़र्व बैंक प्रेषण सुविधा योजना के अन्तर्गत सरकारी खाते में प्राप्तियों और भुगतानों के समेकन तथा समाधान के कार्य करने के लिए मिनी-कम्प्यूटर प्रणाली की शुरूआत करने के प्रस्ताव के संबंध में भी प्रगति हुई।

164. बाहरी चैकों का राष्ट्रीय समाशोधन शुरू करने की दिशा में पहल के तौर पर मैकेनिकल चैक विलगन (सौर्टिंग) की सुविधा के लिए चैक लेखन के लिए मेग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकगनीशन का प्रयोग आरंभ करने के संबंध में एक अंतर-संस्थागत दल अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दे रहा है। दल राष्ट्रीय समाशोधन के लिए चैक प्रपत्रों के मानकीकरण, कागज मुद्रण विनिर्देशन तथा संगठनात्मक व्यवस्था से संबंधित विषयों पर भी विचार करेगा।

165. नियोजक-नियोक्ता संबंध.—पिछले वर्ष की रिपोर्ट में उस आंदोलन का उल्लेख किया गया था जो 12 अप्रैल 1982 से "अखिल भारतीय तृतीय श्रेणी कर्मचारी संघ" द्वारा राष्ट्रीय औद्योगिक विवाद न्यायाधिकरण के निर्णय के कुछ उपबंधों के विरुद्ध चलाया जा रहा था। यद्यपि यह आंदोलन वर्ष की समाप्ति से पहले ही विभिन्न कार्यालयों में समाप्त कर दिया गया था लेकिन यह कलकत्ता में जारी रहा; जिसके कारण विभिन्न विभागों में बहुत अधिक काम इकट्ठा हो गया और इसके परिणामस्वरूप सरकारी प्राप्तियों और भुगतान का काम राष्ट्रीयकृत बैंकों को सौंपना आवश्यक हो गया। कलकत्ता का यह आंदोलन, अगस्त 1982 में समाप्त हुआ तथा नोट परीक्षण और सत्यापन अनुभागों के कर्मचारियों ने काम का पुनरीक्षित कोटा निपटाना शुरू किया। मई 1982 में कर्मचारी संघ ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायाधिकरण के

गठन तथा विशेष रूप से प्रबंध कार्यों से समबद्ध कार्यों से संबंधित मदों के बारे में उसके निर्णय को चुनौती दी, जो अभी तक न्यायालय के विचाराधीन है। इस वर्ष के दौरान बैंक ने न्यायाधिकरण के निदेशों की सीमाओं के भीतर चरणबद्ध रूप से मशीनीकरण और कम्प्यूटरीकरण का काम प्रारंभ किया। मशीनीकरण/कम्प्यूटरीकरण और किन क्षेत्रों में किया जा सकता है इसका अध्ययन किया जा रहा है।

166. बैंक के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के मांगपत्र की कुछ अनिर्णीत मांगों पर विचार-विमर्श करने के लिए मार्च 1983 में बैंक तथा अखिल भारतीय रिज़र्व बैंक कर्मचारी संघ' के बीच एक बैठक का आयोजन किया गया। तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की कुछ समस्याओं को हल करने के लिए भी बैंक और अखिल भारतीय रिज़र्व बैंक कर्मचारी संघ के बीच बैठकों का आयोजन किया गया।

167. इस वर्ष के दौरान "रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर्स एसोसिएशन" के साथ संयुक्त परामर्श परिषद् की बैठक के अलावा अधिकारियों के दोनों संघों के साथ वार्षिक समझौता बैठकें भी आयोजित की गयी जिनमें अधिकारियों के हितों को प्रभावित करने वाले विभिन्न मामलों तथा उनको दी जाने वाली सुविधाओं को उदार बनाने के विषय पर विचार-विमर्श किया गया। वर्ष के दौरान अपने अधिकारियों के साथ बैंक के संबंध सौहार्दपूर्ण बने रहे।

168. दिसंबर 1982 में प्रबंधकों और विभागीय प्रमुखों के एक सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें बाहर के विभिन्न कार्यालयों में औद्योगिक संबंधों की स्थिति, मुद्रा प्रबंध की समस्याओं आदि पर विचार-विमर्श किया गया।

169. बैंक की सेवा में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व.—1 जनवरी, 1983 को बैंक में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की कुल संख्या तीनों वर्गों अर्थात चतुर्थ श्रेणी, तृतीय श्रेणी और प्रथम श्रेणी में क्रमशः 1,915 (अनु० जा० 1,547, अनु० जन० जा० 368), 3,128 (अनु० जा० 2,147, अनु० जन० जा० 981) और 305 (अनु० जा० 268, अनु० जन० जा० 37) थी। इनकी तुलना में पहली जनवरी 1982 की स्थिति के अनुसार श्रेणी IV में 2,154 (अनु० जा० 1,747, अनु० जन० जा० 407), श्रेणी III में 3165 (अनु० जा० 2,159, अनु० जन० जा० 1,006) तथा श्रेणी I में 326 (अनु० जा० 284, अनु० जा० जा० 42) कर्मचारी थे। नाबार्ड से तथा नाबार्ड को कर्मचारियों के स्थानांतरण के कारण जनवरी 1983 तक के इन आकड़ों में कुछ परिवर्तन हो सकता है और अंतिम स्थिति 1984 तक सामने आयेगी।

170. कैलेंडर वर्ष, 1982 के दौरान बैंक में विभिन्न श्रेणियों में की गयी सीधी भर्ती तथा कुल भर्ती में अनु० जा०/अनु० जन० जा० के प्रतिनिधित्व का विवरण निम्न प्रकार है :

श्रेणी	उम्मीदवारों की कुल संख्या	भर्ती किये गये कुल उम्मीदवारों में अनु०जा०/अनु० जन० जा० के उम्मीदवारों की संख्या		भर्ती किये गये कुल उम्मीदवारों में अनु० जा०/अनु० जन० जा० के उम्मीदवारों की प्रतिशत	
		अनु० जा०	अनु जन जा०	अनु० जा०	अनु० जन जा०
श्रेणी I (अधिकारी) . .	192	12	3	6.3	1.6
श्रेणी II (लिपिकीय स्टाफ आदि)	1572	215	127	13.7	8.1
श्रेणी III (अधीनस्थ स्टाफ)					
(i) सफाई कर्मचारियों को छोड़कर)	523	132	43	25.2	8.2
(ii) सफाई कर्मचारी	24	16	5	66.7	20.9

171. पिछले वर्ष की रिपोर्ट में स्टाफ अधिकारी ग्रेड "बी" के पद के लिए लिखित परीक्षा में अनु० जन० जा० के उम्मीदवारों द्वारा स्तरीय उत्तर न दिये जाने के संबंध में जिस अध्ययन का उल्लेख किया गया था, उसे भारतीय शिक्षण संस्थान, पुणे को सौंपा गया था। उक्त संस्थान द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की जांच की जा रही है। भारतीय रिज़र्व बैंक सर्विसेज़ बोर्ड ने स्टाफ अधिकारी ग्रेड "ए" पदों पर नियुक्ति के लिए केवल अनु० जाति/अनु० जन० जा० के उम्मीदवारों से ही आवेदन आमंत्रित करते हुए विशेष विज्ञापन जारी किये हैं ताकि उनके संबंध में बकाया पिछले रिक्त स्थानों की अधिक से अधिक पूर्ति की जा सके। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए स्टाफ अधिकारी ग्रेड "ए" (सीधी भर्ती) हेतु आवेदन के लिए अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के वास्ते निर्धारित 31 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा को और बढ़ाकर अब 34 वर्ष कर दिया गया है।

172. वर्ष के दौरान अनु०जा० और अनु० जन० जा० विषयक संपर्क अधिकारी के एक प्रतिनिधि ने बैंक के पटना और कानपुर कार्यालयों तथा बम्बई में निर्गम विभाग द्वारा रखे जा रहे रोस्टरों का निरीक्षण किया। इन केन्द्रों पर पदोन्नति में आरक्षण हेतु रिज़र्व बैंक की योजना के कार्यान्वयन में जो अनियमितताएं पायी गयीं उनमें से कुछ को सुधारा जा चुका है, तथा अन्य अनियमितताओं को दूर किया जा रहा है।

173. बैंक की सेवा में भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार.—अब यह निर्णय लिया गया है कि अब तक श्रेणी III में सभी अन्य पदों पर भूतपूर्व सैनिकों को दिये जाने वाले आरक्षण को वर्ष 1983 से लिपिक ग्रेड II, सिक्का नोट परीक्षक ग्रेड II के लिए भी उपलब्ध कराया जाये। कैलेंडर वर्ष 1982 के दौरान श्रेणी III (लिपिकों के सामान्य वर्ग को छोड़ कर) तथा श्रेणी IV में भरे गये क्रमशः 251 तथा 634 पदों में से क्रमशः 11 और 75 पदों पर भूतपूर्व सैनिकों की भर्ती की गयी, जबकि निर्धारित दरों अर्थात् श्रेणी III के लिए 14-1/2 प्रतिशत तथा श्रेणी IV के लिए 24-1/2 प्रतिशत के अनुसार क्रमशः 37 और 155 पद उनके लिए आरक्षित थे। भूतपूर्व सैनिकों में से उचित उम्मीदवार उपलब्ध न होने के कारण कुल भर्ती में भूतपूर्व सैनिकों का प्रतिशत श्रेणी III तथा श्रेणी IV में क्रमशः 4.4 तथा 11.8 रहा।

174. हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा.—हिन्दी के प्रयोग से संबंधित वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बैंक ने अपने कार्यालयों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के वास्ते कई उपाय किये।

175. क्षेत्र "क" (हिन्दी भाषी प्रदेश) तथा क्षेत्र "ख" (महाराष्ट्र गुजरात और पंजाब) में स्थित बैंक के विभिन्न कार्यालयों को 1982 के लिए वार्षिक समयबद्ध कार्यक्रम भेजा गया। इस कार्यक्रम के अनुसार यह आवश्यक है कि उक्त कार्यालय अपने कुल पत्राचार में हिन्दी के पत्राचार के प्रतिशत को क्रमशः 66-2/3 तथा 30 तक बढ़ाएं। इसके अलावा इन कार्यालयों से यह भी कहा गया कि वे अपने सभी श्रेणी के कर्मचारियों तथा जनता से संबंधित परिपत्र, आदेश आदि हिन्दी में जारी करें। उक्त आवश्यकताओं का पूर्णतः अनुपालन करने के लिए बैंक के सभी अधिकारियों को जांच-सूची और जांच-बिन्दुओं की प्रतियां भी उपलब्ध करायी गयी हैं।

176. बैंक तथा उससे संबंद्ध संस्थाओं की विविध रिपोर्टों का हिन्दी में प्रकाशन जारी रहा। इनके अलावा निम्नलिखित छः प्रकाशन भी इस वर्ष के दौरान हिन्दी में जारी किये गये। बैंकिंग शब्दावली (हिन्दी-अंग्रेजी), बैंकिंग शब्दावली (अंग्रेजी-हिन्दी), संशोधित संस्करण, उच्च-स्तरीय बैंकिंग उन्मुख हिन्दी पाठ्यक्रम, हिन्दी के प्रयोग के लिए जांच सूची, हिन्दी के प्रयोग लिए जांच-बिन्दु और भारतीय अर्थव्यवस्था मूल सांख्यिकी (फोल्डर)।

177. बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय, बंबई.—बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय ने केन्द्रीय, वाणिज्य और विकास बैंकिंग के क्षेत्र में सामान्य कार्यक्रम, ऋण-क्षेत्र में विशेष/प्रयोजनमूलक कार्यक्रम तथा कार्मिक प्रबंध, औद्योगिक

संबंध और संगठन तथा पद्धति से संबंधित क्षेत्रों के लिए विशेष प्रबंधकीय कार्यक्रमों आदि का आयोजन करना जारी रखा। इसके अलावा निष्पादन बजटिंग, बैंकरों के लिए सांख्यिकी, बैंकिंग के विधिक पहलू, व्यापार बैंकिंग, संकाय विकास, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आदि विषयों पर भी कार्यक्रम आयोजित किये गये।

178. आलोच्य अवधि के दौरान बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय ने नौ नये कार्यक्रम शुरू किये। अन्य बैंकों के अनुरोध पर महाविद्यालय ने अपने संकाय सदस्यों को उनके महाविद्यालयों में सत्रों का संचालन करने के लिए भी प्रतिनियुक्त किया।

179. यह महाविद्यालय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अलावा विशेष अध्ययनों का आयोजन तथा पुस्तकों आदि का प्रकाशन भी करता है। इस वर्ष के दौरान इस महाविद्यालय ने निम्नलिखित पांच प्रकाशन जारी किये :—

बैं० प्र० म०—बुलेटिन, वाणिज्य बैंकों में निष्पादन बजट बनाना, अनुशासनात्मक कार्रवाई पर गाइड, उत्पादकता पर आयोजित सेमिनार का कार्य विवरण और तम्बाकू पर आयोजित सेमिनार का कार्य विवरण।

180. उक्त अवधि के दौरान कुल 78 कार्यक्रमों का आयोजन किया; जिनमें 44 विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम शामिल थे। इनमें से 14 कार्यक्रम अंतर-कंपनी कार्यक्रम थे जो प्रायोजक संस्थाओं (जिनमें से अधिकांश सार्वजनिक क्षेत्र के छोटे बैंक और निजी क्षेत्र के बैंक थे) की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप बनाये गये थे। इन 14 में से 13 कार्यक्रम प्रायोजक संस्थाओं के स्वयं के केन्द्रों पर चलाये गये।

181. उक्त अवधि में महाविद्यालय में भारतीय रिजर्व बैंक, वाणिज्य बैंकों, विकास वित्त संस्थाओं, सरकार और विदेशी बैंकों के 2,440 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया। इस प्रकार 1954 में महाविद्यालय की स्थापना से लेकर अब तक प्रशिक्षित अधिकारियों की कुल संख्या बढ़कर 23,957 हो गयी है।

182. कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, पुणे.—कृषि वित्त और उससे संबंधित विषयों पर सामान्य और विशिष्ट कार्यक्रम करने के अलावा कृषि बैंकिंग महाविद्यालय ने निम्न आय वर्ग वाले व्यक्तियों को उपलब्ध की जानेवाली सेवाओं में सुधार की दृष्टि से ग्रामीण ऋण संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय स्तर की एक प्रशिक्षण कार्यशाला का भी आयोजन किया। यह कार्यशाला खाद्य और कृषि संगठन द्वारा गठित समन्वित ग्रामीण विकास विषयक अंतर-एजेन्सी समिति तथा संयुक्त राष्ट्र-संघ की अन्य संस्थाओं के सहयोग से चलायी गयी।

183. महाविद्यालय ने नवंबर 1982 में "कमजोर वर्गों को ऋण सहायता" पर एक सेमिनार का आयोजन किया। यह सेमिनार केन्द्रीय गृह मंत्रालय के कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा प्रायोजित की गयी थी। इस सेमिनार में वाणिज्य बैंकों, ग्रामीण बैंकों तथा राज्य सरकारों आदि के वरिष्ठ कार्यपालक अधिकारियों ने भाग लिया।

184. महाविद्यालय ने राष्ट्रमण्डल (कामनवेल्थ) सचिवालय, लंदन के सहयोग से लघु कृषक पशुधन, परियोजना तैयार करने के बारे में भी एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया।

185. भारत, बंगलादेश, श्रीलंका और नेपाल के बीच "कृषि बैंकिंग में प्रशिक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग केन्द्र" की स्थापना के बारे में अन्तर सरकार परामर्श के बाद यह निर्णय किया गया कि बैंकिंग में प्रशिक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग केन्द्र की ओर से वर्ष 1983 में यह महाविद्यालय "परियोजना-वित्त" और "उत्पादन वित्त" पर दो कार्यक्रमों का आयोजन करे। महाविद्यालय ने सेंट्रल बैंक ऑफ सीलोन के श्रीलंका स्थित ग्रामीण बैंकिंग और कर्मचारी प्रशिक्षण महाविद्यालय में ग्रामीण बैंकिंग विंग की स्थापना के लिए किया गया परामर्श-अनुबंध भी पूरा कर लिया है।

186. आलोच्य वर्ष के दौरान महाविद्यालय ने 83 नियमित कार्यक्रमों के अलावा 2 विशेष कार्यक्रम और सरकार द्वारा प्रायोजित एक सेमिनार का आयोजन किया जिनमें भारत तथा विदेश की विविध बैंकिंग संस्थाओं तथा सरकार के 1,872 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया। इस प्रकार सितंबर 1969 में महाविद्यालय की स्थापना से लेकर अब तक प्रशिक्षित अधिकारियों की कुल संख्या बढ़कर 19,170 हो गयी है।

187. रिजर्व बैंक स्टॉफ महाविद्यालय, मद्रास.—रिजर्व बैंक स्टॉफ महाविद्यालय बैंक के विभिन्न विभागों में कार्यरत ग्रेड "ए" से ग्रेड "सी" तक के स्टाफ अधिकारियों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पूर्ति करता रहा। आलोच्य वर्ष के दौरान महाविद्यालय ने 57 कार्यक्रमों का आयोजन किया जिनमें 1,332 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया। 1963 में महाविद्यालय की स्थापना से लेकर अब तक प्रशिक्षित अधिकारियों की कुल संख्या 12,151 हो गयी है।

188. सामान्य रूप से चलाये जाने वाले व्यापक तथा अन्य प्रयोजनमूलक कार्यक्रमों के अलावा "निजी सचिव ग्रेड ए" के लिये मार्गदर्शी कार्यक्रम तथा स्टाफ अधिकारी ग्रेड "बी" (सीधी भर्ती) के लिए "व्यवहार विज्ञान" पर कार्यक्रम आयोजित किये गये।

189. सहायक कोषपालों के लिए एक कार्यक्रम पूर्णतः हिन्दी माध्यम से तथा ऋणमूल्यांकन पर एक संशोधित कार्यक्रम भी चलाये गये, जिसमें कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं तथा मीयादी वित्त से संबंधित नवीनतम तकनीकों को शामिल किया गया।

190. अन्तर कंपनी प्रशिक्षण कार्यक्रम—बैंक में ग्रेड "ई" और "एफ" में कार्यरत प्रबंधकों तथा संभावित प्रबंधकों में अवधारणात्मक तथा प्रबंधकीय दक्षता बढ़ाने की दृष्टि से, फरवरी 1983 में नयी दिल्ली में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। मैनेजमेंट डेवलपमेंट इन्स्टिट्यूट नयी दिल्ली के सहयोग से "समय प्रबंध" पर भी दो दिन का एक अंतर-कंपनी कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कुछ तकनीकें अपनाकर समय के अधिक सफल उपयोग के वास्ते कुछ ठोस सुझाव देने के अलावा "समय प्रबंध" के विविध पहलुओं पर जानकारी उपलब्ध कराना था। फरवरी 1983 में एक "कम्प्यूटर परिबोधन सेमिनार" का आयोजन किया गया, जिसमें बैंक के अधिकारियों को यह बताया गया कि एक बड़ी संस्था में आधुनिक कम्प्यूटर प्रणाली का उपयोग और उसकी क्षमताएं क्या हैं।

191. आंचलिक प्रशिक्षण केन्द्र—बैंक द्वारा भायखला (बंबई), कलकत्ता, मद्रास और नयी दिल्ली के आंचलिक प्रशिक्षण केन्द्रों में बैंक के लिपिकीय वर्ग के कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। आंचलिक प्रशिक्षण केन्द्रों ने लिपिकीय कर्मचारियों, लिपिक ग्रेड II तथा टेलर सिक्का नोट परीक्षण ग्रेड I के लिए क्रमशः विशेष पाठ्यक्रमों, प्रारंभिक पाठ्यक्रमों तथा विशेष कार्यक्रमों का आयोजन करना जारी रखा। वर्ष के दौरान आंचलिक प्रशिक्षण केन्द्रों में 2,218 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया और इस प्रकार आंचलिक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना से लेकर अब तक प्रशिक्षण पानेवाले इस प्रकार के स्टाफ की कुल संख्या बढ़कर 24,884 हो गयी।

192. प्रशिक्षण के लिए कर्मचारियों की देश और विदेश में प्रतिनियुक्ति—बैंक ने अपने अधिकारियों को देश विदेश की प्रतिष्ठित संस्थाओं आदि द्वारा आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सेमिनारों और सम्मेलनों में भाग लेने के लिए प्रतिनियुक्त करना जारी रखा।

193. इस वर्ष के दौरान बैंक ने भारत स्थित संस्थाओं द्वारा प्रबंध तथा उससे संबंधित विषयों तथा वाणिज्य बैंकिंग, प्रशासन, विदेशी मुद्रा नियंत्रण आदि विषयों पर आयोजित किये गये विविध कार्यक्रमों में अपने 174 अधिकारियों को नामित किया।

194. बैंक ने अपने 22 अधिकारियों को पश्चिम जर्मनी, अमरीका, जापान, फिलिपाइन्स, इंडोनेशिया, मलयेशिया, थाइलैंड आदि देशों की बैंकिंग और वित्तीय संस्थाओं में अध्ययन के लिए भेजा।

195. विदेशी बैंकों के अधिकारियों को उपलब्ध करायी गयी प्रशिक्षण सुविधाएं—बैंक ने विदेशी केन्द्रीय और वाणिज्यिक बैंकों से प्राप्त विशेष अनुरोधों के अनुसरण में अनके अधिकारियों को प्रशिक्षण और अध्ययन सुविधाएं देना जारी रखा। इनमें एशियाई और पैसिफिक क्षेत्रीय कृषि ऋण संघ (ए पी आर ए सी ए) स्टाफ एक्सचेंज प्रोग्राम, कॉमनवेल्थ फन्ड टेक्निकल को-ओपरेशन लंदन, कोलम्बो प्लान की तकनीकी सहयोग योजना, युनाइटेड नेशन्स् डेवलपमेन्ट प्रोग्राम आदि जैसी अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता की योजनाओं के अंतर्गत प्रायोजित कार्यक्रम भी शामिल थे। जिन 76 प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण सुविधायें प्रदान की गयी उनमें से, 27 श्रीलंका से, 17 नेपाल से, 9 सूडान से तथा 6 तंजानिया तथा केन्या तथा सिंगापुर से दो-दो थे। इनके अतिरिक्त थाइलैण्ड, इंडोनेशिया, मॉरीशस, घाना, भूटान आदि से भी प्रशिक्षणार्थी आये थे।

196. राष्ट्रीय बैंक प्रबंध संस्थान—राष्ट्रीय बैंक प्रबंध संस्थान ने 19 प्रशिक्षण कार्यक्रम/सेमीनार/सम्मेलन/कार्यशालायें आयोजित कीं जिनमें लगभग 800 व्यक्तियों ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त बैंकों में लागत तथा लाभप्रदता, भारतीय वाणिज्यिक बैंकों के घरेलू कारोबार में लाभ तथा लाभप्रदता की प्रवृत्तियां, विदेशी मुद्रा प्रकटन का जोखिम प्रबंध, विभेदक ब्याज दर योजना के प्रभाव का अध्ययन, बैंकरहित क्षेत्रों का विकास और बैंकिंग की भूमिका और समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अध्ययन पर, अनुसंधान परियोजनाएं पूरी की गयी। इस समय जो योजनाएं हाथ में हैं, वे इस प्रकार हैं: कार्यकारी पूंजी प्रबंध (साइकिल उद्योग तथा ऑटोमोबाईल उद्योग के विशेष संदर्भ में) महानगरीय शाखाओं में हाउस कीपिंग समस्याएं, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निष्पादन का मूल्यांकन तथा औद्योगिक ऋण प्रस्तावों की प्रोसेसिंग तथा मंजूरी का अध्ययन।

197. प्रेस संपर्क—प्रेस संपर्क प्रभाग ने रिज़र्व बैंक तथा जनता के बीच रिज़र्व बैंक तथा निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम के विभिन्न विभागों के कार्यों के बारे में जानकारी जारी करते हुए, प्रभावशाली संप्रेषण बनाये रखने का काम जारी रखा।

198. इस प्रभाग ने समस्त भारत से आमंत्रित आर्थिक संपादकों का सम्मेलन आयोजित किया ताकि उनके तथा बैंक के गवर्नर और अन्य वरिष्ठ कार्यपालकों के बीच विचारों के अनौपचारिक आदान प्रदान के जरिये, बैंक की नीतियों को बेहतर तरीके से समझने के लिए वातावरण तैयार किया जा सके।

199. इस प्रभाग ने अनिवासी भारतीयों के लिए उपलब्ध विभिन्न निवेश सुविधाओं पर वर्तमान नीतियों और कार्यविधियों के बारे में सूचना देते हुए पुस्तिका प्रकाशित की। इस प्रभाग ने (i) समाशोधन गृह के लिए मिनी कम्प्यूटर प्रणाली (तथ्य और आंकड़े) तथा (ii) निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम में कम्प्यूटरीकरण पर भी फोल्डर प्रकाशित किये हैं।

200. परिसर—चंडीगढ़ में कार्यालय भवन के निर्माण का पहला चरण पूरा हो गया है। जयपुर में कार्यालय भवन का निर्माण कार्य चल रहा है। नागपुर में अतिरिक्त भवन पर कार्य शुरू कर दिया गया है।

201. आवासीय क्वार्टर—वर्ष के दौरान 306 फ्लैट जिनमें अहमदाबाद में अधिकारियों के लिए 64 फ्लैट (4 स्वयंपूर्ण सिंगल कमरों सहित), भोपाल में अधिकारियों के लिए 110 (8 स्वयंपूर्ण सिंगल कमरों सहित), और श्रेणी III और IV के लिए 112 फ्लैट, नयी दिल्ली में अधिकारियों के लिए 90 फ्लैट तथा 10 स्वयंपूर्ण सिंगल कमरे तथा त्रिवेन्द्रम में श्रेणी IV के लिए 56 फ्लैट शामिल हैं, लगभग पूरे कर लिये गये हैं तथा कब्जा लेने के लिए जल्द ही तैयार हो जायेंगे।

202. 821 फ्लैटों का निर्माण कार्य चल रहा है। इन में अहमदाबाद में श्रेणी III और IV के स्टाफ के लिये 370 फ्लैट, कलकत्ता में अधिकारियों के लिए 92 फ्लैट (और 10 स्वयंपूर्ण सिंगल कमरे सहित) गौहाटी में श्रेणी IV के लिए 196 फ्लैट और श्रेणी IV स्टाफ के लिए 78 फ्लैट एवं कानपुर में अधिकारियों के लिए 85 फ्लैट (6 स्वयंपूर्ण सिंगल कमरे सहित) शामिल हैं।

203. अधिकारियों के लिए 310 फ्लैटों, नयपल्ली, भुवनेश्वर में 100 फ्लैट (8 सिंगल स्वयंपूर्ण कमरों सहित), कल्लूर-कोचीन में 28 फ्लैट, राजेन्द्र नगर-पटना में 4 फ्लैट, अमीर पेठ हैदराबाद में 178 फ्लैट (तथा श्रेणी III और IV के लिए 308 फ्लैटों), कल्लूर-कोचीन में 84 क्वार्टर, दिघा-पटना में 224 क्वार्टर का निर्माण कार्य शीघ्र ही शुरु किये जाने की संभावना है।

204. अंधेरी-बंबई में बैंक के चकाला ऑफिसर्स क्वार्टर्स में अधिकारियों के लिए 36 स्वयंपूर्ण सिंगल कमरे और 4 छोटे फ्लैटों वाले "जी" ब्लॉक का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। मालाड-बंबई में श्रेणी IV स्टॉफ के लिए 120 फ्लैटोंवाली 6 इमारतों वाली आवासीय परियोजना का पहला चरण लगभग पूरा होने वाला है। कनिंघम क्रेसेंट बंगलूर में अधिकारियों के लिए 56 फ्लैटों और शालीमार बाग-नयी दिल्ली में श्रेणी III और IV के स्टाफ के लिए 315 फ्लैटों का निर्माण कार्य भी लगभग पूरा होने वाला है। 547 फ्लैटों जयपुर में अधिकारियों के लिए 108 फ्लैट, (6 सिंगल स्वयंपूर्ण कमरों सहित), पुणे में 41 फ्लैट (अधिकारियों के लिए 17, श्रेणी III स्टाफ के लिए 24 फ्लैट) तथा हैदराबाद में अधिकारियों के लिए 14 फ्लैटों और श्रेणी III स्टाफ के लिए 384 फ्लैटों का निर्माण कार्य चल रहा है।

205. एक मुश्त आधार पर अथवा टर्नकी आधार पर फ्लैटों की खरीद—समीक्षाधीन वर्ष के दौरान एक मुश्त आधार पर 401 फ्लैटों (बेगमपेट, हैदराबाद में श्रेणी III स्टाफ के लिए 384 फ्लैटों तथा गणेशखिंड रोड (पुणे) में अधिकारियों के लिए 9 फ्लैट) तथा कोथरूड़, पुणे में अधिकारियों के लिए चार फ्लैटों की खरीद के लिए तीन करार निष्पादित किये गये।

206. जमीन की खरीद—बंबई में बैंक में बांदरा-कुर्ला कम्प्लेक्स में तथा शिवडी में आवासीय क्वार्टरों के निर्माण के लिए प्लॉट प्राप्त किये। जयपुर में बैंक के स्टाफ के लिए रिहायसी आवास निर्माण के वास्ते 8 एकड़ जमीन खरीदी गयी है।

207. आवासीय ऋण योजना—पहली जुलाई 1982 से 30 जून 1983 तक की अवधि के दौरान नीचे लिखे अनुसार आवासीय ऋण मंजूर किये गये थे—

(क) सहकारी आवासीय समिति	समितियों की संख्या	राशि
		रु०
नयी सहकारी समितियां	9	52,94,822
पहले से गठित सहकारी समितियों को अतिरिक्त ऋण	15	15,73,903
		56,67,833

(ख) ऋण: अलग अलग कर्मचारी	कर्मचारियों की संख्या	राशि
		रुपये
नये ऋण	396	2,06,27,527
पहले ऋण ले चुके कर्मचारियों को अतिरिक्त ऋण	280	64,11,220
		2,70,38,728

1961 में योजना के शुरू होने से लेकर अब तक मंजूर किये गये समिति एवं अलग-अलग ऋणों के जोड़ क्रमशः रु० 13,41,66 620.00 तथा रु० 17 13,81,207.00 बैठते हैं।

208. कुल मिलाकर अब तक 7,608 कर्मचारी इस योजना का लाभ उठा चुके हैं।

209. केन्द्रीय बोर्ड डा० आई जी पटेल 15 सितम्बर को कारोबार की समाप्ति पर बैंक के गवर्नर के पद सेवानिवृत्त हुए। डा० मनमोहन सिंह ने 16 सितम्बर 1982 को गवर्नर के रूप में कार्यभार संभाला। बोर्ड डा० आई०जी०पटेल द्वारा की गयी मूल्यवान सेवाओं की भूरि-भूरि सराहना करता है।

210. सर्वश्री ए. एन हक्सर अकबर हैदरी, जहांगीर सी पटेल शं० ल० किर्लोस्कर तथा एम पी जित्तल और डा० भरत राम डा० कुरियन डा० बी वेंकटप्पय्या तथा डा० डी पी सिंह अपनी नियुक्ति की अवधि की समाप्ति पर केन्द्रीय बोर्ड के निदेशकों के रूप में 18 मार्च को सेवानिवृत्त हुए और उनके स्थान पर उसी तारीख से सर्वश्री जवाहरलाल सेन गुप्ता, अशोक कुमार जैन, आर पी. गोएंका, रघुराज, आदित्य वी बिरला, आर गणेशन तथा पी एन देवराजन एवं डा० एस आर सेन तथा डा ए एस कहलोन नियुक्त किये गये। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 8 (1) (घ) के अंतर्गत नामित निदेशक श्री रा० ना० मल्होत्रा ने 12 अक्तूबर 1982 को त्याग पत्र दिया और उनके स्थान पर श्री एम नरसिंहम नियुक्त किये गये। फिर श्री नरसिंहम द्वारा पहली जुलाई 1983 को पद त्यागने पर श्री पी के कौल उनके स्थान पर 11 जुलाई 1983 को नियुक्त किये गये। बोर्ड सेवानिवृत्त निदेशकों की सेवाओं की सराहना करता है।

211. श्री मा० रामकृष्णय्या ने 31 जुलाई 1983 को बैंक के उपगवर्नर का पद त्याग दिया। बोर्ड उनके द्वारा की गयी बैंक की सेवाओं की भूरि-भूरि सराहना करता है।

212. स्थानीय बोर्ड श्री ए० एन० हक्सर, जो 18 मार्च 1983 को केन्द्रीय बोर्ड के निदेशक पद से सेवानिवृत्त हुए, पूर्वी क्षेत्र के स्थानीय बोर्ड के सदस्य नहीं रहे और उनका स्थान उसी तारीख से श्री जवाहर लाल सेन गुप्ता द्वारा भर गया। 18 मार्च 1983 को उत्तरी क्षेत्र के बोर्ड से सदस्य के रूप में डा० भरत राम की सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप उसी तारीख से उनका स्थान डा० एस० आर० सेन ने ले लिया।

213. वर्ष के दौरान केन्द्रीय बोर्ड की छः बैठकें हुईं। इसमें से दो बंबई में तथा एक-एक मद्रास, कलकत्ता, जयपुर तथा नई दिल्ली में हुई।

214. सर्वश्री आर० मित्रा तथा वा० श्री ताम्बे ने क्रमशः 24 जुलाई 1982 और 10 दिसम्बर 82 से कार्यपालक निदेशकों के पद त्याग दिये। श्री बी० एन० श्रीवास्तव 24 जुलाई 1982 से कार्यपालक निदेशक नियुक्त किये गये थे तथा 11 दिसम्बर से सर्वश्री वि०ब० कदम तथा टी एम० ए० अय्यर कार्यपालक निदेशक नियुक्त किये गये।

215. कार्यालयों का खोला जाना तथा बंद किया जाना ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग के इंदौर क्षेत्रीय कार्यालय तथा शहरी बैंक प्रभाग 23 अप्रैल 1983 से बंद कर दिये गये थे और उन्होंने 2 मई 1983 से भोपाल में कार्य करना शुरू कर दिया।

216. लेखा 30 जून 1983 को समाप्त हुए लेखा वर्ष के दौरान विभिन्न व्यवस्थाओं के लिए समायोजना करने के बाद बैंक को 1,040.42 करोड़ रुपयों की आय हुई जबकि पिछले वर्ष उसे 956.76 करोड़ रुपयों की आय हुई थी। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आय का विवरण आगे दिया गया है।

217. राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घकालीन प्रचलन) निधि राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण स्थिकरण निधि* तथा राष्ट्रीय औद्योगिकरण (दीर्घ कालीन) प्रचलन निधि में वर्ष 1982-83 के दौरान क्रमशः 225 करोड़ रुपयों, 75 करोड़ रुपये और 315 करोड़ रुपये का अंशदान किया गया। ऋण (दीर्घविधि प्रचलन) निधि की राशियां 1981-82 के दौरान क्रमशः 180 करोड़ रुपये, 75 करोड़ रुपये तथा 290 करोड़ रुपये रहीं। पिछले वर्ष में क्रमशः 180 करोड़ रुपये, 75 करोड़ रुपये तथा 290 करोड़ रुपये थीं।

*पहले ये निधियां राष्ट्रीय कृषि निधियां कहलाती थीं।

218. इस वर्ष किये गये 215.42 करोड़ रुपये के कुल व्यय को 426.76 करोड़ की शेष में से निकालने के बाद (पिछले वर्ष की शेष आय 411.76 करोड़ रुपये थी और व्यय की राशि 201.67 करोड़ रुपये थी)। केन्द्रीय सरकार को अदा करने के लिए अलग रखे गये लाभ की अधिशेष राशि 210 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष के बराबर ही) बनाये रखी गयी।

(राशि करोड़ रुपयों में)

	वर्ष	
	1982-83	1981-82
1. राज्य सरकारों के अर्थोपाय अग्रिमों पर ब्याज	26.07	666.01
2. राज्य सरकारों को (ऊपर मद (1) में उल्लिखित अर्थोपाय अग्रिमों को छोड़कर तथा वाणिज्य तथा सहकारी बैंकों को दिये गये ऋणों एवं अग्रिमों पर ब्याज	128.83	95.74
3. रुपयों प्रतिभूतियों पर ब्याज और खजाना बिलों पर बट्टा	626.06	381.51
4. विदेशी प्रतिभूतियों, निवेशों तथा खजाना बिलों पर, ब्याज तथा बट्टा	520.58	598.48
5. कमीशन तथा विनिमय	40.73	42.54
6. अन्य आय	40.73	42.54
	1.34	1.14
	1343.61	1185.42
घटायें : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को उनके द्वारा रिजर्व बैंक के पास रखी गयी अतिरिक्त औसत शेष राशियों पर चुकाया गया ब्याज	303.19	228.66
	1040.42	956.76
घटायें : पैरा 217 में उल्लिखित के अनुसार निधियों को अंतरित	615.00	545.00
	425.42	411.76

219. पिछले वर्ष की 956.76 करोड़ रुपये की कुल आय में इस वर्ष 83.66 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई और यह बढ़कर 1,040.42 करोड़ रुपये हो गयी। इस वृद्धि का मुख्य कारण रुपया तथा विदेशी प्रतिभूतियों में निवेश पर अर्जित उच्चतर ब्याज था, जो अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से अर्जित उच्चतर पैमल बकाया ब्याज जो अंशतः विदेशी मुद्रा आस्तियों से आय में कमी तथा अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को उनकी अतिरिक्त नकदी प्रारक्षती निधियों पर अदा किये गये अधिक ब्याज के कारण निष्प्रभावी हो गया था। व्यय में 13.66 करोड़ रुपये की वृद्धि मुख्यतः सरकारी लेनदेन निपटाने के लिए एजेंसी बैंकों को दिये गए कुल कमीशन की राशि में वृद्धि के कारण थी।

220. लेखा परीक्षक मेसर्स बाटलीबॉय एण्ड पुरोहित, बंबई, मेसर्स लखलोक एण्ड लेधिस, कलकत्ता, मेसर्स डी० रंगास्वामी एण्ड कं०, मद्रास तथा मेसर्स के० सी० खन्ना कं०, नई दिल्ली द्वारा बैंक के लेखों की परीक्षा की गयी। इनमें से पहले तीन को भारत सरकार ने पुनर्नियुक्त किया था, जबकि चौथे क्रम पर उल्लिखित फर्म को सरकार की 8 अप्रैल 1983 की अधिसूचना सं० 1 (4)-83-एकाउंटस द्वारा मेसर्स पी० के० चोपड़ा एण्ड कं० के स्थान पर पहली बार नियुक्त किया गया है। इस वर्ष बैंक के सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा केन्द्रीय कार्यालय, कलकत्ता, मद्रास, नयी दिल्ली और नागपुर स्थित कार्यालयों के अलावा जयपुर और गोहाटी (पिछले वर्ष अहमदाबाद तथा हैदराबाद कार्यालय) की लेखा बहियों की भी परीक्षा की गयी है। लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक प्रत्येक कार्यालय के लिए रु० 15,000 निश्चित किया गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक

30 जून 1983 तक का तुलन-पत्र

निर्गम (इशू) विभाग

देयताएं	रु०	पै०	रु०	पै०	आस्तियां	रु०	पै०	रु०	पै०
बैंकिंग विभाग में रखे हुए नोट	23 78,09,256.00				सोने का सिक्का और बुलियन (क) भारत में रखा हुआ	225,58,28,275.87			
					(ख) भारत के बाहर रखा हुआ	—			
संचलन में नोट	18383,22,09,928.50				विदेशी प्रतिभूतियां	1564,05,75,253.50			
					जोड़			1789,64,03,529.37	
जारी किये गये कुल नोट			18407,00,19,184.50		रुपये का सिक्का			17,52,34,596.57	
					भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियां				
					देशी विनिमय बिल और दूसरे वाणिज्य पत्र			16599,83,81,058.56	
कुल देयताएं			18407,00,19,184.50		कुल आस्तियां			18407,00,19 184.50	

भारतीय रिजर्व बैंक

30 जून 1983 का तुलन-पत्र

बैंकिंग विभाग

देयताएं	रुपये	पैसे	आस्तियां	रुपये	पैसे
प्रदत्त पूंजी	5,00,00,000.00		नोट	23,78,09,256.00	
प्रारक्षित निधि	150,00,00,000.00		रुपया सिक्के	3,65,669.00	
राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि	2230,00,00 000.00		छोटे सिक्के	5,91 155.10	
			खरीदे तथा भुनाये गये बिल:		
जमाराशियां :			(क) आभ्यंतरिक	—	
(क) सरकार			(ख) बाह्य	—	
(i) केन्द्रीय सरकार	553,40,89,627.05		(ग) सरकारी खजाना बिल	7041,89,22,878.10	
(ii) राज्य सरकारें	199,64,91,588.21		विदेशों में रखे गये बकाया शेष	2760,67,12,211.97	
			निवेश*	2989,23,76,625.17	
(ख) बैंक			निम्नलिखित को दिये गये ऋण तथा अग्रिम :		
(i) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	6623,69,58,507.04		(i) केन्द्रीय सरकार	—	
(ii) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	140.85.24,067.51		(ii) राज्य सरकारें@	213,19.00,000.00	
(iii) गैर अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	4,77,83,457.62		निम्नलिखित को दिये गये ऋण तथा अग्रिम		
(iv) अन्य बैंक	15,06.54,857.42		(i) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	544,83,52,047.14	
			(ii) राज्य सहकारी बैंक	51,05,64,500.00	
(ग) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की जमाराशियां :			(iii) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	904,10,40,000.00	
			(iv) अन्य	11,75,59,586.40	
(i) राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि	349,58,65,242.03				
(ii) राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि	281,28,55,673.58				
			राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि से ऋण अग्रिम तथा निवेश :		
(घ) अन्य	4857,21 51,997.27		(क) निम्नलिखित को दिये गये ऋण तथा अग्रिम :		
देय बिल	96,09,58,888.52		(i) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	1827,73,98,575.00	
अन्य देयताएं £	3483,55 45,032.61		(ii) भारतीय निर्यात आयात बैंक	70,00,00,000.00	
			(ख) निम्नलिखित द्वारा जारी किये गये बांडों/डिबेंचरों में निवेश:		
			(i) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक		
			(ii) भारतीय निर्यात-आयात बैंक		
			अन्य आस्तियां†	2551,82,86,435.38	
कुल देयताएं	18990,18,78,938.86		कुल आस्तियां	18990,18,78,938.86	

आकस्मिकता देयता : अंशत : चुकता शेयरों पर 50,000 पौंड के बराबर 7,72,499.03 रुपये ।

£इसमें आकस्मिकता लेखा शामिल है ।

* विदेशों में विदेशी मुद्राओं में रखे हुए 480,45,16,934.37 रुपये शामिल हैं ।

@ अर्थोपाय अग्रिम शामिल हैं ।

† विशेष व्यवस्था के अधीन अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में जमा किये गये या उन्हें अग्रिम के रूप में दिये 1885,19,90,000.00 रुपये शामिल है।

आर० एन० मजुमदार
मुख्य लेखाकार
तारीख 5 अगस्त 1983

मनमोहन सिंह गवर्नर
अमिताभ घोष उप गवर्नर
सी० रंगराजन उप गवर्नर
म० वि० छाटे उप गवर्नर

30 जून 1983 को समाप्त वर्ष का लाभ-हानि लेखा

	रु० पै०
आय	
ब्याज, बट्टा, विनिमय शुल्क, कमीशन आदि $	425,41,84,605.11
	425,41,84,605.11
व्यय	
स्थापना व्यय	79,53,86,973.96
निदेशकों और स्थानीय बोर्डों के सदस्यों की फीस और व्यय	2,16,293.85
लेखा परीक्षकों की फीस .	1,20,000.00
किराया, कर, बीमा बिजली आदि	4,32,03,931.97
विधि प्रभार	10,51,089.15
डाक और तार खर्च . . .	41,54,009.81
कोष-प्रेषण	1,76,66,753.46
लेखन-सामग्री आदि . . .	1,23,41,143.02
प्रतिभूति छपाई (चैक, नोट फार्म, आदि) .	35,93,68,425.58
बैंक संपत्ति का मूल्यह्रास और उसकी मरम्मत .	3,51,78,963.81
एजेंसी प्रभार	82,27,61,920.37
कर्मचारी उपदान और अधिवार्षिकी निधियों में अंशदान	1,35,00,000.00
विविध व्यय	4,92,34,166.55
उपलब्ध शुद्ध शेष राशि .	210,00,00,933.38
जोड़ . .	425,41,84,605.11
केन्द्रीय सरकार को देय अधिशेष . .	210,00,00,933.58

प्रारक्षित निधि लेखा	4,32,03,931.97
30 जून 1983 को शेष . . .	150,00,00,000.00
लाभ-हानि लेखे से अंतरित . .	कुछ नहीं
जोड़ . .	150,00,00,000.00

$भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 47 के अनुसार

नियमित या आवश्यक व्यवस्थाएं करने के बाद

आर० एन० मजुमदार
मुख्य लेखाकार

तारीख : 18 अगस्त 1983

मनमोहन सिह गवर्नर
अमिताभ घोष उप गवर्नर
सी० रंगराजन उप गवर्नर
म० वि० भाटे उप गवर्नर

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

भारत के राष्ट्रपति की सेवा में

हम भारतीय रिजर्व बैंक के अधोहस्ताक्षरित लेखा परीक्षक इसके द्वारा 30 जून, 1983 तक के रिजर्व बैंक के तुलन-पत्र तथा लेखों पर केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

हमने केन्द्रीय कार्यालय और कलकत्ता, बंबई (फोर्ट) मद्रास, नयी दिल्ली, नागपुर, गौहाटी और जयपुर के कार्यालयों के लेखों और उनसे संबंधित प्रमाणपत्रों और वाउचरों से और साथ ही दूसरे कार्यालयों और शाखाओं के प्रबंधकों द्वारा प्रस्तुत और प्रमाणित उन विवरणियों से जिन्हें उक्त तुलन-पत्र में समाविष्ट किया गया है, उपर्युक्त तुलन-पत्र की जांच कर ली है और हम यह सूचित करते हैं कि हमने केन्द्रीय बोर्ड से जो स्पष्टीकरण और जानकारी मांगी है, वह सारा स्पष्टीकरण और जानकारी हमें दी गयी है और वह संतोषजनक है। हमारी राय में यह तुलन-पत्र पूर्ण और सही तुलन-पत्र है। इसमें भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 और उसके अधीन बनाये गये विनियमों द्वारा निर्धारित विवरण दिये गये हैं और इसमें उक्त अधिनियम और विनियमों के अनुसार आस्तियों का मूल्य-निर्धारण किया गया है। यह तुलन-पत्र जहां तक हमारी जानकारी है, तथा हमें दिये गये स्पष्टीकरणों और बैंक की बहियों के अनुसार उचित ढंग से तैयार किया गया है ताकि इससे बैंक कार्यों की सच्ची और सही स्थिति का पता लग सके।

मेसर्स बाटलीबाय एण्ड पुरोहित
मेसर्स डी रंगस्वामी एण्ड कं०
मेसर्स लवलॉक एण्ड ल्यूइस
मैसर्स के सी खन्ना एण्ड कं०
} लेखा परीक्षक

तारीख : 18 अगस्त, 1983

भारतीय रिजर्व बैंक के तुलन-पत्र का विवरण

विवरण	निम्नलिखित तारीख को समाप्त वर्ष 30 जून 1981		30 जून 1982	
	रु० पै०	रु० पै०	रु० पै०	रु० पै०
इशू विभाग				
देयताएं 4				
बैंकिंग विभाग में रखे हुए नोट	13,64,49,690.00		29,80,93,643.00	
संचलन में नोट	14383,44,03,639.50		16034,70,25,652.00	
जारी किये गये कुल नोट		14397,08,53,329.50		16064,51,19,295.50
कुल देयताएं		14397,08,53,329.50		16064,51,19,295.50
आस्तियां				
सोने का सिक्का और बुलियन				
(क) भारत में रखा हुआ	225,58,27,914.78		225,58,28,023.95	
(ख) भारत के बाहर रखा हुआ	......		......	
विदेशी प्रतिभूतियां	2364,05,75,253.50		1564,05,75,253.50	
रुपये का सिक्का	47,53,65,997.06		29,96,70,632.13	
भारत सरकार की रुपया	....		....	
प्रतिभूतियां	11759,90,94,164.16		11244,90,45,385.92	
देशी विनिमय बिल और दूसरे वाणिज्य-पत्र	....		......	
कुल आस्तियां		14397,08,53,329.50		16064,51,19,295.50

भारतीय रिजर्व बैंक के तुलन-पत्र का विवरण (जारी)

विवरण	निम्नलिखित तारीख को समाप्त वर्ष			
	30 जून 1981		30 जून 1982	
	रु०	पै०	रु०	पै०
बैंकिंग विभाग				
देयताएं				
चुकता पूंजी	5,00,00,000.00		5,00,00,000.00	
प्रारक्षित निधि	150,00,00,000.00		150,00,00,000.00	
राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि	1025,00,00,000.00		1205,00,00,000.00	
राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि	356,05,00,000.00		440,00,00,000.00	
राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि	1625,00,00,000.00		1915,00,00,000.00	
जमा राशियां				
(क) सरकारी				
(i) केन्द्रीय सरकार	214,19,36,326.66		152,69,64,302.53	
(ii) राज्य सरकारें	85,46,04,916.55		247,45,88,183.23	
(ख) बैंक				
(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंक	5476,65,26,624.23		5932,14,52,798.59	
(ii) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	96,76,94,390.99		99,79,88,837.59	
(iii) गैर अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	4,24,85,571.49		3,66,14,617.53	
(iv) अन्य बैंक	5,69,18,424.03		8,44,49,052.84	
(ग) अन्य	1727,71,30,546.18		2542,94,67,026.11	
देय बिल	57,20,09,450.21		82,94,97,597.15	
अन्य देयताएं (क)	2159,19,47,556.23		2802,41,88,950.07	
कुल देयताएं		12997,12,53,806.57		15587,52,11,365.64
(क) इसमें आकस्मिकता लेखे शामिल हैं।				
आस्तियां				
नोट	13,64,49,690.00		29,80,93,643.00	
रुपये का सिक्का	4,19,877.00		3,36,507.00	
छोटा सिक्का	6,71,042.99		6,39,904.89	
खरीदे और भुनाये गये बिल				
(क) देशी	3,71,33,861.40			
(ख) विदेशी	..		..	
सरकारी खजाना बिल	4529,87,80,697.45		6701,75,54,790.65	
विदेशों में रखा हुआ बकाया (ख)	1602,64,28,160.37		1364,39,68,647.46	
निवेश	2157,50,02,729.35(ग घ)		2335,47,60,580.05(ग ङ)	
ऋण और अग्रिम	..		..	
(i) केन्द्रीय सरकार को	116,04,00,000.00			
(ii) राज्य सरकारों को (च)	570,69,92,396.18		567,96,94,312.37	
(iii) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को	340,75,09,800.00		630,52,90,500.00	
(iv) राज्य सहकारी बैंकों को (छ)	16,40,76,000.00		6,22,19,000.00	
(v) दूसरों को				
राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से ऋण अग्रिम और निवेश				
(क) ऋण और अग्रिम				
(i) राज्य सरकारों को	128,70,44,388.00		125,23,37,960.00	
(ii) राज्य सहकारी बैंकों को	30,96,28,877.00		32,94,82,516.00	
(iii) केन्द्रीय भूमि बंधक बैंकों को				
(iv) कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम को	366,40,00,000.00		513,93,30,000.00	
(ख) केन्द्रीय भूमि बंधक बैंकों के डिबैंचरों में निवेश	4,69,01,795.00		3,50,17,695.00	
राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से राज्य सहकारी बैंकों को ऋण और अग्रिम	94,79,93,317.00		84,46,19,803.00	

भारतीय रिजर्व बैंक के तुलन-पत्र का विवरण (जारी)

विवरण	निम्नलिखित तारीख को समाप्त वर्ष			
	30 जून 1981		30 जून 1982	
	रु०	पै०	रु०	पै०
राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रचलन) निधि से ऋण, अग्रिम और निवेश				
(क) विकास बैंक को ऋण और अग्रिम	1322,50,78,575.00		1610,59,88,575.00(झ)	
(ख) विकास बैंक द्वारा जारी किये गये बांडों/डिबेंचरों में निवेश				
अन्य आस्तियां	1697,67,42,599.83(ञ)		1580,58,76,931.24(ट)	
कुल आस्तियां		12997,12,53,806.57		15587,52,11,365 64

टिप्पणी : 30 जून 1981—आकस्मिक देयता :

(i) अंशत : चुकता शेयरों पर 50,000 पौंड के बराबर के 8,49,993,20

30 जून 1982—आकस्मिक देयता :

(i) अंशत : चुकता शेयरों पर 50,000, पौंड के बराबर के रु० 8,25,000.83

(ख) इनमें नकदी, सावधि जमाराशियां और अल्पकालीन प्रतिभूतियां शामिल हैं।

(ग) राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रचलन) निधि और राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रचलन) निधि में से किये गये निवेश शामिल नहीं हैं।

(घ) विदेशों में विदेशी मुद्राओं में रखे हुए रु० 360,52,01,369.45 शामिल हैं।

(ङ) विदेशों में विदेशी मुद्राओं में रखे हुए रु० 345,73,03,767.85 शामिल हैं।

(च) राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रचलन) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं।

(छ) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 17(4) (ग) के अधीन अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को मीयादी बिलों पर अग्रिम दिये गये रु० 'कुछ नहीं' शामिल हैं।

(ज) राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रचलन) निधि और राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं।

(झ) निर्यात-आयात बैंक को दिये गये रु० 25,00,00,000.00 के ऋण और अग्रिम शामिल हैं।

(ञ) विशेष व्यवस्थाओं के अधीन अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को अग्रिम दिये गये या उनमें जमा किये गये रु० 1138,11,10,000.00 शामिल हैं।

(ट) विशेष व्यवस्थाओं के अधीन अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को अग्रिम दिये गये या उनमें जमा किये गये रु० 1056,41,50,000.00 शामिल हैं।

30 जून 1981 और 1982 को समाप्त वर्षों का लाभ-हानि लेखा

	1981		1982	
आय	रु०	पै०	रु०	पै०
ब्याज, बट्टा, विनिमय शुल्क, कमीशन आदि	373,95,20,480.32		411,76,16,023.68	
	373,95,20,480.32		411,76,16,023.68	
व्यय				
स्थापना व्यय	71,83,73,677.16		76,21,37,205.92	
निदेशकों और स्थानीय बोर्डों के सदस्यों की फीस और व्यय	1,92,947.32		2,04,826.12	
लेखा परीक्षकों की फीस	1,15,000.00		1,20,000.00	
किराया, कर, बीमा, बिजली आदि	2,89,77,904.60		3,30,23,722.17	
विधि प्रभार	6,86,737.47		8,35,249.32	
डाक और तार खर्च	29,98,712.17		36,16,506.63	
कोष प्रेषण	1,49,17,273.55		1,68,67,824.29	
लेखन सामग्री आदि	1,40,18,699.35		1,15,08,627.55	
प्रतिभूति छपाई (चेक, नोट, फार्म आदि)	23,20,11,612.85		41,57,76,715.55	
बैंक संपत्ति का मूल्यह्रास और मरम्मत	1,87,46,996.12		2,42,64,795.13	
एजेंसी प्रभार	56,09,71,562.84		70,16,50,118.42	
कर्मचारी उपदान और अधिवार्षिकी निधियों में अंशदान	1,05,00,000.00		1,35,00,000.00	
विविध व्यय	3,69,78,980.50		3,41,09,689.39	
उपलब्ध शुद्ध शेष राशि	210,00,00,376.39		210,00,00,712.89	
जोड़	373,95,20,480.32		411,76,16,023.68	
केन्द्रीय सरकार को देय अधिशेष	210,00,00,376.39		210,00,00,712.89	
30 जून को शेष	प्रारक्षित निधि लेखा	150,00,00,000.00		150,00,00,000.00
लाभ हानि लेखे में अंतरित		कुछ नहीं		कुछ नहीं
जोड़		150,00,00,000.00		150,00,00,000.00

†भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 17 के अनुसार नियमित या आवश्यक व्यवस्थाएं करने के बाद।

[सं० एफ० 12/22/83-बी० ओ०-I]

च० वा० मीरचन्दानी, निदेशक

New Delhi, the 17th April, 1984

S.O. 1752.—In accordance with section 52 (2) of the Reserve Bank of India Act, 1934, the Central Board of Directors has submitted to the Government of India the following Annual Report on the working of the Reserve Bank of India during the year ended June 30, 1983.

THE ANNUAL REPORT

ON THE WORKING OF THE RESERVE BANK OF INDIA

For the year July 1, 1982—June 30, 1983

Part I—The Economic Situation

In 1982-83, the economy suffered a serious setback with agricultural output affected by severe drought and a marked decline in the pace of increase in industrial production. In consequence, the national income registered only a marginal rise. The overall balance of payments showed improvement even though it still continued to be understrain. Despite these adverse trends, prices were fairly stable for the greater part of the year.

2. Agricultural Production.—Agricultural output decline during the year mainly on account of a drought of unusual severity. More than 48 million hectares of cropped area in 15 States were affected by the failure of the south-west monsoon which set in late, behaved erratically and withdrew early. It has to be noted that this is the second serious drought suffered by Indian agriculture in the past five years. In 1979-80 also, the south-west monsoon failed and the resultant drought affected about 41 million hectares of cropped area. In 1982-83, the weather factor was most adverse in respect of kharif foodgrains, the production of which is estimated to have declined by over 9 million tonnes from 79.1 million tonnes in 1981-82 to around 69-70 million tonnes. This decline is not so pronounced as that experienced in 1979-80 when kharif foodgrain output decline by as much as 15, millions tonnes. In part, this could be attributed to the fact that in 1979-80, the important food growing States were more seriously affected by the weather factor than in the year under review. At the same time, efforts to alleviate hardship and minimise the adverse impact of monsoon failure through arrangements for maintenance and extension of minor irrigation facilities, provision of fertilisers and other inputs, etc., also helped in salvaging the crop of 1982-83. These efforts were stepped up substantially in the course of the year. Fertiliser consumption in 1982-83 is estimated to have gone up by about 6 per cent over the previous year. Although this is considerably short of the targetted consumption, an increase of this order is not insignificant in a year of unfavourable weather conditions. The rabi output of foodgrains has touched a record level of about 58.0 million tonnes which is higher by about 4.0 million tonnes than the rabi production of 1981-82.

3. Total output of foodgrains during 1982-83 is estimated at 127-128 million tonnes which, even at the higher end, would be 5 million tonnes less than the actual output of 133 million tonnes in the previous year. In respect of non-food crops, the decline in production is most sharp in jute and mesta and oilseeds. The output of jute and mesta would only be about 7.2 million bales as against an output of 8.4 million bales in 1981-82, while oilseeds production may total 11 million tones as against 12.1 million tonnes in the previous year, Sugarcane production is also expected to be somewhat lower at 17.7 million tonnes (in terms of gur) as against the last season's output of 18.7 million tonnes. Cotton output is expected to be at around 8.2 million bales as against the actual production of 8.4 million bales last year.

4. A favourable aspect of the situation is that the drought of 1982-83 did not have any serious impact on food stocks with public distribution agencies. Procurement operations were geared up and the quantity of rice and coarse grains procured (7.1 million tonnes) during this marketing season was only marginally lower than in the previous year (7.3 million tonnes) while the procurement of wheat in the current rabi season has touched a new high of 8.2 million tonnes. In addition, arrangements were finalised for the import of 40 lakh tonnes of wheat from the U.S., of which 14.5 lakh tonnes had been received upto end February 1983. This import was necessary to sustain stock levels which were drawn down because of the increasing outflow through the public distribution system. The offtake of foodgrains totalled 16.4 million tonnes in 1982-83 (July-June) as against 11.8 million tonnes in 1981-82. The average offtake per month has increased from 1.2 million tonnes in 1981-82 to 1.4 million tonnes in 1982-83. The stock of foodgrains with government agencies was 16.5 million tonnes at the end of June 1983, which was higher than the level of 15.5 million tonnes a year earlier. A buffer stock 5 lakh tonnes of sugar was created during the year, consequent on the sharp rise in sugar production in the 1981-82 season.

5. Industrial Output.—More disquieting than the decline in agricultural output, which can be expected to improve with favourable weather conditions, is the deceleration in the growth of industrial production. In the eleven-month period July 1982—May 1983, the overall index of industrial production rose by only 3.2 per cent over the corresponding months of the previous year as against an increase of 7.6 per cent in 1981-82. The symptoms of a declining trend in output were evident even at the commencement of the calendar year 1982. The average increase in the index of industrial production for the quarter January-March 1982 was 6.4 per cent as against 8.8 per cent in the corresponding quarter of 1981. In April-June 1982, the increase at 6 per cent, was at about the same rate but the disparity with the previous year's corresponding quarter, when the growth was 11.3 per cent, was more sharp. The decline in pace became pronounced in July-September 1982 when the average rise in the index dropped to 2.1 per cent, as against 9.1 per cent in July-September 1981. In the October-December quarter, the rise in 1982 was 3.6 per cent as against 8.0 per cent in 1981. The decline obviously continued as the latest data for January to May 1983 show an average rise of only 3.6 per cent as against an increase of 6.6 per cent in the same months of the previous year.

6. According to the setoral classification of the industrial production index, the fall in industrial growth has been mainly on account of the manufacturing sector which carries a weight of 81 pe. cent in the index.

In the eleven-month period July 1982 to May 1983, this sector recorded an increase of a mere 1.7 per cent as against a rise of 6.8 per cent in the previous year. Mining and quarrying increased by 8.4 per cent as against 15.1 per cent in the previous year while in the case of electricity, the growth of 6.7 per cent in 1982-83 (July-May) was marginally lover compared to 7.1 per cent recorded in the corresponding period of 1981-82.

7. An analysis of the use-based classification of the index shows that in capital goods industries, the index recorded an absolute decline of 3.9 per cent in the period July 1982-March 1983 as against a rise of 7.7 per cent in the same period of 1981-82. In consumer goods industries, there was a marginal increase of 0.6 per cent compared to a rise of 10.6 per cent in 1981-82. The intermediate goods industries group showed a rise of 3.2 per cent, about the same as in 1981-82 (3.3 per cent). In the case of basic industries, the increase in 1982-83 (July-March) appears more substantial at 8.4 per cent; however, in the same period of the previous year, the increase registered by this index was as much as 11.0 per cent.

8. A look at the movements in the industrial production index over the year shows that sharp year-to-year fluctuations are a common feature. The rate of growth in the index varied from 10.5 per cent in 1975-76 (July-June) to 1.9 per cent in 1979-80. In the 12-year period since 1971-72 only in 3 years did the growth in the index exceed 7.0 per cent while in 3 years, it was under 3.0 per cent. However, in many of the years with low rates of increase, the poor performance of industry was attributable to shortages of power and other infrastructu al facilities. 1982-83 is somewhat unique in that the performance of the infrastructural sector during the year was, on the whole, good.

9. Power generation in the country in the financial year 1982-83 was 7.0 per cent higher than in the previous year. Thermal and nuclear power generation showed a rise of 13.5 per cent, more than compensating for the decline in hydel generation of 2.6 per cent. The total generation, at 131.6 billion kwh., was short of the target for the year by 0.4 billion kwh. Further, the improvement in generation was not uniform throughout the country and there were regions, such as the south and the east, where power shortage was a serious problem, which had impeded the performance of industries located in these areas. The output of coal during the financial year, at 130.4 million tonnes showed an increase of 4.4 per cent over the previous year's level. However, the offtake of coal was not brisk resulting in the accumulation of pit-head stocks. The output of saleable steel showed a marginal increase of 0.5 per cent. But here again, there was an increase in the stocks of saleable steel with SAIL. Both these features reflect the slackness in demand from user industries. The output of both petroleum refinery products and crude showed good groth of 10.3 per cent and 30.1 per cent, respectively. The output of cement increased by 11.6 per cent and that of nitrogenous and phosphatic fertilisers rose by 8.9 per cent and 3.6 per cent, respectively. The revenue earning traffic originating by the railways during 1982-83 showed an increase of 3.0 per cent.

10. Factors behind Deceleration in Industrial Production.—In interpreting the low rate of growth in industrial production, it has to be borne in mind that weights in the current index of industrial production are derived from the contribution to value added by manufacture by various industries, obtained on the basis of data available for 1970. Some of the new and rapidly growing industries such as crude petroluem and certain engineering industries consequently have low weight in the index.

11. An important factor which has obviously influenced industrial production in the year under review is the overall dampening effect on demand of the severe drought and the consequent decline in agricultural income. The growth recorded by industry in the preceding year (July-June) was fairly high at 7.6 per cent. This trend could not naturally be sustained in a poor agriculture year. Besides, this general factor of the dampening effect on demand of a fall in agriculture production and income, there were other factors contributing to the decline in production which were primarily industry-specific. In the case of a major manufacturing industry, the cotton textile industry, the prolonged strike in Bombay mills affected not only the production of yarn and cloth but also the demand for the products of other industrial groups, such as dyes and cheficals and textile machinery. Some industries, such as commercial vehicles and agriculture tractors, had to reduce production during the year because of substantial increases in output in the two previous years. In these cases, sluggishness in production has been a consequence of adjustment of supply to demand. As mentioned earlier, despite the increase in power generation, there was a gap between availability and requirement which affected industries, particulary in the southern and estern region. Decline in export demand affected the output of some industries such as jute manufactures where a decline in exports of 17.5 per cent slowed down output. It is claimed that liberalised imports have hampered the domestic production of some products. In respect of soda ash, frequently cited as an example, there were substantial imports from 1979-80 onwards. However, imports were reduced considerable in 1982-83. Over the year as a whole, production is estimated to have reached the same level as in the previous year and stocks, as at end of the year, were substantially lower.

12. National Income, Saving and Investment.—Following the decline in agricultural output and the deceleration in the pace of increase in industrial production, growth in national income deteriorated sharply. According to the Reserve Bank's estimates, the growth rate in the net national product in real terms in 1982-83 is between 1 and 2 per cent, in contrast to a growth rate of 5.0 per cent in 1981-82

and 8.1 per cent in 1980-81. Aggregate net domestic saving for 1982-83 has been provisionally estimated at 16.8 per cent of NNP at current market prices against 16.5 per cent in 1981-82. This denotes a marginal rise in the estimated saving. The stability in the rate of aggregate saving is brought about by a moderate fall in the saving of the public sector of 0.8 percentage point, and by an increase of 1.1 per cent in the saving of the household sector. The share of the domestic private corporate sector's saving in NNP is, however, estimated to remain at 0.6 per cent for the third year in succession. Estimates of net domestic saving and investment in terms of their percentages to NNP are given in Table below :—

ESTIMATES OF NET DOMESTIC SAVING AND INVESTMENT AS PERCENTAGE OF NET NATIONAL PRODUCT AT CURRENT MARKET PRICES

Sector/Item	Fiscal Years		
	1980-81	1981-82	1982-83 (Provisional)
1	2	3	4
1. Household Sector . . OF which :	13.4	12.6	13.7
Saving in Financial Assets	6.8	6.2	8.0
2. Public Sector . . .	2.1	3.3	2.5
3. Domestic Private Corporate Sector	0.6	0.6	0.6
. Total Net Domestic Saving (1+2+3) . .	16.1	16.5	16.8
5. Inflow of Foreign Resources	1.9	2.6	2.0
Aggregate Net Investment (4+5) . .	18.0	19.1	18.8

Note :—The ratios for 1980-81 and 1981-82 differ from those given in the last year's Annual Report because of substantial revision in the estimates of national income and those of saving and investment, consequent on the availability of further data.

13. The ratio of saving of the household sector in the form of financial assets showed a significant improvement from 6.2 per cent in 1981-82 to 8.0 per cent of NNP in 1982-83. This is mainly attributable to increase in the households' saving in currency and deposits, the increase in deposits being mainly with commercial banks. Households' saving in the form of currency rose from 0.7 per cent of NNP in 1981-82 to 1.3 per cent in 1982-83 while the saving in the form of deposits was higher at 5.1 per cent in 1982-83 compared with 4.3 per cent in 1981-82. The claim on government which had increased substantially in the last year because of investment in Special Bearer Bonds, declined steeply in 1982-83. Similarly, the liabilities of the household sector also came down to 2.5 per cent of NNP in 1982-83 compared to 2.8 per cent in the previous year, entirely due to the fall in borrowings from commercial banks.

14. Even though the public sector undertakings improved their performance, the estimated saving of the public sector has shown a fall during the year on account of the dis-saving of the Central Government administration and a decline in the saving of State Governments including their departmental undertakings.

15. Despite a marginal rise in the net domestic saving, the net investment in terms of NNP declined from 19.1 per cent in 1981-82 to 18.8 per cent in 1982-83 because of the decline in net inflow of resources from abroad.

DEVELOPMENT IN CREDIT POLICY

16. Credit policy during the greater part of 1982-83 was aimed at ensuring a pace of credit growth that would stimulate and sustain production and at the same time curb the rise of inflationary expectations. Select sectors of industry such as the capital goods sector, which were suffering from slackness of demand, received special attention. In view of the relative stability in general price level, lending rates of commercial banks were lowered. However, the stance of credit policy recently changed to one of caution and restraint, with the decline in agricultural production and with prices showing a tendency to rise sharply. The slack season credit policy that is currently in force, by raising the cash reserve ratio, seeks to immobilise the excess liquidity present in the banking system and to smoothen the flow of credit more evenly over the year.

17. Policy Measures—July 1982.—As detailed in last year's Report, the emphasis of credit policy between April and July 1982, was on the restoration of normalcy in credit operations. With this end in view, and in order to ease the liquidity pressure experienced by banks, the cash reserve ratio was reduced and the refinance formulae liberalised in the latter part of 1981-82. The guideline for credit expansion in the financial year 1982-83, given in July 1982, indicated that expansion in non-food credit could be around the same percentage rate of growth of 16.8 per cent as attained in 1981-82. In absolute terms, this meant a growth of around Rs. 4,600 crores for the system as a whole, as against an actual increase of Rs. 3,943 crores in the previous year. It was anticipated, at that stage, that the growth in aggregate deposits during 1982-83 would range between Rs. 6,600—Rs. 7,000 crores for the system as a whole. It seemed possible that a modest resources gap might emerge in the 1982-83 busy season and the Reserve Bank indicated that it would be prepared to bridge the gap and supplement banks' resources to the extent warranted by genuine credit requirements.

18. Policy Measures—October 1982.—At the time of the busy season review in October 1982, the prospects for the year suggested a slowing down of the growth in the economy which called for continuing caution, particularly in relation to primary money creation. At the same time, there was also the need to provide stimulus to some vital sectors of the economy affected by sluggish demand. In such a situation, credit policy had to assist in the fuller utilization of available capacities without providing support to the revival of inflationary expectations. While genuine productive requirements of the economy required expansion of bank credit, the continuing vigil against the resurgence of inflationary tendencies required that the expansion be carefully control-

led. Thus the credit policy measures, announced on October 25, 1982, were based on the requirements for promoting savings, containing inflationary expectations and controlling monetary expansion while providing increased credit to certain sectors for the stimulation of activity.

19. New Deposit Category.—The category of term deposits of five years and above was revived and an interest rate of 11 per cent was allowed with effect from October 26, 1982. This step followed the recommendation of the Working Group on Bank Deposits. It may be recalled that the deposit category of five years and above was abolished in March 1981 and the maximum interest allowed on term deposits was 10 per cent in respect of deposits of three years and above. The reversion to the long-term maturity category, at a higher interest rate, was intended essentially to offer a better return for saving in the form of longer term bank deposits and to assist banks in their deposit mobilisation efforts. There was no change in lending rates at this stage, but it was indicated that the question of downward adjustment in lending rates would be considered later.

20. Refinance Adjustments.—Certain adjustments were made in the refinance formulae to liberalise the availability of Reserve Bank accommodation to banks. Banks were provided refinance to the extent of 50 per cent of the increase in food credit over the level of Rs. 2,200 crores and 100 per cent refinance over the outstanding level of food credit of Rs. 2,600 crores upto the end of October 1982. With effect from November 1, 1982, the partial refinance over the level of Rs. 2,200 crores was discontinued and banks were provided full (100 per cent) refinance over the outstanding level of Rs. 2,500 crores. In respect of export refinance, the normal practice of bringing forward annually the base level for calculating the entitlement (50 per cent of the increase) was modified; banks were now entitled to refinance to the extent of 50 per cent of the increase in export credit over the monthly average level of 1980 upto the monthly average level of 1981 plus 100 per cent of the increase over the monthly average level of export credit in 1981. This was expected to enhance the ability of banks to increase export credit without any constraint.

21. Stimulation of Investment.—The measures that aimed at stimulation were selective in application, intended for capital and intermediate goods. The IDBI was promised support in case of mis-match between resources and deployment, so as to ensure the sanction of additional limits to State Electricty Boards and State Road Transport Corporations. The ceiling on banks' share in term loans to State Road Transport Corporations was raised from 25—30 per cent to 40 per cent of the term loan component of the project cost. The margin applicable to bank loans for the purchase of tractors and trucks was lowered from 25 per cent to 15 per cent. In the case of private sector parties not covered by the Credit Authorisation Scheme (CAS), the cutoff point for term loans (of over three years) which require prior authorisation by the Reserve Bank was raised from Rs. 25 lakhs to Rs. 50 lakhs. In the case of major export-oriented manufacturing units outside the CAS, whose annual average export turnover in the past three years was more than 25 per cent of total turnover, the cut-off point for term loans (of over three years) which require prior authorisation by the Reserve Bank was raised from Rs. 25 lakhs to Rs. 1 crore.

22. Adjustments in CAS Procedure.—Other liberalisations were also made in the CAS procedures to facilitate the more expeditious sanction of export credit limits. In the case of major export-oriented manufacturing units whose export component in total turnover was more than 25 per cent, the cut-off point for the CAS was raised from Rs. 3 crores to Rs. 5 crores. Also, the sanction of additional packing credit limits requiring prior authorisation was liberalised.

23. Other Concessional Measures.—The other measures announced at this time related to credit to priority or preferred sectors. A concessional rate of 13.5 per cent was specified in respect of advances to State sponsored organisations of Scheduled Castes|Scheduled Tribes. The amount earmarked in total bank lending for housing finance was raised from Rs. 100 crores to Rs. 150 crores.

24. Reduction in Lending Rates.—In the context of the prevailing low rate of inflation, it was felt that real rates of interest were high. It was therefore decided to adjust downwards the structure of lending rates with effect from April 1, 1983. The Government made a contribution towards this end and the tax on interest income was halved with effect from 1983.

25. The reduction inlending rates varied from 0.25 percentage point to 1.5 percentage points and the maximum lending rate reduced from 19.5 per cent to 18.0 per cent. The salient features of the changes are as follows

(i) In the case of lending rates which were fixed at 17.5 per cent and 19.5 per cent or 'not' exceeding' 17.5 per cent and 'not exceeding' 19.5 per cent, an across-the-board reduction was effected as follows :

Lending Rates (Per cent per annum)			
Effective upto March 31, 1983		Effective from April 1, 1983	
17.5			16.5
Not exceeding 17.5		Not exceeding	16.5
19.5			18.0
Not exceeding 19.5		Not exceeding	18.0

(ii) In the case of short-term loans for agriculture, there was a reduction of 1.0 percentage point across-the-board.

(iii) In the case of short-term loans to small scale industry not covered by the reduction at (i) above, reductions ranged between

0.25 percentage point and 1.0 percentage point.

(iv) In the case of short-term loans for exports, there was a reduction of 0.5 percentage point.

(v) For State level Corporations assisting artisans, village and cottage industries and State sponsored Scheduled Castes/Scheduled Tribes Development Corporations, there was a reduction of 1.0 percentage point.

26. The downward adjustment in interest rates was intended to provide relief to a wide spectrum of borrowers including large and medium industry, agriculture, small scale industry and exports. Lending rates in the highest bracket, which had increased by as much as 4.5 percentage points since September 1979, were subjected to a somewhat larger reduction than the rates for other categories, which already had a significant concessional element and which had also experienced minimal increases since September 1979. The revised lending rate structure was expected to stimulate the growth of real output.

27. Policy Measures—April 1983.—At the time credit policy was reviewed in the last week of April 1983, the deceleration in real growth was very evident. Other features of the situation were a substantial build-up of primary money and a subdued demand for commercial credit. This combination of circumstances inevitably resulted in the build-up of sizeable excess liquidity in the banking system. It was also felt that this liquidity could well prove to be a short-term phenomenon, with the increased demand for credit following an increase in the growth of agricultural and industrial production but this demand was likely to emerge only in the latter part of the financial year 1983-84. Meanwhile, it was essential to contain the inflationary potential implicit in the excess liquidity, without harming in any way the essential processes of production. The requirement of the situation was hence to ensure a balance in the use of the liquidity, so that genuine productive requirements were met adequately throughout the year.

28. The guideline in respect of credit expansion during the financial year 1983-84 was spelt out in some detail. As a working estimate, deposit growth in 1983-84 was placed in the region of Rs. 8,000 crores as against a little over Rs. 7,100 crores in 1982-83. Banks were asked to initially give greater attention to the first quarter and the first half of 1983-84, when the banking system's overall liquidity position was expected to be comfortable, although this liquidity would be unevenly distributed amongst banks. Even so, the estimate was that banks would be able to expand credit by Rs. 1,500 crores, which was the order of expansion considered adequate in the prevailing conditions.

29. Management of Excess Liquidity:—Banks, it was anticipated, would be able to meet this requirement out of their own resources and without recourse to Reserve Bank refinance and also build-up additional liquidity by about Rs. 1,000 crores. It was hence considered prudent to conserve liquidity in the first half of the year, while also meeting all genuine productive credit requirements. The main policy measure announced was therefore directed towards assisting such conservation of liquidity. The cash reserve ratio was raised from 7 to 8 per cent of net demand and time liabilities. The increase was to be effected in two phases : a rise of 0.50 percentage point to 7.50 per cent effective from May 27, 1983 and the next rise of 0.50 percentage point taking the ratio to 8 per cent effective from July 29, 1983. It was emphasised that this increase in the ratio was introduced in order to absorb the temporary liquidity, until conditions emerged for the suitable deployment of funds as productive credit.* Simultaneously, the interest on banks' balances with the Reserve Bank in excess of the minimum of 3 per cent was raised from 8 per cent to 9 per cent effective May 1, 1983. In recognition of the fact that the excess liquidity was unevenly distributed within the system, banks which faced difficulties in meeting the enhanced cash reserve requirement were assured of discretionary refinance, provided on merits, for short periods. In respect of the food refinance formula, the cut-off point of outstanding food credit at which 100 per cent refinance was available to banks was raised from Rs. 2,500 crores to Rs. 2,800 crores effective July 1, 1983.

30. Other Measures.—Other measures were taken to provide stimulus to selected sectors. The arrangements made in October 1982 to enlarge the resources of IDBI for the sanction of additional limits to State Electricity Boards and State Road Transport Corporations have been continued. With a view to strengthening the redistributive bias of credit policy, the rates of interest on bank loans granted to self employed professionals belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes as well as women have been reduced. Interest rates applicable to retail trade in fertilisers and for production and distribution of seeds have been lowered. The base for calculating export refinance entitlement of banks was not altered as a measure of support to banks. To ensure that suppliers in the small scale sector secure prompt payment of their bills from producers in the large scale sector, certain credit norms, which had already been set out were reiterated for more effective implementation.

31. With the build-up of substantial liquidity, the situation holds inflationary potential. The object of the credit policy measures currently in force is, therefore, to absorb the short-term excess liquidity in the banking system. At the same time, it has been made clear that there could be changes in policy, should circumstances warrant. The flexibility of credit policy and its ability to react expeditiously to short term changes in the economic situation has been amply demonstrated in the past. Under the prevailing conditions, the emphasis of credit policy will necessarily have to be one of caution.

TRENDS IN MONEY, CREDIT AND PRICES

32. The rate of growth in money supply was higher in the year under review as compared with the previous

*With effect from August 27, 1983 the cash reserve ratio was raised further by one-half of one percentage point to 8.5 percent.

year. As may be seen from Table 1, in 1982-83 (July-June) M1 rose by 12.3 per cent as against a rise of 10.4 per cent in the previous year. In terms of M_3 (M plus time deposits), the increase was 15.3 per cent as against 12.9 per cent.

33. Money Supply.—The factors contributing to the change show some significant features. The increase in net bank credit to Government was substantially lower in 1982-83 as compared to the previous year, the rise in percentage terms being only 14.2 per cent against 22.2 per cent. While the increase in bank credit to the commercial sector was around Rs. 1,343 crores more in 1982-83 (July-June) than in 1981-82, there was not much difference in the growth in percentage terms. A major factor contributing to the higher monetary expansion in the current year was the reduction in the negative impact of a decline in foreign exchange assets. In absolute terms, the fall in the net foreign exchange assets of the banking sector was only of the order of Rs. 381 crores in 1982-83 as against a decline of Rs. 1,955 crores in the corresponding period of the previous year.

June 1983 SUPPLEMENT TO THE RESERVE BANK OF INDIA BULLETIN

TABLE 1—VARIATIONS IN MONEY STOCK (M_3)

(Rs. Crores)

	End-June 1982 over End-June 1981		End-June 1983 over End-June 1982+@	
	Absolute	Percentage	Absolute	Percentage
	1	2	3	4
I. M^3(a+b+c)	**+7,556**	**+12.9**	**+10,108**	**+15.**
(a) Currency with the Public	+1,662	+12.0	+2,378	+15.3
(b) Aggregate Deposits with Banks (*i*+*ii*)	6,021	+13.6	+7,683	—15.2
(*i*) Demand Deposits	—972	+9.8	+835	+7.7
(*ii*) Time Deposits	+5,049	+14.6	+6,848	+17.3
(c) Other Deposits with RBI	—127	—51.8	+47	—39.8
II. M_1 (a+b+(i)+c)	**+2,507**	**+10.4**	**+3,260**	**+12.3**
III. SOURCES OF MONEY STOCK (M_3) (1+2+3+4+5)				
1. Net Bank Credit to Government (A+B)	**+6,284**	**+22.2**	**+4,913**	**+14.2**
(A) RBI's Net Credit to Government (*i*+*ii*)	+4,614	+25.6	+3,044	+13.4
(i) Claims on Government (a+b)	+4,716	+25.7	+3,397	+14.7
(a) Central Government	+4,836	+26.7	+3,184	+13.9
(b) State Government	—120	49.0	+213	+170.4
(*ii*) Government Deposits with RBI (a+b)	+100	+33.3	+353	+88.3
(a) Central Government	-61	—28.5	+400	+261.4
(b) State Government	+161	+187.2	—47	—19.0
(B) Other Bank's Credit to Government	+1,669	+16.2	+1,869	+15.7
Bank Credit to Commercial Sector (A+B)	**+6,402**	**+16.9**	**+7,745**	**+17.5**
(A) RBI's Credit to Commercial Sector*	+417	+23.6	+291	+13.3
(B) Other Bank's Credit to Commercial Sector (*i*+*ii*+*iii*)	+5,985	+16.6	+7,454	+14.7
(*i*) Bank Credit by Commercial Banks	+3,630	+13.7	+5,750	+19.0
(*ii*) Bank Credit by Co-operative Banks	+1,230	+25.4	+564	+9.3
(*iii*) Investment by Commercial and Co-operative Banks in other securities	+1,125	+24.3	+1,140	+19.8
Net Foreign Exchange Assets of the Banking Sector (A+B)	**—1,953**	**+46.2**	**—381**	**—16.7**
(A) RBI's Net Foreign Exchange Assets (*i*+*ii*)	—1,955	—45.7	—381	—16.4
(*i*) Gross Foreign Assets	—1,053	—23.1	—1,531	+43.7
(*ii*) Non-monetary Foreign Liabilities	+902	+330.4	+1,912	+162.7
(B) Other Bank's Net Foreign Exchange Assets	..	..	..	..
Government's Currency Liabilities to the Public	**+36**	**+5.7**	**+7**	**+1.0**
Banking Sector's Net Non-Monetary Liabilities other than Time Deposits (A+B)	**+3,211**	**+25.9**	**+2,176**	**+13.9**
(A) Net Non-monetary Liabilities of RBI	+1,371	+27.7	+119	+1.9
(B) Net Non-monetary Liabilities of other banks (Derived)	+1,840	+24.7	+2,057	+22.1

+ Data are provisional/partially revised.

@ These variations disregard changes in components of sources on July 12, 1982, following reclassification of aggregates necessitated by the establishment of NABARD.

* Excludes, since the establishment of NABARD, its refinance to banks.

Notes :—(1) Constituent items may not add up to the totals due to rounding off.

(2) Reserve Bank data are as on last day of June. Other data are as on last Friday of June.

34. Reserve Money.—The growth in reserve money during the year at 13.8 per cent was higher than the rise of 9.7 per cent recorded in the previous year (Table 2). Reserve Bank's claims on Government increased at a much lower pace than in the previous year—13.4 per cent as against 25.6 per cent—while the claims on commercial and co-operative banks showed a substantial decline. There was a considerable abatement in the decline in foreign exchange assets from Rs. 1,955 crores or 45.7 per cent in 1981-82 to Rs. 381 crores or 16.4 per cent in 1982-83.

TABLE 2—VARIATIONS IN RESERVE MONEY

(Rs. Crores)

	End-June 1982 over End-June 1981		End-June 1983 over End-June 1982@+	
	Absolute	Percentage	Absolute	Percentage
Reserve Money (1+2+3+4)	+2,022	+9.7	+3142	+13 8
1. Currency with the Public	+1,662	+12.0	+2,378	+15.3
2. Other Deposits with R.B.I.	—127	—51.8	+47	+39.8
3. Cash with Banks	+26	+2.4	—23	—2.1
4. Banks' Deposits with R.B.I.	+461	+8.3	+740	+12.2
SOURCES OF RESERVE MONEY (1+2+3U4+5+6—7)				
Reserve Bank's Claims on:				
1. Government (Net)	+4,615	+25.6	+3,044	+13.4
2. Commercial and Co-operative Banks	+279	+26.9	+720	—54.7
3. NABARD	—	—	+1,020	—
4. Commercial Sector*	+417	+23.6	+291	+13.3
5. Net Foreign Exchange Assets of RBI	—1,955	—45.7	—381	+16.4
6. Government's Currency Liabilities to the Public	+36	+5.7	+7	+1.0
7. Net Non-monetary Liabilities of RBI	+1,371	+27.7	+119	—1.9

+Data are provisional/partially revised.

@These variations disregard changes in components of sources on July 12, 1982, following reclassification of aggregates necessitated by the establishment of NABARD.

*Represents investments in shares/bonds of financial institutions, loans to them and holding of internal bills purchased discounted. Excludes, since the establishment of NABARD, its refinance to banks.

Notes 1. Constituent items may not add up to the totals due to rounding off.

2. Data on cash with banks relate to last Friday. Reserve Bank data are as on last day of June.

35. Banking Variables.—Data on banking indicators given in Table 3 show that the growth both in deposits and in credit was higher during 1982-83 as compared to that in 1981-82 and that the rise in credit was more marked. While food credit expanded by a larger amount than in the past year, the disparity was mainly on account of non-food credit to commercial sector which includes public sector units as well. Non-food credit grew by Rs. 4,987 crores or 18.2 per cent in 1982-83 as against Rs. 3,007 crores or 12.4 per cent in 1981-82. The banks' borrowings from the Reserve Bank declined by Rs. 63 crores as compared to a small rise in the previous year. The increase in investments was Rs. 218 crores more than in the last year, indicating that despite the pressure of a larger credit expansion, banks were in a comfortable liquidity position.

TABLE 3—VARIATIONS IN IMPORTANT BANKING INDICATORS

(Scheduled Commercial Banks)

(Rs. Crores)

ITEMS	Amount outstanding as on			Variations during the year	
	June 26,1981	June 25,1982	June 24, 1983*	1981-82	1982-83
	1	2	3	4	5
Total Demand and Time Liabilities (excluding borrowings from RBI/IDBI & NABARD)	44,482	50,009	57,748	+5,527	+7,739
Aggregate Deposits	40,549	46,128	53,566	+5,579 (+13.8)	+7,438 (+16.1)
Borrowings from RBI	564@	572@	509	+8	—63
Bank Credit	26,551	30,180	35,929	+3,629 (+13.7)	+5,749 (+19.1)
Bills rediscounted with RBI	3	—	—	—3	—
Food Credit	2,202	2,825	3,587	+623	+762
Non-food Bank Credit	24,348	27,355	32,342	+3,007 (+12.4	+4,987 (+18.2)
Investments	14,222	16,945	19,886	+2,723 (+19.1)	+2,941 (+17.4)
(a) Government Securities	9,975	11,617	13,460	+1,642	+1,843
(b) Other approved securities	4,247	5,328	6,426	+1,081	+1,098
Cash in hand	985	999	983	+14	—16
Balances with RBI	4,517	4,771	5,143	+254	+372
Credit-Deposit Ratio (%)	65.5	65.4	67.1		
Non-food Credit-Deposit Ratio (%)	60.0	59.3	60.4		

* Partially revised.

@Include RRB borrowings transferred to NABARD on July 12, 1982.

Note : Figures in brackets are percentage variations.

36. Sectoral Deployment.—Data on sectoral deployment of gross bank credit (available upto end-March, 1983) are presented in Table 4. During the period July 1982—March 1983, gross bank credit showed a larger expansion of Rs. 4,295 crores (14.4 per cent) as compared with Rs. 3,274 crores (12.6 per cent) during the corresponding period of 1981-82. The increase in food procurement credit was Rs. 217 crores as against a decline of Rs. 75 crores in the corresponding period of the previous year. Non-food credit increased by Rs. 4,078 crores (15.1 per cent) as compared with Rs. 3,349 crores (14.1 per cent) in the corresponding period of 1981-82. Available data indicate that the larger growth in non-food credit was mainly due to the sizeable rise in incremental credit going to the medium and large industry sector. The rise in credit to public sector units alone accounted for a good portion of this increase. The additional credit utilised by the iron and steel industry, which is almost wholly in the public sector, formed nearly a third of the total increase in credit to medium and large industry. Credit to priority sectors showed a smaller increase than in the previous year.

TABLE 4—SECTORAL DEPLOYMENT OF GROSS BANK CREDIT

(Rs. Crores)

ITEMS	Outstandings		Variations	Outstandings		Variations
	June 1981	March 1982	March 1982 over June 1981	June 1982@	March 1983@	March 1983 over June 1982
1	2	3	4	5	6	7
I. Public Food Procurement	2,202	2,127	—75	2,824	3,041	+217
II. (a) Priority Sectors	8,966	10,676	+1,710 (51.1)	10,685	12,226	+1,543 (37.8)
(i) Agriculture	3,783	4,615	+832 (24.8)	4,588	5,239	+651 (16.0)
(ii) Small Scale Industries	3,406	3,901	+495 (14.8)	3,921	4,447	+526 (12.9)
(iii) Other Priority Sectors	1,777	2,160	+383 (11.5)	2,174	2,540	+366 (8.9)
(b) Industry (Medium and large)	9,983	11,155	+1,172 (35.0)	11,192	13,048	+1,856 (45.5)

1	2	3	4	5	6	7
(c) Wholesale Trade (Other than food procurement)	2,000	2,198	+198 (5.9)	2,152	2,324	+172 (4.2)
(i) Cotton Corporation of India . . .	232	255	+23 (0.7)	271	287	+16 (0.4)
(ii) Food Corporation of India (Fertiliser Credit)	313	411	+98 (2.9)	454	431	−23 (−0.6
(iii) Jute Corporation of India . . .	70	115	+45 (1.3)	102	74	−28 (−0.7)
(iv) Other Trade	1,385	1,417	+32 (1.0)	1,325	1,532	+207 (5.1)
(d) Other Sectors	2,737	3,006	+269 (8.0)	2,918	3,425	+507 (12.5)
III. Non-food Gross Bank Credit (a+b×c+d) . .	**23,686**	**27,015**	**+3,34 (100.0)**	**26,945**	**31,023**	**+4,078 (100.1)**
of which : Export Credit	1,728	1,796	+68	1,735	1,738	+3
IV. Gross Bank Credit (I+III)	**25,888**	**29,162**	**+3,274**	**29,769**	**34,064**	**+4,295**

@Provisional.

Note—1. Data relate to 50 banks which account for about 96 per cent of Gross bank Credit. Further, these data, besides taking into account the bills rediscounted with the RBI, include Bills rediscounted with the IDBI and other approved institutions and participation certificates.

2. Figures in brackets are proportions to non-food incremental credit.

37. Incremental credit to medium and large industry during July 1982-March 1983 amounted to Rs. 1,856 crores as against Rs. 1,172 crores during the corresponding period of the previous year. The share of large and medium industry in total incremental non-food gross credit was higher at 45.5 per cent as compared with 35.0 per cent in the corresponding period of the previous year. Larger flow to public sector units was an important reason for the rise in industrial credit. The outstanding credit to medium and large industry at the end of March 1983 at Rs. 13,048 crores constituted 38.3 per cent of total gross bank credit.

38. The distribution of industrial credit, inclusive, of small-scale industry, is given in Table 5. The major industries which accounted for the increase were iron and steel (Rs. 575 crores), the engineering group (Rs. 572 crores), cotton textiles (Rs. 142 crores) and chemicals and allied industries (Rs. 140 crores).

39. Advances to the priority sectors registered an increase of Rs. 1,543 crores during July 1982-March 1983 as compared with a rise of Rs. 1,710 crores in the corresponding period of the previous year. At the end of March 1983, priority sector advances constituted 37.0 per cent of net bank credit as against 37.7 per cent a year earlier. The decline is accounted for by the sharp rise in bank credit to the commercial sector, particularly to the public sector units from December 1982. However, all the banks have stepped up their advances to the priority sector in the past few months. Credit budget discussions held with individual banks indicate that banks will be in a position to meet the target set for them in respect of priority sector advances.

40. Of the increase of Rs. 1,543 crores in advances to the priority sectors during the period July 1982-March 1983, agriculture and small-scale industries accounted for Rs. 651 crores and Rs. 526 crores, respectively, as compared with increases of Rs. 832 crores and Rs. 495 crores, respectively, in the corresponding period of last year. Advances to agriculture at the end of March 1983 amounted to Rs. 5,239 crores and formed 42.9 per cent of total priority sector advances as against 43.2 per cent a year ago, while advances to small-scale industries at Rs. 4,447 crores accounted for 36.4 per cent of total as against 36.5 per cent a year earlier.

41. Advances to wholesale trade (other than food procurement) showed an increase of Rs. 172 crores as compared with Rs. 198 crores during the previous year. This was due to a rise in credit made available mainly to 'other trade' (Rs. 207 crores) and partly to the Cotton Corporation of India (Rs. 16 crores). Credit to the Jute Corporation of India, however, declined by Rs. 28 crores. Credit to 'Other Sectors', which represents residual sectors and includes advances to financial institutions hire purchase agencies, personal loans, etc., showed a sizeably larger increase of Rs. 507 crores during (July-March) 1982-83 compared with a rise of only Rs. 269 crores in the corresponding period of 1981-82.

TABLE 5—INDUSTRY-WISE DEPLOYMENT OF GROSS BANK CREDIT

(Rs. Crores)

ITEMS	Outstandings		Variations	Outstandings		Variations
	June 1981	March 1982	March 1982 over June 1981	June 1982@	March 1983@	March 1983 over June 1982
Industry (Total of Small, Medium and Large Scale Industries)	13,389	15,056	+1,667	15,113	17,495	+2,382
1. Coal	55	53	—2	72	59	—13
2. Iron and Steel	648	856	+208	942	1517	+575
3. Other Metals and Metal Products	462	527	+65	524	601	+77
4. All Engineering	3,266	3,817	+551	3,831	4,403	+572
5. Electricity (Generation and Transmission)	181	259	+78	227	249	+22
6. Cotton Textiles	1,174	1,281	+107	1,200	1,342	+142
7. Jute Textiles	168	187	+19	181	202	+21
8. Other Textles	723	842	+119	842	944	+102
9. Sugar	278	403	+125	527	570	+43
10. Tea	232	265	+33	272	277	+5
11. Vegetable Oils (Including Vanaspati)	188	215	+27	208	234	+26
12. Tobacco & Tobacco Products	138	133	—5	146	143	—3
13. Paper & Paper Products	298	357	+59	360	398	+38
14. Rubber & Rubber Products	264	280	+16	275	306	+31
15. Chemicals, Dyes, Paints, Drugs & Pharmaceuticals	1,529	1,672	+143	1,711	1,851	+140
Of which: Fertiliser	(299)	(329)	(+30)	(360)	(336)	—24
16. Cement	135	158	+23	157	192	+35
17. Leather & Leather Products	188	220	+32	220	262	+42
18. Construction	125	143	+18	151	192	+41
19. SAFAUNS	303	307	+4	309	327	+18
20. Petroleum	687	431	—256	299	102	—197
21. Residual	2,347	2,650	+303	2,659	3,324	+665

@Provisional

42. Sugar Buffer Stock.—An important development in regard to commodity financing was the Government's decision to create a buffer stock of 5 lakh tonnes of sugar out of the free sale quota of the production in the 1981-82 sugar year. The buffer stock is to be maintained by the sugar mills as sequestered stock on a pro-rata basis. Banks are required to finance the buffer stock in full, with a waiver of any margin requirement. There is no concession in regard to the interest charged. The Government of India would reimburse the mills the cost and interest charges incurred in holding the buffer stock. To make the scheme self-financing, the cess charged on sugar was raised from Rs. 5 to Rs. 14 per quintal with effect from November 1982. During the 1981-82 season bank credit to the sugar industry touched a peak level of Rs. 527 crores in June 1982, which was substantially higher than the previous seasonal peak of Rs. 348 crores in April 1981.

43. Reserve Bank Accommodation to Banks.—Within the basic structure of Reserve Bank accommodation policy for the scheduled commercial banks, certain modifications were made during the year in the refinance facilities. As already indicated, changes were made in respect of entitlements to refinance against food and export credit so as to enable banks to meet their commitments to these sectors without undue resources constraint. The stand-by refinance facility was also liberalised with a view to assisting banks in their resources managment. The trends in accommodation provided by the Reserve Bank during the year are discussed below :

44. Food Credit Refinance.—As on the last Friday of June 1982, banks were entitled to a food refinance limit of Rs. 347 crores, of which only Rs. 29 crores were utilised. The entitlement reached a peak level of Rs. 1,094 crores as on June 17, 1983 and the peak outstandings amounted to Rs. 389 crores on December 31, 1982. Subsequently, the outstandings declined to Rs. 113 crores against an entitlement of Rs. 1,087 crores on the last Friday of June 1983.

45. Export Credit Refinance.—The export refinance entitlement of banks as on the last Friday of June 1982 was Rs. 163 crores. Thereafter, there was a gradual decline in banks' export refinance entitlement which touched a low level of Rs. 57 crores on December 3, 1982. Since then, a gradual rise was observed and as on the last Friday of June 1983, banks were entitled to export refinance of Rs. 161 crores which was marginally lower than the entitlement of Rs. 163 crores a year ago. The utilisation of the export refinance entitlement by banks fluctuated between a low of Rs. 7 crores as on December 10, 1982 and a high of Rs. 99 crores in April 1983. As on the last Friday of June 1983, the outstandings amounted to Rs. 33 crores.

46. Stand-by Refinance.—There was no stand-by refinance outstanding as on the last Friday of June 1982. The maximum level of stand-by refinance limit sanctioned to banks during July 1982—June 1983 amounted to Rs. 24 crores in April 1983 against which Rs. 15 crores were outstanding as compared with the peak limit of Rs. 97 crores sanctioned in April 1982 against which outstandings amounted to Rs. 67 crores. As on the last Friday of June 1983, the limit sanctioned amounted to Rs. 20 crores against which no outstanding was recorded.

47. Discretionary Refinance.—The discretionary refinance limits sanctioned to banks recorded sharp decline during the year; the maximum level of limits sanctioned to banks aggregated Rs. 24 crores in 1982-83 as compared with that of Rs. 121 crores during the preceding year. The peak level of utilisation of the discretionary refinance limit was significantly low at Rs. 8 crores in 1982-83 as against Rs. 82 crores during 1981-82.

48. Overall Position.—The aggregate of limits available under various Reserve Bank refinance facilities to scheduled commercial banks (excluding special refinance against shipping loans and duty drawback) recorded a significant rise of Rs. 777 crores during the year as against an increase of Rs. 309 crores recorded last year. During 1982-83, the aggregate of various limits sanctioned to the banks attained a peak of Rs. 1,298 crores as on June 17, 1983 and thereafter marginally declined to Rs. 1,288 crores on June 24, 1983. The outstanding against these limits increased by Rs. 86 crores to Rs. 146 crores during July 1982—June 1983 as against a marginal increase of Rs. 4 crores registered in the preceding year. The peak level of outstandings against the various limits during 1982-83 totalled Rs. 457 crores in March 1983, as compared with that of Rs. 335 crores in 1981-82.

49. Government Finances.—The budget of the Government of India for 1983-84 envisages an overall deficit of Rs. 2,250 crores at 1982-83 level of taxation. However, if account is taken of the net additional revenue of Rs. 695 crores* that would accrue to the Centre as a result of its additional resources mobilisation efforts during 1983-84, the budgeted deficit would be reduced to Rs. 1,555 crores as compared with Rs. 1,935 crores in the revised estimates for 1982-83. The combined overall budgetary position of the State Governments @ shows an aggregate deficit of Rs. 969 crores for 1983-84 as compared to a deficit of Rs. 806 crores in the revised estimates for 1982-83. The budgetary deficit of the Centre as well as States for 1982-83, excludes an amount of Rs. 1,743 crores of loan assitance received by the States to clear their deficits as on March 31, 1982. States' overall deficit for 1983-84 is estimated to be reduced substantially to Rs. 553 crores as a result of States' additional resources mobilisation amounting to Rs. 315 crores as well as their share of Rs. 101 crores in Centre's additional taxation during the year.

50. Consolidated Position A Centre and States.—The combined position of the Central and State Governments' recepits and disbursements is shown in Table 6. Aggregate receipts in 1983-84 are budgeted to reach a level of Rs. 52,593 crores as compared with the budget estimates of Rs. 44,886 crores in 1982-83—a rise of 17.2 per cent as compared with 19.5 per cent in the previous year (R.E. over R.E.) £

* Excludes post-budget tax concessions announced on April 27, 1983.

@ Excludes Jammu and Kashmir and Tripura, data in respect of which are not available.

£ If the B.E. of 1983-84 is compared with the R.E. of the preceding year, the rise in total receipts works. out to 8.1 per cent and that in total expenditure, 6.4 per cent.

Similarly, if the R.E. for 1982-83 is compared to the Accounts of 1981-82, the increase in receipts would be 17.6 per cent and that in expenditure 17.4 per cent.

TABLE 6—COMBINED RECEIPTS AND DISBURSEMENTS OF THE CENTRAL AND STATE GOVERNMENTS (1981-82—1983-84)

(Rs. Crores)

Items	1981-82 (Revised Estimates)	1981-82 (Accounts)	1982-83 (Bugdet Estimates)	1982-83 (Revised Estimates)		1983-84* (Budget Estimates)	
	Amount	Amount	Amount	Amount	Percentage variation over the correspon-ing revised estimates of the previuos year	Amount	Percent-age varia-tion over the corres-ponding budget estimates of the previous year
	1	2	3	4	5	6	7
I. Total Receipts (A+B)	**40,727**	**41,360**	**44,886**	**48,660**	**+19.5**	**52,593**	**+17.2**
A. Revenue Receipts	29,702	30,033	33,641	34,488	+16.1	38,505	+14.5
Of which :							
Tax Receipts	23,741	23,962	27,717	27,376	+15.3	31,419	+13.4
B. Capital Receipts	11,025	11,327	11,245	14,172	+28.5	14,088	+25.3
II. Total Disbursements (A+B+C)	**43,065**	**43,773**	**46,278**	**51,401**	**+19.4**	**54,701**	**+18.2**
A. Developmental Expenditure							
(a+b+c)	28,292	28,333	29,552	33,802	+19.5	34,603	+17.1
(a) Revenue	16,010	16,060	17,348	19,582	+22.3	20,788	+19.8
(b) Capital	7,186	7,129	7,388	7,733	+7.6	7,820	+5.8
(c) Loans and Advances	5,096	5,144@	4,816	6,487	+27.3	5,995	+24.5
B. Non-Developmental Expenditure							
(a+b+c)	13,558	13,509	16,019	16,428	+21.2	19,316	+20.6
(a) Revenue	12,779	12,691	14,956	15,314	+19.8	18,149	+21.3
(b) Capital	522	596	786	807	+54.6	871	+10.8
(c) Loans and Advances	257	232	277	307	+19.5	296	+6.9
C. Others	1,215	1,931	707	1,171	—3.6	782	+10.6
III. Overall Surplus (+) or Deficit (—) (I—II)	**—2,338**	—2,413	**—1,392**	**—2,741**		**—2,108**	

Notes : 1. Data do not cover Union Territories with Legislatures. Data in respect of States relate to 20 States (i.e. excluding Jammu & Kashmir and Tripura). Data for Assam and Andhra Pradesh relate to vote on account budget.

2. Other disbursements comprise discharge of internl and externdl debt, compensation and assignments to local bodies and panchayatiraj institutions, appropriation to contingency funds, remittances (net) and adjusted for difference in the figures of repayment of loans by State Governments to the Central Government given in their respective budgets.

*Including effects of budget proposals and exclu les post-budget tax concessions announced on April 27, 1983 in respect of Government of India Budget.

@As the details of loans and advances given by the Assam State into developmental and non-developmental are not available, the entire amount has been treated as loans and advances for developmental purposes.

Aggregate disbursements are estimated at Rs. 54,701 crores in 1983-84 as compared with Rs. 46,278 crores in the budget estimates for the previous year—a rise of 18.2 per cent as compared with 19.4 per cent in 1982-83. The growth rate of 17.1 per cent in developmental expenditure in 1983-84 is projected to show a modest decline from the likely increase of 19.5 per cent in 1982-83. The growth in non-developmental expenditure too is expected to record a decline to 20.6 per cent as compared with 21.2 per cent in 1982-83.†

51. Market Borrowings.—As against the budget estimates of Rs. 3,200 crores, the Central Government's net market borrowings aggregated Rs. 3,800 crores in 1982-83, which were higher by Rs. 897 crores over 1981-82. The net market borrowings of the State Governments at Rs. 399 crores, on the other hand, recorded a modest rise of Rs. 63 crores as against a rise of Rs. 130 crores in the preceding year. Net borrowings by local authorities and institutions sponsored by the Central and State Governments were higher by Rs. 145 crores at Rs. 1,503 crores in 1982-83 as against a rise of Rs. 359 crores to Rs. 1,358 crores in the previous year. The details are given in table 6(a).

* If the B.E. of 1983-84 is compared with the R.E. of the preceding year, the rise in developmental expenditure works out to 2.4 per cent and that in non-developmental expenditure 17.6 per cent. Similarly, if R.E. for 1982-83 is compared to the Accounts of 1981-82, the increase in developmental expenditure would be 19.3 per cent and that in non-developmental expenditure 21.6 per cent.

TABLE 6(a)—MARKET BORROWINGS OF CENTRAL AND STATE GOVERNMENTS, LOCAL AUTHORITIES AND INSTITUTIONS SPONSORED BY CENTRAL AND STATE GOVERNMENS
1981-82 AND 1982-83

(Rs. Crores)

	Gross Market Borrowings		Repayments		Net Market Borrowings	
	1981-82	1982-83	1981-82	1982-83	1981-82	1982-83
Central Government	3,190	4,166	287	366	2,903	3,800
State Governments	506	556	170	157	336	399
Local Authorities and Institutions sponsored by Central and State Governments@	1,601	1,721	243	218	1,358	1,503
TOTAL	**5,297**	**6,443**	**700**	**741**	**4,597**	**5,702**

Note Data relate to fiscal year.

@ Institutions sponsored by the Central Government such as the Industrial Finance Corporation of India, the National Bank for Agriculture and Rural Development, the Industrial Credit and Investment Corporation of India, the Industrial Development Bank of India, the Rural Electrification Corporation, the Housing and Urban Development Corporation, the National Co-operative Development Corporation, the Industrial Reconstruction Corporation of India, the Damodar Valley Corporation and institutions sponsored by State Governments, *viz.*, State Electricity Boards, Housing Boards, Road Transport Corporations, Industrial Investment Corporations, Industrial Development Corporation, State Finance Corportions, Municipalities, State Land Development Banks and other institutions.

52. The Central Government approached the market six times during the year and also sold securities to the Reserve Bank once for subsequent release to invstors.

53. Gross borrowings of State Governments during 1982-83 amounted to Rs. 556 crores, of which Rs. 490 crores were on a cash basis and Rs. 66 crores by way of conversion of maturing loans. Taking into account the repayment of matured loans of Rs. 157 crores, the States' net market borrowings mounted to Rs. 399 crores. Aggregate net market borrowings (Central plus States) as a proportion of the gross domestic product (at current market prices) moved up slightly from 2.20 per cent in 981-82 to 2.72 per cent in 1982-83.

54. Central Loans—1983-84.—For 1983-84, the Central Government has budgeted for net market borrowings of Rs. 4,000 crores. The Central Government entered the market on May 30, 1983 with its rst tranche of borrowing and offered 10 per cent oan 2014 for an aggregate amount of Rs. 500 crores ntirely on a cash basis, subscription to which mounted to Rs. 550 crores, with all the subscribers etting full allotment. The Central Government approached the market for the second time on July 15, 983 with the floatation of two loans viz., 7.75 per ent loan, 1991 and 10 per cent loan, 2014 (Second sue) on a cash-cum-conversion basis and raised an regate amount of Rs. 825 crores, of which s. 602 crores were in cash and the rest by way of ersion. With these two tranches, the Central overnment raised from the market a net amount of s. 1,031 crores accounting for 25.8 per cent of the tal budgeted market borrowings (net) for 1983-84.

55. Reserve Bank's Support to Central Loans.—significant feature of Government finance is the owth in the Central Government's borrowing proamme and the extent of support required from the Reserve Bank. The Annual Report for 1980-81 drew attention to the emergence of a structural imbalance in the finances of the Government of India, as seen in the deficits in the revenue account, the consequent increasing resort to market borrowings and the rising share of the Reserve Bank in Government loans arising from the lack of adequate absorptive capacity in the market. The data for the past two years show some improvement in this regard. While the feature of a deficit in the revenue account has persisted, the overall deficit as a proportion to total receipts has declined from 11.6 per cent in 1980-81 (accounts) to 4.6 per cent in 1983-84 (B.E.). The proportion of gross market loans to total recepits has not shown much change, but the proportion that the increase in the Reserve Bank's holdings of dated securities bears to Government borrowing each year has declined from the abnormally high level of 43.1 per cent in 1980-81 (accounts) to 38.6 per cent in 1981-82 (accounts) and further to 25 per cent in 1982-83 (R.E.) (Table 7). Though the trend is in the downward direction, the support by the Reserve Bank is still high. It is relevant to recall that this proportion was only 1.6 per cent as recently as in 1978-79 and even in 1979-80, it was relatively low at 18.1 per cent. However, to some extent, a rise in the Reserve Bank's support is a reflection of the use by the Government of the Extended Fund Facilities provided by the I.M.F.

56. 3-Year National Rural Development Bonds.—At present, an assessee can avail of exemption of long term capital gains from taxation where the net consideration received on transfer of any long-term capital asset is invested in the 7-Year National Rural Development Bonds. As this maturity period of 7 years was considered to be rather long, the Government decided to introduce a new 3-Year National Rural Development Bonds (Second Issue) which will be on tap from July 7, 1983 and carry an interest rate of 7.5 per cent per annum. Investment of the net consideration in respect of long-term capital

gains arising after February 28, 1983, in these bonds will entitle the investor to avail of the exemption from capital gains tax.

57. 7-Year National Rural Devlopment Bonds.—The 7-Year National Rural Development Bonds introduced on July 9, 1979 continued to be on tap during the year. The total subscription to these bonds since inception amounted to Rs. 178.40 crores as on June 30, 1983.

58. Social Security Certificates.—Social Security Certificates, introduced on June 1, 1982, collected subscriptions to the extent of Rs. 11.96 crores as at end-April 1983.

TABLE 7—BUDGETARY DEFICIT, MARKET LOANS AND RBI'S SUPPORT TO MARKET LOANS OF THE CENTRAL GOVERNMENT

(1980-81 To 1983-84)

(Rs. Crores)

Items	1980-81 (Accounts)	1981-82 (Accounts)	1982-83 (Budget Estimates)	1982-83 (Revised Estimates)	1983-84(*a*) (Budget Estimates)
1. Revenue Account					
(a) Revenue	12,828.6	15,574.2	17,595.3	18,117.0	20,625.4
(c) Surplus (+)/Deficit (—)	—1,715.0	—293.5	—632.0	—1,293.0	—1,793.5
2. Capital Account					
(a) Receipts	9,432.3(*b*)(*c*)	10,155.7—	11,068.2	13,253.3	13,451.5
(b) Disbursements	10,294.6(*c*)	11,254.1	11,810.8	13,890.2(*d*)	13,212.7
(c) Surplus (+)/Deficit(—)	—862.3	—1,098.4	—742.6	—636.9	—238.8
3. Total Receipts [1(a)—2(a)]	**22,260.9**	**25,729.9**	**28,663.5**	**31,663.5**	**34,076.9**
4. Overall Surplus (+)/Deficit(—)	—2,577.3	—1,391.9	—1,374.6	—1,934.9	—1,544.7
5. (4) as per cent of (3)	11.6	5.4	4.8	6.2	4.6
6. Gross Market Loans	2,848.5	e3,198.3	3,566.0	e4,166.0	4,344.0
7. (6) as per cent of (3)	12.8	12.4	12.4	13.3	12.7
8. RBI's holdings of Dated Securities (Increases)*	1,299	1,236	1,041	1,041	..
9. (8) as per cent of (6)	43.1	38.6	29.2	25.0	

Data relate to Fiscal Years.

(*a*) Includes effects of budget proposals and excludes post-budget tax concessions announced on April 27, 1983.

(*b*) Includes accounting adjustments relating to the write-off of Rs. 938.3 crores of loans advanced to State Governments prior to 1979-80 in pursuance of the recommendations of the Seventh Finance Commission.

(*c*) Includes notional receipt/expenditure of Rs. 588.2 crores on account of the subscription to I.M.F. in the form of securities and Special Drawing Rights.

(*d*) Excludes Rs. 1,743.4 crores of loans to State Governments to clear their deficits as on 31st March 1982.

* On book value basis.

(*e*) Excludes special securities of Rs. 3,500 crores issued in favour of Reserve Bank of India in lieu of *ad hoc* treasury bills funded.

59. Capital Investment Bond.— Subscriptions to Capital Investment Bonds since their issue on June 28, 1982 amounted to Rs. 88.93 crores as on June 30, 1983 as against the original estimates of Rs. 250 crores for 1982-83, revised subsequently downward to Rs. 170 crores. For 1983-84, the budget estimates a subscription of Rs. 200 crores.

60. Ways and Means Advances and Overdrafts.—Mention was made in last year's Report about the package of measures evolved by the Centre to help the States to clear their outstanding overdrafts with the Reserve Bank at the close of March 1982. 18 States were granted medium term loans totalling Rs. 1,743.46 crores to clear their closing deficts at the end of 1981-82. Deficits incurred during the first quarter of 1982-83 were also cleared though additional short-term assistance of Rs. 787 crores. Also, the ways and means limits enjoyed by the State Governments with the Reserve Bank were doubled effective July 1, 1982, Despite these efforts, overdrafts remerged even in July 1982. As on March 25, 1983, 11 State governments had overdrafts totalling Rs. 212.27 crores as compared to Rs. 1,450.88 crores by 18 States as on March 26, 1982. The position subsequently deteriorated in regard to the magnitude of overdrafts, the number of States having overdrafts as well as the number of days for which overdrafts remained outstanding. As on June 24, 1983, 11 out of 20 States keeping accounts with the Reserve Bank had overdrafts totalling Rs. 579.22 crores. The overdrafts were cleared by the concerned State Governments with the help of assistance released by the Central Government and there were no outstanding overdrafts as at the end of June 1983. The continued existence of large overdrafts, even after doubling the State entitlement of ways and means advances, points to the unhappy position of States' finances.

61. Developments in Capital Market.— The private corporate sector continued to make concerted efforts at mobilising funds directly from the market. Provisional data of capital raised through equity and preference shares and debentures during 1982-83 (April-March) at Rs. 705.30 crores show an increase of 33.2 per cent over Rs. 529.36 crores mobilised in 1981-82. As in the previous year, during 1982-83 also, the prominence of debentures continued, and as against 52.6 per cent in 1981-82, the share of debentures in capital raised during 1982-83 was 63.3 per cent. The data show that companies have resorted to issues of non-convertible debentures in an increase way, despite the public preference for convertible debentures. In the total debentures raised during the financial year 1982-83, the share of non-convertible debentures increased to 36.5 per cent from 22.6 per cent in 1981-82. Besides the hike in interest ceiling and provision for premium on redemption allowed since April 1982, the Government adopted some more measures to encourage issues of non-convertible debentures. With a view to providing liquidity to investment in non-convertible debentures, on the recommendation of the Working Group on Secondary Market for Debentures appointed by the Reserve Bank, companies issuing such debentures have been allowed to have a buy-back arrangement. Under this scheme, companies can buy back non-convertible debentures at par from any debenture holder whose holding does not exceeed Rs. 40,000 and who has held the debentures for a period of at least one year. Companies in turn can place these debentures with GIC, LIC and UTI, the participating institutions in the scheme. The institutions would purchase these debentures at a discount of 2½ per cent which would be levied as a commitment charge. The withdrawal of the restriction on public financial Institutions to subscribe or underwrite debenture issues of FERA/MRTP companies has also helped issues of debentures. The financial institutions have been permitted by the Government to underwrite/subscribe, amongst themselves, upto 50 per cent of any debenture issue made by FERA/MRTP companies.

62. Assistance by Financial Institutions.— Total assistance sanctioned and disbursed by the all-India financial institutions (viz; IDBI, IFCI, ICICI, IRCI, LIC, UTI and GIC and their subsidiaries) during 1982-83 (April-March) aggregated Rs. 3,053.3 crores and Rs. 2,193.3 crores, respectively. This represented a growth of 22.3 per cent in respect of sanctions as against 19.8 per cent in 1981-82. The rate of growth in disbursement was 18.2 per cent as against 28.8 per cent in the previous year.

63. Investment by Non-residents.— Another important development bearing on the capital market was the further simplification of procedures relating to investment by non-residents of Indian nationality/origin (including overseas companies, partnership firms, societies, and other corporate bodies owned to the extent of at least 60 per cent by non-residents of Indian nationality/origin, as well as overseas trusts in which at least 60 per cent of the beneficial interest is irrevocably held by such persons) and repatriation of sale proceeds of such investments. The tax incentives in respect of non-resident Indian citizens and foreign national of Indian origin have also been further liberalised. The incomes derived by the non-resident Indian investors from their investments, including shares and debentures of Indian companies made through foreign exchange remittances, now attract a flat rate of tax of 20 per cent plus surcharge. Long-term capital gains arising on transfer of such investments would also attract tax at the same flat rate. Besides, such investment would also be exempt from wealth tax and gifts of these assets made by Indian citizens and persons of Indian origin settled abroad to their relatives in India would also be exempt from gift-tax. More recently, Government imposed a ceiling of five per cent of paid up value of shares and convertible debentures on the aggregate portfolio investment by non-residents in a company. For exceeding the five per cent ceiling, the permission of the Reserve Bank would be required.

64. Forign Trade.— The significance of foreign trade in the Indian economy has been rising. The proportion that total foreign trade bears to NNP at current market prices has increased from 8.4 per cent in 1970-71 to 15.7 per cent in 1982-83. The current world economic situation continued to be unfavourable to trade prospects. The real gross national product of industrial countries showed a slight decline in 1982, after the marginal increases recorded in both 1980 and 1981. The volume of world trade, which had stagnated in 1981, declined in 1982 by over 2 per cent taking the level of world trade to that obtaining in 1979. The principal reasons for the decline in world trade were the global recession and the intensification of protectionist measures in many industrial countries. Despite these developments, there was some improvement in the position relating to the balance of trade of the country as suggested by the available provisional data relating to foreign trade. In the period April-March 1982-83, exports totalled Rs. 8,638 crores and imports Rs. 14,047 crores, resulting in an adverse trade balance of Rs. 5,409 crores which is noticeably lower than the deficit of Rs. 5,752 crores (provisional) in 1981-82. However, the composition of the exports would indicate that the increase in exports was largely on account of the export of crude oil.

65. Invisibles.—The available information suggests that during the financial year 1982-83, the surplus in the net invisibles account may be at around the same level as in the previous year. Investment income on the Bank's foreign currency assets was about one-fifth lower than that in the previous year. Interest payments on increased commercial borrowings and IMF drawings, on the other hand, rose. Private transfer receipts might not have been as much affected in 1982-83, as was earlier presumed. On the whole, the current account deficit during the year might not have been materially different than in the preceding fiscal year.

66. External Assistance.—The increasing trend in gross external assistance evidenced since 1979-80 appears to have continued during 1982-83 (April-March). Gross aid during 1982-83, is provisionally placed at Rs. 2,145 crores, indicating a rise of Rs. 177 crores over that in 1981-82. Debt service payments also increased to Rs. 953 crores in 1982-83 from Rs. 915 crores

(Revised) in 1981-82. As a result, the net inflow of external assistance in 1982-83 is expected to be at Rs. 1,192 crores, which is higher by Rs. 139 crores than Rs. 1,053 crores (Revised) in 1981-82. During the fiscal year 1982-83, India had drawn Rs. 1,893 crores from the IMF under its Extended Fund Facility (EFF). Such drawals had amounted only to Rs. 637 crores during 1981-82.

67. Foreign Currency Assets.—During 1982-83 (July-June), foreign currency assets of the Reserve Bank of India recorded an increase of Rs. 1,531 crores to Rs. 4,805 crores.

68. During 1982-83 (July-June), India had benefited from drawals from the Fund under the EFF to the extend of Rs. 1,908 crores. If these receipts are excluded, foreign currency assets of the Bank would show a decline of Rs. 377 crores. The fall in foreign currency assets during this year was less than one-fifth of the decline of Rs. 2,001 crores during 1981-82 excluding the IMF drawals (of Rs. 948 crores).

69. Special Drawing Rights.—Holding of Special Drawing Rights (SDRs) declined during 1982-83 by SDR 179 million to SDR 220 million as against a decline of SDR 82 million in 1981-82. The sharp fall in SDR holdings during the year under review was mainly due to the use of SDRs for the payment of charges (net of interest earned on SDR holdings, and remuneration received from the Fund) amounting to SDR 174 million on various drawals from the Fund and due to sales of SDR 4.5 million to two countries. In 1981-82, SDR 34 million were utilised for repayment of the earlier Fund obligations and SDR 48 million were used for payment of charges (again net of interest on SDR holdings and remuneration received from the Fund).

70. Gold.—Gold holdings of the Reserve Bank remained unchanged at Rs. 226 crores (valued at the statutory holding price of Rs. 84.39 per 10 grammes). There were no changes in the gold holdings in the previous year as well.

71. Movements in FCNR and NRE Accounts.—A factor of importance influencing the improvement in foreign exchange reserves is the growth in deposits under the Foreign Currency Non-Resident Account (FCNR) Scheme and the Non-Resident External Rupee Account (NRE) Scheme. With effect from March 1, 1982, term deposits of one year and above under these two schemes were allowed rates of interest two percentage points higher than the rates permissible on domestic deposits of comparable maturities. With the decline in deposit rates abroad, this interest differential has proved effective. Outstanding FCNR deposits increased by Rs. 2,31 crores during the year 1982-83 as against a decline of Rs. 13 crores in 1981-82. The corresponding movements in the NRE accounts were an increase of Rs. 435 crores in the year 1982-83 as against Rs.265 crores in the previous year.

72. International Monetary Relations.—The strains in the world economy,which affected non-oil developing countries with particular severity, persisted during the year. The recovery in industrial countries is still not pronounced and the policies pursued by them are not conducive to the promotion of international economic co-operation For any improvement in the situation, and for the alleviation of the special difficulties of the poorer countries, greater efforts are obviously needed on the part of international financial institutions. The IMF, in particular, would have to play a central role in the provision of adequate finance to support the balance of payments of developing countries and assist them in the process of adjustment.The case for the provision of unconditional resources through a renewed allocation of SDRs has become even stronger as a result of a slow-down ingrowth in international reserves. While the recent agreement to increase the Fund's quotas is welcome, it still falls short of the resources needed for the Fund to play an effective role in supporting members' requirements. Further, the suggestion of abridging "access limits," or the limits upto which members can obtain assistance under the Fund's various facilities, would dilute the effectiveness of any increase in quotas. Also, since the access to the Fund's resources is determined by conditionality, this has to be imposed with flexibility if developing countries are to benefit from borrowings from the Fund.

73. Exchange Rate Movement.—The movements in the international foreign exchange markets during the year were characterised by long swings and a high degree of day-to day volatility. For example, it has been calculated that in 1982,volatility in the Yen/Dollar spot rate, measured as the average absolute value of day-to-day percentage changes, was above 0.6 per cent which was the highest in any year since the transition to floating rates in 1973. Apart from volatility, to other prominent feature of exchange rate movements was the continued strength of the U.S. dollar despite deterioration in the current account balance of the United States. The Pound sterling, which depreciated considerably in the latter half of 1982 and early 1983 primarily because of the decline in oil prices, somewhat improved after March 1983.

74. Changes in the Exchange Rate of the Rupee.—The exchange value of the rupee continued to be determined in relation to a basket of currencies with the pound sterling as the intervention currency. The exchange rate of the rupee underwent 113 changes during the year. The value of the rupee appreciated, in terms of the pound sterling, by 6.8 per cent over the year, following a decline in the middle rate of the rupee per pound sterling from Rs. 16.50 at the end of June 1982 to Rs. 15.45 at the end of June 1983. The maximum appreciation in the exchange rate of the rupee to the pound ever since the rupee was linked to a basket of currencies in September 1975 occurred during the year when the middle rate appreciated to Rs. 14.65 on March 24, 1983. The rupee appreciated also against the French Franc (5.7 per cent), the Belgian Franc (2.6 per cent) and the Italian Lira (2.9 per cent), however, it depreciated against certain other currencies like the U.S. Dollar (5.7 per cent), the Deutsche Mark (2.5 per cent) and the Japanese Yen (11.5 per cent). The rupee—SDR rate also depreciated by 3.9 per cent.

75. Price Situation.—The behaviour of prices during the greater part of the year under review appears relatively stable in the background of the decline in agricultural output, slackening in industrial growth and a more rapid monetary expansion. On a point-to-point basis, the rise in the "all-commodities' index of wholesale prices was 7.0 per cent between end-June

1982 and end-June 1983, as compared with an increase of 2.5 per cent in 1981-82. However, seen on a weekly average basis, the rise in 1982-83 at 4.2 per cent was lower than that of 5.8 per cent in 1981-82.

76. All the three major groups in the index viz., primary articles, fuel, power, light and lubricants and manufactured products recorded increases during the period as shown in the table below :

EXTENT OF PRICE RISE AND WEIGHTED CONTRIBUTION OF MAJOR COMMODITIES GROUPS IN WHOLESALE PRICE INDEX

(1970-71=100)

	Weight	Variation in per cent		Weighted Contribution (Approximate)	
		End-June 1982 over End-June 1981	End-June 1983-over End-June 1982	1981-82	1982-83
Commodities	1000.00	+ 2.5	+ 7.0	+ 100.0	+ 100.0
Primary Articles	416.67	+ 4.8	+ 8.9	+ 74.0	+ 50.1
Fuel, Power, Light and Lubricants	84.59	+ 11.7	+ 6.5	+ 56.0	+ 12.2
Manufactured Products	498.74	+ 1.6	+ 5.6	+ 30.0	+ 37.7

77. The highest increase was recorded by the primary articles group which contributed 50 per cent to the overall increase in the index. The weighted contribution of the manufactured products group at 38 per cent, was also substantial. Among primary articles, the rise of 16.3 per cent in the index for cereals is particularly significant. Among manufactured products, the sugar group showed a small increase in comparison with the substantial fall registered in the previous year. Edible oils rose sharply as against a decline in the previous year. Other manufactured products which recorded increases in 1982-83 as well as in 1981-82 include textiles, paper and paper products, cement, chemicals and chemical products basic metals alloys and metal products and machinery and transport equipment (vide Table 8).

78. Three distinct phases are discernable in the movement of the whole-sale price index during 1982-83. In the first eight weeks of this period (upto August 21), prices showed a fairly sharp uptrend, with the 'all-commodities' index recording an increase of 2.5 per cent. Cereals and pulses exerted a strong influence in this rise, along with some other components of primary commodities, such as milk and milk products, and eggs, fish and meat. Among manufactured products two food products sub-groups, sugar, khandsari and gur and edible oils registered increases. In the next phase of 17 weeks (upto December 18), the index declined by 2.7 per cent which was almost the same as the rise in the previous phase, the commodities that exerted pressure in the former period declined in price; however, the decline in the case of cereals was only marginal. The sugar group and fruits and vegetables were the major influences in the decline

79. At the end of December 1982, the wholesale price index was almost exactly at the same level as six months earlier, at the end of June. From then, until the end of June 1983, the index registered an increase of 7.3 per cent. In this phase, while fruits and vegetables and the sugar group, which may be considered as seasonal influences, contributed most to the price rise, the index also rose in respect of cereals, pulses and edible oils, commodities which would have a long-term impact on the general price level. It is this feature that is of significance in the immediate outlook for prices.

80. Changes in Administered Prices.—Changes effected in the administered prices of various commodities contributed to the price rise during the year. Among primary commodities, the procurement prices of paddy and wheat were raised by Rs. 7 and Rs. 9 per quintal, respectively. The purchase price of coarse grains was also raised by Rs. 2 per quintal and a purchase price of Rs. 235 per quintal was announced for gram. Following the enhancement in procurement price, the issue prices of common, fine and superfine varieties of rice were raised uniformly by Rs. 13 per quintal with effect from October 1, 1982. In the case of wheat, the increase in the issue price which took effect from April 15, 1983 raised the price for the issue through the public distribution system by Rs. 12 and that for roller flour mills by Rs. 23 per quintal. It may be noted that the increases in issue prices of foodgrains have been higher than those in procurement prices. This may bring the former closer to prevailing market price which can have some dampening effect on the offtake from the public distribu-

TABLE 8—INDEX NUMBERS OF WHOLESALE PRICES (BASE : 1970-71 = 100).

Major Groups/Groups/Sub-Groups/Commodities	Weights	End-June 1981	End-June 1982	End-June 1983*	Percentage change 1981-82 (3 over 2)	Percentage change 1982-83 (4 over 3)
	1	2	3	4	5	6
ALL COMMODITIES	**1000**	**280.7**	**287.8**	**308.0**	**+2.5**	**+7.0**
I. PRIMARY ARTICLES	**417**	**260.9**	**273.5**	**297.8**	**+4.8**	**+8.9**
1. Food Articles	298	229.6	250.4	279.2	+9.1	+11.5
Foodgrains (a+b)	129	234.1	236.5	269.0	+1.0	+13.7
(a) Cereals	107	212.7	223.6	260.1	+5.1	+16.3
(i) Rice	51	220.8	243.2	296.6	+10.1	+22.0
(ii) Wheat	34	184.8	191.3	210.0	+3.5	+9.8
(b) Pulses	22	339.9	300.2	313.3	—11.7	+4.4
(c) Fruits and Vegetables	61	238.1	275.1	305.8	+15.5	+11.2
(d) Milk and Milk Products	62	202.3	230.5	238.3	+13.9	+3.4
(e) Other Food Articles	16	244.0	261.5	384.9	+7.2	+47.2
Tea	11	263.7	282.4	446.7	+7.2	+58.2
2. Non-Food Articles	106	241.1	239.7	268.6	—0.6	+12.1
Fibres	32	218.1	206.3	224.9	—5.4	+9.0
Raw Cotton	22	234.2	209.2	219.5	—10.7	—1.7
Oilseeds	42	263.4	246.6	279.6	—6.4	+13.4
3. Minerals	13	1175.7	1112.8	989.3	—5.4	—11.1
Petroleum Crude and Natural	6	2162.3	2006.4	1739.5	—7.2	—13.3
II. FUEL, POWER, LIGHT AND LUBRICANTS	**84**	**401.0**	**447.9**	**477.1**	**—11.7**	**+6.5**
Coal	10	432.1	502.3	512.7	+16.2	+2.1
Mineral Oils	49	468.0	513.9	534.7	+9.8	+4.0
III. MANUFACTURED PRODUCTS	**499**	**276.8**	**272.5**	**287.8**	**—1.6**	**+5.6**
1. Food Products	133	336.4	270.7	288.5	—19.6	+6.6
(a) Sugar, Khandsari and Gur	72	403.5	283.4	293.0	—29.8	+3.4
Sugar	22	276.5	238.5	233.8	—13.3	—2.0
Gur	46	462.3	306.2	323.4	—33.8	+5.6
(b) Miscellaneous Food Products	49	261.7	256.8	284.8	—1.9	+10.9
Edible Oils	37	262.8	259.0	285.4	—1.4	+10.2
2. Textiles	110	223.2	229.6	241.6	+2.9	+5.2
3. Paper and Paper Products	9	270.9	302.4	314.6	+11.6	+4.0
4. Cement	7	231.7	357.2	399.7	+54.2	+11.9
5. Chemicals and Chemical Products	56	254.7	265.6	277.7	+4.2	+4.6
6. Basic Metals, Alloys and Metal Products	60	305.7	349.2	375.4	+14.2	+7.5
7. Machinery and Transport Equipment	67	259.0	275.5	288.3	+6.4	+4.6

*Provisional.

tion system. The support prices of some major oilseeds were also raised, increase in respect of groundnut-in-shell being Rs. 25 per quintal. A support price of Rs. 355 per quintal for mustard seed was announced after a gap of three years.

81. The selling prices of various petroleum products (other than petrol) were raised in February 1983. Among manufactured products, the Joint Plant Committee revised upwards the prices of pig iron and other steel items in October 1982. The price of pig iron was raised by Rs. 100 per tonne, plates and chequered plates by Rs. 250 per tonne, structurals by Rs. 100 per tonne, wheels by Rs. 800 per tonne and angles by Rs. 1,000 per tonne. Consequent on the increase and adjustment in railway freight rates, the Joint Plant Committee increased the price of pig iron by Rs. 105 per tonne and steel items by Rs. 160 per tonne with effect from April 1, 1983. The issue price of levy sugar was raised by 10 paise per kg. in December 1982. The administered price of white printing paper was raised by Rs. 1,200 per tonne in April 1983. Government reduced the prices of all types of fertilisers by 7.5 per cent effective June 29, 1983. The increase in the freight rates effected in the Railway budget for 1983-84 are applicable to a variety of commodities and range from 1 paise to 3.6 paise per tonne km. The non-agricultural commodities, the administered prices of which have been raised during the year have a total weight of about 8 per cent in the wholesale price index. Since these are mainly intermediate pro-

ducts there would be a further impact on the prices of manufactured products.

82. Consumer Price Index.—The All-India Consumer Price Index for Industrial Workers (1960=100) rose sharply by 13.4 per cent in 1982-83 (July-June) as against a smaller increase of 7.1 per cent in the year 1981-82. The average increase, however, was lower at 9.0 per cent in 1982-83 as against 10.8 per cent in the previous year. As was discussed in last year's Report, the difference in the nature and the composition of the wholesale price index and the consumer price index provides an explanation for the disparities in their movements in the short run. Over a longer time period, however, there is a closer correspondence in the movements.

ASSESSMENT AND PROSPECTS

83. The combination of a decline in agricultural production with a deceleration in industrial growth had a serious impact on national income, with real national income showing only a small rise in 1982-83. It is a reflection of the increased resilience of the economy and of the effectiveness of supply and demand management policies that there was relative stability in prices during the year. The orderly management of both the price situation and the country's external payments in face of a severe drought and deteriorating external environment for aid and trade is indeed a very encouraging feature of the economic performance during 1982-83.

84. The economic outlook for 1983-84 is one of distinct improvement in agriculture. Industrial production can also be expected to show better growth, with an improvement in demand consequent on increase in agricultural production and with some of the short-run features, such as the mis-matching of supply and demand, working themselves out. However, care has to be taken to ensure that inadequacy of infrastructure does not emerge as a constraint on output. All in all, 1983-84 promises to be a year of substantial improvement. At the same time, careful watch will have to be maintained on the price front. To the extent that the pressure on prices witnessed in recent months represents operation of seasonal factors, a favourable monsoon will no doubt help in the build-up of supplies and also curb inflationary expectations. However, the negative influence on the general price level that came from the sugar group in the past year is unlikely to continue. The impact of the earlier increases in the prices of petroleum products, steel and coal to bring about a further rise in costs and prices of manufactures has also to be kept in view.

85. While the outlook for the immediate future is encouraging, some issues arising from the medium-term prospects for the economy that have a bearing on policy formulation need to be stressed.

86. The first of these is related to agriculture. Concern has been voiced recently on the slow growth in agricultural production and the view expressed that a plateau has been reached particularly with respect to the output of foodgrains. In this context, it is pointed out that the maximum output of foodgrains achieved so far is 133 million tonnes in 1981-82, which is only about 1 million tonnes higher than the former peak reached three years earlier in 1978-79. While this is true, it has to be taken into account that the weather has not been truly favourable after 1978-79, which is considered the best monsoon year of the century. A severe drought followed in 1979-80, while the overall weather conditions in the two succeeding years may at best be described as "not unfavourable." The drought of 1982-83 is considered as even worse than that of 1979-80. Thus, there has been no truly good year from the point of view of weather in the past four years. It is also appropriate to note here that such phases of stagnation in food output are not uncommon. For example, after reaching a peak of 108.4 million tonnes in 1970-71, output remained more or less depressed, moving in the range of 97 to 105 million tonnes till 1974-75. Output then jumped to a new peak in the following year. There have been similar examples of stagnation followed by a sharp jump in the fifties and sixties. Foodgrains production seems to be moving up more or less in a stepwise fashion. A critical analysis of the data on foodgrains output for the 1970s, both in the aggregate and crop-wise, does not indicate any deceleration in the rate of growth. All the same, the rate of growth of 2.50 per cent per annum achieved in the last decade is only marginally higher than the increase in population, leaving the per capita availability of foodgrains almost unchanged. It has been clear for some time that agriculture needs a fresh impetus to develop and extend technology to new crops and new areas. A fuller utilisation of the irrigation potential already created, research on drought resistance varieties of seeds, development of dry farming and more effective extension work to reach the small farmers are some of the urgent requirements.

87. Even though the balance of payments position may be under control and manageable in the next few years, careful planning will be necessary to ensure continued viability of the country's external payments. The burden of servicing and repaying substantial foreign debt incurred in the recent past will increase considerably in the latter half of the eighties. We have also to reckon with uncertainties about the future flow of remittances on private account in the context of changes in oil prices. The outlook for external aid is also not encouraging. To cope with such a situation, the trade deficit will have to be considerably narrowed to begin with. The logic of the situation requires renewed emphasis on export promotion and import substitution. Export promotion especially in the prevailing inhospitable international climate requires, above all, reduction in cost and improvement in quality. With respect to imports, the most encouraging feature relates to crude oil. There has been a significant increase in domestic production thus reducing imports as percentage of total availability. Nevertheless, there is need to reduce our dependence on imported sources of energy by reducing the current rate of growth in energy consumption. Besides crude oil, there are other commodities in respect of which dependence on imports has been increasing sharply, as for instance, vegetable oils. Utmost emphasis has to be laid on increasing the production of foodgrains so that the

country does not have to depend on imports to feed its growing population. Thus a faster rate of growth in agriculture becomes a necessity from the point of view of narrowing the deficits in the balance of payments as well.

88. Another concern that may be of relevance not only for the immediate future but also over the next several years, relates to inflation and its control. It is now well recognised that inflation is a phenomenon that is hardly conducive to economic growth The option of "living with" inflation is no longer seen as an option. Also, control of inflation becomes a necessity if viability of our balance of payments and in particular, the competitiveness of our exports is to be maintained. Hence, the relevant question now is that of the appropriate dimensions of anti-inflationary policy. Regardless of the nature of the inflation, whether it is primarily demand-induced or whether cost push factors are more significant, an important element of policy is the control of monetary expansion. If the goal that is sought to be achieved is one of price stability, obviously, the rate of growth of money and credit over any period of time cannot be far out of line with the increase in real output. However, as a matter of practical policy, a view can be taken on the desirable degree of overall expansion taking into account not only the growth in real output but also some acceptable degree of increase in price level. Since the process of money creation is also a process of credit creation, it is not enough to determine by how much money supply can increase; it is equally necessary to determine how the credit will be allocated among the different users. Therefore, once a view on the desirable expansion is taken, the users of credit both in the Government and in the commercial sectors would have to be subject to the inescapable discipline of minimising the increase of credit and maintaining total expansion within the limits set. It is only under such conditions that money supply becomes an aggregate truly under the control of the monetary authority.

89. This is, however, not to imply that in all situations of increases in prices the remedy is one of monetary regulation alone. In seeking to control prices, the impact of such fundamental factors as productivity cannot be ignored. Monetary control may not be the appropriate policy instrument to use if the price increases emanate from rising unit cost of production. Under such condition, long-term policy must focus on improving the efficiency in the use of inputs. In the Indian situation, increasing output under conditions of constant cost would require stepping up the savings rate and improving the efficiency in the use of capital. Even if the investment rate is to be maintained at the existing level, a rise in the domestic savings rate becomes necessary to compensate for the decline in the foreign savings, which is part of process of structural adjustment required to narrow the balance of payments gap. A rise in the savings rate will again be of no avail if it is not accompanied by an efficient use of capital.

90. For the immediate future, credit policy, while taking note of the need to keep in check the tendency for price increase, must aim at supporting the increase in production that is likely to occur in the agricultural and industrial sectors. In modulating the growth of credit and money to meet the changing conditions, the objective should be to regulate the quantum of liquidity in the system so as to keep inflationary expectations under control, while facilitating the full realisation of the productive potential of the economy.

PART II—BANKING AND OTHER DEVELOPMENTS

91. The major monetary and credit policy developments during the year were covered in the earlier part. This part of the Report deals with the other important developments no only in the banking and monetary spheres but also in the various areas of the Reserve Bank's work. The balance sheet and accounts of the Bank for the year 1982-83 (July-June) are presented at the end.

DEVELOPMENTS IN BANKING

92. Branch Expansion Policy for 1982-83.—The main thrust of the branch licensing policy formulated by the Bank for the three-year period April 1982 to March 1985, referred to in the last year's Report, continues to be on improving banking facilities in rural and semi-urban areas and reducing inter-regional disparities in the spread of such facilities. The policy aims at achieving a coverage of one bank office, on an average, for population of 17,000 in rural and semi-urban areas on the basis of 1981 census. The State governments were asked to identify the unbanked centres in rural areas where the new bank offices could be located. Based on the recommendations of the concerned State governments, the branch expansion programmes for rural areas of 18 States and 5 Union Territories have been finalised. In respect of the remaining States|Union Territories, the programme is at various stages of finalisation. On the basis of the suggestions of State governments regarding the centres in rural areas identified for opening new bank offices, 5,100 centres have so far been allotted to banks. As at the end of April 1983, banks were holding authorisations|licences for opening offices at 5,946 centres.

93. During the period July 1982 to April 1983, commercial banks opened 2,278 offices as against 3,115 offices in the corresponding period of the previous year. Of these, 363 offices were opened by the State Bank of India and its associate banks, 750 by nationalised banks and 99 by private sector banks. The regional rural banks opened 1,066 offices. Unbanked centres accounted for 1,720 offices or 75.5 per cent of the total number of new branches. The average population per bank office came down to 17,000 as at the end of April 1983 from 18,000 at the end of June 1982. The average for June 1969 was as high as 65,000. The proportion of bank offices in rural areas to the total, which was 52.0 per cent as at the end of June 1982, increased to 53.5 per cent at the end of April 1983; in June 1969, the percentage was 22.1.

94. During the year under review, only one branch of an Indian bank was opened abroad, that of Indian Overseas Bank in Sri Lanka. As at the end of June 1983, 12 Indian commercial banks had 138 branches in 25 countries, excluding 17 non-functioning offices in Pakistan and 22 in Bangladesh.

95. The State Bank of India opened a representative office each at Moscow (USSR) and Milan (Italy) during the year. Its representative

offices at Toronto (Canada) and Lagos (Nigeria) were closed consequent on the setting up of a subsidiary bank at Toronto (Canada) and a joint venture merchant bank in Nigeria during the year. The bank's representative office at Dar-es-salaam (Tanzania) was also closed during the year. With these closures, the number of representative offices of Indian banks abroad declined to 12.

96. The State Bank of India established two wholly-owned subsidiary banks, viz., State Bank of India (California) Ltd. at Los Angeles in U.S.A. and State Bank of India (Canada) Ltd. in Canada. It also took 40 percent equity participation in a joint venture merchant bank at Lagos (Nigeria) are entered into a management contract with it.

97. One foreign bank, viz., Bank of Credit and Commerce International (Overseas) Ltd., Cayman Islands, opened its first branch at Bombay by upgrading its existing representative office in India, raising the number of foreign banks operating in India to 17; the total number of branches of foreign banks as at the end of June 1983 was 131. Licences have also been issued to Oman Arab African Bank (Oman) and Bank of Nova Scotia (Canada) to commence banking business in India, the latterby upgrading its existing representative office. The Bank for Foreign Trade of the USSR opened its representative office in Bombay. As at the end of June 1983, 14 foreign banks had a representative office each in the country.

98. Regional Rural Banks.—During the year under review, 21 new regional rural banks (RRBs) were established, raising the total to 142 RRBs covering 245 districts at end-June 1983, as against the Sixth Five-year Plan target of 170 RRBs covering 270 districts to be attained by March 1985. The deposits and advances of RRBs as at the end of June 1983 stood at Rs. 517.9 crores and Rs. 623.7 crores, respectively, as compared with Rs. 380.7 crores and Rs. 465.6 crores, respectively, a year ago.

99. Registration of New Urban Co-operative Banks.—During the year, the Reserve Bank cautioned organisers of new urban co-operative banks not to enrol members or collect share capital from them until the proposals in question were scrutinised and cleared for registration. They were also asked to submit along with proposals preliminary survey reports and broad occupation-wise classification of prospective membership in order to enable the Reserve Bank to assess, among others, the genuine need for formation of the proposed banks in the area and also the extent to which they would serve the needs of the weaker sections in the area. This step had to be taken as the organisers, in a number of cases had undertaken a drive for enrolment of members and collection of share capital even though the proposals did not conform to the norms relating to areas of operation, average population coverage per bank office in the area, etc. These proposals had to be rejected by the Reserve Bank and the organisers had to deregister the members already enrolled by them.

100. Working Group on the Role of Banks in Implementation of New 20-Point Programme.—The recommendations made by the Working Group on the Role of Banks in Implementation of New 20-Point Programme were accepted by the Government of India and the Reserve Bank of India with certain modifications. The Reserve Bank issued instructions to banks on February 7, 1983 regarding the implementation of this programme and the realisation of various targets and sub-targets for lending to priority sector particularly to the weaker sections. With a view to ensuring that the thrust of the priority sector lending is towards financing small borrowers the definitions of some components of priority sector were revised. While the overall target of 40 per cent of bank credit set for priority sectors advances was left unchanged, the sub-targets for lending to agriculture and weaker sections were revised. Banks were asked to ensure that, as against the existing sub-target of 16 per cent for both direct and indirect finance for agriculture and allied activities, direct finance extended to agriculture (including allied activities) alone would reach a level of at least 15 per cent of total credit by March 1985 and at least 16 per cent of total credit by March 1987. The definition of weaker sections in priority sector was revised to correspond to the beneficiaries under the 20-Point Programme, the thrust of which is on the improvement in the living standards of the weakest sections of the society. Accordingly, the weaker sections in priority sector now comprise (a) small and marginal farmers with land holdings of five acres and less, landless labourers, tenant farmers and share croppers; (b) artisans, village and cottage industries; (c) beneficiaries of the Integrated Rural Development Programme (IRDP); (d) scheduled castes and scheduled tribes (SC|ST) and (e) Differential Rates of Interest (DRI) Scheme beneficiaries. It has also been stipulated that advances to weaker sections should reach a level of 25 per cent of priority sector advances or 10 per cent of total bank credit by the end of March 1985.

101. Banks and IRDP.—The IRDP, now in operation in all the blocks of the country, aims at improving the lot of the poorest of the poor—small and marginal farmers, share croppers, agricultural labourers, rural artisans, scheduled castes|tribes and other weaker sections—with the help of Government subsidy and institutional finance. Although detailed guidelines were issued to banks in December 1981 indicating the lines on which they should take action in order to accelerate the pace of lending under IRDP, the progress was not as expected. In a meeting which the Governor had with the Chief Executives of public sector banks in February 1983, their attention was drawn to this and they were asked to ensure that effective action was taken to fulfil the targets of lending under the IRDP. Apart from this, there has to be proper monitoring of the end use of credit so that the basic objectives of the programme are fulfilled.

102. DRI Scheme.—Further progress was made by public sector banks in respect of lending under the DRI Scheme. According to the latest data available, the number of borrowal accounts rose from 25.10 lakhs at the end of December 1980 to 29.25 lakhs at the end of December 1981. The amount of loans outstanding in these accounts went up by Rs. 63 crores from Rs. 194 crores to Rs. 257 crores. DRI advances at the end of December 1981 as a proportion of total advances (at the end of December 1980) touched the level of 1.17 per cent as against 1.04 per cent a year before. There was also improvement in the coverage of SC|ST borrowers under the Scheme,

the number of borrowal accounts rising from 11.18 lakhs at the end of December 1980 to 13.76 lakhs at the end of December 1981 and the amount of loans outstanding from Rs. 88 crores to Rs. 123 crores. Outstanding advances to SCs|STs as a proportion of total advances under the Scheme increased from 45.4 per cent in December 1980 to 47.9 per cent in December 1981.

103. Credit Facilities to SCs|STs.—With a view to increasing the flow of institutional credit to members of scheduled castes|scheduled tribes, banks were advised in September 1982 to ensure that the bank staff helped the poor borrowers in filling up the forms and completing other formalities so that they were able to get credit facility without delay and that their field staff contacted illiterate borrowers and explained to them the salient features of the schemes as also the advantages that would accrue. They were also advised in November 1982 to treat the advances sanctioned to State-sponsored development organisations of these segments for the specific purpose of purchase and supply of inputs to and|or the marketing of the output of, the beneficiaries of these organisations as priority sector advances and charge a concessional rate of interest at 13.5 per cent per annum, lowered to 12:5 per cent with effect from April 1, 1983, subject to certain conditions.

104. Credit Authorisation Scheme.—Reference was made in the last year's Report to the increase announced on July 17, 1982 in the cut-off point for working capital limits for the private sector borrowers from Rs. 2 crores to Rs. 3 crores. Some further changes in policy guidelines relating to the Credit Authorisation Scheme effected during the year are indicated below :

105. In respect of export-oriented manufacturing units whose annual average export turnover during the preceding three calendar years was more than 25 per cent of the total turnover of goods manufactured by them and whose export turnover in the following years would not fall below 25 per cent of total turnover, the cut-off point for working capital limits was raised to Rs. 5 crores. The cut-off point for individual term loans granted by banks to non-CAS parties in the private sector, singly or jointly with other banks, was raised from Rs. 25 lakhs to Rs. 50 lakhs. Further, in the case of export-oriented manufacturing units, as described above, the cut-off point for term loans was fixed at Rs. 1 crore.

106. Certain credit facilities were exempted from prior authorisation under CAS. These included additional packing credit limits upto 25 per cent of the existing packing credit limits or Rs. 50 lakhs, whichever was lower, for a period not exceeding three months, purchase of third party outstation cheques/ bank drafts, advances against fixed deposits in borrowers' names, temporary working capital limits upto 10 per cent of such existing facilities or Rs. 50 lakhs, whichever was lower, for a period not exceeding three months and interim working capital limits upto Rs. 25 lakhs where release of higher facilities sanctioned by banks was pending authorisation by the Reserve Bank.

107. Consequent on the increase in cut-off points, the number of parties covered under CAS declined to 897 (inclusive of 188 public sector undertakings) at the end of June 1983 from 1,251 at the end of June 1982 (inclusive of 204 public sector undertakings). The total working capital limits in force relating to parties covered under the Scheme, however, increased to Rs. 17,051 crores from Rs. 15,906 crores. The share of public sector undertakings at Rs. 10,380 crores rose by Rs. 2,010 crores while that of private sector at Rs. 6,671 crores shrank by Rs. 865 crores.

108. Committee to Review the Working of Credit Authorisation Scheme.—The Reserve Bank of India appointed in November 1982 a Committee to review the working of the Credit Authorisation Scheme from the point of view of its operational aspects. The terms of reference of the Committee were as follows :

(i) to examine the objective, scope and content of the Scheme and make suggestions with regard to making modifications therein, if any, having regard to the changing economic situation;

(ii) to examine the adequacy or otherwise of the credit appraisal machinery|procedures in commercial banks, and based thereon, suggest modifications, if any, in the modalities in this behalf;

(iii) to study the existing set-up for compliance with the requirements of the Scheme within the commercial banks both at the Head and Regional Office levels and suggest any modification therein considered necessary to facilitate proper appraisal and expeditious disposal of applications and monitoring thereof;

(iv) to examine the existing data base relevant for making recommendations by banks, to Reserve Bank of India for authorising a given level of credit for a particular party and suggest modification|simplification, if any, in that behalf;

(v) to examining the existing format for submitting applications by banks to Reserve Bank of India in respect of seeking authorisation and suggest modifications therein, if necessary;

(vi) to study the desirability of introducing time-bound guidelines to be observed within commercial banks and Reserve Bank for speeding up the processing and disposal of applications; and

(vii) to make any other recommendations which are germane to the Scheme.

109. The Committee submitted its report to the Reserve Bank in June 1983 and the same is being processed.

110. Sick Industrial Units.—The provisional data on sick units with credit limits of Rs. 1 crore and

above from the banking system furnished by banks showed that the number of sick units in this category at the end of June 1982 was 439 involving aggregate outstanding bank credit of Rs. 1,728.40 crores as compared to 422 units with aggregate outstanding bank credit of Rs. 1,453.29 crores at the end of June 1981. Of the 439 large sick units identified by banks, viability studies in respect of 374 units have been completed; of these, 320 units are considered as potentially viable and 235 units have been put under nursing programme.

111. Further, as at the end of June 1982, banks had identified 26,973 small-scale sick units involving aggregate bank finance of Rs. 393.67 crores, as compared to 22,360 sick units involving aggregate bank finance of Rs. 321.52 crores at the end of June 1981. Of these, 5,316 units were considered by banks as potentially viable and 14,576 units as non-viable. Banks have put 1,982 viable units under nursing programme.

112. General Line of Credit to NABARD.—The National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) started functioning from July 12, 1982 as mentioned in last year's Report. To provide funds to NABARD so as to enable it to extend short term refinance to State Co-operative Banks (SCBs) and RRBs, a general line of credit was opened. A short-term credit limit of Rs. 1,200 crores has been sanctioned to it under Section 17 (4E) of the Reserve Bank of India Act, 1934. The interest presently charged on this accommodation is 4.75 per cent below the Bank Rate.

113. Assistance to other Term Lending Institutions.—The Reserve Bank provides long-term loans as well as medium and short-term credit facilities to financial institutions notified by the Central Government. Long-term loans sanctioned to the Industrial Development Bank of India (IDBI) during 1982-83 from the National Industrial Credit (Long-Term Operations) NIC (LTO) Fund amounted to Rs. 245 crores, as compared with Rs. 265 crores during 1981-82. The IDBI utilised the entire limit. The amount borrowed by IDBI from the NIC (LTO) Fund and remaining outstanding as on June 30, 1983 was Rs. 1,828 crores.

114. Long-term loans sanctioned to the Export-Import Bank of India (Exim bank) during 1982-83 from the NIC (LTO) Fund amounted to Rs. 45 crores as compared to Rs. 25 crores in 1981-82. The Exim bank utilised the entire limit. The amounted borrowed by the Exim bank from the NIC (LTO) Fund and remaining as on June 30, 1983 was Rs. 70 crores.

115. The amount of short-term credit limits sanctioned to IDBI against the security of eligible bills rediscounted by it in 1982-83 was Rs. 225 crores, as compared to Rs. 190 crores in 1981-82. These short-term limits were sanctioned to IDBI to enable it to tide over temporary resource constraints as also to meet mismatch between the funds obtained by it from investment institutions like the LIC and UTI for financing the State Road Transport Corporations and State Electricity Boards and the actual disbursements of IDBI to these bodies. The IDBI availed of loans aggregating Rs. 43.27 crores from the above limit on several occasions for short periods and the amount outstanding as on June 30, 1983 was Rs. 1.97 crores.

116. The short-term borrowing limit of Rs. 3 crores sanctioned to the Industrial Finance Corporation of India (IFCI) was renewed by the Reserve Bank for a further period of one year ended December 1982. Credit limit of Rs. 10 crores sanctioned to the Industrial Credit and Investment Corporation of India Ltd. (ICICI) in June 1982 is due to expire in August 1983. The Corporation availed of the limit on several occasions for very short periods.

117. The Bank sanctioned during 1982-83 fresh borrowing limits aggregating Rs. 20.35 crores to 9 State Financial Corporations (SFCs) against their ad hoc bonds and also extended the period of borrowing limits amounting to Rs. 9.60 crores in respect of 3 SFCs.

118. At the end of June 1983, there were no outstanding against the short-term limits sanctioned to IFCI and ICICI. The outstanding amount in respect of limits sanctioned to SFCs as on June 30, 1983 were Rs. 12 crores.

119. Finance for Sugar Mills.—In view of the extended crushing season of 1981-82 and the urgent need for clean loans to complete off-season repairs before the commencement of crushing operations for the 1982-83 season, scheduled commercial banks were advised on November 5, 1982 that the Reserve Bank's prior authorisation was not required for grant of clean loans to sugar mills upto Rs. 25 lakhs for such purposes. These loans were, however, to be repaid as soon as possible after the commencement of the 1982-83 crushing season but in any case not later than March 31, 1983. Since the immediate financial problems faced by most of the units in the industry was their inability to adjust the margin deficit in their accounts, banks were asked to review individual cases and provide relief on merit.

120. Scheduled commercial banks were advised on November 6, 1982 to keep in mind the minimum cane price fixed by the Government of India in considering credit limits for the 1982-83 season (during which production was estimated to be around 80 lakh tonnes) and were permitted subject to the estimates of sugar production of individual units, to sanction limits upto 125 per cent of the maximum amount availed of during the 1981-82 season (excluding temporary excess drawings) without obtaining the Reserve Bank's prior authorisation. The actual drawings in borrowal accounts were to be regulated on the basis of the deficit as disclosed in the monthly cash budgets of mills. Banks were also asked to continue the practice of monitoring the payment of cane dues of sugar mills to growers and the system of earmarking of funds out of the advances against pledge/hypothecation of sugar for payment to cane growers as hitherto in consultation with the borrowers.

121. Standing Committees on Jute, Tea, Sugar and Fertilisers.—Standing Committees on Co-ordination of Institutional Finance to study the financial problems of industries on an on-going basis were constituted by the Reserve Bank, for jute and tea in November 1982 and for sugar and fertilisers in January

1983. Members of the Committees are drawn from the Reserve Bank of India, term-lending institutions, concerned industries, Central Government and experts|technologists.

122. Selective Credit Control.—The existing selective credit control measures in respect of advances against sensitive commodities continued to operate during the year with adjustments in margin requirements against a few commodities and some additions to the exempted categories of advances.

123. In the context of the substantially higher production of sugar during the 1981-82 season and larger stocks with mills, the margin requirement on advances against 'non-released' stocks of sugar was reduced from 25 per cent to 20 per cent effective September 13, 1982. Simultaneously, the margin on advances to manufacturers of gur and khandsari against stocks of these commodities was reduced from 65 per cent to 50 per cent. The margin on 'non-released' stocks of sugar (excluding buffer stocks) was further reduced from 20 per cent to 17.5 per cent effective November 18, 1982. The banks were advised to ensure that the additional amount that became available to sugar units on this basis was utilised by them for making cane payments wherever they were in arrears and for meeting start-up expenses.

124. On a review of the role of the Khadi and Village Industries Commission (KVIC) in providing institutional support for generating employment opportunities, advances granted to KVIC and all its associate institutions against sensitive commodities were given complete exemption from the purview of selective credit controls effective October 26, 1982.

125. With a view to providing assistance to cotton textile mills affected by the prolonged strike in Bombay and to help in their speedy rehabilitation, the Reserve Bank reduced, on December 4, 1982, the margin on advances to mills, including those under the National Textile Corporation operating in Bombay, against stocks of cotton and kapas by 10 percentage points for a period of six months upto June 3, 1983.

126. Reference was made in Part I of this Report to the reduction in lending rates of banks with effect from April 1, 1983. The minimum rate of interest applicable to commodities subject to selective credit control (other than advances to sugar mills) was also reduced from 19.5 per cent to 18 per cent. In case of advances to sugar mills in respect of all stocks, the minimum rate was fixed at 16.5 per cent and banks were allowed to charge a rate which is between this rate and the general ceiling rate on advances, i.e., 18 per cent.

127. Banks are permitted to provide packing credit to exporters of decilled and defatted cakes against the security of the relative raw materials (e.g., groundnut, cottonseed and rice bran) to the extent of the raw material required even though the amount so advanced exceeds the value of the export order. This facility is, however, subject to the condition that the amount in excess of the export value is adjusted either in cash or by sale of the by-product oil as soon as the extraction of oil is completed but within a period of 15 days from the date of the advance. In view of the difficulties faced by the exporter-borrowers to adjust the excess packing credit, the Reserve Bank raised the period for adjustment of the excess packing credit advance from 15 days to 30 days for packing credit sanctioned on or after July 1, 1983.

128. Inspection of Banks:—During the year under review, the second round of inspection under the system of annual appraisal of all public sector banks was almost completed. Inspections under the third round were taken up in 17 banks. Further, financial inspections of 24 banks and inspections of 13 overseas offices of Indian banks in the U.K. were also taken up. In addition, a number of scrutinies was carried out. These pertained to verification of claims paid, applications in respect of small borrowers as also test check inspections of small scale industries (S.S.I.) advances covered under guarantees issued by the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC), investigations into various complaints|frauds|allegations against banks|their employees and compliance with the provisions of selective credit control directives.

129. Frauds in Banks.—The Governor, in his meeting with the Chief Executives of public sector banks on February 25, 1983, expressed concern at the dwindling image of the banking system and the growing number of complaints about poor service, prevalence of corruption|malpractices in banks and increasing incidence of frauds. Banks were, therefore, advised to review and revamp the vigilance machinery, take urgent steps to tone up control and supervision, strengthen management information system, follow-up and inspection|audit arrangements and draw up a time-bound programe for clearing arrears in the balancing of books and reconciliation of inter-branch and other accounts. Also, detailed guidelines were issued to them in April 1983 for prevention of frauds. A Special Investigation Cell has been set up in the Bank for carrying out, inter alia, special investigations into the major frauds coming to the notice of the Bank and to closely monitor the implementation of the various guidelines issued with a view to preventing frauds.

130. Customer Service in Banks.—The Bank convened a meeting with the nationalised banks, the State Bank of India and the Indian Banks Association (IBA) to discuss certain critical areas of banking service where concerted efforts could be made to improve customer service. Banks have been asked to concentrate more on areas such as introduction of teller system, issue|payment of bank drafts, arrangements for payment of travellers' cheques, collection of outstation cheques, immediate credit against the lodgement of outstation cheque for collection upto an amount of Rs. 2,500/-, timely submission of statement of accounts to customers, attitude of staff and general discipline, follow-up action on complaints| suggestions from bank users and overseeing and monitoring the implementation of the recommendations of the Working Group on Customer Services at the banks' level. The public sector banks have been requested to furnish their progress reports to the Bank.

131. Capital Base of Banks.—It was stated in the last year's Report that, in the context of the growing international exposure of Indian banks and the need to project their image abroad, it was decided that the capital base of the banks should be increased. The Government of India had subscribed

Rs. 25 crores towards the additional capital of 8 nationalised banks in 1981-82. A further contribution of Rs. 5 crores was made towards the additional share capital of 3 othe nationalised banks during the year under review. Further, Section 36 of Income-Tax Act, 1961 has been amended whereby such banks as are notified by Government will be in a position to transfer amounts not exceeding 40 per cent of the total income to a 'Special Reserve Account' which will be eligible for deduction in computing income for the purpose of income tax.

132. Working Group on Bank Deposits.—Recommendations.—As mentioned in Part I of this Report, the Bank had accepted the recommendation of the Working Group on Bank Deposits for reviving the category of term deposits of five years and above and allowing an interest rate of 11 per cent thereon. The Bank initiated action on certain other recommendations made in the Report and a few modifications were made in the provisions governing bank deposits. The rate of penalty for premature withdrawal of deposits has been reduced from two per cent to one per cent. The interest admissible on premature withdrawal or renewal of a deposit under reinvestment scheme would be at compound interest at the permissible rate, instead of simple interest. Balances under the Daily Deposit Scheme and the Recurring Deposit Scheme can be converted into Fixed Deposits before maturity without penalty. Interest payable on the balances lying in a current account in the name of a deceased depositor is to be at the savings deposit rate till the balances are paid to the legal heirs. Institutions which are not liable to pay income-tax under the Income-Tax Act, 1961, will also be eligible to earn interest on their savings bank accounts with banks, besides certain organisations which have been already declared eligible. Certain other recommendations made in the Report are under the Bank's active consideration.

133. Banking Laws (Amendment) Bill.—The Banking Laws (Amendment) Bill containing certain import provisions was introduced in the Lok Sabha on May 10, 1983. The Bill seeks, among others, to provide nomination facilities in respect of bank accounts, prohibit acceptance of deposits by individuals, firms, etc., from more than the number of depositors prescribed therein, empowers the Reserve Bank to vary the Statutory Liquidity Ratio from 25 per cent to 40 per cent by issue of a notification, enable banks to undertake innovative measures like leasing activities and restrict the tenure of directors of private sector banks who hold office continuously for a period exceeding eight years.

134. Committee to Review Working of Monetary System.—The Reserve Bank appointed a five member Committee in December 1982 to undertake an in-depth study of the working of the monetary system. The terms of reference of the Committee are as follows :

(i) to critically review the structure and operation of the monetary system of the context of the basic objectives of planned development;

(ii) to assess the inter-action between monetary policy and other policies particularly fiscal policy and public debt management insofar as they have a bearing on the effectiveness of monetary policy;

(iii) to evaluate the various instruments of monetary and credit policy in terms of their impact on the credit system and on the economy. In this context, links among the banking sector, the non-banking financial institutions and the unorganised sector could be assessed;

(iv) to recommend measures for improvement in the formulation and operation of monetary and credit policies and to suggest specific areas where the various policy instruments need strengthening; and

(v) to make such other recommendations as the Committee may deem relevant to the effective operation of monetary and credit policy.

135. The Committee has been requested to furnish its report by the end of June 1984.

136. Panels of Economists.—With a view to establishing a closer contact with the academic community, the Reserve Bank constituted during the year four panels of Economists which could meet periodically and discuss matters relating to : (1) Macro-Economic System, (2) Industry and Industrial Finance, (3) Agriculture and Rural Development, and (4) Balance of Payments.

137. Committee to Study Trends of Agricultural Production and Productivity in Eastern India.—As the recent trends of agricultural production and productivity in Eastern India have been causing concern, the Reserve Bank of India and National Bank for Agriculture and Rural Development appointed a Committee in March 1983 to study these trends and suggest measures especially in the field of agricultural credit that may be adopted for realising as much of the production potential as possible before the close of the decade of the Eighties.

138. The terms of reference of the Commitee are to review the trends of agricultural production and productivity in Bihar, West Bengal, Orissa and Eastern U.P., in recent years and compare with the potential of the area and trends in the rest of the country; to identify the various constraints in achieving the potential levels of production in the States mentioned above and to suggest measures, with particular reference to credit and investment, necessary for achieving as much of the potential as possible by the end of the decade, viz., 1990.

139. The Committee has been requested to submit its report within six months.

DEVELOPMENTS RELATING TO EXCHANGE CONTROL AND OTHER MATTERS

140. Investment by Non-residents of Indian Nationality or Orgin.—A brief reference was made in Part I

to the simplification of procedures delating to investments by non-residents of Indian nationality or origin and repatriation of sale proceeds of such investments. More details are given below :

141. The facility for portfolio and direct investment in equity shares of Indian companies available to non-residents of Indian nationality or origin (including overseas bodies owned by such persons to the extent of at least 60 per cent) has been extended to investment in preference shares and debentures (convertible and non-convertible).

142. Also, the portfolio investment scheme for non-resident Indians has been modified in the light of experienced gained in its operation. Under the modified scheme, designated banks can purchase equity shares and convertible debentures without the Reserve Bank's specific approval for each transaction, to the extent of 1 per cent per non-resident investor, subject to an overall ceiling of 5 per cent of the total paid-up equity capital of the investee company and 5 per cent of the total paid up value of each series of convertible debentures issued by the company. The limit of 5 per cent applies to purchases of equity shares and convertible debentures through stock exchanges, both on repatriation and non-repatriation basis. Equity shares which non-resident investors can acquire on conversion of debentures would not be included for the purpose of computing the 5 per cent ceiling. The overall ceiling would be monitored by the Reserve Bank's central office at Bombay. Purchase of equity shares and convertible debentures on behalf of non-resident Indians in excess of the 5 per cent limit through stock exchanges would need prior permission of the Reserve Bank.

143. Further, the facility of direct investment in new issues with full repatriation benefits under the 40 per cent and 74 per cent schemes, which was earlier available in respect of new issues of companies engaged in manufacturing activities and specified priority industries, has been extended to investment in hospitals as well as three-star, four-star and five-star hotels.

144. Non-residents of Indian nationality or origin and overseas bodies owned by them to the extent of at least 60 per cent are now permitted to place funds with public limited companies (including Government undertakings with limited liability) as deposits for a period of three years with full repatriation benefits, subject to the conditions that the funds should be provided through remittances from abroad or from NRE Rupee Accounts/FCNR Accounts and that the deposits should be in conformity with the prevailing rules for acceptance of such deposits by public limited companies.

145. The facility of repatriation of sale proceeds of shares acquired by non-residents through stock exchanges on repatriation basis is available only if the investment is retained by the holder for a period of at least one year from the date of registration of shares in his name or in the name of the bank designated by him or the bank's nominee. In such cases, the sale proceeds to the extent of the cost of acquisition of the investment or the actual sale proceeds, whichever is less, are allowed to be repatriated without production of a 'no objection' or tax clearance production of tax clearance certificate from the tax authorities.

146. With a view to promoting direct investment in the new issues of shares and debentures, the Reserve Bank will permit Indian companies to appoint agents abroad and to pay them compensation upto a reasonable extent on the basis of the quantum of investment actually secured with their help.

147. Expert Committee on Exports and Imports.—The Reserve Bank appointed in November 1982 an Expert Committee to review the exchange control regulations relating to exports and imports and to suggest measures designed to simplify and streamline the documentation and procedures. The Committee is also to review the exchange control regulations relating to allied issues such as opening of offices abroad by Indian firms/companies, payment of commission to trade representatives, remittance of royalties, licence fees, deputation of Indian personnel abroad etc.; to study the present system of delegation of powers to authorised dealers in foreign exchange and suggest areas where further delegation could be made; and to examine the scope for further decentralisation of functions to the regional offices of the Exchange Control Department. The Committee is expected to submit its report by December 1983.

148. Relaxation/Simplification of Procedures.—The per capita limit for taking out of India personal jewellery, made wholly or mainly of gold by persons permanently resident in India, has been raised from Rs. 5,000 to Rs. 10,000. The limit for taking out of India precious stones or jewellery other than articles made wholly or mainly of gold by any traveller going to any country other than Afghanistan, Iran and Gulf countries has also been raised from Rs. 5,000 to Rs. 10,000.

149. The limit for loans granted to non-residents against the security of their NR (E) rupee and FCNR deposits for purposes other than investment has been increased from Rs. 25,000 to Rs. 50,000.

150. Authorised dealers in foreign exchange are permitted to allow foreign nationals permanently resident in India, who have secured the Reserve Bank's permission under Section 30 of the Foreign Exchange Regulation Act (FERA), 1973, to make recurring remittances to their own countries for family maintenance, etc., upto 50 per cent of their net monthly income. The earlier monetary ceiling of Rs. 2,500 per month has been removed.

151. Foreign Travel Scheme.—Travel under the Foreign Travel Scheme can now be combined with travel abroad for any other purpose except tours on export promotion or business grounds, Haj pilgrimage and travel under the Neighbourhood Travel Scheme.

152. Indianisation of Foreign Companies and Dilution of Foreign Equity.—As at the end of June 1983, the number of cases in which final orders under section 29(2)(a) of FERA, 1973, were passed requiring dilution/Indianisation of companies to specified levels, was 365. During the course of the year, 15 more companies complied with the directives, bringing the total number of such companies to 332. The remaining 33 companies are at various stages of compliance.

153. Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation.—Besides operating a deposit insurance

scheme and four credit guarantee schemes relating to non-industrial and small-scale industrial sectors, the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation introduced from January 1, 1983 another credit guarantee scheme relating to the co-operative sector [viz., Small Loans (Co-operative Credit Societies) Guarantee Scheme, 1982].

154. The number of insured banks under the deposit insurance scheme increased from 1,661 at the end of June 1982 to 1,718 at the end of June 1983, comprising 83 commercial banks, 140 RRBs and 1,495 co-operative banks. The scheme now covers deposits of co-operative banks in 14 States and 3 Union Territories. The number of insured accounts increased from 1,377 lakhs with total assessable deposits of about Rs. 35,004 crores as on June 30, 1981 to 1,598 lakh accounts with total assessable deposits of about Rs. 42,360 crores as on June 30, 1982.

155. During the year under review, 19 RRBs joined the Small Loans Guarantee Scheme, 1971, and 9 RRBs joined the Service Co-operative Societies Guarantee Scheme, 1971. With this the number of credit institutions participating in these two schemes rose to 188 (75 commercial banks and 113 RRBs) and 149 (61 commercial banks, 51 RRBs and 37 co-operative banks), respectively. The number of institutions participating in the Financial Corporation's Guarantee Scheme, 1971, remained unchanged at 18. The total guaranteed advances under the three guarantee schemes relating to non-industrial sector increased from Rs. 4,840 crores at the end of June 1982 to Rs. 5,025 crores at the end of December 1982, indicating a rise of 3.9 per cent.

156. The number of institutions participating in the Corporation's Small Loans Guarantee Scheme, 1981, as at the end of June 1983 rose to 339, comprising 71 commercial banks, 88 RRBs, 15 State Financial Corporation, 5 other State development agencies and 160 co-operative banks. Two State financial corporations, one State development agency and four co-operative banks have expressed their willingness to join the scheme, but they have yet to execute the agreement. The guaranteed advances to small-scale industries as on December, 1982 amounted to Rs. 4,087 crores.

157. Deposits of Non-banking Companies.—The surveys of deposits with non-banking companies conducted by the Department of Financial Companies have revealed that the increasing trend in the growth of deposits has continued. Total deposits with companies increased by Rs. 1,304 crores (including exempted deposits) to Rs. 5,492 crores during the year ended March 1982. Out of 5,420 reporting companies, 2,750 non-financial companies, 2,129 financial companies and 541 miscellaneous non-banking companies (chit fund companies) accounted for Rs. 3,476 crores (68.2 per cent), Rs. 1,535 crores (28.0 per cent) and Rs. 211 crores (3.8 per cent), respectively, of outstanding deposits.

158. Currency Chests.—The total number of currency chests in the country as at the end of June 1983 was 4,327, of which 593 were depositories. Of these, 15 currency chests are maintained with Reserve Bank, 3,095 with State Bank group, 352 with nationalistd banks, 268 with Government treasuries|sub-treasuries and 4 with Jammu and Kashmir Bank Ltd.

159. Serveys|Seminars.—Processing of data and generation of statistical tables for the 'All India Debt and Investment Survey 1981-82' made progress during the year. This Survey was organised by the National Sample Survey Organisation (NSSO) at the instance of the Reserve Bank.

160. A census of "India's Foreign Liabilities and Assets, 1981 and 1982" has been taken up. Broadly, the information on the foreign liabilities and assets, comprising item such as shares and debentures, deferred credit relating to exports and imports, deposits and advances, is being collected in the census.

161. It is proposed to conduct a survey of small-scale industrial units assisted by commercial banks during the year 1983-84, on lines similar to the earlier survey conducted by the Bank in 1977.

162. A seminar was organised in March 1983 on the Report of the Working Group on Savings appointed by the Government of India at which the concepts, definitions, methodology, sources of data and interpretation and policy implications of the estimates of saving and capital formation were discussed.

163. C. D. Deshmukh Memorial Lecture.—In recognition of the meritorious service rendered by the late C. D. Deshmukh to the Reserve Bank and nation and to perpetuate his memory, the Reserve Bank of India has decided to institute an annual "Dr. C. D. Deshmukh Memorial Lecture" to be delivered by a distinguished person in India or abroad on any subject related to economic development, money and central banking.

ORGANISATIONAL MATTERS AND ACCOUNTS OF THE BANK

164. Organisational Reforms.—Consequent on the transfer of some of the functions of the Reserve Bank to the National Bank for Agriculture and Rural Development with effect from July 12, 1982, a new department called the Rural Planning and Credit Department (RPCD) was set up in the Reserve Bank. The Urban Banks Cell, hitherto attached to the Agricultural Credit Department which has become a part of NABARD, has been transferred to the Department of Banking Operations and Development of the Reserve Bank and is now functioning as the Urban Banks Division. The RPCD deals with the Lead Bank Scheme, including formulation of District Credit Plans; priority sector advances, credit to weaker sections under special programmes and rural development schemes; compliance with the various sections of the Reserve Bank of India Act, 1934 and the Banking Regulation Act, 1949 insofar as they relate to State co-operative banks, central co-operative banks and regional rural banks, as well as submission of statutory returns by these banks; directives on interest rates on deposits and advances to State co-operative banks and their branches; liaison with the NABARD in the form of expert guidance| assistance and general line of credit to the NABARD; special studies for promoting IRDP and framing Reserve Bank policy on rural development. The Urban Banks Division handles

all matters relating to urban banks-licensing of banks and compliance with provisions relating to the Reserve Bank of India Act and the Banking Regulation Act.

165. Mechanisation|Computerisation.—For improving productivity and customer service, mechanisation|computerisation has been extended during the year in the areas like maintenance of current accounts in Deposit Accounts Department and the clearing house operations at Bombay, Madras and New Delhi. The issue and servicing of the 7 per cent capital investment bonds and pay roll work at Bombay have also been computerised. Besides, progress was made in regard to the proposal to introduce a mini-computer system for handling the work of consolidation of receipts and payments on Government Account and reconciliation under R. B. I. Remittance Facilities Scheme in the Central Accounts Section, Nagpur.

166. An inter-institutional group is finalising its report for introduction of Magnetic Ink Character Recognitions (MICR) technology for cheque writing to facilitate mechanised cheque sorting as a prelude to introduction of National clearing of outstation cheques. The group will also work out relevant details like standardisation of cheque forms, paper|printing specifications and organisational arrangements for national clearing.

167. Employee-Employer Relations.—A reference was made in the last year's Report about the agitation launched by the All India Association of the Class III employees from April 12, 1982 against certain provisions of the award of the National Industrial Tribunal. Though the agitation was called off at various offices before the year-end, it continued at Calcutta, resulting in the piling up of huge arrears of work in different departments which necessitated transfer of certain items of work relating to Government receipts and payments to nationalised banks. The agitation was called off at Calcutta in August 1982 and the staff in the note examination and verification sections started doing revised quotas of work. A writ petition, filed by the Association in the Calcutta High Court in May 1982 challenging the constitution of the Tribunal as also its Award, mainly relating to items concerning management functions, is still pending in the court. During the year, the Bank introduced mechanisation and computerisation of work in a phased manner within the ambit of the Tribunal's directions. Further extension of the areas of mechanisation|computerisation is under study.

168. A meeting was held between the Bank and the All India Reserve Bank Workers' Federation in March 1983 to discuss some outstanding issues of the last charter of demands of Class IV staff of the Bank. Meetings were also held between the Bank and the All India Reserve Bank Employees' Association to sort out some current problems relating to Class III staff.

169. During the year, apart from a joint consultation council meeting with the Reserve Bank of India Officers' Association, the annual conciliation meeting with each of the two Officers' Associations was also held when several matters affecting the interests of the officers and liberalisation of facilities for them were discussed. The relations of the Bank with its officers continued to be cordial throughout the year.

170. A conference of the managers and departmental heads was held in December 1982 during which the industrial relations situation in various offices of the Bank, problems of currency management, etc., were discussed.

171. Representation of Scheduled Castes|Scheduled Tribes in the Bank's service.—The total strength of scheduled caste and scheduled tribe employees in each of the three classes in the Bank as on January 1, 1983 was 1,915 (SC-1,547, ST-368) in Class IV, 3,128 (SC-2,147, ST-981) in Class III and 305 (SC-268, ST-37) in Class I as compared to 2,154 (SC-1, 747, ST-407) in Class IV, 3,165 (SC-2,159, ST 1,006) in Class III and 326 (SC-284, ST-42) in Class I as on January 1, 1982. The figures as on January, 1983 may undergo some change consequent upon the transfer of staff to and from NABARD and the final picture will emerge by January, 1984.

172. Particulars of direct recruitment made in various classes of services in the Bank during the calendar year 1982 and the representation of SCs|STs in the total recruitment are given below:—

Category	Total no. of Candidates	No. of SC/ST among the total recruited		Percentage of SC/ST among the total recruited	
		S.C.	S.T.	S.C.	S.T.
Class I (Officers)	192	12	3	6.3	1.6
Class III (Clerical staff etc.)	1,572	215	127	13.7	8.1
Class IV (Subordinate staff) :					
(i) Other than sweepers	523	132	43	25.2	8.2
(ii) Sweepers	24	16	5	66.7	20.9

173. The study on the poor performance of the ST candidates at written test for the post of Staff Officer Grade 'B', referred to in the last year's Report, was entrusted to the Indian Institute of Education, Pune. The Institute's report is being examined. The Reserve Bank Services Board has issued a special advertisement inviting applications exclusively from SCs|STs for the posts of Staff Officers Grade 'A' so as to enable the Bank to clear the accumulated backlog in their recruitment to the maximum ex-

tent possible. To attain this target, the age limit for SC employees applying for Staff Officer Grade 'A' (DR), which was 31 years, has been further relaxed upto 34 years now.

174. During the year, a representative of the Liaison Officer for SCs and STs inspected the rosters maintained in the Bank's offices at Patna and Kanpur and the Issue Department at Bombay. Certain irregularities observed in these centres in implementing the Bank's scheme for reservation in promotions have already been rectified and others are being rectified.

175. Employment of Ex-servicemen in the Bank's Service.—A decision has now been taken to extend the reservation hitherto provided for ex-servicemen in all other posts in Class III to the post of Clerk Grade II|Coin|Note Examiner Grade II also from the year 1983 onwards. During the calendar year 1982, out of 251 posts filled in Class III (other than Clerks in the common cadre) and 634 posts filled in Class IV, 11 posts and 75 posts, respectively, were filled by ex-servicemen, as against the 37 posts and 155 posts required to be filled in at the prescribed rates of reservation i.e. 14½ per cent for Class III and 24½ per cent for Class IV. Due to non-availability of suitable ex-servicemen candidates, the share of ex-servicemen in total recruitment was 4.4 per cent in Class III and 11.8 per cent in Class IV.

176. Promotion of Hindi.—Several new measures were taken by the bank to promote the progressive use of Hindi in its offices in compliance with the statutory requirements in this regard.

177. The Bank's offices in regions 'A' (Hindi speaking areas) and 'B' (Maharashtra, Gujarat and Punjab) were provided with the annual time-bound programme for the year 1982. Under the programme, these offices are required to increase their Hindi correspondence (originating) to 66-2|3 per cent and 30 per cent respectively of the total correspondence. Besides, they are also required to issue, in Hindi, circulars, office orders, etc., intended for all categories of staff and members of the public. In order to ensure full compliance with such requirements, copies of checklist and check points were made available to all officers of the Bank.

178. The various reports of the Bank as well as the Bank's associate institutions continued to be brought out in Hindi. In addition to these, six publications were also brought out during the year : Banking Glossary (Hindi-English), Banking Glossary, Revised Edition (English-Hindi), Advanced Banking-Oriented Course in Hindi, Check-list for use of Hindi, Check points for use of Hindi, and Indian Economy —Basic Statistics (folder).

179. Bankers Training College (BTC), Bombay.—The Bankers Training College continued to conduct general broad spectrum programmes in the fields of central, commercial and development banking: specialised technical|functional programmes in credit, foreign exchange and inspection areas and specialised managerial programmes relating to personnel management, industrial relations and organisation and methods. Other subjects covered were performance budgeting, statistics for bankers, legal aspects of banking, merchant banking, faculty development portfolio management, etc.

180. The College introduced nine new programmes during the period under review. It also provided faculty assistance to other banks' colleges in response to their requests, by deputing its faculty members for taking sessions in their courses.

181. Besides conducting training programmes, the College undertook special studies and publication of books. It brought out during the year five publications—BTC Bulletins, Performance Budgeting in Commercial Banks, Guide to Disciplinary Action, Proceedings of Seminar on Productivity, and Proceeding of Seminar on Tobacco.

182. Of the 78 programmes covering 44 different types of courses conducted during the period, 14 were in company programmes tailored to the specific requirements of the sponsoring institutions (mostly smaller public sector banks and banks in private sector) of which 13 programmes were held at their own centres.

183. During the period, 2,440 officers from the Reserve Bank, commercial banks, development finance institutions, Government and foreign banks were trained at the College, raising the total number of participants trained since the inception of the College in 1954 to 23,957.

184. College of Agricultural Banking (CAB), Pune.—In addition to the various broad spectrum and specialised programmes on agricultural finance and allied subjects the College of Agricultural Banking also arranged a country level training workshop for the personnel of rural credit institutions for improving the services to low-income groups. This was done in collaboration with the inter-Agency Committee on Integrated Rural Development formed by the Food and Agriculture Organisation (FAO) and other United Nations' Organisations.

185. A seminar on loan assistance to weaker sections sponsored by the Department of Personnel and Administrative Reforms of the central ministry of Home Affairs was conducted by the College in November 1982, which was attended by senior executives of commercial and rural banks, State Governments, etc.

186. The College also conducted a training programme on small holder livestock project preparation, in collaboration with the Commonwealth Secretariat, London.

187. Following inter-Governmental consultations between India, Bangladesh, Sri Lanka and Nepal for the establishment of a Centre for International Co-operation in Training for Agricultural Banking (CICTAB), it was decided that two training programmes should be conducted by the College on "Project Finance" and "Production Finance" during 1983 on behalf of CICTAB. The College also completed a consultancy assignment with the Central Bank of Ceylon for setting up a rural banking wing in their Rural Banking and Staff Training College in Sri Lanka.

188. During the year under review, the College trained 1,872 officers from various banking institutions in India and abroad and government officials through 83 regular programmes, 2 special programmes and a government sponsored seminar, raising the total number of participants trained since its inception in September 1969 to 19,170.

189. Reserve Bank Staff College (RBSC) Madras.—The Reserve Bank Staff College continued to cater to the training needs of Staff Officers Gr. A to Gr. C in the different departments of the Bank. During the period under report, 1,332 officers were trained through 57 programmes, raising the total number of officers trained since the inception of the College in 1963 to 12,151.

190. Apart from the usual broad spectrum and functional programmes, pilot programmes for 'Private Secretaries' Gr. A and 'Behavioural Science' for Staff Officers Gr. B (DRs) were arranged.

191. An Assistant Treasures' Programme was conducted exclusively in Hindi medium and a revised Credit Appraisal Programme incorporating the latest techniques of appraising working capital needs and term finance were also conducted.

192. In-company Training Programmes.—A workshop for developing conceptual and managerial skills of managers and potential managers of the Bank in Grades E and F was organised at New Delhi in February 1983. Also, a two-day in-company programme on 'Time-Management' was organised in collaboration with the Management Development Institute, New Delhi. The programme aimed at providing information on various aspects of time-management besides suggesting certain concrete pointers towards more successful utilisation of time by adoption of certain techniques. A 'Computer Appreciation Seminar' was organised in February 1983 to explain to the officers of the Bank the use and capabilities of a modern computer system in a large organisation.

193. Zonal Training Centres.—The Zonal Training Centres (ZTCs), of the Bank at Byculla (Bombay), Calcutta, Madras and New Delhi, look after the training needs of the Bank's staff at the clerical level. The ZTCs continued to conduct special courses for clerical staff, induction courses of Clerks Gr. II at the entry point and special programmes for Tellers/ Coin-Note Examiners Gr. I. In all, 2,218 members of the clerical staff received training at the ZTCs during the year raising the total number of such staff that received training since the setting up of ZTCs to 24,884.

194. Deputation of Staff for Trainig in India and Abroad.—The Bank continued to depute its officers to participate in the training programmes, seminars and conferences organised by institutes of repute both in India and abroad.

195. During the year, the Bank nominated 174 officers to various programmes conducted by institutes in India on topics ranging from management and allied areas to functional programmes for trainers, commercial banking, administration, exchange control, etc.

196. Twenty two officers of the Bank were deputed for study visits to banking and financial institutions in West Germany, the U.S.A., Japan, the Philippines, Indonesia, Malaysia, Thailand, etc.

197. Training Facilities Extended to Officers of Foreign Banks.—The Bank continued to extend training and study facilities to the participants from foreign central and commercial banks in response to specific requests received from them, including those sponsored under schemes of international cooperation, such as Asian and Pacific Regional Agricultural Credit Association (APRACA) Staff Exchange Programme, Commonwealth Fund Technical Co-operation, London, Technical Cooperation Scheme (T.C.S.) of Colombo Plan, United Nations Development Programme, etc. Of the 76 delegates who were afforded training facilities, 27 were from Sri Lanka, 17 from Nepal, 9 from Sudan, 6 from Tanzania, 2 each from Kenya and Seychelles besides participants from Thailand, Indonesia, Mauritius, Ghana, Bhutan, etc.

198. The National Institute of Bank Management.—The National Institute of Bank Management organised 19 training programmes/seminars/conferences/workshops wherein about 800 participants took part. Besides, research projects on cost and profitability in banks, trends in profit and profitability of domestic business of Indian commercial banks, risk management of foreign currency exposure, study of impact of Differential Rates of Interest Scheme, development of unbanked areas and role of Banking system and study of Integrated Rural Development Programme were completed. Among the projects taken on hand are : working capital management (with special reference to bicycle industry and automobile industry), housekeeping problems at metropolitan branches, survey of bank deposits, performance appraisal of public sector banks and study of processing and sanctioning of industrial loan proposals.

199. Press Relations.— The Press Relations Division continued to maintain an effective communication link between the Bank and the public by disseminating information on the working of the different departments of the Bank and the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation.

200. The Division organised a conference of economic editors from all over India with a view to promoting better understanding of the Bank's policies through an informal exchange of views between them and the Governor and other senior executives of the Bank.

201. The Division brought out a booklet on the various investment facilities available to non-resident Indians, explaining the current policies and procedures. It also brought out two folder-leaflets on (i) Mini-Computer System for Clearing House (Facts and Figures) and (ii) Computerisation in DICGC.

202. Premises.—The first phase of construction of the office building at Chandigarh has been complet-

ed. The construction work of the office building at Jaipur is in progress. Work on the additional office building at Nagpur has been started.

203. Residential Quarters.—During the year, 306 flats comprising 64 officers' flats (including 8 single self-contained rooms) at Ahmedabad, 110 flats (including 8 single self-contained rooms) for officers and 112 flats for Class III and IV staff at Bhopal, have been completed and occupied. Besides, the construction of 100 flats (including 10 single self-contained rooms) for officers at New Delhi and 56 flats for Class IV staff at Trivandrum has been virtually completed and will be ready for occupation shortly.

204. The construction work of 821 flats, 370 flats for Class III and IV staff at Ahmedabad, 92 flats (including 10 single-self-contained rooms) for officers at Calcutta, 196 flats for Class III and 78 for Class IV staff at Gauhati and 85 flats (including 6 self-contained single rooms) for officers at Kanpur is in progress.

205. The construction of 310 flats for officers (100 flats, (including 8 single self-contained rooms) at Nayapalli, Bhubaneswar, 28 flats at Kaloor, Cochin, 4 flats at Rajendranagar, Patna, 178 flats at Ameerpet, Hyderabad) and 308 quarters for Class III and IV staff (84 quarters at Kaloor, Cochin and 224 quarters at Digha, in Patna) is expected to be taken up shortly.

206. At Andheri, Bombay, the construction of the 'G' Block, comprising 36 self-contained single rooms and 4 smaller flats, for officers in the Bank's Chakala Officers' quarters is completed. The first phase of the housing project for Class IV staff at Malad (Bombay), comprising 6 buildings with 120 flats, has also been virtually completed. The construction of 56 flats for officers at Conningham Crescent, Bangalore and 315 flats for Classes III and IV staff at Shalimar Bagh, New Delhi is also nearing completion. The construction work of 547 flats (108 flats (including 6 single self-contained rooms) for officers at Jaipur, 41 flats, (Officers 17 flats, Class III staff 24 flats) at Pune, and 14 flats for officers and 384 flats for Class III staff at Hyderabad) is in progress.

207. Purchase of Flats on 'Package Deal' or on Turnkey Basis.—During the year under review, three agreements for purchase of 401 flats (384 flats for Class III staff at Begumpet, Hyderabad, 9 flats for officers at Ganesh Khind Road, Pune, and 8 flats for officers at Kothrud, Pune) on 'package deal' basis were executed.

208. Purchase of Land.—In Bombay, the Bank has acquired plots in the Bandra-Kurla complex and at Sewri for construction of residential quarters. At Jaipur, 8 acres of land have been purchased for construction of residential accommodation for Bank's staff.

209. Housing Loan Scheme.—During the period July 1, 1982 to June 30, 1983, housing loans were sanctioned as under.

A. Co-operative Housing Society	No. of societies	Amount Rs.
New co-operative societies	9	52,94,822
Additional loans to co-operative societies already assisted	15	15,73,903
		68,68,725

B. Individual members of staff	No. of employees	Amount Rs.
New loans	396	2,06,27,527
Additional loans to employees who had already availed of loans	280	64,11,202
		2,70,38,729

The totals of the society and individual loans sanctioned since the introduction of the scheme is 1961 amount to Rs. 13,41,66,620.00 and Rs. 17,13,81,207.00, respectively.

210. In all, 7,608 employees have availed themselves of this facility.

211. Central Board.—Dr. I. G. Patel retired as Governor of the Bank at the close of business on September 15, 1982. Dr. Manmohan Singh assumed charge as Governor on September 16, 1982. The Board takes this opportunity to place on record its appreciation of the eminent services rendered by Dr. I. G. Patel.

212. Sarvashri A. N. Haksar, Akbar Hydari, Jehangir P. Patel, S. L. Kirloskar and M. P. Chitale and Drs. Bharat Ram, V. Kurien, B. Venkatappiah and D. P. Singh retired as Directors of the Central Board on the expiry of their terms of appointment on March 18, 1983 and in their place Sarvashri Jaharlal Sen Gupta, Ashok Kumar Jain, R. P. Goenka, Raghu Raj, Aditya V. Birla, R. Ganesan and P. N. Devarajan and Drs. S. R. Sen and A. S. Kahlon were appointed with effect from the same date. Shri R. N. Malhotra, Director nominated under Section 8(1) (d) of the RBI Act relinquished charge on October 12, 1982 and Shri M. Narasimham was appointed in his place. On the latter's relinquishing charge on July 1, 1983, Shri P. K. Kaul was appointed as Director in his place on July 11, 1983. The Board wishes to place on record the services rendered by the retired Directors.

213. Shri M. Ramakrishnayya relinquished office as Deputy Governor of the Bank on July 31, 1983. The Board wishes to place on record its appreciation of the services rendered by him to the Bank.

214. Local Boards.—Shri A. N. Haksar, who retired as Director of the Central Board on March 18, 1983, ceased to be a member of the Eastern Area of the Local Board and his place was filled by Shri Jaharlal Sen Gupta with effect from the same date. Dr. Bharat Ram's place as member of the Northern Area of the Local Board was taken by Dr. S. R. Sen on March 18, 1983 consequent on the retirement of the former on the same date.

215. Six meetings of the Central Board were held during the year, two of which were held in Bombay and one each in Madras, Calcutta, Jaipur and New Delhi.

216. Sarvashri R. Mitra and W. S. Tambe relinquished charge as Executive Directors on July 24, 1982 and December 10, 1982, respectively. Shri B. N. Srivastava was appointed as Executive Director on July 24, 1982 and Sarvashri V. B. Kadam and T. N. A. Iyer as Executive Directors with effect from December 11, 1982.

217. Opening and Closing of Offices.—The Indore Regional Offices of the RPCD and Urban Banks Division were closed down on April 23, 1983 and they resumed functioning at Bhopal from May 2, 1983.

218. Accounts.—During the accounting year ended June 30, 1983, the Bank's income after making adjustment for various provisions amounted to Rs. 1040.42 crores as compared to last year's income of Rs. 956.76 crores. The details of the income from various sources are given below :

(Amount in Rupees crores)

	Year 1982-83	1981-82
(1) Interest on Ways & Means Advances to State governments	26.07	66.01
(2) Interest on Laons & Advances to State governments (other than on Ways & Means Advances referred to at item (1) above) and Commercial & Co-operative banks	128.83	95.74
(3) Interest on Rupee Securities & Discount on Rupee Treasury Bills	626.06	381.51
(4) Interest & Discount on Foreign Securities, Investments & Treasury Bills	520.58	598.48
(5) Commission & Exchange	40.73	42.54
(6) Other Income	1.34	1.14
	1343.61	1185.42
Less : Interest paid to the Scheduled Commercial banks on the additional average balances maintained by them with the Reserve Bank	303.19	228.66
	1040.42	956.76
Less : Transfers to Funds as stated in paragraph 219.	615.00	545.00
	425.42	411.76

219. The contributions to the National Rural Credit (LTO) Fund,* the National Rural Credit (Stabilisation) Fund* and the National Industrial Credit (LTO) Fund were Rs. 225 crores, Rs. 75 crores and Rs. 315 crores during the year 1982-83 as against Rs. 180 crores, Rs. 75 crores and Rs. 290 crores, respectively, during the year 1981-82.

220. Out of the balance of income amounting to Rs. 425.42 crores, after allowing for the total expenditure of Rs. 215.42 crores during the year (as against the balance of income amounting to Rs. 411.76 crores and expenditure of Rs. 201.76 crores in the previous year), the surplus profit set aside for payment to the Central Government was Rs. 210 crores (same as in the previous year).

221. The rise of Rs. 83.66 crores in the income from the level of Rs. 956.76 crores last year to Rs. 1040.42 crores was due to higher interest earned on investment in Rupee & Foreign securities, higher penal/overdue interest earned from scheduled commercial banks partly offset by decrease in the income from foreign assets coupled with more interest paid to scheduled commercial banks on their additional cash reserves. The rise of Rs. 13.66 crores in the expenditure was mainly due to increase in the amount of turnover commission paid to the agency banks for handling Government transactions.

222. Auditors.—The accounts of the Bank have been audited by M/s. Batliboi & Purohit, Bombay, M/s. Lovelock & Lewes, Calcutta, M/s. D. Rangaswamy & Co., Madras and M/s. K. C. Khanna & Co., New Delhi. While the first three firms were reappointed by the Government of India, the last mentioned has been appointed for the first time in place of M/s. P. K. Chopra & Co., vide their notification No. 1(4)83-Accts dated April 8, 1983. In addition to Central Office, Bombay, Calcutta, Madras, New Delhi & Nagpur offices, books of accounts of Jaipur & Gauhati offices (last year Ahmedabad & Hyderabad offices) have been audited by the Bank's statutory auditors this year. The remuneration of the auditors has been fixed at Rs. 15,000 per office.

RESERVE BANK OF INDIA
BALANCE SHEET AS AT 30TH JUNE 1983
ISSUE DEPARTMENT

LIABILITIES	Rs. P.	Rs. P.	ASSETS	Rs. P.	Rs. P.
Notes held in the Banking Department	23,78,09,256.00		Gold Coin and Bullion:		
			(a) Held in India	225,58,28,275.87	
Notes in circulation	18383,22,09,928.50		(b) Held outside India		
			Foreign Securities	1564,05,75,253.50	
Total Notes issued		18407,00,19,184.50	Total		1789,64,03,529.37
			Rupee Coin		17,52,34,596.57
			Government of India Rupee Securities		16599,83,81,058.56
			Internal Bills of Exchange and other Commercial Paper		—
Total Liabilities		**18407,00,19,184.50**	**Total Assets**		**18407,00,19,184.50**

*Earlier these funds were termed as National Agricultural Credit Funds.

BANKING DEPARTMENT

LIABILITIES	Rs. P.	ASSETS	Rs. P.
Capital Paidup	5,00,00,000.00	Notes	23,78,09,256.00
Reserve Fund	150,00,00,000.00	Rupee Coin	3,65,669.00
National Industrial Credit (Long-Term Operations) Fund	2230,00,00,000.00	Small Coin	5,91,155.10
Deposits :—		Bills Purchased and Discounted :—	
(a) Government		(a) Internal	..
(i) Central Government	553,40,89,627.05	(b) External	..
(ii) State Governments	199,64,91,588.21	(c) Government Treasury Bills	7041,89,22,878.10
(b) Banks		Balances Held Abroad	2760,67,12,211.97
(i) Scheduled Commercial Banks	6623,69,58,507.04	Investments*	2989,23,76,625.17
(ii) Scheduled State Co-operative Banks	140,85,24,067.51	Loans and Advances to :—	
(iii) Non-Scheduled State Co-operative Banks	4,77,83,457.62	(i) Central Government	..
(iv) Other Banks	15,06,54,857.42	(ii) State Governments@	213,19,00,000.00
(c) NABARD Deposit		Loans and Advances to :—	
(i) NRC (LTO) Fund	349,58,65,242.03	(i) Scheduled Commercial Banks	544,83,52,047.14
(ii) NRC (Stabilisation) Fund	281,28,55,673.58	(ii) State Co-operative Banks	51,05,64,500.00
(d) Others	4857,21,51,997.27	(iii) NABARD	904,10,40,000.00
Bills Payable	96,09,58,888.52	(iv) Others	11,75,59,586.00
Other Liabilities £	3483,55,45,032.61	Loans, Advances and Investments from National Industrial Credit (Long-Term Operations) Fund :—	
		(a) Loans and Advances to :—	
		(i) Industrial Development Bank of India	1827,73,98,575.00
		(ii) Export Import Bank of India	70,00,00,000.00
		(b) Investment in bonds/debentures issued by :—	
		(i) Industrial Development Bank of India	..
		(ii) Export Import Bank of India	..
		Other Assets+	2551,82,86,435.38
Total Liabilities	**18990,18,78,938.86**	**Total Assets**	**18990,18,78,938.86**

Contingent Liability :
On partly paid Shares
Rs. 7,72,499.03 equivalent of £ 50,000

£ Includes Contingency Account.
* Includes Rs. 480,45,16,934.37 held abroad in freign currencies.
@ Includes Ways and Means Advances.
\+ Includes Rs. 1885,19,90,000 advanced to or deposited with scheduled commercial banks under special arrangements.

R. N. MAJUMDAR
Chief Accountant

MANMOHAN SINGH *Govenor*
A. GHOSH *Deputy Governor*
C. RANGARAJAN *Deputy Governor*
M. V. HATE *Deputy Governor*

Dated the 5th August 1983

PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 1983

INCOME	Rs. P.
Interest, Discount, Exchange Commission, etc.*	425,41,84,605.11
	425,41,84,605.11

EXPENDITURE	
Establishment	79,53,86,973.96
Director's & Local Board Members' Fees & Expenses	2,16,293.85
Auditors Fees	120,000.00
Rent, Taxes, Insurance, Lighting etc.	4,32,03,931.97
Law Charges	10,51,089.15
Postage and Telegraph Charges	41,51,009.81
Remittance of Treasure	1,76,66,753.46

* After making statutory contributions and the usual or necessary provisions in terms of Section 47 of the Reserve Bank of India Act.

LIABILITIES		ASSETS	
Stationery, etc			1,23,41,143.02
Security Printing (Cheque, Note Forms, etc.)			35,93,68,425.58
Depreciation and Repairs to Bank Property			3,51,78,963.81
Agency Charges			82,27,61,920.37
Contributions to Staff Gratuity and Superannuation Funds			1,35,00,000.00
Miscellaneous Expenses			4,92,34,166.55
	Net available balance		210,00,00,933.58
	Total		**425,41,84,605.11**
Surplus payable to the Central Government			210,00,00,933.58

RESERVE FUND ACCOUNT

By Balance on 30th June 1983	150,00,00,000.00
By Transfer from Profit and Loss Account	Nil
Total	**150,00,00,000,00**

R. N. MAJUMDAR
Chief Accountant

MANMOHAN SINGH *Governor*
A. GHOSH *Deputy Governor*
C. RANGARAJAN *Deputy Governor*
M. V. HATE *Deputy Governor*

Dated the 5th August 1983

REPORT OF THE AUDITORS

TO THE PRESIDENT OF INDIA

We, the undersigned Auditors of the Reseve Bank of India, do hereby report to the Central Government upon the Balance Sheet and Accounts of the Bank of as at 30th June, 1983.

We have examined the above Balance Sheet with the Accounts, Certificates and Vouchers relating thereto of the Central Office and of the Offices at Calcutta, Bombay Fort, Madras, New Delhi, Nagpur, Gauhati & Jaipur and with the returns submitted and certified by the Managers of the other Offices and Branches which returns are incorporated in the above Balance Sheet, and report that where we have called for explanations and information from the Central Board such information and explanations have been given and have been satisfactory. In our opinion the Balance Sheet is a full and fair Balance Sheet containing the particulars prescribed by and in which the assets have been valued in accordance with the Reserve Bank of India Act, 1934 and Regulations framed thereunder and is properly drawn up so as to exhibit, a true and correct view of the states of the Bank's affairs according to the best of our information and the explanations given to us and as shown by the Books of the Bank.

Messrs. BATLIBOI & PUROHIT
Messrs D. RANGASWAMY & CO.
Messrs LOVELOCK & LEWES
Messrs. KC. KHANNA & CO.
Auditors

Dated the 18th August 1983

STATEMENT ON RESERVE BANK OF INDIA BALANCE SHEET

Particulars	For the year ended June 30, 1981		For the year ended June 30, 1982	
	Rs. P	Rs. P.	Rs. P.	Rs. P
ISSUE DEPARTMENT				
LIABILITIES				
Notes held in the Banking Department	13,64,49,690.00		29,80,93,643.00	
Notes in circulation	14383,44,03,639.50		16034,70,25,652.50	
Total notes issued		14397,08,53,329.50		16064,51,19,295.50
Total Liabilities		**14397,08,53,329.50**		**16064,51,19,295.50**

STATEMENT ON RESERVE BANK OF INDIA BALANCE SHEET—(*Contd.*)

LIABILITIES		ASSETS	
ASSETS :			
Gold Coin and Bullion			
(a) Held in India	225,58,27,914.78		225,58,28,023.95
(b) Held outside India	—		—
Foreign Securities	2364,05,75,253.50		1564,05,75,253.50
Rupee Coin	47,53,55,997.06		29,96,70,632.13
Government of India Rupee Securities	11759,90,94,164.16		14244,90,45,385.92
Internal Bills of Exchange and Other Commercial Paper	—		—
Total Assets		**14397,08,53,329.50**	**16064,51,19,295.50**
BANKING DEPARTMENT :			
LIABILITIES :			
Capital Paid-up	5,00,00,000.00		5,00,00,000.00
Reserve Fund	150,00,00,000.00		150,00,00,000.00
National Agricultural Credit (Long-Term Operations) Fund	1025,00,00,000.00		1205,00,00,000.00
National Agricultural Credit (Stabilization) Fund	365,00,00,000.00		440,00,00,000.00
National Industrial Credit (Long-Term Operations Fund)	1625,00,00,000.00		1915,00,00,000.00
Deposits			
(*a*) Government			
(*i*) Central	214,19,36,326.66		152,69,64,302.53
(*ii*) States	85,46,04,916.55		247,45,88,183.23
(*b*) Banks			
(*i*) Scheduled Commercial Banks	5476,65,26,624.23		5932,14,52,798.59
(*ii*) Scheduled State Co-op. Banks	96,76,94,390.99		99,79,88,837.59
(*iii*) Non-Scheduled State Co-op. Banks	4,24,85,571.49		3,66,14,617.53
(*iv*) Other Banks	5,69,18,424.03		8,44,49,052.84
(*c*) Others	1727,71,30,546.18		2542,94,67,026.11
Bills Payable	57,20,09,450.21		82,94,97,597.15
Other Liabilities (a)	2159,19,47,556.23		2802,41,88,950.07
Total Liabilities		**12997,12,53,806.57**	**15587,52,11,365.64**

(*a*) Includes Contingency Accounts.

Particulars	For the year ended June, 30 1981		For the year ended June 30, 1982	
ASSETS :	Rs. P.	Rs. P	Rs. P	Rs. P.
Notes	13,64,49,690.00		29,80,93,643.00	
Rupee Coin	4,19,877.00		3,36,507.00	
Small Coin	6,71,042.99		6,39,904.87	
Bills Purchased and Discounted :				
(*a*) Internal	3,71,33,861.40		—	
(*b*) External	—		—	
(*c*) Government Treasury Bills	45,29,87,80,697.45		6701,75,54,790.65	
Balance held abroad (*b*)	1602,64,28,160.37		1364,39,68,647.46	
Investments	2157,50,02,729.35(*cd*)		2335,47,60,580.05(*ce*)	
Loans and Advances to :				
(*i*) Central Government	—		—	
(*ii*) State Governments (*f*)	116,04,00,000.00		—	
(*iii*) Scheduled Commercial Banks (*g*)	570,69,92,396.18		567,96,94,312.37	
(*iv*) State Co-operative Banks(*h*)	340,75,09,800.00		630,52,90,500.00	
(*v*) Others	16,40,76,000.00		6,22,19,000.00	
Loans, Advances and Investments from National Agricultural Credit (Long-Term Operations) Fund :				
(*a*) Loans and Advances to :				
(*i*) State Governments	128,70,44,388.00		125,23,37,960.00	
(*ii*) State Co-operative Banks	30,96,28,877.00		32,94,82,516.00	

Particulars	For the year ended June 30, 1981	For the year ended June 30, 1982
(iii) Central Land Mortgage Banks	..	
(iv) Agricultural Refinance and Development Corporation	366,40,00,000.00	513,93,30,000.00
(b) Investment in Central Land Mortgage Bank Debentures	4,69,01,795.00	3,50,17,695.00
Loans and Advances from National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund to State Co-operative Banks	94,79,93,317.00	84,46,19,803.00
Loans, Advances and Investments from National Industrial Credit (Long-Term Operations) Fund :		
(a) Loans and Advances to the Development Bank	1322,50,78,575.00	1610,59,88,575.00(i)
(b) Investment in Bonds/Debentures issued by the Development Bank	..	..
Other Assets	1697,67,42,599.83(j)	1580,58,76,931.24(k)
Total Assets	**12997,12,53,806.57**	**15587,52,11,365.64**

Note : June 30, 1981—Contingent liability : on partly paid shares Rs. 8,49,993.20 equivalent of £ 50,000.
June 30, 1982—Contingent liability : on partly paid shares Rs. 8,25,000.83 equivalent of £ 50,000.

(b) Includes Cash, Fixed Deposits and Short-term Securities.

(c) Excluding Investments from the National Agricultural Credit (Long-Term Operations) Fund and the National Industrial Credit (Long-Term Operations) Fund.

(d) Includes Rs. 360,52,01,369.45 held abroad in foreign currencies.

(e) Includes Rs. 345,7 3,03,767.85 held abroad in foreign currencies.

(f) Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long-Term Operations) Fund.

(g) Includes Rs. Nil advanced to Scheduled Commercial Banks against usance bills under Section 17(4) (c) of the Reserve Bank of India Act.

(h) Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long-Term Operations) Fund and the National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund.

(i) Includes Rs. 25,00,00,000.00 Loans and Advances to Exim Bank.

(j) Includes an amount of Rs. 1138,11,10,000.00 advanced to or deposited with Scheduled Commercial Banks under Specia arrangements.

(k) Includes an amount of Rs. 1056,41,50,000.00 advanced to or deposited with Scheduled Commercial Banks under special arrangements.

PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEARS ENDED 30TH JUNE 1981 AND 1982

	1981 Rs. P.	1982 Rs. P
INCOME		
Interest, Discount, Exchange, Commission, etc.	373,95,20,480.32	411,76,16,023.68
	373,95,20,480.32	**411,76,16,023.68**
EXPENDITURE		
Establishment	71,83,73,677.16	76,21,37,205.92
Director's and Local Board Members' Fees and Expenses	1,92,947.32	2,04,826.12
Auditors' Fees	1,15,000.00	1,20,000.00
Rent, Taxes, Insurance, Lighting, etc.	2,89,77,904.60	3,30,23,722.47
Law Charges	6,86,737.47	8,35,249.32
Postage and Telegraph Charges	29,98,712.17	36,16,506.63
Remittance of Treasure	1,49,17,273.55	1,68,67,824.29
Stationery, etc.	1,40 18,699.35	1,15,08,627.55
Security Printing (Cheque, Note Forms, etc.)	23,20,41,612.85	41,57,76,745.55
Depreciation and Repairs to Bank Property	1,87,46,996.12	2,42,64,795.13
Agency Charges	56,09,71,562.84	70,16,50,118.42
Contributions to Staff Gratuity and Superannuation Funds	1,05,00,000.00	1,35,00,000.00
Miscellaneous Expenses	3,69,78,980.50	3,41,09,689.39
Net Available Balance	210,00,00,376.39	210,00,00,712.89
TOTAL	**373,95,20,480.32**	**411,76,16,023.68**
Surplus Payable to Central Government	210,00,00,376.39	210,00,00,712.89
RESERVE FUND ACCOUNT		
By Balance on 30th June	150,00,00,000.00	150,00,00,000.00
By Transfer from Profit and Loss Account	Nil	Nil
TOTAL	**150,00,00,000.00**	**150,0 0,00,000.00**

$After making the usual or necessary provisions in terms of Section 47 of the Reserve Bank of India Act.

[No. F. 12/22/83—BO. II]

C.W. MIRCHANDANI, Director

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 23 मई, 1984

का० आ० 1753.—केन्द्रीय सरकार, काफी नियम, 1955 के नियम 3 और नियम 4 के उपनियम (1) के साथ पठित काफी अधिनियम, 1942 (1942 का 7) की धारा 4 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री टी० चन्द्रशेखर रेड्डि, संसद सदस्य, राज्य सभा सेवा निवृत्त के स्थान पर श्री आर० रामाकृष्णन संसद सदस्य, राज्य सभा को 1 जून, 1984 से तीन वर्षों की अवधि के लिए अथवा जब तक वह राज्य सभा के सदस्य बने रहते हैं तब तक इनमें से जो भी पूर्वतर हो काफी बोर्ड के सदस्य के रूप में निर्वाचन को अधिसूचित करती है।

[फा० संख्या 2/2/84-प्लाट (बी)]

बी० एम० एस० नेगी, अवर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 23rd May, 1984

S.O. 1753.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of section 4 of the Coffee Act, 1942 (7 of 1942) read with rule 3 and sub-rule (1) of rule 4 of the Coffee Rules, 1955, the Central Government hereby notifies the election of Shri R. Ramakrishnan, M.P. Rajya Sabha, as a member of Coffee Board for a period of three years from 1st June, 1984, or so long as he continues to be a member of the Rajya Sabha whichever is earlier, vice Shri T. Chandrasekara Reddy, M.P. Rajya Sabha, retired.

[File No. 2|2|84-Plant (B)]

B.M.S. NEGI, Under Secy.

(मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय)

नई दिल्ली, 3 मई, 1984

आदेश

का० आ० 1754.—मेजर हरजिन्दर सिंह, कोठी नं० 1, पंजाबी बाग, पटियाला को 43,000/- रु० की एक आईसुज जेमिनी कार का आयात करने के लिए एक आयात लाइसेंस सं० पी/एफ/2030237, दिनांक 5-3-83 को प्रदान किया गया था। आवेदक ने उपर्युक्त लाइसेंस की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति और सीमाशुल्क निकासी प्रति के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल आयात लाइसेंस (मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति एवं सीमाशुल्क निकासी प्रति) खो गया है। आगे यह भी कहा गया है कि मूल आयात लाइसेंस मुद्रा विनिमय नियंत्रण एवं सीमाशुल्क निकासी प्रति) किसी भी सीमाशुल्क प्राधिकारी के पास पंजीकृत नहीं करवाया गया है और जैसा कि आयात लाइसेंस (मुद्रा विनिमय नियंत्रण एवं सीमाशुल्क निकासी प्रति) का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया गया है।

2. अपने तर्क के समर्थन में लाइसेंसधारी ने उपर्युक्त न्यायिक प्राधिकारी के सामने विधिवत् शपथ लेकर एक शपथ पत्र दाखिल किया है। तदनुसार, मैं संतुष्ट हूं कि मूल आयात लाइसेंस सं० पी/एफ/2030237 दिनांक 5-3-83 आवेदक द्वारा खो गया है। समय-समय पर यथासंशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 दिनांक 7-12-55 की उप-कंडिका 9 (गग) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए मेजर हरजिन्दर सिंह को जारी किए गए उक्त मूल आयात लाइसेंस सं० पी/एफ/2030237 दिनांक 5-3-83 को एतद्द्वारा रद्द किया जाता है।

3. आयात लाइसेंस (मुद्रा विनिमय नियंत्रण एवं सीमाशुल्क निकासी प्रति) की अनुलिपि प्रति पार्टी को अलग से जारी की जा रही है।

[मि० सं० एफ-34/82-83/बीएलएस/292]

एन० एस० कृष्णमूर्ति, उप-मुख्य नियंत्रक, आयात, निर्यात

(OFFICE OF THE CHIEF CONTROLLER OF IMPORTS AND EXPORTS)

New Delhi, the 3rd May, 1984

ORDER

S.O. 1754.—Major Harjinder Singh, Kothi No. 1, Punjabi Bagh, Patiala was granted Import Licence No. P/F/2030237 dt. 5-3-83 for Rs. 43,000/- for import of one Isuzu Gemini Car. The applicant has applied for issue of Duplicate copy of the above mentioned Import Licence (E. C. copy and Customs Copy) on the ground that the original Import-licence (E. C. copy and Customs Copy) has been misplaced. It has further been stated that the original Import Licence (E. C. copy and Customs Copy) was not registered with any Customs Authority and as such the Import Licence (E. C. copy and Customs Copy) was not utilised at all.

2. In support of his contention, the licensee has filed an affidavit duly sworn before an appropriate judicial authority. I am accordingly satisfied that the original Import Licence No. P/F/2030237 dt. 5-3-83 has been lost by the applicant. In exercise of the powers conferred under Sub-clause 9 (cc) of the Import (Control) Order, 1955 dt. 7-12-1955 as amended from time to time the said original Import Licence No. P/F/2030237 dated 5-3-83 issued to Major Harjinder Singh is hereby cancelled.

3. A duplicate copy of the Import Licence (Customs Copy and Exchange Control Copy) is being issued to the party separately.

[F. No. F-34/82-83|BLS/292]

N. S. KRISHNAMURTHY, Dy. Chief Controller of Imports & Exports

परमाणु ऊर्जा विभाग

बम्बई, 7 मई, 1984

का० आ० 1755.—डा० पी० आर० वर्स्टीदार, निदेशक, रिएक्टर वर्ग, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र को नियुक्ति श्री वी०एन० मैकोनी, जो कि स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो गए हैं, के स्थान पर भाणु ऊर्जा विभाग सुरक्षा पुनरीक्षा समिति के अध्यक्ष के पद पर हो जाने पर राष्ट्रपति ने डा० वर्स्टीदार को 11 अप्रैल, 1984 से परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया है।

[सं० 25/2/83-ई आर/1540]

(कुमारी) एच० बी० विजयकर, अवर सचिव

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

Bombay, the 7th May, 1984

S.O. 1755.—Pursuant to the appointment of Dr. P. R. Dastidar, Director, Reactor Group, Bhabha Atomic Research Centre as Chairman, Department of Atomic Energy Safety Review Committee, vice Shri V. N. Meckoni, voluntarily retired, President is pleased to appoint Dr. Dastidar as member of the Atomic Energy Regulatory Board with effect from April 11, 1984.

[No. 25/2/83-ER/1540]

(Kum.) H. B. VIJAYAKAR, Under Secy.

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(नागरिक पूर्ति विभाग)

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 1984

का० आ० 1756.—केन्द्रीय सरकार भारतीय मानक संस्था (प्रमाण चिन्ह) नियम 1955 के नियम 13 के साथ पठित भारतीय मानक

संस्था (प्रमाणन चिन्ह) अधिनियम 1952 (1952 का 36) की धारा 10 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय मानक संस्था से परामर्श करके यह निदेश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 3 के खण्ड (ङ) के अधीन उक्त संस्था द्वारा प्रयोग की जाने वाली किन्हीं शक्तियों का प्रयोग पंजाब राज्य के भीतर विनिर्मित की जाने वाली निम्नलिखित वस्तु/वस्तुओं के वर्ग के बारे में उद्योग निदेशक पंजाब सरकार द्वारा भी किया जाएगा :—

बिजली के घरेलू उपकरणों की सूची

क्रम संख्या	बिजली के घरेलू उपकरण	मानक
1.	बिजली के इमर्सन वाटर हीटर्स	आई. एस. : 368-1977
2.	भण्डारण-किस्म के बिजली के स्वचालित वाटर हीटर्स	आई. एस. : 2082-1978
3.	बिजली की इस्तरी	आई. एस. : 366-1976
4.	बिजली के स्टोव	आई. एस. : 2994-1965
5.	बिजली की हाट प्लेटें	आई. एस. : 365-1965
6.	बिजली के घरेलू खाद्य मिक्सचर (लिक्वीडाइजर्स ब्लेन्डर्स तथा ग्राइंडर्स)	आई. एस. : 4250-1980
7.	बिजली के टोस्टर	आई. एस. : 1287-1965
8.	बिजली के काफी पर्कोलेटर (बिना-रेग्यूलेटर वाली किस्म के)	आई. एस. : 3514-1966
9.	घरेलू तथा इसी प्रकार के प्रयोग के लिए बिजली की केतलियां तथा जग	आई. एस. : 367-1977
10.	कपड़े धोने की बिजली की घरेलू मशीनें (गैर-स्वचालित)	आई. एस. : 6390-1971
11.	बिजली के रेडियेटर	आई. एस. : 369-1965
12.	बिजली के वाटर-बायलर	आई. एस. : 3412-1965
13.	मेन्स आपरेटेड इलेक्ट्रिक हेयर ड्रायर्स	आई. एस. : 7154-1973
14.	मेन्स आपरेटिड इलेक्ट्रिक शेवर्स	आई. एस. : 5159-1969
15.	खाना पकाने के बिजली के घरेलू ओवन	आई. स. : 5790-1970
16.	भाप की इस्तरी	आई. एस. : 6290-1971
17.	पोर्टेबल, हैंडहेल्ड मेन्स आपरेटिड इलेक्ट्रिक ट्रक मैसेजर्स	आई. एस. : 7137-1973
18.	पोर्टेबल लो स्पीड फूड ग्राइंडिंग मशीनें	आई. एस. : 7603-1975
19.	तत्काल पानी गर्म करने वाले बिजली के हीटर	आई. एस. : 8978-1978
20.	सिंगल वाल्ड बेकिंग ओवन	आई. एस. : 8985-1978

[संख्या 6/2/83-आई० एस० आई०]

उ. र. कुर्लेकर, उप सचिव

MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Civil Supplies)

New Delhi, the 23rd April, 1984

S.O. 1756—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 10 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Act, 1952, (36 of 1952), read with rule 13 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Rules, 1955 the Central Government, in consultation with the Indian Standards Institution, hereby directs that any powers exercisable by the said Institution, under clause (e) of section 3 of the said Act shall be exercisable also by the Director of Industries, Government of Punjab inrelation to the following articles/class of articles manufactured within the State of Punjab, namely :

Schedule of Household Electrical Appliances

S.No.	Household electrical appliances	Standard
1.	Electric immersion water heaters	IS : 368-1977
2.	Storage type automatic electric water heaters	IS : 2082-1978
3.	Electric Irons	IS : 366-1976
4.	Electric stoves	IS : 2994-1965
5.	Electric hot plates	IS : 365-1965
6.	Domestic electric food mixers (liquidizers, blenders and grinders).	IS : 4250-1980
7.	Electric toasters	IS : 1287-1965
8.	Electric Coffee percolaters (Non-regulator type)	IS : 3514-1966
9.	Electric kettles and jugs for household and similar use	IS : 367-1977
10.	Domestic electric clothes washing machine (Non-automatic)	IS : 6390-1971
11.	Electric radiators	IS : 369-1965
12.	Electric water boilers	IS : 3412-1965
13.	Mains-operated electric hair dryers	IS : 7154-1973
14.	Mains,operated electric shavers	IS : 5159-1969
15.	Domestic electric cooking ovens	IS : 5790-1970
16.	Steam Irons	IS : 6290-1971
17.	Portable, hand-held mains-operated electric massagers	IS : 7137-1973
18.	Portable low spped food grinding machines	IS : 7603-1975
19.	Electric instantaneous water heater	IS : 8978-1978
20.	Single walled baking oven	IS : 8985-1978

[No. 6/2/83-SI]

U.R. KURLEKAR, Dy. Secy.

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, 17 मई, 1984

का०आ० 1757.—राष्ट्रपति, मूल नियम के नियम 45 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :—

अनु० नि० 317-ख ग-1

संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारम्भ :—

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम तिलहन विकास, हैदराबाद (सरकारी निवास स्थान आबंटन) नियम, 1984 है।

(2) ये नियम तिलहन विकास निदेशालय, हैदराबाद में नियोजित सरकारी सेवकों को प्राथमिक रूप से निवास स्थान आबंटन के लिए लागू होंगे।

(3) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे

अनु०नि० 317-ख ग-2

परिभाषाएं—

इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) "आबंटन" से, इन नियमों के उपबंधों के अनुसार किसी निवास स्थान को अधिभोग में रखने के लिए अनुज्ञप्ति देना अभिप्रेत है;

(ख) "आबंटन वर्ष" से पहली जनवरी को प्रारंभ होने वाला वर्ष या ऐसी अन्य अवधि अभिप्रेत है जो राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित की जाए;

(ग) "निदेशक" से तिलहन विकास निदेशालय, हैदराबाद का निदेशक अभिप्रेत है।

(घ) "पात्र कार्यालय" से तिलहन विकास निदेशालय का कार्यालय अभिप्रेत है।

टिप्पण : अधिशेष क्वार्टर, यदि कोई हो (तिलहन विकास निदेशालय के कर्मचारिवृन्द की आवश्यकता को पूरा करने के पश्चात) तो उन्हें केन्द्रीय सरकार के अन्य कर्मचारियों और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नियंत्रण के अधीन कार्यालयों /संस्थाओं के पदधारियों को जो हैदराबाद और सिकन्दराबाद शहरों में स्थित कार्यालयों में केन्द्रीय सरकार के ऐसे कर्मचारी हैं जो साधारण पूल वास सुविधा के पात्र हैं, आबंटित किए जा सकते हैं और वे इन नियमों द्वारा, सिवाय इसके कि उनसे अनुज्ञप्ति फीस मू० नि० 45-ख+घ ग के अधीन प्रभारित की जाएगी, शासित होंगे। ऐसे पदधारियों से अनुज्ञप्ति फीस की "वसूली विभाग के प्रधान" के माध्यम से निदेशक द्वारा की जाएगी। "इन मामलों में क्वार्टरों का आबंटन अनंतिम होगा और उस आशय का एक मान्य विधिक वचनबन्ध देने के अधीन होगा कि जैसे ही तिलहन विकास निदेशालय में कोई अधिकारी आबंटन का पात्र होगा वैसे ही वह क्वार्टर आबंटित व्यक्ति द्वारा खाली कर दिया जाएगा।

(ङ) "उपलब्धियों" से मूल नियम 45 ग में यथापरिभाषित उपलब्धियां अभिप्रेत हैं परन्तु इसमें प्रतिकरात्मक भत्ते सम्मिलित नहीं है।

स्पष्टीकरण :—निलम्बित अधिकारी की दशा में "उपलब्धियों" से वे उपलब्धियां मानी जाएंगी जो उसमें उस आबंटन वर्ष के पहले दिन प्राप्त की हैं जिसमें वह निलम्बित किया गया है अथवा यदि वह आबंटन वर्ष के पहले दिन ही निलम्बित किया गया है तो जो उसके द्वारा उस दिन से ठीक पहले प्राप्त की गई है ;

(च) "सम्पदा अधिकारी" से तिलहन विकास हैदराबाद का निदेशक या ऐसा कोई अन्य अधिकारी जो तिलहन विकास हैदराबाद की सम्पदा के प्रशासन के लिए उत्तरदायी है, अभिप्रेत है।

(छ) "कुटुम्ब" से अभिप्रेत है, यथास्थिति, पत्नी अथवा पति और संतान, सौतेली संतान, वैध रूप से दत्तक ली गई संतान, माता-पिता, भाई अथवा बहनें, जो सामान्यतया अधिकारी के साथ निवास करते हैं और जो उस पर आश्रित हैं ;

(ज) "सरकार" से, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, हो, केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है ;

(झ) "हैदराबाद की बृहत्तर नगर पालिका"—हैदराबाद की बृहत्तर नगरपालिका की सीमाओं के भीतर वे क्षेत्र जिन्हें सम्पदा अधिकारी तिलहन विकास निदेशालय, हैदराबाद में निवास स्थान के आबंटन के लिए पात्रता प्रदान करने वाला घोषित करें, अभिप्रेत है।

(ञ) "अनुज्ञप्ति फीस" से इन नियमों के अधीन आबंटित निवास स्थान के संबंध में मूल नियमों के उपबन्धों के अनुसार मासिक रूप से देय धनराशि अभिप्रेत है।

(ट) अधिकारी, का० नि० 327 ख ग 4(1) के उपबन्धों के अधीन जिस प्रकार के निवास स्थान का पात्र है, उसके संबंध से उसकी "पूर्विकता तारीख" से वह पूर्वतन तारीख अभिप्रेत है जब से वह, छुट्टी की अवधि के सिवाय, निरन्तर उतनी उपलब्धियां केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा अन्यत्र सेवा के अधीन पद पर प्राप्त करता रहा है जो किसी विशिष्ट टाईप अथवा किसी उच्चतर टाईप के आबंटन के लिए सुसंगत है।

परन्तु टाईप-1, टाईप 2, टाईप 3 या टाईप 4 के निवासस्थानों के संबंध में, वह तारीख जब से अधिकारी केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार की सेवा में, जिसमें अन्यत्र सेवा की अवधि भी है, निरन्तर रहा है, उसकी उस टाईप के लिए पूर्विकता तारीख होगी :

परन्तु यह और कि जहां दो या अधिक अधिकारियों की पूर्विकता तारीख एक ही हो वहां उनके बीच ज्येष्ठता उपलब्धियों की रकम से अवधारित की जाएगी। अधिक उपलब्धियां प्राप्त करने वाले अधिकारी को कम उपलब्धियां प्राप्त करने वाले अधिकारी से अग्रता दी जाएगी, और जहां उपलब्धियां समान है वहां ज्येष्ठता सेवा काल की दीनता के अनुसार अवधारित की जाएगी;

(ठ) "निवास स्थान" से ऐसा कोई निवास स्थान अभिप्रेत है जो समय निदेशक के प्रशासनिक नियंत्रण में है।

(ड) "शिकमी देने" के अन्तर्गत किसी आबंटित द्वारा अन्य व्यक्ति के साथ उस व्यक्ति द्वारा अनुज्ञप्ति फीस का संदाय करने पर अथवा उसके बिना वास सुविधा का सहभोग करना भी है।

स्पष्टीकरण : आबंटिती द्वारा अपने निकट संबंधियों के साथ वाससुविधा का सहभोग शिकमी देना नहीं समझा जाएगा;

(ढ) "अस्थायी स्थानांतरण" से ऐसा स्थानान्तरण जिसमें अनुपस्थिति की अवधि चार मास से अनधिक है, अभिप्रेत है।

(ण) "स्थानान्तरण" से हैदराबाद / सिकन्दराबाद से किसी अन्य स्थान को या तिलहन विकास निदेशालय के कार्यालय से हैदराबाद या सिकन्दराबाद में किसी अन्य कार्यालय में स्थानान्तरण अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत राज्य सरकार के अधीन सेवा में स्थानांतरण अथवा प्रतिवर्तन और किसी अन्य कार्यालय संगठन में किसी पद पर प्रतिनियुक्ति भी है ;

(त) किसी अधिकारी के संबंध में "टाईप" से निवास स्थान का वह टाईप अभिप्रेत है जिसको वह भू० नि० 317 ख ग 5(1) के अधीन पात्र है।

भ० नि० 317-ख ग-3 जिन अधिकारियों के अपने मकान हैं उनको आबंटन :—

(1) इस नियम में :—

(क) "लगी हुई नगरपालिका अभिप्रेत है जो किसी स्थानीय नगरपालिका से लगी हुई है ;

(ख) किसी अधिकारी या उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य के सम्बन्ध में 'मकान' से ऐसा भवन या उसका कोई भाग अभिप्रेत है जिसका प्रयोग निवास के प्रयोजन के लिए किया जा रहा हो और जो स्थानीय नगरपालिका या किसी लगी हुई नगरपालिका की अधिकारिता के भीतर स्थित हो।

स्पष्टीकरण :—किसी भवन का कोई भाग जिसका प्रयोग निवास के के प्रयोजन के लिए किया जा रहा है, इस खण्ड के प्रयोजन के लिए इस बात के होते हुए भी मकान समझा जाएगा कि उसका कोई भाग अनिवार्यी प्रयोजनों के लिये प्रयोग में लाया जा रहा है;

(ग) किसी अधिकारी के संबंध में "स्थानीय नगरपालिका" से वह नगर पालिका अभिप्रेत है जिसकी अधिकारिता के भीतर उस अधिकारी का कार्यालय स्थित है ;

(घ) किसी अधिकारी के संबंध में "कुटुम्ब के सदस्य" से यथास्थिति, पति/पत्नी, या अधिकारी की उस पर आश्रित सन्तान अभिप्रेत है ;

(ङ) नगरपालिका" के अन्तर्गत नगरनिगम, नगरपालिका समिति या बोर्ड, टाऊन एरिया समिति, नोटीफाईड एरिया समिति और छावनी बोर्ड आते हैं।

(2) यदि किसी अधिकारी के नाम में या उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य के नाम में कोई मकान उसकी ड्यूटी के स्थान में या उससे लगी हुई नगरपालिका में, उसके स्वामित्व में है तो वह सरकार द्वारा समय समय पर अवधारित की गई ऐसी दर पर सरकारी वाससुविधा के लिए अनुज्ञप्ति फीस का संदाय करके सरकारी निवास स्थान के आबंटन के लिए पात्र होगा।

(3) यदि किसी अधिकारी को जिसके पास सरकारी निवास स्थान है, वह या उसके कुटुम्ब का कोई व्यक्ति उस अधिकारी के ड्यूटी के स्थान में या उससे लगी हुई नगरपालिका में किसी मकान का स्वामी हो जाता है, तो ऐसा अधिकारी उस तथ्य की बाबत ऐसे मकान को किराये पर दिए जाने या अधिभोग की तारीख से या मकान पूरा किया जाने की तारीख से इनमें से जो भी पहले हो एक मास के भीतर संपदा अधिकारी को सूचित करेगा।"

अनु० नि० 317—ख ग—4 पति और पत्नी को आबंटन, एक दूसरे से विवाहित अधिकारियों के मामले में पात्रता :—

(1) किसी अधिकारी को, यथास्थिति, जिसकी पत्नी या जिसके पति को पहले ही निवास स्थान आबंटित किया जा चुका है, इन नियमों के अधीन कोई निवास स्थान तब तक आबंटित नहीं किया जाएगा जब तक ऐसा निवास स्थान अभ्यर्पित नहीं कर दिया जाता ;

परन्तु यह उपनियम वहां लागू नहीं होगा जहां पति और पत्नी किसी न्यायालय द्वारा किए गए न्यायिक पृथक्करण के आदेश के अनुसरण में पृथक पृथक निवास कर रहे हैं।

(2) जहां दो अधिकारी, जो इन नियमों के अधीन पृथक रूप से आबंटित निवास स्थानों के अधिभोगी हैं एक दूसरे से विवाह कर लें वहां वे विवाह के एक मास के भीतर उन निवास स्थानों में से एक अभ्यर्पित कर देंगे।

(3) यदि निवास स्थान का अभ्यर्पण उपनियम (2) की अपेक्षानुसार नहीं किया जाता है तो निम्नतर टाईप के निवास स्थान का आबंटन ऐसी अवधि के अवसान पर रद्द समझा जाएगा और यदि निवास स्थान एक ही टाईप है तो संपदा अधिकारी के विनिश्चयानुसार उनमें से एक का आबंटन ऐसी अवधि के अवसान पर रद्द समझा जाएगा।

(4) जहां पति और पत्नी दोनों ही तिलहन निदेशालय हैदराबाद में या किसी ऐसे कार्यालय में जिसके कर्मचारिवृन्द को निवास स्थान के आबंटन के लिए पात्र घोषित किया गया है नियोजित है वहां उन दोनों में से प्रत्येक को इन नियमों के अधीन निवास स्थान के आबंटन के हक पर स्वतंत्र रूप से विचार किया जाएगा।

(5) उपनियम (1) से (4) तक में किसी बात के होते हुए भी—

(क) यदि यथास्थिति पत्नी या पति को जो इन नियमों के अधीन निवास स्थान का आबंटिती है ऐसे पूल से, जिसे ये नियम लागू नहीं होते, एक ही स्टेशन पर बाद में निवास स्थान संबंधी कोई वास-सुविधा आबंटित कर दी जाती है तो यथास्थिति पत्नी या पति ऐसे आबंटन के एक मास के भीतर इन निवास स्थानों में से कोई एक अभ्यर्पित कर देगा :—

परन्तु यह खंड वहां लागू होगा जहां पति और पत्नी किसी न्यायालय द्वारा किए गए न्यायिक पृथक्करण के आदेश के अनुसरण में पृथक पृथक निवास कर रहे हैं—

(ख) जहां दो अधिकारी, जो एक ही स्टेशन पर ऐसे पृथक निवास स्थानों के अधिभोगी हैं जिनमें से एक निवास स्थान इन नियमों के अधीन आबंटित किया गया है और दूसरा ऐसे पूल से, जिसे ये नियम लागू नहीं होते, एक दूसरे से विवाह करलें, वहां उनमें से कोई भी एक अधिकारी ऐसे विवाह के एक मास के भीतर उन निवास स्थानों में से किसी एक को अभ्यर्पित कर देगा;

(ग) यदि निवास स्थान का अभ्यर्पण (क) या खंड (ख) की अपेक्षानुसार नहीं किया जाता है तो निवास स्थान का आबंटन ऐसी अवधि के अवसान पर रद्द समझा जाएगा और उसके पश्चात निवास के अभिभोग के लिए नुकसानी वसूलीय होगी।

अनु० नि० 317—ख ग 5 निवास स्थानों का वर्गीकरण

इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, आबंटन के प्रयोजनों के लिए कोई अधिकारी नीचे दी गई सारणी में दर्शित टाईप के निवास स्थान के आबंटन का पात्र होगा :—

निवास स्थान का टाईप	उस आबंटन वर्ष के पहले दिन जिसमें आबंटन किया जाता है, अधिकारी का प्रवर्ग या उसकी मासिक उपलब्धियां
1	2
टाईप—1	260 रुपए से अधिक
टाईप—2	500 रुपए से कम किन्तु 260 रुपए से कम नहीं
टाईप—3	1000 रु० से कम किन्तु 500 रु० से कम नहीं
टाईप—4	1500 रु० से कम किन्तु 1000 रुपए से कम नहीं
टाईप—5	1500 रुपए और उससे अधिक
टाईप—6	तिलहन विकास हैदराबाद के निदेशक के लिए अलग से रखा जाएगा।

(2) यदि तिलहन विकास निदेशालय के किसी अधिकारी के लिए उस टाईप की वास सुविधा जिसका वह हकदार है, उपलब्ध नहीं है तो सम्बद्ध अधिकारी में आबंटन पर ठीक उससे नीचे वाली टाईप की वास सुविधा का आबंटन, ऐसी वास सुविधा के लिए हकदार व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति किए जाने के पश्चात तब किया जा सकता है जब ऐसी कोई वास सुविधा उपलब्ध हो और वह इस शर्त के अधीन होगा कि ज्यों ही उस टाईप की वास सुविधा जिसका वह हकदार है उपलब्ध होती वह सम्बद्ध व्यक्ति को आबंटित कर दी जाएगी।

(3) यह और कि, निदेशक, तिलहन विकास निदेशालय हैदराबाद के किसी ऐसे कर्मचारिवृन्द को जिसे उस टाईप की वास सुविधा जिसका वह हकदार है, आबंटित नहीं हुई है, अनुरोध पर उस टाईप से जिसका/जिसकी वह हकदार है, ठीक एक ऊपरवाली निवासी वास सुविधा का आबंटन निम्नलिखित शर्तों के अधीन कर सकेगा, अर्थात :-

(क) ऐसी वास सुविधा के आबंटन के समय, तिलहन विकास निदेशालय, हैदराबाद के ऐसी कर्मचारिवृन्द की ऐसी उच्चतर टाईप की वास सुविधा की बाबत वेतनमान के अनुसार उनके हकदार होने की आवश्यकताओं को पूर्ण रूप से पूरा कर दिया गया है ;

(ख) जैसा खंड (क) में दर्शित किया गया है, जहां उच्चतर टाईप की वास सुविधा तिलहन विकास निदेशालय के कर्मचारिवृन्द की आवश्यकताओं से अधिक है वहां उसे तिलहन विकास निदेशालय के ऐसे कर्मचारिवृन्द को आबंटित की जा सकती है जो कि उसका हकदार नहीं है ;

परन्तु यह कि उक्त अधिकारी जो उक्त उच्चतर वास सुविधा का हकदार नहीं है ऐसे आबंटन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर उप नियम (1) के अनुसार उस वास सुविधा का हकदार हो जाएगा उस वास सुविधा के लिए हकदार न होने की अवधि के दौरान वसूलीय अनुज्ञप्ति फीस मू० नि० 45-क के अधीन उपलब्धियों को 10 प्रतिशत तक सीमित किए बिना पूर्ण मानक अनुज्ञप्ति फीस होगी।

अनु० नि० 317—ख ग 6 आबंटन के लिए आवेदन :—

प्रत्येक सरकारी सेवक, तिलहन विकास निदेशालय, हैदराबाद में या हैदराबाद और सिकन्दराबाद में स्थित किसी अन्य केन्द्रीय सरकार के कार्यालय में अपनी तिनुक्ति/तैनाती के एक माह के भीतर अपनी पर्याप्त प्रास्थिति के लिए समुचित टाईप के निवासीय क्वार्टर के आबंटन के लिए आवेदन कर सकेगा। सभी टाईप के निवासों के आबंटन के लिए आवेदन उचित माध्यम से निदेशक को भेजे जाएंगे जो प्रत्येक टाईप के निवास स्थानों के लिए, प्रतीक्षा सूची बनाए रखेगा जिसमें से एक सूची तिलहन विकास निदेशालय के कर्मचारियों के लिए और दूसरी सूची अन्यों के लिए पृथक पृथक होगी प्रतीक्षा सूची अधिकारियों की पूर्विकता की तारीख के अनुसार क्रमांकित की जाएगी। ऐसे अधिकारी जिनके पास पहले से ही वास सुविधा है वह स्वतः ही उच्चतर टाईप के निवास स्थान के लिए उस तारीख से जिस तारीख से वह ऐसी टाईप की वास सुविधा के लिए हकदार होंगे प्रतीक्षा सूची में आ जाएंगे हकदार बनने की तारीख के आधार पर प्रतीक्षा सूची के अनुसार आबंटन किया जाएगा।

अनु० नि० 317—ख ग 7 निवास स्थानों का आबंटन और प्रस्थापनाएं:—

(1) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, किसी निवास स्थान के खाली होने पर वह निदेशक द्वारा अधिमान्यतः उस आवेदक को आबंटित किया जाएगा जो उस टाईप की आवास सुविधा का परिवर्तन चाहता है, और यदि उस प्रयोजन के लिए अपेक्षित न हो तो, उस आवेदक को आबंटित किया जाएगा जिस के पास उस टाईप की आवास सुविधा नहीं है और जिसकी, उस टाईप के लिए पूर्विकता तारीख सब से पहले हो, आबंटन निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा।

(1) संपदा अधिकारी उस टाईप से उच्चतर टाईप का निवास स्थान आबंटित नहीं करेगा जिसका आवेदक पात्र है ;

(2) संपदा अधिकारी किसी आवेदक को इस बात के लिए विवश नहीं करेगा कि वह जिस टाईप के निवास स्थान का पात्र है उससे निम्नतर टाईप का निवास स्थान स्वीकार करें ;

(2) संपदा अधिकारी निम्नतर प्रवर्ग के निवास स्थान के आबंटन के लिए किसी आवेदक (जो केवल तिलहन विकास निदेशालय का होगा) के अनुरोध पर उसे ऐसे टाईप में ठीक निम्नतर टाईप के निवास स्थान को आबंटित कर सकता है जिसके लिए आवेदक उसके लिए अपनी पूर्विकता तारीख के आधार पर पात्र है।

(3) यदि किसी अधिकारी के अधिभोग के निवास स्थान को खाली करवा अपेक्षित हो तो संपदा अधिकारी उस अधिकारी का विद्यमान आबंटन रद्द कर सकता है और उसे उसी टाईप का अनुकल्पी निवास स्थान या अत्यावश्यकता की स्थिति में, उस अधिकारी के अधिभोग के निवास स्थान के टाईप से ठीक निम्नतर टाईप का अनुकल्पी निवास स्थान आबंटित कर सकता है ;

(4) खाली निवास स्थान को, पूर्वोक्त उपनियम (1) के अधीन उसे किसी अधिकारी को आबंटित किए जाने के अतिरिक्त अन्य पात्र अधिकारियों को, उनकी पूर्विकता तारीखों के क्रम से, आबंटन के लिए प्रस्थापित किया जा सकता है।

अनु० नि० 317 ख ग 8 आबंटन या प्रस्थापना का स्वीकार न किया जाना या आबंटित स्थान को स्वीकार करने के पश्चात अधिभोग में न लेना :—

(1) यदि कोई अधिकारी किसी निवास स्थान का आबंटन, आबंटन पत्र की प्राप्ति की तारीख से पांच दिन के भीतर स्वीकार नहीं करता है अथवा स्वीकार करने के बाद भी आठ दिन के भीतर उस निवास स्थान का कब्जा नहीं लेता है तो वह उस आबंटन पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि पर्यन्त दूसरे आबंटन का पात्र न होगा।

(2) यदि किसी अधिकारी को, जिसके अधिभोग में किसी निम्नतर टाईप का निवास स्थान ऐसे टाईप का निवास स्थान आबंटित या प्रस्थापित किया जाता है जिसके लिए वह का० नि० ख ग 5 (1) के अधीन पात्र है या जिसके लिए वह का० नि० ख ग 5(2) के अधीन आवेदन किया है तो उसे उक्त आबंटन को या आबंटन की प्रस्थापना को अस्वीकार कर देने पर, पूर्वतन आबंटित निवास स्थान में रहने के लिए निम्नलिखित शर्तों पर अनुज्ञात किया जा सकता है, अर्थात :—

(क) ऐसा अधिकारी, उच्चतर श्रेणी वास सुविधा के लिए आबंटन की तारीख से वह 6 मास की अवधि के लिए अन्य आबंटन के लिए पात्र नहीं होगा,

(ख) वर्तमान निवास स्थान रखे रहने के दौरान उस पर वही अनुज्ञप्ति फीस प्रभारित की जाएगी, जो उसे म० नि० 45-क के अधीन इस प्रकार आबंटित या प्रस्थापित निवास स्थान के लिए संदत्त करनी पड़ती अथवा वह अनुज्ञप्ति फीस जो उस निवास स्थान के लिए देय है जो पहले ही उसके अधिभोग में है, दोनों में से जो भी अधिक हो।

अनु० नि० 317 ख ग 9 आबंटन प्रभावी रहने की अवधि और तत्पश्चात कब्जा बनाए रखने की रियायती अवधि :—

(1) आबंटन उस तारीख से प्रभावी होगा जिसको वह अधिकारी द्वारा स्वीकार किया जाता है और तब तक प्रवृत्त रहेगा जब तक कि—

(क) अधिकारी के कर्तव्यारूढ़ न रह जाने के पश्चात वह रियायती अवधि समाप्त नहीं हो जाती जो उपखंड (2) के अधीन अनुज्ञेय है ;

(ख) वह संपदा अधिकारी द्वारा रद्द नहीं कर दिया जाता या इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों के अधीन रद्द किया गया नहीं समझा जाता ;

(ग) वह अधिकारी द्वारा अभ्यर्पित नहीं कर दिया जाता;

(घ) अधिकारी निवास स्थान का अधिभोग समाप्त नहीं कर देता।

(2) अधिकारी उसे आबंटित निवास स्थान को उपनियम (3) के अधीन रहते हुए निम्न सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट घटनाओं में से किसी के होने पर उस अवधि पर्यन्त अपने पास रख सकता है जो उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है; परन्तु यह तब जब कि वह निवास स्थान उस अधिकारी या उसके कुटुम्ब के सदस्यों के वास्तविक उपयोग के लिए अपेक्षित हो ;

घटनाएं	निवास स्थान पर कब्जा बनाए रखने की अनुज्ञेय अवधि
1	2
1. पदत्याग, पदच्युति या सेवा से हटाया जाना पूर्व सेवा का पर्यवसान अथवा बिना अनुज्ञा के अप्राधिकृत अनुपस्थिति	एक मास
2. सेवा निवृत्ति या सेवान्त छुट्टी	दो मास
3. आबंटिती की मृत्यु	चार मास
4. हैदराबाद से बाहर किसी स्थान के लिए स्थानान्तरण	दो मास
5. किसी ऐसे कार्यालय को स्थानान्तरण जो इन नियमों के अधीन निवास स्थान के लिए पात्र नहीं है	दो मास
6. भारत से अन्यत्र सेवा पर जाना	दो मास
7. भारत में अस्थायी स्थानान्तरण अथवा भारत से बाहर किसी स्थान के लिए स्थानान्तरण	चार मास
8. (छुट्टी) जो निवृत्ति पूर्व छुट्टी, अस्वीकृत छुट्टी की अवधि पर्यन्त किन्तु छुट्टी, सेवान्त छुट्टी, चिकित्सीय छुट्टी या अध्ययनार्थ छुट्टी से भिन्न हो	चार मास से अधिक नहीं।

1	2
9. निवर्तित पूर्व छुट्टी या मू० नि० 86 या के० सि० से० छुट्टी नियम, 1972 के नियम 39 के अधीन दी गई अस्वीकृत छुट्टी।	पूरे औसत वेतन पर छुट्टी की पूर्ण अवधि पर्यन्त किन्तु चार मास की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए इसमें सेवा निवृत्ति की दशा में अनुज्ञेय अवधि भी सम्मिलित है।
10. अध्ययनार्थ छुट्टियां भारत से बाहर प्रतिनियुक्ति	छुट्टी की पूरी अवधि के लिए किन्तु छह मास से अधिक नहीं।
11. चिकित्सीय आधार पर छुट्टी	छुट्टी की पूर्ण अवधि पर्यन्त
12. भारत मे अध्ययनार्थ छुट्टी	छुट्टी की पूर्व अवधि पन्त किन्तु छह मास से अधिक नहीं।
13. प्रशिक्षणार्थ जाने पर	प्रशिक्षण की पूर्ण अवधि पर्यन्त।

स्पष्टीकरण I जहां स्थानांतरण या अन्यत्र सेवा में किसी अधिकारी को छुट्टी दी जाती है और वह नए कार्यालय में ड्यूटी प्रारंभ करने से पूर्व उसका उपभोग करता है वहां उसको मद संख्या (4), (5), (6), (7) और (8) के सामने उल्लिखित अवधि के लिए या छुट्टी की अवधि के लिए, इनमें से जो भी अधिक हो, निवास स्थान प्रतिधारित करने की अनुज्ञा दी जाएगी।

स्पष्टीकरण–II जहां किसी ऐसे अधिकारी को स्थानांतरण का या भारत में अन्यत्र सेवा का आदेश जारी किया जाता है जो पहले से ही छुट्टी पर है तो स्पष्टीकरण के खंड (1) के अधीन अनुज्ञात अवधि, ऐसे आदेश के जारी किए जाने की तारीख से संगणित की जाएगी।

(3) यदि उपनियम (2) के अधीन किसी निवास स्थान का कब्जा बनाए रखा जाता है तो आबंटन, अनुज्ञेय रियायती अवधि के अवसान पर रद्द समझा जाएगा जब तक कि उसके अवसान पर तुरन्त अधिकारी किसी पात्र कार्यालय में ड्यूटी पुनः प्रारंभ न कर दे।

(4) जब कोई अधिकारी बिना वेतन और भत्तों के चिकित्सा छुट्टी पर है तो वह उपनियम (2) के नीचे सारणी के पद (11) के अधीन रियायत के आधार पर अपने निवास स्थान का कब्जा बनाए रख सकता है :

परन्तु यह तब जब कि वह ऐसे निवास स्थान के लिए अनुज्ञप्ति फीस प्रतिमास नकद भेजता रहता है और जहां वह ऐसी अनुज्ञप्ति दो क्रमवर्ती मास की अधिक फीस दो मास के अधिक तक न भेजने में असफल रहता है तो आबंटन रद्द हो जाएगा।

(5) वह अधिकारी जिसने उपनियम (2) के नीचे सारणी की मद (1) या मद (11) के अधीन रियायत के आधार पर निवास-स्थान का कब्जा बनाए रखा है वह किसी पात्र कार्यालय में उक्त सारणी में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर पुनः नियोजित हो जाने पर इस बात का हकदार होगा कि उस निवास स्थान का कब्जा बनाए रखें और वह इन नियमों के अधीन निवास-स्थान के और किसी आबंटन का भी पात्र हो जाएगा :

परन्तु यह कि यदि ऐसे पुनर्नियोजन पर अधिकारी की उपलब्धियां उसे उस टाइप के क्वार्टर के लिए जिसका अधिभोग वह कर रहा है हकदार नहीं बनाती हैं तो उसे निम्नतर टाइप का निवास-स्थान आबंटित किया जाएगा।

(6) इस नियम के उपनियम (2) का उपनियम (3) या उपनियम (4) में किसी बात के होते हुए भी जब कोई अधिकारी पदच्युत किया जाता है या सेवा से हटाया जाता है या जब उसकी सेवा पर्यवसित की जाती है और उस विभाग के प्रधान को जिसमें वह अधिकारी; ऐसी पदच्युति; हटाए जाने या समापन के ठीक पूर्व नियोजित था; यह समाधान हो जाता है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह सम्पदा अधिकारी से यह अपेक्षा कर सकेगा कि उस अधिकारी को किए गए निवास स्थान का आबंटन या तो तुरन्त रद्द कर दे या उस तारीख से रद्द कर दे जो उपनियम (2) के नीचे की सारणी के मद (1) में निर्दिष्ट एक मास की अवधि की समाप्ति से पूर्वतर है और जो वह विनिर्दिष्ट करे तथा सम्पदा अधिकारी तदनुसार कार्रवाई करेगा।

अ० नि० 317 खण्ड–10 अनुज्ञप्ति फीस से संबंधित उपबंध :—

(1) जहां जब वास-सुविधा या अनुकल्पिक वास-सुविधा का आबंटन स्वीकार कर लिया जाता है तो अनुज्ञप्ति फीस का दायित्व अधिभोग की तारीख से अथवा आबंटन की प्राप्ति की तारीख के आठवें दिन से जो भी पूर्वतर हो; प्रारम्भ होगा।

(2) कोई अधिकारी जो आबंटन स्वीकार करने के तत्पश्चात् उस वास-सुविधा का कब्जा आबंटन-पत्र की प्राप्ति की तारीख से आठ दिन के भीतर नहीं लेता उससे उस तारीख से बारह दिन की अवधि तक अनुज्ञप्ति फीस ली जाएगी परन्तु यह कि इसमें अंतर्विष्ट कोई भी बात उस मामले में लागू नहीं होगी जिसमें लोक निर्माण विभाग यह प्रमाणित करता है कि निवास स्थान अधिभोग के योग्य नहीं है और उसके परिणाम-स्वरूप अधिकारी ने निवास-स्थान का अधिभोग पूर्वोक्त अवधि के भीतर नहीं किया।

(3) जहां किसी अधिकारी को जो एक निवास-स्थान का अधिभोगी है दूसरा निवास-स्थान आबंटित किया जाता है और वह नए निवास-स्थान का अधिभोग प्राप्त कर लेता है तो पहले निवास-स्थान का आबंटन नए निवास-स्थान का अधिभोग प्राप्त करने की तारीख से रद्द समझा जाएगा। तथापि निवास-स्थान के परिवर्तन के लिए वह पहले निवास-स्थान को उस दिन तथा उसके बाद के एक दिन तक बिना अनुज्ञप्ति फीस दिए अपने पास रख सकता है।

अनु० नि० 317-खण्ड 11: निवास स्थान के खाली किए जाने तक अधिकारी का अनुज्ञप्ति फीस देने का वैयक्तिक दायित्व तथा अस्थायी अधिकारियों द्वारा प्रतिभू दिया जाना :—

(1) वह अधिकारी जिसको निवास-स्थान का आबंटन किया गया है उसकी अनुज्ञप्ति फीस के संदाय तथा उस नुकसान के लिए व्यक्तिगत रूप से दायी होगा जो उचित टूट-फूट के अतिरिक्त हो और जो उस निवास-स्थान को अथवा सरकार द्वारा उसमें दिए गए फर्नीचर; फिक्सचर; फिटिंग या सेवा-व्यवस्था को उस अवधि के दौरान हो; जब निवास-स्थान उसे आबंटित कर दिया जाता है और उसे आबंटित रहता है या; जहां आबंटन इन नियमों के किसी उपबंध के अधीन रद्द कर दिया जाता है; वहां जब तक निवास-स्थान तथा उससे संलग्न उपग्रह खाली नहीं कर दिए जाते हैं और उनका पूर्णतः खाली रूप में कब्जा सरकार को वापस नहीं कर दिया जाता है।

(2) जहां वह अधिकारी जिसे निवास-स्थान आबंटित किया गया है; न तो स्थायी सरकारी सेवक है और न स्थायीवत् वहां वह प्रतिभू सहित; केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विहित प्ररूप में; प्रतिभूति-पत्र निष्पादित करेगा। वह प्रतिभू केन्द्रीय सरकार के अधीन सेवा करने वाला स्थायी सरकारी सेवक होना चाहिए। वह प्रतिभूति पत्र अनुज्ञप्ति फीस तथा अन्य ऐसे प्रभारों के संदाय के लिए होगा जो उस निवास-स्थान और अन्य सेवाओं की बाबत तथा उसके बदले में दिए गए किसी अन्य निवास-स्थान की बाबत उसके द्वारा देय हों।

(3) यदि प्रतिभू सरकारी सेवा में नहीं रह जाता या दिवालिया हो जाता है या किसी अन्य कारण से उपलब्ध नहीं रह जाता है तो अधिकारी किसी अन्य प्रतिभू द्वारा निष्पादित एक नया बन्धपत्र उस घटना या

सक्ष्य की जानकारी प्राप्त होने की तारीख से तीस दिन के भीतर देगा और यदि वह ऐसा न करे तो; जब तक कि निदेशक अन्यथा विनिश्चय न करे; उस निवास-स्थान का उसे आबंटन उस घटना की तारीख से रद्द किया गया समझा जाएगा।

अनु० नि० 317 ख०ग० 12 आबंटन की अभ्यर्पण और सूचना की अवधि :—

(1) अधिकारी ऐसी सूचना देकर जो निवास-स्थान को खाली करने की तारीख से कम से कम दस दिन पूर्व निदेशक के पास पहुंच जाए किसी भी समय आबंटन को अभ्यर्पित कर सकता है। निवास-स्थान का आबंटन उस दिन के पश्चात् जिसको पत्र निदेशक को प्राप्त होता है; ग्यारहवें दिन से या पत्र में विनिर्दिष्ट तारीख से; जो भी पश्चातवर्ती हो; रद्द किया गया समझा जाएगा। यदि अधिकारी सम्यक सूचना न दे तो वह दस दिन की अथवा दस दिन की सूचना देने में जितने दिन की कमी हो उतने दिन की अनुज्ञप्ति फीस देने के लिए उत्तरदायी होगा परन्तु निदेशक अवधि की सूचना स्वीकार कर सकता है यदि उसका समाधान हो जाता है कि विहित सूचना उस कारण से न दी जा सकी जो आबंटिती के नियंत्रण से परे था।

(2) उप-नियम (1) के अधीन निवास-स्थान अभ्यर्पित करने वाले अधिकारी के संबंध में उसी स्टेशन पर सरकारी आवास-सुविधा का आबंटन करने के लिए ऐसे अभ्यर्पण की तारीख से एक वर्ष की कालावधि तक पुनः विचार नहीं किया जाएगा।

अनु० नि० 317 ख०ग० 13 :—निवास-स्थान का परिवर्तन :—

(1) जिस अधिकारी को इन नियमों के अधीन निवास स्थान का आबंटन किया गया है वह आवेदन कर सकता है कि उसको उसके बदले में उस टाइप का अथवा उस टाइप का जिसका वह पात्र है निवास-स्थान दिया जाए। किसी अधिकारी को आबंटित एक टाइप के निवास-स्थान की बाबत केवल एक बार से अधिक परिवर्तन की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी। किसी विशेष निवास-स्थान के लिए परिवर्तन की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

(2) परिवर्तन के लिए वे सभी आबंटन जो संपदा अधिकारी द्वारा विहित प्ररूप में किए गए हों और किसी कलैण्डर मास के उन्नीसवें दिन तक प्राप्त हों अगले मास की प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित किए जाएंगे। इन नियमों के प्रयोजनों के लिए; वे अधिकारी; जिनके नाम पूर्ववर्ती मास की प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित किए गए हैं; समुच्चयित रूप से उन अधिकारियों से ज्येष्ठ होंगे जिनके नाम पश्चातवर्ती मास की सूची में सम्मिलित किए जाते हैं। किसी विशिष्ट मास की सूची में सम्मिलित किए गए अधिकारियों की परस्पर ज्येष्ठता उनकी पूर्विकता तारीखों के क्रम में अवधारित की जाएगी।

(3) परिवर्तन का अवसर; उपनियम (2) के अनुसार अवधारित ज्येष्ठता के क्रम से तथा अधिकारियों की अपनी पसन्द का यथासंभव स्थान रखते हुए दिया जाएगा।

(परन्तु अधिवार्षिता की तारीख से ठीक छः मास पहले की अवधि के दौरान निवास के परिवर्तन की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी)।

(4) यदि कोई अधिकारी निवास स्थान के परिवर्तन की प्रस्थापना या आबंटन जारी किए जाने के पांच दिन के भीतर उसे स्वीकार नहीं करता तो उसके नाम पर; उस टाइप के निवास स्थान के परिवर्तन के लिए पुनः विचार नहीं किया जाएगा।

(5) जो अधिकारी; निवास स्थान का परिवर्तन स्वीकार करने के पश्चात् उसका कब्जा नहीं लेता उससे ऐसे निवास स्थान के लिए अनु० नि० 317-ख०ग–11 के उपनियम (1) के उपबंधों के अनुसार अनुज्ञप्ति फीस ली जाएगी, जो उस निवास स्थान के लिए जो पहले ही उसके कब्जे में है और जिसका आबंटन बराबर बना रहेगा; मू०नि० 45-क के अधीन प्रसामान्य अनुज्ञप्ति फीस के अतिरिक्त होगी।

अनु० नि० 317 ख०ग–14 निवास-स्थानों का पारस्परिक विनिमय :—

जिन अधिकारियों को इन नियमों के अधीन एक ही टाइप के निवास स्थान आबंटित किए गए हैं वे आवेदन कर सकते हैं कि उन्हें अपने निवास स्थानों का पारस्परिक विनिमय करने की अनुज्ञा दी जाए। जब इस बात की उचित तौर पर प्रस्थापना हो कि दोनों अधिकारी ऐसे विनिमय के अनुमोदन की तारीख से कम से कम छह मास कर्तव्यारूढ़ रहते और पारस्परिक रूप से विनिमय में प्राप्त अपने निवास स्थानों में रहेंगे तब पारस्परिक विनिमय की अनुज्ञा दी जा सकती है।

अनु० नि० 317 ख०ग–15—निवास स्थान का रख रखाव :—

(1) जिस अधिकारी को निवास स्थान का आबंटन किया गया है वह उसे और परिसरों को केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग तथा हैदराबाद नगर निगम के समाधानप्रद रूप से साफ दशा में रखेगा। ऐसा अधिकारी उस निवास स्थान से संलग्न किसी बाग; लॉन या चार दिवारी में न तो सरकार या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के विरुद्ध कोई वृक्ष गाड़ी या पौधे उगाएगा और न ही किसी विद्यमान वृक्ष या झाड़ी को केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना काटेगा या छांटेगा। इस नियम के उल्लंघन में उगाए गए वृक्ष पौधे या वनस्पति संबंधित अधिकारी की जोखिम पर और उसके खर्च पर निदेशक या लोक निर्माण विभाग द्वारा हटवाए जा सकेंगे।

अनु० नि० 317 ख०ग–16 निवास स्थान की शिकमी देना और सहभोग :—

(1) कोई अधिकारी अपने आबंटित निवास स्थान या उससे संलग्न उपगृहों, गैरजों और अस्तबलों का सहभोग इन नियमों के अधीन निवास स्थान के आबंटन के पात्र केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के साथ ही करेगा। सेवक निवासों, उपगृहों और गैरजों का उपयोग केवल उचित प्रयोजनों के लिए, जिनके अन्तर्गत आबंटिती के सेवकों का निवास भी है, या अन्य ऐसे प्रयोजनों के लिए किया जाएगा जिनकी मंडल अधिकारी अनुज्ञा दे।

(2) कोई अधिकारी अपने सम्पूर्ण निवास स्थान को शिकमी नहीं देगा :

परन्तु छुट्टी पर जाने वाला अधिकारी अपने निवास स्थान में किसी अन्य अधिकारी को, जो सरकारी निवास स्थान का सहभोग करने के लिए पात्र है, देखभाल करने वाले के रूप में अ० नि० 317 ख०ग 9 में विनिर्दिष्ट अवधि पर्यन्त, किन्तु छह मास से अधिक नहीं रख सकता है।

(3) जो अधिकारी अपने निवास स्थान का सहभोग करे या उसे शिकमी दे वह ऐसा अपनी जोखिम और उत्तरदायित्व पर करेगा और उस निवास स्थान की बाबत देय कोई अनुज्ञप्ति फीस देने के लिए और ऐसे किसी नुकसान के लिए वैयक्तिक रूप से उत्तर-दायी बना रहेगा, जो निवास स्थान को या उसकी सीमाओं या भूमियों को या सरकार द्वारा उसमें की गई सेवा व्यवस्थाओं को पहुंचे और जो उचित टूट-फूट के अतिरिक्त हो।

(4) निवास स्थान का सहभोग केवल निदेशक की पूर्व अनुज्ञा से ही किया जा सकता है।

अनु० नि० 317 ग-17 उन स्थानों के लिए स्थानान्तरण जहां कुटुम्ब नहीं रखा जा सकता :—

यदि किसी अधिकारी का स्थानान्तरण किसी ऐसे स्थान को किया जाता है जहां उसे अपना कुटुम्ब साथ ले जाने के लिए सरकार द्वारा

अनुज्ञा नहीं दी जाती या सलाह नहीं दी जाती और इन नियमों के अधीन उसे आबंटित निवास स्थान उसकी संतान को वास्तविक शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं के लिए कुटुम्ब द्वारा अपेक्षित है तो उसे, प्रार्थना करने पर, अपनी संतान के चालू शैक्षणिक सत्र के अंत तक मु० नि० 45 क के अधीन अनुज्ञप्ति फीस के संदाय पर निवास स्थान रखने के लिए अनुज्ञा दी जा सकती है। तथापि यह नियम आरक्षित आवास के मामले में लागू नहीं होता जिसमें मंडल अधिकारी का आदेश का० ज्ञा० सं० 2/52/64 ए सी सी/ता. 20 मार्च, 1965 आरक्षित आवास का कब्जा बनाए रखने को विनियमित करेगा।

अनु० नि० 317 ख ग-18 नियमों और शर्तों को भंग करने का परिणाम:—

(1) यदि वह अधिकारी जिसे निवास स्थान आबंटित किया गया है, अप्राधिकृत रूप से निवास स्थान शिकमी देता है या सहभोगी से अनुज्ञप्ति फीस ऐसी दर से लेता है जिसे निदेशक अत्यधिक समझता है अथवा कोई अप्राधिकृत संरचना अथवा उसके किसी भाग का निर्माण उन प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिए करता है जिनके लिए वह अभिप्रेत है अथवा विद्युत या जल के कनेक्शन को बिगाड़ता है अथवा इन नियमों का आबंटन के निबंधनों और शर्तों को भंग करता है अथवा किन्हीं ऐसे प्रयोजनों के लिए, जिन्हें निदेशक अनुचित समझे, निवास स्थान या परिसर का उपयोग करता है या किए जाने की अनुज्ञा देकर नुकसान पहुंचाता है अथवा स्वयं ऐसा आचरण करता है या जो संपदा निदेशक की राय में उस अधिकारी के पड़ोसियों से शान्तिपूर्ण संबंधों को बनाए रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है, अथवा आवंटन प्राप्त करने की दृष्टि से किसी आवेदन या लिखित कथन में कोई गलत जानकारी जानबूझकर देता है, तो निदेशक उसे अनुशासनिक कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जो उस अधिकारी के विरुद्ध की जा सकती है, निवास स्थान का आबंटन रद्द कर सकता है।

स्पष्टीकरण — इस उपनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, "अधिकारी" पद के अन्तर्गत उसके कुटुम्ब का कोई सदस्य और ऐसे अधिकारी के माध्यम से दावा करने वाला कोई व्यक्ति भी है।

(2) यदि कोई अधिकारी उसे आबंटित निवास स्थान को या उसके किसी भाग को या उससे संलग्न किसी उपगृह, गैरेज को इन नियमों का उल्लंघन करके शिकमी देता है तो, ऐसी किसी अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जो उसके विरुद्ध की जा सकती हो, उससे उतनी वर्धित अनुज्ञप्ति फीस ली जा सकेगी, जो मूल नियम 45-क के अधीन मानक अनुज्ञप्ति फीस के चार गुना से अधिक न हो। प्रत्येक मामले में बात का विनिश्चय कि कितनी अनुज्ञप्ति फीस वसूल की जाए और किसी अवधि के लिए वसूल की जाए, निदेशक गुणा व गुण के आधार पर करेगा। इसके अतिरिक्त उस अधिकारी को भविष्य में ऐसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए जो निदेशक द्वारा विनिश्चित की जाए निवास स्थान का सहभोग करने से विवर्जित किया जा सकेगा।

(3) जहां आबंटिती द्वारा परिसर के अप्राधिकृत रूप से शिकमी दिए जाने के कारण आबंटन को रद्द करने की कार्रवाई की जाती है वहां आबंटिती तथा उसके साथ उसमें निवास करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को परिसर को खाली करने के लिए साठ दिन का समय दिया जाएगा। आबंटन परिसर खाली किए जाने की तारीख या आबंटन रद्द करने के आदेश की तारीख से, जो भी पूर्वतर हो, साठ दिन की अवधि समाप्त होने पर रद्द हो जाएगा।

(4) जहां निवास स्थान का आबंटन ऐसे आचरण के कारण रद्द किया जाए जो पड़ोसियों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला हो वहां, उस अधिकारी को मंडल अधिकारी के विवेकानुसार उसी वर्ग का अन्य निवास स्थान किसी अन्य स्थान में आबंटित किया जा सकेगा।

(5) मंडल अधिकारी इस नियम के उपनियम (1) से (4) तक के अधीन सभी कार्रवाइयां या कोई कार्रवाई करने के लिए तथा ऐसे अधिकारी को, जो नियमों का तथा उसको जारी किए गए अनुदेशों को भंग करता है, तीन वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए वास सुविधा के आबंटन के लिए अपात्र घोषित करने के लिए भी सक्षम होगा।

(6) जहां इस नियम के अधीन कोई शास्ति निदेशक द्वारा अधिरोपित की जाती है, वहां व्यथित व्यक्ति शास्ति अधिरोपित करने वाले आदेशों की अपने या अपने नियोजक द्वारा प्राप्ति के इक्कीस दिन के भीतर निदेशक को अभ्यावेदन कर सकेगा।

(7) शास्ति अधिरोपित करने वाला मूल आदेश तब तक वैध रहेगा जब तक वह अभ्यावेदन के परिणाम स्वरूप उपान्तरित या निलंबित न हो जाए।

अनु० नि० 317 खग–19 आवंटन के रद्द किए जाने के पश्चात् निवास स्थान में बने रहना:—

जहां कोई आबंटन उन नियमों के किसी उपबंध के अधीन रद्द किया जाता है या रद्द कर दिया गया समझा जाता है और तत्पश्चात् वह निवास स्थान उस अधिकारी के, जिसे वह आबंटित किया गया था या उसके माध्यम से दावा करने वाले व्यक्ति के अधिभोग में बना रहता है या बना रहा है वहां ऐसा अधिकारी उस निवास-स्थान सेवाओं, फर्नीचर के उपयोग और अधिभोग के लिए उतनी नुकसानी और बाग प्रभार का देनदार होगा, जो सरकार द्वारा समन्वय पर अवधारित मार्केट रेन्ट के बराबर हो:

परन्तु यह कि किसी अधिकारी को, विशेष दशा में निदेशक द्वारा अ० नि० 317–खग–9 (2) के अधीन अनुज्ञात अवधि से आगे छह मास से अनधिक अवधि के लिए अ० नि० 45-क के अधीन मानक अनुज्ञप्ति फीस के दुगने राशि का संदाय करने पर निवास स्थान का कब्जा बनाए रखने की अनुज्ञा दी जा सकेगी।

अनु० नि० 317 खग–20 इन नियमों के जारी किए जाने के पहले किए गए आवंटनों का बना रहना :—

निवास स्थान के किसी ऐसे विधिमान्य आबंटन के बारे में जो इन नियमों के प्रारंभ के ठीक पूर्व तत्समय प्रवृत्त नियमों के अधीन अस्तित्व में हो यह समझा जाएगा कि वह इन नियमों के अधीन सम्यक् रूप से किया गया आबंटन है भले ही यह अधिकारी जिसे वह आबंटन किया गया हो, उस टाइप का निवास स्थान का हकदार न हो तो उस आबंटन और उस अधिकारी के संबंध में इन नियमों के सभी पूर्वगामी उपबंध तदनुसार लागू होंगे।

अनु० नि० 317 खग 21– नियमों का निर्वचन :—

यदि इस प्रभाग के नियमों के निर्वचन की बाबत कोई प्रश्न उठता है तो उसका विनिश्चय केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाएगा।

अनु० नि० 317 खग–नियमों का शिथिलीकरण :—

केन्द्रीय सरकार ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे इस प्रभाग के नियमों के सभी उपबंधों को या उनमें से किसी को किसी अधिकारी या निवास स्थान के मामले में या अधिकारियों के किसी वर्ग या निवास स्थानों के किसी टाइप के बारे में शिथिल कर सकेगी।

अनु० नि० 317 खग–23-शक्तियों या कृत्यों का प्रत्यायोजन :—

केन्द्रीय सरकार इस प्रभाग के नियमों द्वारा उस प्रदत्त कोई शक्ति या सभी शक्तियां अपने नियंत्रणाधीन किसी अधिकारी को ऐसी शर्तों के अधीन प्रत्यायोजित कर सकेगी, जिन्हें, प्रत्यायोजित करना वह ठीक समझे।

[सं० 8-1/75-सी० ए०-4]

आर० डी० मित्तल, अवर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture & Cooperation)

New Delhi, the 17th May, 1984

S.O. 1757.—In pursuance of the provisions of rule 45 of the Fundamental Rules, the President hereby makes the following Rules, namely :—

S.R. 317-BC-1. Short title, Application and Commencement.—(1) These rules may be called the Directorate of Oilseeds Development, Hyderabad (Allotment of Government Residences) Rules, 1984.

(2) These rules shall apply to the allotment of residences primarily to the Government Servants employed in the Directorate of Oilseeds Development, Hyderabad.

(3) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

S.R. 317-BC-2. Definition.—In these rules unless the context otherwise requires,—

(a) 'allotment' means the grant of a licence to occupy a residence in accordance with the provisions of these rules;

(b) 'allotment year' means the year beginning on the 1st day of January or such other period as may be notified by the President.

(c) 'Director' means the Director of the Directorate of Oilseeds Development, Hyderabad.

(d) 'Eligible Office' means the office of the Directorate of Oilseeds Development, Hyderabad.

Note :—Surplus quarters, if any (after meeting the requirement of the staff of the Directorate of Oilseeds Development) may be allotted to the other Central Government Employees and officials of Offices/Institutions under the control of Indian Council of Agricultural Research eligible for General Pool Accommodation of the Central Government Employee in the offices situated in twin cities of Hyderabad and Secunderabad and will be governed by these rules except that they will be charged licence fee under F.R. 45-B+DC The recovery of the Licence fee will be made by the Director through the 'Head of Department' of such officials. The allotment in these cases will be provisional on furnishing acceptable legal undertaking to the effect that the quarter thus allotted are to be vacated by them as and when the officers in the Directorate of Oilseeds Development become eligible.

(e) 'emoluments' means the emoluments as defined in F.R. 45-C but excluding the compensatory allowances

Explanation.—In case of an officer who is under suspension the emoluments drawn by him on the first day of the allotment year in which he is placed under suspension, or if he is placed under suspension on the first day of the allotment year, the emoluments drawn by him immediately before that day shall be taken as emoluments.

(f) 'Estate Officer' means the Director of Oilseeds Development Hyderabad, or any other officer responsible for administering the estate of Oilseeds Development, Hyderabad.

(g) 'family' means the wife or husband, as the case may be and children, step children, legally adopted children, parents, brothers or sisters as ordinarily reside with and are dependent on the officer.

(h) 'Government' means the Central Government unless the context otherwise requires.

(i) 'Greater Municipal Corporation of Hyderabad' means the areas within the limits of the Greater Municipal Corporation of Hyderabad which the Estate Officer may declare as conferring eligibility for the allotment of accommodation in the Directorate of Oilseeds Development, Hyderabad.

(j) 'licence fee' means the sum of money payable monthly in accordance with the provisions of the Fundamental rules in respect of a residence allotted under these rules.

(k) 'priority date' of an officer in relation to a type of residence to which he is eligible under the provisions of S. R. 317-BC. 4(1) means the earliest date from which he has been continuously drawing emoluments relevant to a particular type or a higher type in a post under the Central Government or a State Government or on foreign service, except for periods of leave :

Provided that in respect of a type-I, type II, type III or type IV residence, the date from which the officer has been continuously in service under the Central Government or State Government including the periods of foreign service shall be his priority date for that type :

Provided further that where the priority date of two or more officers is the same, seniority among them shall be determined by the amount of emoluments; the officer in receipt of higher emoluments taking precedence over the officer in receipt of lower emoluments, and where the emoluments are equal, by the length of service;

(l) 'residence' means any residence for the time being under the administrative control of the Director;

(m) 'sub-letting' includes sharing of accommodation by an allottee with another person with or without payment of rent by such other person;

Explanation.—Any sharing of accommodation by an allottee with close relations shall not be deemed to be sub-letting.

(n) 'temporary transfer' means a transfer which involves an absence for a period not exceeding four months.

(o) 'transfer' means a transfer from Hyderabad/Secunderabad to any other place or from the Directorate of Oilseeds Development office to any other office in Hyderabad or Secunderabad and includes a transfer or reversion to service under a State Government and also deputation to a post in any other office or Organisation;

(p) 'type' in relation to an officer means the type of residence to which he is eligible under Rule S.R. 317-BC. 5(1);

S.R. 317-BC-3. Allotment to house owning officers—

(1) In this rule :—

(a) "adjoining municipality" means any municipality contiguous to a local municipality;

(b) "house" in relation to an officer or member of his family means a building or part thereof used for residential purposes and situated within the jurisdiction of a local municipality or of any adjoining municipality.

Explanation.—A building, part of which is used for residential purposes, shall be deemed to be a house for the purposes of this clause notwithstanding that any part of it is used for non-residential purposes;

(c) "local municipality" in relation to an officer means the municipality within whose jurisdiction his office is located;

(d) "member of family" in relation to an officer means the wife or husband, as the case may be, or a dependent child of the officer;

(e) "Municipality" includes a municipal corporation, a municipal committee or board, a town area committee a notified area committee, and a cantonment board.

(2) An officer owing a house either in his own name or in the name of any member of his family at the place of his duty or in an adjoining municipality shall be eligible for allotment of Government residence on payment of licence fee for the Goverment accommodation allotted to him at such rate as may be determined from time to time by the Government.

(3) When after a Government residence has been allotted to an officer, he or any member of his family becomes owner of a house at the place of his duty or in an adjoining municipality, such officer shall notify the fact to the Estate Officer within a period of one month from the date the house is let out or occupied, or the date of completion, whichever is earlier".

S.R. 317-BC. 4. Allotment to Husband and wife, eligibility in cases of officers who are married to each other.

(1) No officer shall be allotted a residence under these rules if the wife or the husband, as the case may be, of the officer has already been allotted a residence, unless such residence is surrendered;

Provided that this sub-rule shall not apply where the husband and wife are residing separately in pursuance of an order of judicial separation made by any court.

(2) Where two officers in occupation of separate residences allotted under these rules marry each other, they shall, within one month of the marriage, surrender one of the residences.

(3) If a residence is not surrendered as required by sub-rule (2), the allotment of the residence of the lower type shall be deemed to have been cancelled on the expiry of such period and if the residences are of the same type, the allotment of such one of them, as the Estate Officer may decide, shall be deemed to have been cancelled on the expiry of such period.

(4) Where both husband and wife are employed in the Directorate of Oilseeds Development, Hyderabad, or in any of the offices whose staff has been declared as eligible for allotment of residences, the title of each of them to allotment of a residence under these rules shall be considered independently.

(5) Not withstanding anything contained in sub-rules (1) to (4) :—

(a) If a wife or husband, as the case may be, who is an allottee of a residence under these rules, is subsequently allotted a residential accommodation at the same station from a pool to which these rules do not apply, she or he, as the case may be, shall surrender any one of the residence within one month of such allotment :

Provided that this clause shall not apply where the husband and wife are residing separately in pursuance of an order of judicial separation made by any court.

(b) Where two officers, in occupation of separate residences at the same station, one allotted under these rules and another from a pool to which these rules do not apply, marry each other, anyone of them shall surrender any one of the residences within one month of such marriage;

(c) If a residence is not surrendered as required under clause (a) or clause (b) the allotment of the residence shall be deemed to have been cancelled on the expiry of such period and for subsequent occupation of the residence damages will be recoverable.

S. R. 317-BC. 5 Classification of Residences.(1)—For the purpose of allotment, the residences are classified as under and save as otherwise provided by these rules, an officer shall be eligible for allotment of a residence of the type shown in the table below :—

Type of residence	Category of Officer or his monthly emoluments as on the first day of the allotment year in which the allotment is made.
Type-I	Less than Rs. 260/-
Type-II	From Rs. 260/- to Rs. 499/-
Type-III	From Rs. 500/- to Rs. 999/-
Type-IV	From Rs. 1,000/- to Rs. 1,499/-
Type-V	Rs. 1,500/- and above.
Type-VI	Earmarked to the Director of Oilseeds Development, Hyderabad.

(2) If however, accommodation of entitled type is not available for an officer of the Directorate of Oilseeds Development, on application from the concerned officer, the next below type can be allotted if one such is available after meeting the requirements of those entitled to that type of accommodation subject to the condition that the person concerned shall be allotted the entitled type of accommodation as soon as one is available. The concession will be available only to employees of the Directorate of Oilseeds Development, Hyderabad.

(3) Further, the Director may on request allot to the staff of the Directorate of Oilseeds Development, Hyderabad, who is not able to get allotment of entitled type of accommodation, residential accommodation of a type one higher than that to which he/she is entitled subject to the following conditions namely :—

(a) at the time of such allotment the requirements of the staff of the Directorate of Oilseeds Development, Hyderabad as per entitlement according to pay range in respect of such higher type of accommodation have been fully met;

(b) where higher type of accommodation is surplus to the requirements of the staff of the Directorate of Oilseeds Development as indicated in clause (a), it may be allotted to a non-entitled officer of the Directorate of Oilseeds Development :

Provided that the said non-entitled officer will become entitled to the said higher type of accommodation as per sub-rule (1) above within a period of one year from the date of such allotment. The licence fee recoverable during the period of non-entitlement shall be full standard licence fee under F. R. 45-A, without limiting the emoluments to 10%.

S. R. 317-BC-6.—Applications for allotment.—Every Government servant within a month of his appointment/posting in the Directorate of Oilseeds Development, Hyderabad, or any other Central Government office located in Hyderabad and Secunderabad may apply for the allotment of a residential quarter of a type appropriate to his official status. Applications for allotment of all types of residences shall be made to the Director through proper channel, who shall maintain a waiting list for each type of residence, separately one for the staff of the Directorate of Oilseeds Development, and another for others. The waiting list shall be arranged according to the date of priority of the Officer Officers already in occupation of accommodation shall automatically go on waiting list for the higher type of residence from the date on which they become entitled to such type of the accommodations. Allotments shall be made according to the waiting lists based on the dates of entitlements.

S.R. 317-B.C.-7.—Allotment of residences and officers.—(1) Save as otherwise provided in these rules, a residence on falling vacant, will be allotted by the Director preferably to an applicant desiring a change of accommodation in that type, and if not required for that purpose, to an applicant without accommodation in that type having the earliest priority date for that type of residence subject to the following conditions, namely :—

(i) the Estate Officer shall not allot a residence of a type higher than that to which the applicant is eligible.

(ii) the Estate Officer shall not compel any applicant to accept a residence of a lower type than that to which he is eligible.

(2) The Estate Officer, on request from an applicant (belonging to the Directorate of Oilseeds Development only) for allotment of a lower category residence, might allot to him a residence next below the type for which the applicant is eligible on the basis of his priority date for the same.

(3) The Estate Officer may cancel the existing allotment of an Officer and allot to him an alternative residence of the same type or in emergent circumstances an alternative residence of the type next below the type of residence in occupation of the officer if the residence in occupation of the officer is required to be vacated.

(4) A vacant residence may, in addition to allotment to an officer under sub-rule (1) above, be offered simultaneously to other eligible officers in order of their priority dates.

S.R. 217-BC-8.—Non-acceptance of allotment or offer or failure to occupy the allotted residence after acceptance.—(1) If any officer fails to accept the allotment of a residence within five days or fails to take possession of that residence after acceptance within eight days from the date of receipt of the letter of allotment, he shall not be eligible for another allotment for a period of one year from the date of allotment letter.

(2) If an Officer occupying a lower type residence is allotted or offered a residence of the type for which he is eligible under Rules S.R. BC. 5(1) or for which he has applied under Rule S.R. BC. 5(2), he may on refusal of the said allotment or offer of allotment, be permitted to continue in the previously allotted residence on the following conditions, namely :—

(a) that such an officer shall not be eligible for another allotment for a period of six months from the date of allotment letter for the higher class accommodation;

(b) while retaining the existing residence he shall be changed the same licence fee which he would have had to pay under F.R. 45-A in respect of the residence so allotted or offered or the licence fee payable in respect of the residence already in his occupation whichever is higher :—

S.R. 317-MC-9—Period for which allotment subsists and the concessional period for further retention:

(1) An allotment shall be effective from the date on which it is accepted by the officer and shall continue in force until :—

(a) the expiry of the concessional period permissible under sub-clause (2) of this rule after the officer ceases to be on duty.

(b) it is cancelled by the Estate Officer or is deemed to have been cancelled under the provisions of these Rules.

(c) it is surrendered by the office, or,

(d) the officer ceases to occupy the residence.

(2) A residence allotted to an officer may, subject to sub-rule (3) of this rule, be retained on the happening of any of the events specified in column 1 of the table below for the period specified in the corresponding entry in column 2 thereof, provided that the residence is required for the bona-fide use of the officer or members of his family :—

Events	Permissible period for retention of the residence
1	2
(i) Resignation, dismissal or removal from service, termination of service or un-authorised absence without permission.	1 month.
(ii) Retirement or terminal leave	2 months.
(iii) Death of allottee	4 months.
(iv) Transfer to a place outside Hyderabad.	2 months.
(v) Transfer to an ineligible office in the Station.	2 months.
(vi) On proceeding on foreign service in India.	2 months
(vii) Temporary transfer in India on transfer to a place outside India.	4 months.
(viii) Leave (other than leave preparatory to retirement, refused leave terminal study leave).	For the period of leave but not exceeding four months.
(ix) Leave preparatory to retirement or refused leave granted under FR. 86 or rule 39 of CCS (Leave) rules, 1972.	For the full period of leave on full average pay subjec to maximum of 4 months inclusive of the period permissible in the case of retirement.
(x) Study leave or deputation outside India.	For the period of leave but not exceeding six months.
(xi) Leave on medical grounds.	Full period of leave.
(xii) Study leave in India.	For the period of leave but not exceeding six months.
(xiii) On proceeding on training	For full period of training.

Explanation.—(I) Where an officer on transfer or foreign service in India is sanctioned leave and avails of it before joining duty at the new office, he may be permitted to retain the residence for the period mentioned against items (iv), (v), (vi) and (vii) or for the period of leave, whichever is more.

Explanation.—(II) Where an order of transfer or foreign service in India is issued to an officer while he is already on leave, the period permissible under clause (I) of the explanation shall count from the date of issue of such order.

(3) Where a residence is rentained under sub-rule (2) the allotment shall be deemed to be cancelled on the expiry of the admissible concessional periods unless immediately on the expiry thereof the officer resumes duty in an eligible office.

(4) Where an officer is on medical leave without pay and allowances, he may retain his residence by virtue of the concession under item (xi) of the Table below sub-rule (2), provided he remits the licence fee for such residence in cash every month and where he fails to remit such licence fee for more than 2 consecutive months, the allotment shall stand cancelled.

(5) An officer who has retained the residence by virtue of the concession under item (i) or (ii) of the Table below sub-rule (2), shall, on re-employment in an eligible office, within the period specified in the said Table, be entitled to retain that residence and he shall also be eligible for any further allotment of residence under these rules;

Provided that if the emoluments of the officer on such re-employment do not entitle him to the type of residence occupied by him, he shall be allotted a lower type of residence.

(6) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2) or sub-rule (3) or sub-rule (4), of this rule when an officer is dismissed or removed from service or when his services have been terminated and the Head of the Department in respect of the office in which such officer was employed immediately before such dismissal, removal or termination is satisfied that it is necessary or expedient in the public interest so to do, he may require the Estate Officer to cancel

the allotment of the residence made to such officer either forthwith or with effect from such date, such date prior to the expiry of the period of one month referred to in item (i) of the Table below sub-rule (2) as he may specify and the Estate Officer shall act accordingly.

S.R. 317-BC-10.—Provision relating to licence fee.—(1) Where an allotment of accommodation or alternative accommodation has been accepted, the liability for licence fee shall commence from the date of occupation or eighth day from the date of receipt of the allotment letter whichever is earlier.

(2) An Officer who after acceptance fails to take possession of that accommodation within eight days from the date of receipt of allotment letter, shall be charged licence fee from such date upto a period of twelve days, provided nothing contained herein shall apply where the Central Public Works Department certifies that the accommodation is not fit for occupation and as a result thereof the officer did not occupy the accommodation within the period aforesaid.

(3) Where an officer, who is in occupation of a residence, is allotted another residence and he occupies the new residence, the allotment of the former residence shall be deemed to be cancelled from the date of occupation of the new residence. He may, however, retain the former residence without payment of licence fees for that day and the subsequent day for shifting.

S.R. 317-BC. 11—Personal liability of the officer for payment of licence fee till the residence is vacated and furnishing of surety by temporary officer.

(1) The Officer to whom a residence has been alloted shall be personally liable for the payment of licence fee thereof and for any damage beyond fair wear and tear caused thereto or to the furniture, fixtures or fittings or services provided therein by Government during the period for which the residence has been and remains allotted to him, or where the allotment has been cancelled under any of the provisions of these rules, until the residence along with the out-houses appurtenant thereto have been vacated and full vacant possession thereof has been restored to Government.

(2) Where the officer to whom a residence has been allotted is neither a permanent nor a quasi-permanent Government servant, he shall execute a security bond in the form prescribed in this behalf by the Central Government with a surety, who shall be a permanent Government servant serving under the Central Government for due payment of licence fee and other charges due from him in respect of such residence and services and any other residence provided in lieu.

(3) If the surety ceases to be in Government service or becomes insolvent or ceases to be available for any other reasons, the officer shall furnish a fresh bond executed by another surety within 30 days from the date of his acquiring knowledge of such event or fact, and if he fails to do so, the allotment of the residence to him shall, unless otherwise decided by the Director, be deemed to have been cancelled with effect from that date of that event.

S.R. 317-B.C. 12—Surrender of an allotment and period of notice.—(1) An Officer may at any time surrender an allotment by giving intimation so as to reach the Director at least ten days before the date of vacation of the residence. The allotment of the residence shall be deemed to be cancelled with effect from the eleventh day after the day on which the letter is received by the Director or the date specified in the letter, whichever is later. If he fails to give due notice he shall be responsible for payment of licence fee for ten days or the number of days by which the notice given by him falls short of ten days, provided that the Director may accept a notice for a shorter period if he is satisfied that the prescribed notice could not be given owing to circumstances beyond the control of the allottee.

(2) An Officer who surrenders the residence under sub-rule (1) shall not be considered again for allotment of Government accommodation at the same station for a period of one year from the date of such surrender.

S.R. 317-BC. 13—Change of residence.—(1) An officer to whom a residence has been allotted under these rules may apply for a change to another residence of the same type or a residence of the type to which he is eligible. Not more than one change shall be allowed in respect of one type of residence allotted to the officer, Request for change to a particular residence shall not be entertained.

(2) All applications for change made in the form prescribed by the Estate Officer and received upto the 19th day of a calendar month shall be included in the waiting list in the succeeding month. For purposes of this rule the officers whose names are included in the waiting list in an earlier month shall be senior en block to those whose names are included in the list in subsequent months. The inter se seniority of the officers included in the list in any particular month shall be determined in the order of their priority dates.

(3) Change shall be offered in order of seniority determined in accordance with sub-rule (2) and having regard to the officer's preference's as far as possible.

(Provided that no change of residence shall be allowed during a period of six months immediately preceding the date of superannuation).

(4) If an officer fails to accept the change of residence offered to him within five days of the receipt of such offer or allotment, he shall not be considered again for a change of residence of that type.,

(5) An officer who, after accepting a change of residence fails to take possession of the same, shall be charged licence fee for such residence in accordance with the provision of sub-rule (1) of S.R. 317-B.C. 11 in addition to the normal licence fee under FF 45-A for the residence already in his possession, the allotment of which shall continue to subsist.

S.R. 317-BC-14.—Mutual exchange of residences.—Officers to whom residences of the same type have been allotted under these rules may apply for permission, to mutually exchange their residences. Permission for mutual exchanges may be granted if both the officers are reasonably expected to be on duty and to reside in their mutually exchanged residences for at least six months from the date of approval of such exchange.

S.R. 317-BC. 15—Maintenance of residence—The officer to whom a residence has been allotted, shall maintain the residence and premises in clean condition to the satisfaction of the Central Public Works Department and Municipal Corporation of Hyderabad. Such officers shall not grow any tree, shrubs or plants contrary to the instructions issued by the Government or Central Public Works Department nor cut or lop off any existing tree or shrub in any garden, courtyard, or compound attached to the residence save with the prior permission in writing of the Director or Public Works Department. Trees, plantation or vegetation, grown in contravention of this rule may be caused to be removed by the Director or Public Works Department at the risk and cost of the officer concerned.

S.R. 317-BC-16.—Sub-letting and sharing of residence.—(1) No officer shall share the residence allotted to him or any of the out-houses, garages and stables appurtenant thereto except with the employees of the Central Government eligible for allotment of residence under these rules. The servant quarters, out-houses, garages and stables may be used only for the bonafide purposes including residence of the servants of the allottee or for such other purposes as may be permitted by the Director.

(2) No officer shall sub-let the whole of his residence :

Provided that an officer proceeding on leave may accommodate, in the residence of any other officer eligible to share Government residence as a Caretaker, for the period specified in rule SR. 317-BC. 9(2), but not exceeding six months.

(3) Any officer who shares or sublets his residence shall do so at his own risk and responsibility and shall remain

personally responsible for any licence fee payable in respect of the residence and for any damage caused to the residence or its precincts or grounds or services provided therein by Government beyond fair wear and tear.

(4) The sharing of residence is allowed only with the prior permission of the Director.

S.R. 317-BC. 17.—Transfer to non-family station.—If an officer is transferred to a station where he is not permitted or advised by Government to take his family with him and the residence allotted to him under these rules is required by the family or the bonafide educational needs of his children, he may be allowed, on request, to retain the residence on payment of licence fee under FR-45-A, till the end of the current academic session of his children.

S.R.-317-BC-18.—Consequences of breach of rules and conditions.—(1) If an officer to whom a residence has been allotted unauthorisedly sublets the residence or charges rent from the sharer at a rate which the Director considers excessive or erects unauthorised structure or any portion thereof for any purposes other than that for which it is meant or tampers with the electric or water connection or commits any other breach of the rules or of the terms and conditions of the allotment or uses the residence or premises or permits or suffers the residence or premises to be used for any purpose which the Director considers to be improper or conducts himself in a manner which in his opinion is prejudicial to the maintenance of harmonious relations with his neighbours or has knowingly furnished incorrect information in any application or written statement with a view to securing the allotment, the Director, may, without prejudice to any other disciplinary action that may be taken against him, cancel the allotment of the residence.

Explanation.—In this sub-rule the expression 'Officer' includes unless the context otherwise requires, a member of his family and any other person claiming through the officer.

(2) If an officer sub-lets a residence allotted to him or any portion thereof or any of the out-houses, garages or stables appertenant thereto, in contravention of these rules, he may, without prejudice to any other action that may be taken against him, be charged enhanced licence fee not exceeding four times the standard licence fee under FR. 45-A. The quantum of licence fee to be recovered and the period for which the same may be recovered in each case shall be decided by the Director on merits. In adition, the officer may be debarred from sharing the residence for a specified period in future as may be decided by the Director.

(3) Where an action to cancel the allotment is taken on account of unauthorised sub-letting of the premises by the allottee, a period of sixty days shall be allowed to the allottee, and any other person residing with him therein to vacate the premises. The allotment shall be cancelled with effect from the date of vacation of the premises or expiry of the period of sixty days from the date of the orders, for the cancellation of the allotment, whichever is earlier.

(4) Where the allotment of a residence is cancelled for conduct prejudicial to the maintenance of harmonious relations with neighbours, the officer at the discretion of the Director may be allotted another residence in the same class.

(5) The Director shall be competent to take all or any of the actions under sub-rule (1) to (4) and also to declare the officer who commits a breach of the rules and instructions issued to him to be eligible for allotment to residential accommodation for a period not exceeding three years.

(6) Where any penalty under this rule is imposed by the Director the aggrieved person may within twentyone days of the receipts of order by him or his employer imposing the penalty file a representation to the Director.

(7) The original order imposing the penalty shall stand unless it is notified or rescinded as a result of the representation.

S.R. 317-BC-19.—Overstayal in residence after cancellation of allotment:—

Where, after an allotment has been cancelled or is deemed to be cancelled under any provinsion contained in these rules, the rsidence remains or has remained in occupation of the officer whom it was allotted or of any person claiming through him, such officer shall be liable to pay damages for use and occupation of the residence, services, furniture and garden charges, equal to the market rent as may be determined by Government from time to time:

Provided that an officer, in special cases, may be allowed by the Director to retain a residence on payment of twice the standard licence fee under FR. 45-A, for a period not exceeding six months beyond the period permitted under S.R. 317-BC-9(2).

S.R. 317-BC-20-Continuance of allotments made prior to the issue of these rules :—

Any valid allotment of a residence which is subsisting immediately before the commencement of these rules under the rules than in force shall be deemed to be an allotment duly made under these rules notwithstanding that the officer to whom it has been made is not entitled to a residence of that type and all the preceding provisions of these rules shall apply in relation to that allotment and that officer accordingly.

S.R. 317-BC-21—Interpretation of rules—If any question arises as to the interpretation of these rules, it shall be decided by the Central Government.

S.R. 317-BC-22—Relaxation of rules.—The Government may, for reasons to be recorded in writing, relax all or any of the provisions of these rules in the case of any officer or residence or class of officers or type of residence.

S.R. 317-BC-23—Delegation of power or functions—The Government may delegate any or all the powers conferred upon it by these rules to any officer under its control, subject to such conditions as it may deem fit to impose.

[No. 8-1/75-C.A.IV]

R. D MITTAL, Under Secy.

संचार मंत्रालय

(डाक तार बोर्ड)

नई दिल्ली, 19 मई, 1984

का० आ० 1758:—स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किये गये भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434 के खण्ड III के पैरा (क) के अनुसार डाक-तार महानिदेशक ने आटो नगर टेलीफोन केन्द्र में दिनांक 1-6-1984 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है।

[संख्या 5-8/84 पीएच बी].

वाई० आर० भसीन, सहायक महानिदेशक (पी० एच० बी०)

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(P & T Board)

New Delhi, the 19th May, 1984

S.O. 1758.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Posts and Telegraphs hereby specified 1-6-1984 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Auto Nagar Telephone Exchange Andhra Pradesh Circle.

[No. 5/8/84—PHB]

Y. R. BHASIN, Asstt. Director General (PHB)

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 18 मई, 1984

का० आ० 1759:—केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उप-नियम (4) के अनुसरण में, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय की निम्नलिखित क्षेत्रीय प्रचार यूनिटों, को, जिनके कर्मचारी-वृन्द ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है :—

1.	क्षेत्रीय प्रचार यूनिट,		बेगूसराय (बिहार)
2.	—तथैव—	"	छपरा (बिहार)
3.	—तथैव—	"	बालाघाट (मध्य प्रदेश)
4.	—तथैव—	"	सागर (मध्य प्रदेश)
5.	—तथैव—	"	छिन्दवाड़ा (मध्य प्रदेश)
6.	—तथैव—	"	सोलापुर (महाराष्ट्र)
7.	—तथैव—	"	नांदेड़ (महाराष्ट्र)
8.	—तथैव—	"	अहमदनगर (महाराष्ट्र)
9.	—तथैव—	"	जलगाव (महाराष्ट्र)
10.	—तथैव—	"	औरंगाबाद (महाराष्ट्र)
11.	—तथैव—	"	नासिक (महाराष्ट्र)
12.	—तथैव—	"	नागपुर (महाराष्ट्र)
13.	—तथैव—	"	वर्धा (महाराष्ट्र)
14.	—तथैव—	"	मैनपुरी (उत्तर प्रदेश)
15.	—तथैव—	"	आजमगढ़ (उत्तर प्रदेश)
16.	—तथैव—	"	दिल्ली

[संख्या ई. 11011/35/83-हिन्दी]

इन्दु भूषण कर्ण, अवर सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 18th May, 1984

S.O. 1759.—In pursuance of sub-rule (4) of rule 10 of the Official Languages (use for official purposes of the union) Rules, 1976, the Central Government hereby notifies the following field publicity units of the Dte. of Field Publicity of the Ministry of Information and Broadcasting, the staff whereof have acquired the working knowledge of Hindi:—

1. Field Publicity Unit, Begusarai, (Bihar)
2. Field Publicity Unit, Chhapra, (Bihar)
3. Field Publicity Unit, Balaghat (M.P.)
4. Field Publicity Unit, Sagar, (M.P.)
5. Field Publicity Unit, Chhindawara (M.P.)
6. Field Publicity Unit, Solapur (Maharashtra)
7. Field Publicity Unit, Nanded, (Maharashtra)
8. Field Publicity Unit, Ahmednagar, (Maharashtra)
9. Field Publicity Unit, Jalgaon, (Maharashtra)
10. Field Publicity Unit, Aurangabad, (Maharashtra)
11. Field Publicity Unit, Nasik, (Maharashtra)
12. Field Publicity Unit, Nagpur, (Maharashtra)
13. Field Publicity Unit, Wardha, (Maharashtra)
14. Field Publicity Unit, Mainpuri, (U.P.)
15. Field Publicity Unit, Ajamgarh (U.P.)
16. Field Publicity Unit, Delhi.

[No. E-11011/35/83—Hindi]

I. B. KARN, Under Secy.

इस्पात और खान मंत्रालय

(इस्पात विभाग)

नई दिल्ली, 19 मई, 1984

का०आ० 1760—केन्द्रीय सरकार, सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 की धारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस्पात विभाग (इस्पात और खान मंत्रालय) की अधिसूचना सं० का०आ० 2597, तारीख 16 अगस्त, 1983 को जो भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (2), तारीख 15 सितम्बर, 1973 में प्रकाशित की गई थी, अधिक्रांत करते हुए, नीचे की सारणी के स्तंभ (1) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए ऐसे अधिकारियों के रूप में नियुक्त करती है, जो उक्त सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट सरकारी स्थानों के संबंध में अपनी-अपनी स्थानीय अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन सम्पदा अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और उन पर अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेंगे।

सारणी

अधिकारी का पदाभिधान	सरकारी स्थानों के प्रवर्ग और अधिकारिता स्थानीय सीमाएं
1	2
1. कार्मिक अधिकारी/सहायक कार्मिक प्रबंधक/कार्मिक प्रबंधक, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड, बेलाडिला आयरन और प्रोजेक्ट डिपाजिट नं० 14, जिला बस्तर, मध्य प्रदेश	बेलाडिला डिपोजिट नम्बर 14, जिला बस्तर, मध्य प्रदेश ये क्षेत्र मध्य प्रदेश के जिला बस्तर में स्थित डिपाजिट नम्बर 1 से 14 से मिलकर बनते हैं। इन डिपाजिटों के अन्तर्गत किरंदुल टाउनशिप है (हिलटाप टाउनशिप भांसी और बछेली हैं)
2. कार्मिक अधिकारी/सहायक कार्मिक प्रबंधक/कार्मिक प्रबंधक, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड, बेलाडीला डिपाजिट नम्बर, 5 जिला बस्तर, मध्य प्रदेश	बेलाडिला डिपाजिट नम्बर 5, जिला बस्तर, मध्य प्रदेश भांसी कैंप, बछेली टाउनशिप, आपरेशन टाउनशिप हिलटाप स्थित अस्थाई कालोनी, ये सभी मध्य प्रदेश के बस्तर जिले की तहसील दांतेवाड़ा में है।
3. सहायक कार्मिक अधिकारी/सहायक कार्मिक प्रबन्धक/डायमंड माइनिंग प्रोजेक्ट पन्ना।	डायमंड माइनिंग प्रोजेक्ट, पन्ना, मध्य-प्रदेश। पन्ना कालोनी में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के क्वार्टर में पन्ना ग्राम मझगांव और बिनोटस ग्रामों में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के अमबासी क्वार्टर।
4. कार्मिक अधिकारी/सहायक कार्मिक प्रबंधक /कार्मिक प्रबंधक दोनीमलाई आयरन और प्रोजेक्ट जिला बेलरी कर्नाटक	दोनीमलाई आयरन और प्रोजेक्ट, जिला बेलरी, कर्नाटक, दोनीमलाई आयरन और प्रोजेक्ट की अधिकारिता के अन्तर्गत आने वाले राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड के स्थान पर और क्षेत्र।

[सं० 3 (2)/82-आर एम आई]

नरदेवसिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF STEEL & MINES

(Department of Steel)

New Delhi, the 19th May, 1984

S.O.1760.—In exercise of the powers conferred by Section 2 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 and in supersession of the Department of Steel (Ministry of Steel and Mines) Notification No. S.O.2597 dated the 16th August,1973 published in the Gazette of India, Part II Section 3, Sub Section (ii) dated 15th September, 1973 the Central Government hereby appoints the officers mentioned in column(1) of the Table below being the officers for the purpose of the said Act, who shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed on the estate officers by or under the said Act within the local limits of their respective jurisdiction in respect of the public premises specified in (column 2) of the said table.

TABLE

Designation of the officer	Categories of public premises and local limits of jurisdiction.
1	2
1. Personnel Officer/Asstt. Personnel Manager/ Personnel Manager, National Mineral Development Corporation, Bailadila Iron Ore Project Deposit No. 14 Distt. Bastar Madhya Pradesh.	Bailadila Deposit No 14 District Bastar, Madhya Pradesh. The areas constituted of deposit No. 1 to 14 which are situated in District Bastar, Madhya Pradesh The deposits include township of Kirandul, Hill top Township, Bhansi and Bachelil.
2. Personnel Officer/Assistant Personnel Manager/Personnel Manager, National Mineral Development Corporation, Bailadila Deposit No. 5, District Bastar, Madhya Pradesh.	Bailadila Deposit No.5 District Bastar, Madhya Pradesh. Bhansi Camp, Bacheli Township Operation town hip Temporary Colony at Hill Top, all in Tehsil Dantewad of District Bastar, Madhya Pradesh.
3. Assistant Personnel Officer/ Assistant Personnel Manager, Diamond Mining Project, Panna.	Diamond Mining Project, Panna, Madhya Pradesh. National Mineral Development Corporation quarters in Panna Colony residential quarters of National Mineral Development Corporation at Panna village, Majhgawan and Binots, villages and Ramkheria Villages.
Personnel Officer/Assistant Personnel Manager/Personnel Manager, Donimalai Iron Ore Project District Bellary, Karnataka.	Donimalai Iron Ore Project District Bellary, Karnataka. Premises or areas of the National Minieral Development Corporation falling under the jurisdiction of Donimalai Iron Ore Project.

[F.No. 3(2)/82-RMI]

NARDEO SINGH, Under Secy.

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(हिन्दी अनुभाग)

नई दिल्ली, 14 मई, 1984

का०आ० 1761.—भारत सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उपनियम (4) के अनुसरण में नौवहन और परिवहन मंत्रालय के प्रशासनीक नियंत्रण में स्थित इंडियन रोड कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली, कार्यालय को, जहां 80 प्रतिशत और उससे अधिक कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है।

[सं० एच पी यू/147/84]

गोबिन्द जी मिश्र, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Hindi Section)

New Delhi, the 14th May, 1984.

S.O. 1761.—In pursuance of sub-rule (4) of Rule 10 of the Official Language (Use for the official purposes of the Union) Rules, 1976, the Government of India hereby notifies the office of Indian Road Construction Corporation Ltd. New Delhi under the administrative control of Ministry of Shipping and Transport, 80% staff whereof have acquired working knowledge of Hindi.

[No. HPU/147/82]

G. J. MISRA, Jt. Secy.

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय

नई दिल्ली, 18 मई, 1984

का० आ० 1762.—अन्तरराष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1971 (1971 का 43) की धारा 3 के उप धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एयर मार्शल पी० एस० डेरे को पद का कार्यभार सम्भालने की तारीख से अधिवर्षता की तारीख अर्थात 6 जून 1986 तक भारत अन्तरराष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पूर्ण-कालिक सदस्य- (परिचालन) के रूप में नियुक्त करती है।

[एवी 24012 / 1 /80-ए०ए०एफ०-II]

एस०सी० कोहली, वित्त नियंत्रक

MINISTRY OF TOURISM & CIVIL AVIATION

New Delhi, the 18th May, 1984

S.O. 1762.—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (3) of Section 3 of the International Airports Authority Act, 1971 (43 of 1971), the Central Government is pleased to appoint Air Marshal P. S. Dere as a whole-time Member (Operations) of the International Airports Authority of India with effect from the date of his assuming charge of the post upto the date of his superannuation namely 6th June, 1986.

[AV 24012/1/80—AA. F. II]

S. C. KOHLI, Financial Controller.

निर्माण और आवास मंत्रालय

(निर्माण प्रभाग)

नई दिल्ली, 24 मई, 1984

का०आ० 1763.—केन्द्रीय सरकार, राजघाट समाधि अधिनियम, 1951 (1951 का 41) की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री मदन लाल गंगाहेरी और श्रीमति सत्या चौधरी को राजघाट समाधि के समिति के सदस्यों के रूप में नामनिर्दिष्ट करती है और भारत सरकार के निर्माण और आवास मंत्रालय की अधिसूचना सं० 618 तारीख 24 दिसम्बर, 1977 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में क्रम संख्यांक 6 और 7 के सामने, "श्री बृज कृष्ण चण्डी वाला" और "श्री रूप नारायण" नामों के स्थान पर क्रमशः "श्री मदन लाल गंगाहेरी" और "श्रीमती सत्या चौधरी" नाम रखे जाएंगे ।

[सं० 25012/1/60-डब्ल्यू 3]

राजेश छाबड़ा, निदेशक (निर्माण)

MINISTRY OF WORKS & HOUSING

(Works Division)

New Delhi, the 24th May, 1984

S.O. 1763.—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (1) of section 4 of the Rajghat Samadhi Act, 1951 (41 of 1951) the Central Government hereby nominates Shri Madan Lal Gengahery and Smt. Satya Chaudhry as members of the Rajghat Samadhi Committee and makes the folowing further amendment in the notification of Government of India in the Ministry of Works & Housing No. S.O. 618 dated the 24th December, 1977, namely :—

In the said notification against serial numbers 6 and 7 for the names "Shri Brij Krishan Chandiwala" and "Shri Roop Narain" the names "Shri Madan Lal Gangahery" and "Smt. Satya Chaudhary" shall respectively be substituted.

[No. 25012/1/80-W3]

RAJESH CHHABRA, Director (Works)

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय

(श्रम विभाग)

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 1984

आदेश

का० आ० 1764.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में इंडिया सीमेंट लिमिटेड, शंकर नगर के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध एक औद्योगिक विवाद नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच विद्यमान है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ,

अतः, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उप-धारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री टी० अरुलराज होंगे, जिनका मुख्यालय मद्रास में होगा और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

"क्या सर्वश्री एम० पीर माइदीन, वी० रवी, एस० कोथाडा रमन, के० मुथुपांडी, के० मदासामी, एस० बास्कर, एस० लक्ष्मनन, एम० मायान्डी, के० अरूनुगम, आर० कन्डासामी, एम० चिन्नाथम्बी पुत्र मुथन, कोमु पुत्र मुथैया, एस० पण्डारम पुत्र सुदालाई, सुदालई पुत्र ईसाक्को असरी; वेलुचामी पुत्र सुदालाई; करूप्पासामी पुत्र चित्रैवेल, वेरैया पुत्र सुदालई, मुरूगसेन पुत्र पेरूमल, चेलाप्पा पुत्र पादयाची, सुन्दरम पुत्र शंकरलिंगम, पौचामी पुत्र मुथैया, रामामूर्ति पुत्र, शनमुगम, थीरूमल पुत्र परदेश और मेंगाराज पुत्र रामकृष्णन इंडिया सीमेन्ट लि० थालैयुथु, शंकर नगर, जिला तिरूनेलवेली की खदानों में नैमित्तिक/अस्थाई कर्मकारों के रूप में एक से 3 वर्ष या इससे ज्यादा अवधि के लिए नियोजित थे ? यदि हां, तो क्या इन्डिया सीमेन्ट लि० के प्रबंधतंत्र ने कानून के उपबन्धों का अनुसरण किए बिना उनकी सेवाओं को समाप्त किया था, और यदि हां, तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष के हकदार हैं ?

(ख) क्या तिन्नेवेली तालुक नेशनल जनरल वर्कर्स यूनियन की :

(i) इंडिया सीमेन्ट लि० की खानों के भूवैज्ञानिक अनुभाग में नियोजित सर्व श्री एस० थांगराज, पी० आथी, पी० बालकृष्णन, के मुथु, ए० कृष्णन और पीर माईदीन को नियमित करने; और

(ii) श्री के० मुन्नियांडी, जिसका टोकन नं० 5566 है, को ड्रिलर ग्रेड से वैगन ड्रिल आपरेटर के रूप में पदोन्नत करने की मांग न्यायोचित है ?

यदि हां, तो संबंधित कर्मकार किस अनुतोष के हकदार है ?

[सं० एल-29011/76/83-डी-3 (बी)]

MINISTRY OF LABOUR & REHABILITATION

(Department of Labour)

New Delhi, the 23rd April, 1984

ORDER

S.O. 1765.—Whereas the Central Government of opinion that an industrial dispute existing between the employers in relation to the mangement of India Cements Ltd., Sankarnagar and their workmen in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed ;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7A, and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri T. Arul Raj shall be the Presiding Officer, with headquarters at Madras and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

(a) "Whether S/Shri M. Peer Mydeen, V. Ravi, S. Kothanda Raman, K. Muthu Pandi, K. Madasamy, S. Baskar S. Lakshmanan, M. Mayandi, K. Arumugam, R. Kandasamy, M. Chinnathambi S/o Muthan, Komu S/o Muthiah, S. Pandaram S/o Sudalai, Sudalai S/o Esakki Asari, Veluchamy S/o Sudalai, Karuppasamy S/o Chitraivel, Veriah S/o Sudalai, Marugesen S/o Perumal, Chellappa S/o Padayachi, Sundaram S/o Sankaralingam, Paulhamy S/o Muthiah, Ramamurthy S/o Shunmugam, Thirumal S/o Paradesh and Mengaraj S/o Ramakrishan were employed as casual/temporary workman in the quarries

of India Cements Ltd., at Thalaiyuthu, Sankarnagar, Distt. Tirunelveli for the period ranging from one to three years or more ? If so, did the mangement of India Cements Ltd. terminate their services without following the provisions of law, and if so, to what relief are the said workmen entitled ?"

(b) Is Tinnevelly Taluk National General Workers Union justified in demanding :

(i) regularisation S/Shri S. Thangaraj, P. Aathi, P. Balakrishnan, K. Muthu, A. Krishnan and M. Peer Mydeen employed in the Geological Section of the mines of India Cements Ltd., and

(ii) promotion of Shri K. Munniyandi, Token No. 556 from the Grade of Driller to Wagon Drill Operator;

If so, to what relief are the workmen concerned entitled?"

[No. L-29011/76/83-D. III(B)]

नई दिल्ली, 3 मई, 1984

आदेश

का० आ० 1765 :—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में अगनीगुण्डाला लैड प्रोजेक्ट, हिन्दुस्तान जिंक लि०, बन्दालामोत्तु के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध एक औद्योगिक विवाद नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः; केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उप-धारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री एम. श्रीनिवास राव होंगे जिनका मुख्यालय हैदराबाद में होगा और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

"क्या अगनीगुण्डाला लैड प्रोजेक्ट, हिन्दुस्तान जिंक लि०, बन्दालामोत्तु के प्रबन्धतंत्र की ड्रिलर-एवं-ब्लास्टर, श्री एम. वेंकटेश्वलु को बर्खास्तगी का दण्ड देने की कार्रवाई न्यायोचित है? यदि नहीं, तो संबंधित कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?"

[सं० एल-29012/58/83- डी-3 (बी)]

नन्द लाल, अवर सचिव

New Delhi, the 3rd May, 1984

ORDER

S.O. 1765.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Agnigundala Lead Project, Hindustan Zinc Ltd., Bandalamottu and their workmen in respect of the matters specied in the Schedule hereto annexed;

And Whereas the Central Government considers it desirebel to refer the said dispute for adjudication;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A, and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri M. Srinivasa Rao shall be the Presiding Officer, with headquarters at Hyderabad and refersthe said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

Whether the action of the management of Agnigundala Lead Project,Hindustan Zinc Ltd., Bandalamottu, in awarding the punishment of discharging to Shri M. Venkateshwarlu, Driller-cum-Blaster is justified If not, to what relief is the workman concerned entitled?

[No. L-29012/58/83-D.III (B)]

NAND LAL, Under Secy.

New Delhi, the 23rd May, 1984

S.O. 1766.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Industrial Tribunal, Bangalore, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Messrs Tungabhadra Minerals Pvt. Ltd., Sandur Taluk Bellary Dist: and their workmen, which was received by the Central Government on 3-5-1984.

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL IN KARNATAKA, BANGALORE

Dated this the 17th day of April, 1984

PRESENT :

Sri B. N. Lalage, B.A., (Hons.), LL.B, Presiding Officer.

Central Reference No. 7 of 1984

I PARTY

The General Secretary, the Bellary District Mysore Minerals Mines Workers Union, Taranagar, Post Office Sandur Taluk (Karnataka).

Vs.

II PARTY

The Agent, M/s. Tungabhadra Minerals Pvt. Ltd., Taranagar, Post Office Sandur Taluk, Bellary Distt., Mysore State.

APPEARANCES :

For the I Party—Sri V. K. Ramakrishna, Vice President.

For the II Party—Sri N. S. Prasad, Advocate, Bangalore.

AWARD

By Order No. L-29011/40/73-LRIV/D. III dated 10-2-1984 the Government of India has made the present reference on the following points of dispute :—

(1) Whether all the employees are entitled to bonus for the accounting years 1971-72 and 1972-73 and what is the quantum of bonus they are entitled to ?

(2) Whether the fixation of Shri C. K. Bhaskar, Compressor Operator, in Grade II needs review and consideration ? If so, to what relief is he entitled and from what date ?

2. Notice has been issued for appearance of the parties.

3. Today, Sri N. S. Prasad has filed a joint memo and submitted that an award may be passed in terms of the settlement.

4. The contents and execution of the settlement are admitted. From the terms of the settlement, it appears that Sri C. K. Bhaskar has been paid some ex-gratia amount equal to one month's pay of Rs. 585 and that he has settled the dispute. Regarding the claim for bonus the workmen have withdrawn the demand. I find that the settlement is in the interest of workmen and it deserves to be accepted.

5. In the result, an award is passed in terms of the settlement. The settlement shall form part of the award.

(Dictated to the stenographer, transcribed and typed by him and corrected by me).

B. N. LALAGE, Presiding Officer

[No. L-29011/40/73-LR.IV/D.III (B)]

NAND LAL, Under Secy.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, BANGALORE

Reference No. 4 of 1973

BETWEEN

M/s. Tungabhadra Minerals Private Ltd. Taranagar B.P.O. Sandur Taluk, Bellary District Karnataka State.

AND

Bellary District Mysore Minerals Mines Workers Union, Sandur.

The Government of India, Ministry of Labour, vide Notification No. L-29011/40/73-LR-IV dated 29-9-1973 has referred the industrial dispute between the above mentioned parties for adjudication. Both the parties hereby submit that they had discussed the issues and came to an understanding and signed a memorandum of settlement dated 2-1-1984. While submitting a copy of the memorandum of settlement both the parties pray the Hon'ble Tribunal to give a consent Award keeping in view the terms of the settlement.

On behalf of the Management of

M/s. Tungabhadra Minerals Private Ltd.:

(K. V. SATHYANARAYANA)
Personnel Officer

On behalf of the Bellary Dist. Mysore Minerals Mines Workers Union :

(V. K. RAMAKRISHNA)
Vice-President.

(T. N. SHIVASANKARAN)
General Secretary.

Bangalore,

Dated : 2-1-1984.

Memorandum of Settlement under Sec. 2(p) of Industrial Disputes Act, 1947 in the industrial dispute raised by Bellary District Mysore Minerals Mines Workers Union, regarding alleged illegal retrenchment of 18 workmen w.e.f. 9th June 1977 and 128 workmen w.e.f. 18th June 1973; payment of bonus for the accounting years 1971-72 and 1972-73 and fixation of Grade II to Shri C. K. Bhaskar, Compressor Operator.

PRESENT :

Representing the Management of

Tungabhadra Minerals Ltd. :

Shri K. V. Sathyanarayana,
Personnel Officer.

Representing the Bellary Dist. Mysore Minerals

Mine Workers Union :

1. Shri T. N. Shivasankaran,
General Secretary.

2. Shri V. K. Ramakrishna,
Vice-President.

Short Recital of the Case

Whereas the Government of India, Ministry of Labour, in exercise of the powers conferred by section 7A and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, constituted an Industrial Tribunal with headquarters at Bangalore and referred the dispute for adjudication on the following issues :—

1. Whether the action of the management in retrenching 18 workmen on the 9th June, 1973 and 128 workmen on tse 18th June 1973 is legal and justified ? If not to what relief are the affected workmen entitled ?

2. Whether all the employees are entitled to bonus for the accounting years 1971-72 and 1972-73 and what is the quantum of bonus they are entitled to ?

3. Whether fixation of Grade II to Shri C. K. Bhaskar needs review and consideration ? If so, to what relief is he entitled and from what date ?

Whereas the management of Tungabhadra Minerals Private Ltd. has filed a Writ Petition No. 1464 of 1974 in the High Court of Karnataka at Bangalore questioning the legality of the reference of the above dispute for industrial adjudication;

Whereas the Hon'ble High Court of Karnataka at Bangalore, in its decision dated 3rd day of August 1983 has held that there was no dispute at all in respect of retrenchment of 18 workmen with effect from 9-6-73 and 128 workmen w.e.f. 18-6-73 and allowed the Writ Petition by setting aside the reference made by the Central Government in respect of retrenchment of workmen mentioned above.

As regards the second demand viz. payment of bonus for the accounting years 1971-72 and 1972-73, the Union stated that M/s. Tungabhadra Minerals Pvt. Ltd. is a successor of the business of M/s. Mysore Minerals Ltd. and was required to pay bonus for the accounting years 1971-72 and 1972-73 as per the provisions of the Payment of Bonus Act, 1965. The Management on the other hand stated that the Company M/s. Tungabhadra Minerals Pvt. Ltd. was incorporated on 27-4-71 and commenced the business operation from 14-6-71. The Company is a legal entity registered under the Indian Companies Act 1956. With a view to establish an Iron Ore based Industry after detailed exploration of the deposits and prepration of Project Report in order to facilitate the main objection. The Company started the mining operations and supplied ore to Minerals and Metals Trading Corporation of India Ltd. on behalf of Mysore Minerals Ltd. In the circumstances, they stated that they cannot be considered as the Successor of the business of Mysore Minerals Ltd. Further, the company has not taken over the Assets and Liabilities of Mysore Minerals Ltd. which is run by the Government of Karanaka. The Management, therefore, stated that they are not required to pay bonus for the accousting years 1971-72 and 1972-73 in view of the protection under Sec. 16 (1A) of Payment of Bonus Act 1965. They, however, stated that they have started paying minimum bonus as per the provisions of P.B. Act. For the accounting year 1982-83 they are paying bonus at the rate of 20% of the gross wages by the end of January 1984 (approached appropriate authorities for extending time limit from 30th November '83 to 31st January '84).

As regards review of fixation of Grade II to Shri C. K. Bhaskar, Compressor Operator, the Union stated that Shri Bhaskar was not given Gr. I in the year 1972 although the other employee Shri Basha was given Gr. I w.e.f. 1-4-72. The Management stated that they have fixed Shri C. K. Bhaskar in Gr. II w.e.f. 1-4-72 after proper job evaluation and also merit-rating. However, in the year 1975 Shri Bhaskar was also promoted as Grade-I Operator based on the progress and performance of the employee.

After referring the matters to the Tribunal, the Management and the Usion discussed bilaterally on different dates and finally on 2nd January 1984 and agreed to resolve the above dispute on the following terms :

Terms of Settlement

1. In order to have cordial industrial relations and keeping in view all the provisions of the Payment of Bonus Act 1965, the Union agrees to withdraw the claim for bonus for the a/c years 1971-72 and 1972-73 irrespective of the merits/demerits of the demand made by the Union earlier.

2. The Management of M/s. Tungabhadra Minerals Ltd. agrees to pay one month's salary of Rs. 585 as ex-gratia to Shri C. K. Bhaskar Compressor Operator, on or before 31-1-1984. In view of the above, the Union agrees not to press their demand for review of fixation of pay of Shri C. K. Bhaskar and to place him in Gr. I w.e.f. 1-4-1972.

3. Both the parties agree to file this Memorandum of Settlement before the Hon'ble Industrial Tribunal, Bangalore and pray for issuing a consent award.

Dated at Bangalore this 2nd day of January 1984.

On behalf of the Management of
M/s. Tungabhadra Minerals Ltd
(K. V. SATHYANARAYANA)

On behalf of the Bellary Dist. Mysore
Minerals Mine Workers Union.

(T. N. SHIVASANKARAN)
(V. K. RAMAKRISHNA)

Witnesses :

1. [J. Kanakiah, Regional Labour Commissioner (Central) Bangalore]

2. [S. M. Kurup, Office Superintendent, Office of the Regional Labour Commissioner (C), Bangalore]

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL AT BANGALORE

Central Ref. No. 7/1984

BETWEEN

The General Secretary.
The Bellary District Mysore Minerals
Mines Workers Union,
Taranagar. I. Party

Vs.

Tungabhadra Minerals Limited II Party

JOINT MEMO

The Central Government had made earlier Central Ref. No. 4/73 by order dated 29-9-73 to this Hon'ble Tribunal. The following three questions for adjudication :

1. Whether the action of the Management in retrenching 18 workmen on the 9th June, 1973 and 128 workmen on the 18th June, 1973 is legal and justified ? If not, to what relief are the affected workmen entitled.

2. Whether all the employees are entitled to bonus for the accounting years 1971-72 and 1972-73 and what is the quantum of bonus they are entitled to ?

3. Whether fixation of grade II to Sri C. K. Bhaskar needs review and consideration? If so, to what relief is he entitled and from what date ?

The II party had challenged the above reference No. 4/73 in W.P. No. 1464/74 on the file of the High Court of Karnataka. The Hon'ble High Court by its judgement of 3-8-83 quashed the reference in so far as the first question and thus the remaining questions had to be adjudicated upon.

After the order of the High Court conciliation proceedings were started by the Regional Labour Commissioner (Central) Bangalore on the remaining two questions, and the parties arrived at a settlement and signed the some on 2-1-1984 before the Regional Labour Commissioner (Central) Bangalore settling the dispute as follows : Copy of which is annexed to this Memo.

Both the I party and II party have filed joint memo in Central Ref. 4/73 and prayed that an award be passed in terms of the settlement dated 2-1-84 before this Hon'ble Tribunal.

In the meantime the Central Government has by their order dated 10-2-1984 referred to this Hon'ble Tribunal the two questions which had not been touched upon by the High Court for adjudication. This has been numbered as Central Ref. 7/84. The two questions referred by the Central Government in the present reference which is numbered as Central Reference No. 7/84 is the two came questions 2 and 3 of earlier Central Ref. 4/73.

Both the parties have already settled the dispute referred to in the present ref. 7/84 as per the settlement dated 2-1-84 filed in Central Ref. 4/73. Thus there is no dispute that is surviving between the I and II party which require adjudication.

Therefore it is prayed by both the parties that this Hon'ble Tribunal may close the present reference as not surviving in view of the settlement arrived at between the parties on 2-1-84 and filed in Central Ref. 4/73 before this Hon'ble Tribunal for passing an award in terms of the settlement.

I Party :

On behalf of the Bellary District Mysore
Minerals Mines Workers Union.

(V. K. RAMAKRISHNA)
Vice President.

II Party :

On behalf of the Management of
M/s. Tungabhadra Minerals Limited.
(K. V. SATHYANARAYANA),
Personnel Officer.

नई दिल्ली, 17 मई, 1984

का०आ० 1767.—केन्द्रीय सरकार ने यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (द) के उपखण्ड (II) के उपबन्धों के अनुसरण में भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का०आ० 4631 तारीख 9 दिसम्बर, 1983 द्वारा लौह अयस्क खनन उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 9 दिसम्बर 1983 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था;

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है;

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (4) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 9 जून, 1984 से छः मास की और कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा० एस०-11017/8/81-डी-1 (ए)]

New Delhi, the 17th May, 1984

S.O. 1767.—Whereas the Central Government having been satisfied that the public interest so required had, in pursuance of the provision of sub-clause (vi) of clause (n) of Section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), declared by the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 4631 dated the 9th December, 1983, the iron ore mining industry to be a public utility service for the purposes of the said Act, for a period of six months, from the 9-12-1983;

And, whereas, the Central Government is of opinion that public interest requires the extension of the said period by a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of Section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby, declares the said industry to be a public utility service for the purposes of the said Act, for a further period of six months from 9-6-1984.

[No. S-11017/8/81-D.I(A)]

नई दिल्ली, 21 मई, 1984

का० आ० 1768:—केन्द्रीय सरकार ने यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (न) के उपखण्ड (vi) के उपबंधों के अनुसरण में भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 4728 तारीख 2 दिसम्बर, 1983 द्वारा कोल उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 2 दिसम्बर, 1983 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था;

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (न) के उपखण्ड (vi) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 2 जून, 1984 से छः मास की और कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा० एस-11017/13/1981-डी-1(ए)]

एस. एच. एस. अय्यर, अवर सचिव

New Delhi, the 21st May, 1984

S.O. 1768.—Whereas the Central Government having been satisfied that the public interest so required had, in pursuance of the provisions of sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), declared by the notification of the Government of India in the Ministry of Labour S.O. No. 4728 dated the 2nd December, 1983, the Coal Industry to be public utility service for the purposes of the said Act, for a period of six months from the 2nd December, 1983;

And whereas, the Central Government is of opinion that public interest requires the extension of the said period by a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section (2) of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the said industry to be a public utility service for the purposes of the said Act, for a further period of six months from the 2nd June, 1984.

[No. S-11017/13/81-D.I(A)]

S.H.S. IYER, Under Secy.

नई दिल्ली, 17 मई, 1984

का०आ० 1769.—केन्द्रीय सरकार, अभ्रक खान श्रम कल्याण निधि नियम, 1948 के नियम 3 के साथ पठित अभ्रक खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1946 (1946 का 22) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र के भाग II खंड 3, उपखंड (2), दिनांक 17 अक्तूबर, 1981 के पृष्ठ 3490-91 पर का०आ० संख्या 2884 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :—

उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या 2 तथा 10 के सामने निम्नलिखित रखा जायेगा, अर्थात् :—

"2. कल्याण आयुक्त,
श्रम कल्याण संगठन,
भारत सरकार,
श्रम और पुनर्वास मंत्रालय,
(श्रम विभाग),
5-52 गली संख्या-8,
हुब्सिगुंदा,
हैदराबाद —उपाध्यक्ष (पदेन)"

10. कल्याण प्रशासक,
श्रम कल्याण संगठन,
कालिचेडु, जिला नेल्लौर,
आन्ध्र प्रदेश,
सचिव (पदेन)"

[फा० संख्या० यू-18012/2/80-एम०III/डब्ल्यू-II]

New Delhi, the 17th May, 1984

S.O. 1769.—In exercise of the powers conferred by section 4 of the Mica Mines Labour Welfare Fund Act, 1946 (22 of 1946) read with rule 3 of the Mica Mines Labour Welfare Fund Rules, 1948, the Central Government hereby amends the notification published vide S.O. number 2884 at pages 3490-91 of the Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 17th October, 1981, as under :—

In the said notification, at serial number 2 and 10, the following shall be substituted, namely :—

"2. Welfare Commissioner
Labour Welfare Organisation,
Government of India,
Ministry of Labour & Rehabilitation
(Department of Labour)
5-52, Street No. 8
Hubsiguda, Hyderabad——Vice Chairman (ex-officio)"

"10. Welfare Administrator,
Labour Welfare Organisation,
Kalichedu, Distt. Nellore,
Andhra Pradesh—Secretary. (ex-officio)"

[F. No. U-18012/2/80-MIII/W.II]

का०आ० 1770.—केन्द्रीय सरकार, लौह अयस्क खान, मैंगनीज अयस्क तथा क्रोम अयस्क खान श्रम कल्याण निधि नियम, 1978 के नियम 3 के साथ पठित लौह अयस्क खान, मैंगनीज अयस्क खान तथा क्रोम अयस्क खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1976 (1976 का 61) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राजपत्र के भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), दिनांक 3 अक्तूबर, 1981 के पृष्ठ 3334 तथा 3335 पर प्रकाशित भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का०आ० 2692 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:—

उक्त अधिसूचना में क्र० संख्या-10 के सामने निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"10. श्री डी०डी०सिंह,
संयुक्त निदेशक, कच्चा माल व खान केन्द्र,
लोहा व इस्पात अनुसंधान व विकास केन्द्र,
डाकघर हिनू, डोरानडा,
राँची-834002"

[सं०-यू० 23017(10)/80-एम० IV/डब्ल्यू II]

S.O. 1770.—In exercise of the powers conferred by section 6 of the Iron Ore Mines, Manganese Ore Mines and Chrome Ore Mines Labour Welfare Fund Act, 1976 (61 of 1976) read with rule 3 of the Iron Ore Mines Labour Welfare Fund Rules 1978, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification number S.O. 3021 published at page 3057 of Part-II section 3, sub-section (ii) of the Gazette of India dated the 28th August, 1982;

In the said notification, against serial number-10, the following shall be substituted, namely :—

Shri G. D. Singh,
Joint Director,
Centre for Raw Materials & Mines,
Research & Development Centre for
Iron & Steel, P.O. Hinoo, Doranda,
Ranchi-834002.

[No. U-23017/(10)/80-MIV/W.II]

का० आ० 1771—केन्द्रीय सरकार, लौह अयस्क खान, मैंगनीज अयस्क खान तथा क्रोम अयस्क खान, श्रम मंत्रालय, श्रम कल्याण निधि नियम, 1978 के नियम 3 के साथ पठित लौह अयस्क खान, मैंगनीज अयस्क खान, तथा क्रोम अयस्क खान, श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1976 (1976 का 61) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र के भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) दिनांक 12-9-1981 के पृष्ठ शून्य पर क्रमांक 2415 पर प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 13 अगस्त, 1981 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में क्रमांक 3 के सामने निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"3. क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय),
भारत सरकार,
श्रम और पुनर्वास मंत्रालय,
(श्रम विभाग)
6/7 क्रेसेन्ट रोड,
हाई ग्राउंडस,
बंगलोर-560001—केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि (पदेन)

[फा० सं० यू-23017/8/80-एम० IV/डब्ल्यू II]
कंवर राजिन्द्र सिंह, अवर सचिव

S.O. 1771.—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Iron Ore Mines and Manganese Ore Mines and Chrome Ore Mines Labour Welfare Fund Act, 1976 (61 of 1976) read with rule 3 of the Iron Ore Mines, Manganese Ore Mines and Chrome Ore Mines Labour Welfare Fund Rules 1978, the Central Government hereby amends the notification dated the 13th August, 1981 published vide S.O. No. 2415 at page Nil of the Gazette of India Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 12th September, 1981.

In the said notification, at serial number 3, the following shall be substituted, namely :—

"3. Regional Labour Commissioner (Central)
Government of India
Ministry of Labour and Rehabilitation
(Department of Labour)
6/7, Crecent Road, High Grounds,
Bangalore-560001. Central Government
Representative (ex officio)

[F. No. U-23017/8/80-M. IV/W. II]
KANWAR RAJINDER SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 17 मई 1984

का० आ० 1771—मैसर्स टाटा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, [(नेदर डिविजन), देवास-455001 (मध्य प्रदेश/2298)] जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उप-धारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है :

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, उक्त स्थापन जीवन बीमा के स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, मध्य प्रदेश ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसा लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के पन्द्रह दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

3. जीवन बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित जीवन बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु-संख्या की भाषा में उसकी उनकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, जीवन बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम की संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते है तो, नियोजक जीवन बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि करने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए जीवन बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है।

7. जीवन बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होगी, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. जीवन बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, मध्य प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन के से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश उक्त स्थापन के कर्मचारी उक्त स्थापन की जीवन बीमा स्कीम के अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं तो छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो उक्त स्थापन की जीवन बीमा स्कीम के अधीन नियत की जाए, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन भूत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिवारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/120/81-पी०एफ०-2]

New Delhi, the 17th May, 1984

S.O. 1772.—Whereas Messrs Tata Exports Limited, (Leather Division), Dewas-455001 (MP/2298) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) ;

And, whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Life Cover Scheme of the said establishment in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Life Cover Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Life Cover Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Life Cover Scheme and pay necessary premium in respect of him.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits avalaible to the employees under the Life Cover Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Life Cover Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Life Cover Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Life Cover Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Life Cover Scheme of the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed under the Life Cover Scheme of the said establishment, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it.

[No. S-35014(120)/81-PF. II]

नई दिल्ली, 19 मई, 1984

शुद्धि-पत्र

का० आ० 1773:—भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 1 अक्तूबर, 1983 के पृष्ठ 3833 पर प्रकाशित भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 3730, तारीख 20 सितम्बर, 1983 में दूसरी पंक्ति में, "6/14/1 बी" के स्थान पर "6/1ए-1 बी" पढ़ें।

[सं० एस-35017/68/83-पी०II]

ए० के० भट्टाचार्य, अवर सचिव

(Department Of Labour)

New Delhi, the 19th May, 1984

CORRIGENDUM

S.O. 1773.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Labour S.O. No. 3730 dated 20th September, 1983 published in part II Section 3, Sub-section (ii) of the Gazette of India dated 1st October 1983 at page 3833 in line 4, for the words "6/14-1B" read "6|1A-1B".

[No. S.35017|68|83-P.F.II]
A. K. BHATTARAI, Under Secy.

New Delhi, the 18th May, 1984

S.O. 1774.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Chandigarh in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Beas Sutlej Link Project and their workman which was received by the Central Government on the 8th May, 1984.

BEFORE SHRI I. P. BASISHTH, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, CHANDIGARH

Case No. I.D. 49/1983 (CHD) 124/1981 (N. Delhi)

PARTIES :

Employers in relation to the management of Beas Sutlej Link Project, Sundernagar.

AND

Their Workman—Shri Krishan Dev

APPEARANCES :

For the Employers—S/Shri M. K. Bohra and R. L. Dogra.

For the Workman—Shri M. S. Toggar.

Beas Sutlej Link Project STATE : Himachal Pradesh.

AWARD

Dated, the 2nd of May, 1984

The Central Government Ministry of Labour, in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947, hereinafter referred to as the Act, vide their Order No. L-42012(19)/81-D.II(B) dated the 26th of August 1981 read with S.O. No. S-11025 (2)/83 dated the 8th of June, 1983 referred the following Industrial dispute to this Tribunal for adjudication :—

"Whether the action of the employer in relation to Beas Sutlej Link Project is justified in striking off the name of the workman Shri Krishan Dev, Painter, from their rolls amounting to termination of his service with effect from 26-6-1976 ? (sick ? 26-8-1976) ? If not, to what relief is Shri Krishan Dev entitled ?"

2. Brief facts of the case, according to the petitioner-Workman, are that he was working as a Painter under the control of Executive Engineer Electrical Divn. No. 4 at BSL Project Sundernagar up to June 1976 on 1-7-1976 when he went to attend duty, the S.D.O. Admn., informed him that he had been transferred to the Township Division and, therefore, he should report there. However, the S.D.O. did not issue him the Transfer Card on the pretext that it had already been despatched by post. But when the petitioner contacted the XEN of the Township Divn. he was dismayed to know that no such Transfer Card had been received by them. This confused state of affairs caused grave prejudice to the petitioner in the sense that his attendance was not marked in the either of the Divisions". He, therefore, again contacted the S.D.O. Admn., and Executive Engineer Divn., No. IV for regularisation of his service but this time he was asked to report in Gate Erection Division for duty and since no post was available for him there also, so he was advised to proceed on leave. Thus the petitioner contacted the XEN Personnal Divn., who instructed the S.D.O. Admn., to regularise his service and record his attendance, but instead of showing any contructive response, the Executive Engineer Electrical Divn., No. IV struck off his name from the rolls w.e.f. 26-8-76. It was avered that otherwise also, the transfer was bad in the eye of law because in the Electrical Divn. he was enjoying the benefits under the scheme relating to Employees Provident Fund which was not available in the Township Divn. and no notice under Section 9-A of the Act had been given to him to effect the service conditions.

3. Forced by the Circumstances, the petitioner filed a service appeal, which also proved futile and, thus, he raised an Industrial dispute; but as the same could not be settled amicably despite the intervention of the A.L.C. (C) during the Conciliation proceedings, hence the Reference.

4. Resisting the proceedings, the Management denied any impropriety or illegality in their action in striking off the petitioner's name from their rolls. It was contended that a prior notice under section 9-A was issued on 9-1-1976 declaring him as "surplus" and thus clearing the passage for his transfer to any other place in the Project even where the E.P.F. scheme was not applicable. It was alleged that the petitioner had refused to accept his transfer card to the Township Division w.e.f. 1-7-1976 and so the same was sent to the concerned Executive Engineer by post who, however, reported back that the petitioner was not required there. Accordingly on 8-7-1976 he was transfered to the Gatte Errection Division but as he did not report there for duty so he was treated as absent and a notice to this effect pasted on the Notice Board. Elaborating their version, the Management pleaded that the petitioner had appeared in the Office for short durations on 29-7-76, 13-8-76; 19-8-76 and 25-8-76 but did not join duty and also refused to receive the Transfer Cards; so much so that on 30 and 31 August, 1976 letters were issued to him with a caution that either he should report on duty or it would be assumed that he had voluntarily abandoned his job. But all this exercise proved futile and so under the orders dated 15-9-76 passed by the Executive Engineer Div., No. IV his name was struck off the rolls by virtue of Section 14(a) of the Certified Standing Order w.e.f. 26-8-1976.

5. Since the pleadings of the parties were found fully convered under the term of reference, therefore, they were called upon to adduce evidence in support of their respective versions. Accordingly, the management examined their XEN (Per) Shri Narinder Singh whereas the petitioner himself appeared in the witness box. Of course both the parties also produced a few documents of the admitted nature.

6. On a careful consideration of the entire material on records and hearing the parties I am not inclined to sustain the Management's action in terminating the petitioner's services under the impugned order dated 15-9-76 [Ex. R12] primarily because it is based on the assumption of his culpable absence from duty for a period of more than ten days w.e.f. 26-8-1976 whereas no enquiry of fact was ever undertaken by the Dept. on joining him in the proceedings even though it had through out been a matter of dispute between the parties as to whether the petitioner was deliberately avoiding the Transfer Orders or his Supervisory officers were toying with him on the pretext of his transfer from one Division to the other on different occasions. Amongst others, letter Ex. R6 is crucial in the sense that it contained a direction from the S.D.O. Admn., to his counterpart in the Electrical Sub. Divn. for marking the attendance of the petitioner in the 2nd shift w.e.f. 25-8-76 as per order of the Executive Engineer, meaning thereby that atleast at that stage the Dept. had realised that there was some force in his stand that he was not being assigned any duty and entered in the attendance Register inspite of his persistent efforts. The inference draws implied support even from the impugned order which is absolutely silent regarding the petitioner's alleged absence prior to 26-8-76 even though a case to this effect was sought to be built up in the pleadings and propogated through a number of office orders.

7. The learned representative of the management drew my attendance towards, their correspondence with the petitioner contained in the documents Ex. R7, R8 and R9 revealing "inter-alia" that time and again letters were written to the petitioner that he was unreasonably avoiding the Transfer Orders, rather he was defaulting in joining duty and expos-

ing himself to the risk of termination on the assumption of voluntary resignation; so much so that in the letter Ex. R8 it was categorically emphasised that on his failure to report on duty by 4-9-76, he was likely to lose his job. It was thus argued that since there was a stark failure on the part of the petitioner to report for duty, therefore the Management was fully justified in striking off his name from the rolls by virtue of Section 14(a) of the Certified Standing Orders.

8. Inspite of seeming attraction, the submission failed to carry conviction with me because none of the aforesaid letters can be magnified in isolation on divorcing the attendant circumstances. Letter Ex. W-7 was written by the XEN Personnal Divn. to his counter part in the Gate Errection Division on 27-7-76, advising him to refrain from harassing the petitioner any more. In the same sequence, the author pointed out that the Dept. was bound to assign him duty and that there was no force in the pretext that there was no scope of his absorption in the painter's trade to which he belonged. No action was taken on this letter till 13-8-76 when the letter Ex. W-8 was addressed to the petitioner by the S.D.O. Admn., containig a veiled threat to do away with his services in case of his failure to report at Pung on or before 20-8-76, for receiving the transfer order from the Executive Engg. Electrical Divn. No. IV for Gate Errection Divn. I fail to understand as to what prevented the S.D.O. Admn., in despatching the Transfer order also alongwith his letter; **Anyway** the petitioner lost no time in replying to the said letter and sent application Ex. W-9 dated 16-8-76 expressing his willingness to attend the office to receive the Transfer Orders, simultaneously he also prayed for the regularisation of his services for the period when he was being shuttle cocked from one office to the other. His letters. Ex. W-10 dated 19-8-76 further reveals that they did attend the office on that date but was not given any Transfer Orders, and that was how that he contacted the XEN Electrical Divn. No. IV. Sundernagar who advised his counterpart Shri K. V. Motwani per letter Ex. W-11 dated 23-8-76 for petitioner's retention in his Divn. But no constructive action was taken and thus the petitioner was forced to issue Regd. Notice Ext. W-12 dated 27-8-76 for being provided with duty. Similarly his efforts to seek redress by moving the higher authorities through letters Ex. W-15 and 16 dated 6-9-76 and 13-9-76 respectively, also appear to have fallen on deaf ears.

9. Be that as it may, the aforesaid circumstances do indicate that there was a bonafide and triable dispute of fact as to whether the petitioner was avoiding duty or was being forced by the powers that be to do so for the reasons better known to them; and obviously the truth could be known only after going in for an enquiry of fact on joining the petitioner in the proceedings. In short, a model and judicious Management could not accept the exparte version of the supervisory Officers that he was deliberately absenting himself from duty so as to apply the gullotine under Section 14(a) of the Certified Standing Orders; and since no such effort was made by the Respdt., therefore, one can not possibly approve their action.

10. Accordingly, I set aside the impugned termination and direct for his forthwith re-instatement. All the same the petitioner would not be paid any back wages because his statement, recorded during the proceedings before me, indicates that he had through out been gainfully employed; and even though he tried to play smart by concealing some important information, yet he stood exposed on the acid test of cross-examination that as a matter of fact, during the meanwhile he had been abroad also in search of green pastures.

11. To conclude, I return my award in favour of the petitioner Workman for his qualified reinstatement in the light of my observations in the proceeding para.

Chandigarh.

Dated : 2-5-1984.

I. P. VASISHTH, Presiding Officer

[No. L-42012/19/81-D.II(B)]

S.O. 1775.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Chandigarh in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Bhakra Beas Management Board and their workmen which was received by the Central Government on the 8th May, 1984.

BEFORE SHRI I. P. VASISHTH, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, CHANDIGARH

Case No. I.D. 142/81 (N. Delhi) 87/83 CHD

PARTIES :

Employers in relation to the management of Bhakra Beas Management Board-Nangal Township-Punjab.

AND

Their Workmen—Gandharb Singh and another.

APPEARANCES :

For the Employers—Shri R. L. Kaith.

For the Workman—Shri R. K. Singh.

Bhakra Beas Management Board Nangal—Punjab

AWARD

Dated, the 3rd May, 1984

The Central Government Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947, hereinafter referred to as the Act, per their Order No. L-42012(25)/81-D.II(B) dated the 22nd of October, 1981 read with S.O. No. S-11025 (2)/83 dated the 8th of June, 1983 referred the following Industrial dispute to this Tribunal for adjudication :—

"Whether the demand of the workmen that S/Shri Gandharb Singh and Harbhajan Singh, retrenched firemen, be employed by the employer in relation to Bhakra Beas Management Board in view of Section 25-H of the Industrial Disputes Act is justified ? If so, to what relief the workmen are entitled and from what date."

2. Brief facts of the case, according to the petitioner/Workmen, are that both of them were retrenched by the Respdt. Board after putting in more than 2 years' continuous service as Firemen in late November 1969 due to reduction in the cadre strength; that their work and conduct had through out been upto the entire satisfaction of the Management; and so much so that some of their reports were assessed as 'out-standing'. It was avered that the Management recruited one Nank Chand son of Shri Shiv Ram as Fireman w.e.f. 27-9-1975 and promoted another 28 Workmen from the lower ranks to the cadre of Firemen w.e.f. 5-9-1980 without considering their claims to employment as required under the mandatory provisions of Section 25-H of the Industrial Disputes Act, 1947. They, therefore, raised an Industrial Dispute which defied an amicable settlement despite the intervention of the ALC(C) during the Conciliation proceedings and hence the Reference.

3. Resisting the proceedings on all counts, the Management questioned the propriety of reference for want of any existing or apprehended dispute. It was contended that otherwise also it was highly belated and bad for misjoinder and nonjoinder of necessary parties. On facts, it was conceded that the petitioners were retrenched w.e.f. 30-11-1969 due to reduction in cadre strength and one Nank Chand was recruited as a Fireman in the year 1975, but this action was sought to be justified on the ground that his father Shiv Ram had died as a member of the Fire Crew and so he was recruited on purely compassionate grounds as a policy matter envisaged for the welfare of the Workmen. Similarly appointment of 28 additional hands as Firemen in the year 1980 was also not denied but it was explained that all of them were old guards and recruited from the surplus pool, on the basis of their experience.

4. In the light of pleadings the following issue was framed over and above the terms of reference.

1. Whether the reference is legally infirm and incompetent as alleged ? O.P.R.

5. In support of their respective versions, the parties adduced verbal as well as documentary evidence which I have carefully persued and heard them. My issue-wise discussion and findings are as follows :—

ISSUE NO. 1

6. The contention that there was neither any pending nor apprehended dispute is completely devoid of force because had it been so, the Management would have straight away conceded to the petitioners' demand, particularly in view of the common proposition that they were their retrenched employees and had put in a good quality of service before being disengaged. Similarly it is a misconceived notion to attack the maintainability of the reference on the ground of laches because the cause of action accrued to the petitioners in the year 1975 when Shiv Ram was recruited and again in September 1980 when rankers were promoted as Firemen in disregard of their preferential right envisaged by Section 25-H. It may be worth-while to note that immediately thereafter a demand was raised by them and that was how that on the failure of the Conciliation proceedings. Appropriate Government made the reference in the year 1981. It is beside the point that there is no fixed limit under Act to bind down the aggreived Workmen for raising their demand within a particular period from the point of accrual of course of action. I, therefore, answer the issue against the Management.

REFERENCE AND RELIEF

7. At the risk of repetition, it may be pointed ont that the petitioners have claimed relief on two grounds; firstly that a raw hand named Nanak Chand was recruited by the Management as a Fireman in September, 1975, and secondly, that they have also promoted 28 Beldar/Helpers to the post of Firemen w.e.f. 5-9-1980 without affording them (petitioners) an opportunity of reemployment within the perview of Section 25-H read with Rule 77 framed under the Act. Neither of these facts was controverted by the Management, rather some explanations were projected to justifying the action.

8. However on an over all assessment of the situation, I am not inclined to sustain the Management's view point even though I would not take the recruitment of Nank Chand as a case of infringement of the legislative spirit of Section 25-H because his father had died accidently while serving on duty and he was appointed on purely compassionate grounds to provide a sort of succour to the berieved family who had lost their bread earner. But all the same the Management had no legitimate reason, to over look the claims of the petitioners while promoting the junior rankers like Beldars and Helpers in September, 1980. The argument that there rankers were tried soldiers of the Trade and came from the surplus pool pales into insignificance when we go into the pleading and find that both the petitioners had performed good quality of work till the time of their retrenchment. A ready hand reference may also be made to their discharge certificates Exts. W-3 and W-4 in support of the proposition.

8. Interestingly enough, during the pendancy of the reference proceedings, the Management appears to have realized the hollowness of their defence and that was how that both the petitioners were given fresh employment w.e.f. 27-11-82 in recognition of their claim, as should be evident from the closing part of the cross-examination of their Chief Fire Officer Shri T. N. Kaur M.W. 1 and suggestion floated to the petitioner Harbhajan Singh in his cross-examination, as MW-1.

9. It thus becomes abundantly clear that the Management was at fault in ignoring the petitioners claim at least at the time of promoting the junior rankers to the trade of Firemen in September, 1980. However, it was urged that since the petitioners have now being reemployed in recognition of their right granted by Section 25-H of the Act, therefore, the reference proceedings have become infructuous and no further relief may be given to them. On the other hand, the petitioners prayed for substantial relief alongwith all the attendant benefits on the assumption that they were recruited in service as Firemen at least w.e.f. 4-9-80 i.e. a day prior to the appointment of the aforesaid 28 promotees.

10. In my considered opinion, the judicial propriety calls for striking a balance; since the Management was guilty of violating the letter and spirit of Section 25-H at the time of making the departmental promotion as above; therefore, under a legal liction, it would be assumed that the petitioners had joined service immediately before their recruitment and to that extent they will be deemed to be senior to be aforesaid promotees. But in so far as their claim for the wages is conceded I think that it will be going too far to burden the public exchequor with an excessive fiscal liability for the period for which neither of the petitioner had rendered any service. To be precise ends of justice would be sufficiently achieved by awarding them a token monetary compensation and, as such, I direct the Management to pay a consolidated amount of Rs. 1000 to each of them. (Rs. One thousand each).

11. Thus to sum up my aforesaid discussion on the limited available data and the points raised before me, I return my Award in favour of the petitioner Workmen in the light of my observations in the preceding para.

CHANDIGARH,

Dated : 3-5-1984.

I. P. VASISHTH, Presiding Officer

[No. L-42012/25/81-D.II (B)]

T. B. SITARAMAN, Under Secy.

New Delhi, the 16th May, 1984

S.O. 1776.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, No. 3 Dhanbad in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Toposi Colliery of M/s. Eastern Coalfields Ltd. and their workmen, which was received by the Central Government on the 9th May, 1984.

BEFORE THE CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT NO. 3, DHANBAD

Reference No. 44/82

AND

PRESENT :

Shri J. N. Singh, Presiding Officer.

PARTIES :

Employers in relation to the management of Toposi Colliery of M/s. Eastern Coalfields Ltd.

Their workmen.

APPEARANCES :

For the Employers—Shri N. Das, Advocate.

For the Workman—Shri D. K. Verma, Advocate.

INDUSTRY : Coal. STATE : West Bengal.

Dated, the 30th April, 1984

AWARD

The Government of India in the Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them U/S 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 14 of 1947 has referred the dispute to this Tribunal for adjudication under Order No. L-19011(4)/82-D.IV(B) dated the 4th May, 1982

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Toposi Colliery in stopping the work of wagon loaders for the period from 15-11-81 to 20-11-81 is justified ? If not, to what relief the workmen are entitled ?"

2. From the terms of Reference it will appear that there are 4 unions who have been made party in it viz. West Bengal Colliery Mazdoor Congress (HMS), Khan Mazdoor Karamchari Union, Janata Colliery Mazdoor Congress and Colliery Mazdoor Sabha of India (CITU). All the aforesaid 4 unions have filed their respective written statements but

none of them, except West Bengal Colliery Mazdoor Congress, have come forward to contest it. From the record it will also appear that in all there are 149 wagon loaders working in this colliery out of whom the contesting union viz. West Bengal Colliery Mazdoor Congress have come with the case of 32 wagon loaders as mentioned in their written statement. Their case is that on 15-11-81 being a Sunday and a holiday the aforesa d wagon loaders 32 in number did not go to perform their work and as such they were not aware of the happenings of that day that transpired between the management and the wagon loaders. On 16-11-81 when these 32 wagon loaders of their union reported for their usual duties they found that some wagon loaders of other union with the help of some outsiders restrained and stopped them from performing their work. The matter was verbally reported to the Manager from whom these wagon loaders sought protection but no step was taken. They also requested the management to provide them with work and through their union demanded for wages for the period under reference.

3. It is stated that these 32 workers reported for duty on all the subsequent dates till 20-11-81 but they were not given any work and on 20-11-81 after the intervention of the R.L.C. all the wagon loaders were provided with work from 21-11-81. It is submitted that these 32 wagon loaders did not resort to any illegal strike nor they stopped work and hence they are entitled to wages from 16-11-81 to 20-11-81.

4. The defence of the management, however, is that there are 149 wagon loaders on the rolls of this colliery and they work by forming gangs by which a wagon is loaded normally by 5 wagon loaders as per workload prescribed in the Coal Wage Board recommendation. Normally 25 wagon loaders are required daily but there is no fixity in the number of wagons to be supplied by the Railways on each day and on such days the management has to pay full back wages to them.

5. It is then alleged that on 14-11-81 which was a Saturday the Railway supplied 25 empty wagons for loading but out of them 9 wagons could not be loaded and the management took steps for getting the 9 wagons loaded on 15-11-81 which was a Sunday by paying overtime wages as per rule. But on 15-11-81 all the wagon loaders demanded work which was not feasible because only 45 wagon loaders were required for the job on that date. This created an annoyance and the remaining wagon loaders did not allow the wagon loaders who had been engaged on 15-11-81 to complete the loading all the 9 wagons and 3 wagons were left incomplete. Thereafter from 16-11-81 all the wagon loaders resorted to an illegal strike and they stopped loading of wagons completely and the wagons supplied were kept detained without any loading till 20-11-81.

6. It is submitted that the management made repeated appeals to the concerned workman by letters and given due notice to the R. L. C. regarding the said strike, but the wagon loaders continued their strike uptil 20-11-81 when on the intervention of the R. L. C. they resumed their work on and from 21-11-81.

7. It is also submitted that as these wagon loaders resorted to illegal strike from 16-11-81 to 20-11-81 they are not entitled to any wages for the above days as claimed in the terms of reference.

8. The point for consideration is as to whether the action of the management of Toposi Colliery in stopping the work of wagon loaders from 15-11-81 to 20-11-81 is justified. If not, to what relief they are entitled.

9. From the written statement filed by the different unions it will appear that the wagon loaders were on strike on the relevant dates. But all the unions have taken a plea that though the member of other unions resorted to strike but the members of their union were willing to join their duty, but they were not allowed to do so by the management. The contesting union in their evidence have come with a plea that on 16-11-81 the Naxalite party came variously armed and did not allow them to do work. But in their written statement it is clearly stated that the members of other union did not allow them to do work. It is thus clear from the written statement of the contesting union that the members of other union did not allow these workmen to do their work even if they had any willingness to do so. According to the management, however, these 32 wagon loaders had also resorted to illegal strike and this is supported by the evidence of MW-2 Smt. R. Rathore working as Sr. Personnel Officer in Toposi Colliery. She has stated that she herself made appeal and negotiated with the union to end the strike but they did not. Similar is the evidence of Sru Jai Ram Singh, MW-1 Sr. Personnel Manager of Kunustoria Area under which this colliery falls.

10. From the evidence of these witnesses it is clear that the management was not at fault, rather the wagon loaders themselves did not perform their duties, may be due to the attitude of other wagon loaders. Further it is also clear that there was some law and order situation also and in that circumstances it was not possible for the management to allow any of them to perform their duty as that would have risked the life of the worker who were fighting among themselves. The law and order problem is the affair of the State Govt. and the management had no alternative but to make repeated appeals to the workers which they did but still the workers resorted to illegal strike. The fact that the worker had struck work illegally is also proved from the notice Ext. M-1 which was sent by the management to different authorities in Form No. Ext. M-2 is a notice dated 16-11-81 issued by the management to all the wagon loaders informing them that they had refused to load wagons and had resorted to an illegal strike without any prior notice and hence no wages for the days would be paid to them and further they were advised to call off the strike. Similaar notice was issued on 17-11-81 also. There is also another notice of the same date which shows that the Agent, Toposi colliery along with Sr. Personnel Officer went to the siding and held discussion with all the trade union leaders and all the leaders were requested to use their good offices to solve the problem and start wagon loading which they agreed. But at 3-30 p. m. it was found that no wagon loading was started. There is another letter dated 18th/19th November'81 sent by the Agent to the R. L. C. informing that wagon loaders were continuing their strike till then and all the negotiations had failed and so he was requested to intervene in the matter. On the same day a notice was issued to the wagon loaders also requesting them to resume their work. Prior to this a notice had been issued on 8-8-81 to the wagon loaders informing that there will be no wagon supply on Sunday which will be a rest day for all wagon loaders and if there will be any wagon supply the same will be loaded on overtime wages.

11. All the above documents as also evidence on the record clearly indicate that the wagon loaders resorted to strike from 16-11-81 when all of them were not provided with work on 15-11-81 which was a Sunday because only a few number of wagons had been supplied on that day and it was not feasible for the management to provide work to all of them on that date. In such circumstances if the wagon loaders resorted to illegal strike with effect from 16-11-81, they are not entitled to any wages for the period of strike from 16-11-81 to 20-11-81.

12. Considering the evidence on record, I hold that the action of the management in the circumstances is justified and the concerned workmen are not entitled to any relief.

13. The award is given accordingly.

J. N. SINGH, Presiding Officer

[No. L-19011(4)|82-D. IV(B)]

S. S. MEHTA, Desk Officer

New Delhi, the 14th May, 1984

S.O. 1777.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 3 Dhanbad in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Central Store Barkana, of M/s. Central Coalfields Limited and their workmen, which was received by the Central Government on the 9th May, 84.

BEFORE THE CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT NO. 3, DHANBAD

Reference No. 5/83

PRESENT :

Shri J. N. Singh, Presiding Officer.

PARTIES :

Employers in relation to the management of Central Store, Barkakana of M/s. Central Coalfields Ltd.

AND

Their workman

APEPARANCES :

For the Employers.—Sri A K. Tarafdas, Personnel Manager.

For the Workman.—None.

INDUSTRY : Coal. STATE : Bihar.

Dhanbad, the 30th April, 1984

AWARD

The Govt. of India in the Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them U/s. 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 14 of 1947 has referred the dispute to this Tribunal for adjudication under Order No. L-20012-(478)/82-D. III(A) dated the 21st May, 1983.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Central Store, Barkakana of M/s. Central Coalfields Ltd., in not considering the candidature of Shri A. M. Ganguli, Senior Store Keeper for promotion to the post of Chief Store Keeper on the basis of his specialised skill and long experience of Store, by relaxing the minimum educational quallfication, is justified and reasonable ? If not to what relief is the workman entitled ?".

2. It appears that the Secretary of the union sent a letter dated 19-3-84 to the Tribunal informing that the union had decided to withdraw the aforesaid case and pray that the case may be held to have been withdrawn by them. On receipt of this notice and before passing the order it was thought proper to hear the parties in the matter and accordingly a notice was issued to both the management and the union in the matter in question.

3. On receipt of this notice the union again sent a letter dated 24-4-84 informing that the case may be ordered to be withdrawn and permission may be accorded. Shri A. K. Tarafdas, Personnel Manager also filed a petition on behalf of the management on 27-4-84 the date fixed stating that the union had prayed for withdrawal of the case and the management has no objection to the aforesaid prayer and he also certified that the letter on behalf of the union was signed by its Secretary, Sri Sitaram is genuine.

4. In such circumstances it is clear that the parties have got now no dispute and hence a 'no dispute' award is passed.

J. N. SINGH, Presiding Officer

[No. L-20012(478)/82-D. III(D)]

A.V.S. SARMA, Desk Officer

New Delhi, the 16th May, 1984.

S.O. 1778.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 3 Dhanbad, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Chairman-cum-Managing Director's Office of M|s. E.C. Ltd. Sanctoria P.O Dishergarh, Burdwan and their workmen which was received by the Central Government on the 10th May, 1984.

BEFORE THE CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT NO. 3, DHANBAD

Reference No. 18|82

APPEARANCES :

Shri J.N.Singh, Presiding Officer.

PRTIES :

Employers in relation to the management of Chairman-cum-Managing Director's Office of M|s. E.C. Ltd., Sanctoria, P.O. Dishergarh (Burdwan).

AND

Their Workmen

APPEARANCES :

For the Employers—Shri B.N. Lala, Advocate
For the Workmen—Shri J. D. Lal, Advocate.

INDUSTRY : Coal. STATE : West Bengal

Dated, the 4th May, 1984

AWARD

The Govt. of India in the Mihistry of Labour in exercise of the powers conferred on them U|S 10 (1) (d) of the Industrial Disputes Act, 1947, (14 of 1947) has referred the dispute to this Tribunal for adjudication under Order No. L-19012(32)/81-D.IV(B) dated the 20th February, 1982.

SCHEDULE

"Whether the management of Chairman-cum-Managing Director's Office of M|s. E.C. Ltd., Sanctoria, P.O. Dishergarh was justified in not fixing 39 hours duty period in a week at per with others w.e.f. 2-7-75 in respect of the following workmen? If not to what relief the said workmen entiled ?"

Name of the Workmen

1. Shri Balram Nayak, Mali.
2. Bajkunt Samal Mali.
3. Mewaram Mali.
4. Badal Mali.
5. Joy Badyakar Mali.
6. Kali Charan Mali.
7. Baikantha Pari Mali.
8. Mongal Mukhi Mali.
9. B. Mehato Mali.
10. Debu Bouri Mali.
11. Mayadhar Samal Mali.
12. Judhisthir Mali.
13. Sh. Bharat Mali.
14. Raja Bouri Mali.
15. Sahadev Mali .
16. Kailash Mali.
17. Indramaoni Baral Mali.
18. P. B. Gnl. Mazdoor Mali.
19. Gagan Paridha Gnl. Mazdoor
20. Ajit Bouri Gn. Mazdoor
21. Rambrich Gnl. Mazdoor
22. Malu Mahato, Gnl. Mazdoor
23. Rakhal. Gnl. Mazdoor.
24. Sambhoo, Gnl. Mazdoor
25. Smt. Bharamra Bopure, Kamin Gnl. Mazdoor.

2. The case of the Workmen is that they are employed as Mali and General Mazdoor under the establishment of C.M. D. office of Eastern Coalfields Ltd., Dishergarh where the duty hours of clerks and other employees connected with the office is 39 hours a week but the concerned workman have to work 48 hours in a week which is discriminatory. Their prayer is that their duty hours should be fixed at 39 hours per week as prevalent in the office establishment of the General Manager and they should be paid overtime wages with effect from 1-5-1973.

3. The case of the management, however, is that prior to nationalisation the duty hours of the staff connected

with the office establishment of the headquarter was 39 hours a week while those of other namely Malis, Pump Khalasis, Electricians, Fitters, Security Guards, Drivers etc. had 48 hours duty in a week and that the same systemis continuing till to-day even after nationalisation. It is also stated that as per Section 14 of the Coal Mines Nationalisation Act the concerned workmen most of whom are taken over employees were taken on the rolls of the present management on the same terms and conditions of service and they have no right to make any demand for relaxation of duty hours. It is further stated that the hours of work of the employees connected with the office work is 39 hours in a week since before nationalisation but the Malis and General Mazdoors cannot be equated with the clerks and other office staff and their job description is mentioned in the Coal Wage Board recommendation itself.

4. On the above ground it is submitted that the Reference is unjustified.

5. The further case of the management is that these workmen started enjoying half weekly rest days on all Saturdays with effect from 9-6-80 and the management illegally deducted wages of these workmen on the ground of resorting to illegal strike. A demand was made by the union for restoration of illegal wage cut and for payment of overtime wages from 1-5-73 for working more than 39 hours a week as per working hours of the C.M.D. estabilshment. The dispute was thus raised on the above two issues but the terms of Reference shows that it is otherwise and not in consonance with the demand or the dispute raised by the union and on this score also the Reference is illegal.

6. The point for consideration is as to whether the management was justified in not fixing 39 hours duty period in a week at par with others w.e.f. 2-7-75 in respect of the workmen concerned. If not, to what relief they are entitled.

7. It may be stated that the date 2-7-75 has been mentioned in the terms of reference on the demand of the workmen on the ground that on 2-7-75 the management issued an office order (Annexure B of the written statement on the union) changing the office hours of the headquarter, Sanctoria. This office order would only indicate that only the timing was changed but not the total number of office hours which was 39 hours a week and therefore the date 2-7-75 is not very material.

8. The management has examined 2 witnesses in this case viz. Sri A. Bhattacharjee, MW-1 Sr. Personnel Officer in the Headquarter and MW-2 Sri K. K. Bakshi, Personnel Manager in the Administrative Department. From their evidence it will apear that the concerned workmen were employees of the erstwhile management Bengal Coal Company prior to nationalisation and they were working at the headquarters. MW-2 has stated that the concerned workmen are Malis and Garden Mazdoors and they are employed as such since before the nationalisation. Their service cards Ext. M series have also been filed to show that they are taken over employees. He has further stated that after take over the same working hours continued for these workmen and it is the same till today. According to him the office hours of clerks and persons connected with the office at the headquarter was 39 hours a week and the same system is continuing till today and there has been no change. It is also stated that Pump Khalasis, Mechanical Fitters, Drivers etc. who are at the headquarters have still to perform 8 hours duty and there is no reason as to why the duty hours of the concerned workmen should be reduced. Almost same is the evidence of MW-1 the Sr. Personnel Officer. The attendance register Ext. M-3 series also prove the same fact. Ext. M-5 is the pay slips which are not relevant in this case.

9. On behalf of the workmen, however, no witness has been examined and none has come to support their case nor have come to state as to on which ground their duty hours should be reduced.

10. It will also apnear that the concerned workmen had filed a case U/S 33-A of the I.D. Act before the Calcutta Tribunal claiming the wages which has been deducted from their pay for not working for full time on Saturdays but they subsequently withdrew their application vide Ext. M-4 (certified copy of the award filed in this case. Ext. M-2 is a letter dated 7-10-80 from the Vice-President of the union raising the present dispute. From this letter also it will appear that their main claim was for payment of wages deducted from their pay for not working full hours on Saturdays. Thus the demand originally was a different one and on this score also the Reference cannot be said to be proper.

11. It will also appear that U/S 14 of the Coal Mines Nationalisation Act the employees of the erstwhile management were to be taken on the rolls of the present management on the same ttrms and conditions of service It is definite case of the management that even prior to nationalisation the working hours of the concerned workmen was 48 hours a week. No reason has been assigned as to why this duty hours should be reduced. Further the duty hours of the clerks and other staff connected with the office work at the headquarters cannot be equated with the job performed by the Malis and Garden Mazdoors. As the job of two sets of workmen are quite different and on the pattern of the office staff, the concerned workmen are not justified in demanding reduction of their duty hours.

12. Considering the entire evidence and facts and circumstances of the case, I hold that the action of the management in not fixing 39 hours duty period in a week for the concerned workmen is fully justified and the workmen concerned are not entitled to any relief.

13. The award is passed accordingly.

J. N. SINGH, Presiding Officer

[No. L-19012(32)/81-D.IV(B)]

S.O. 1779.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Ropeways of Messrs Bharat Coking Coal Ltd., Bhulanbararee Camp. P. O. Patherdih, Distt. Dhanbad, and their workmen which was received by the Central Government on the 8th May, 1984.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT CALCUTTA

Reference 31 of 1983

PARTIES :

Employers in relation to the management of Roneways of Messrs Bharat Coking Coal Ltd., Bhulandararee Camp., P. O. Patherdih, District Dhanbad.

AND

Their Workmen

PRESENT :

Mr. Justice M. P. Singh.—Presiding Officer.

APPEARANCE :

On behalf of Employers.—Mr. R. S. Murthy, Advocate.
On behalf of Workmen.—Mr. A. Das Chowdhury, Advocate.

STATE : West Bengal. INDUSTRY : Coal.

AWARD

By Order No. L-19011(42)/82-D. IV(B) dated 3 May, 1983, the Government of India, Ministry of Labour & Rehabilitation, Dept. of Labour referred the following dispute to this Tribunal for adjudication :

"Whether the demand of the following Convevor operators working in Bunker 'F' in Ropeways Bharat Coking Coal Limited, for placing them in cat. IV of NCWA-II from 1-4-80 is justified ? If so, to what relief are the workmen entitled ?"

ANNEXURE

Sl. No.	Name of the workmen	Place of duty	Scale of pay
1.	S/Shri Rakhal Gorain	MB F Area	Cat. III (1-4-75)
2.	,, Prahlad Bouri	-do-	-do-
3.	,, Bhusan Das	-do-	-do-
4.	,, Phatik Das	-do-	-do-
5.	,, Narayan Mahato	-do-	-do-
6.	,, Binod Bouri	-do-	-do-
7.	,, Barsidhar Kulmbhakar	-do-	-do-
8.	,, Binod Kumar	-do-	-do-
9.	,, Kariman	-do-	-do-
10.	,, Gopal Bouri No. I	-do-	-do-
11.	,, Madhab Chandra Mahato	-do-	-do-
12.	,, Nakul Banerjee	-do-	-do-
13.	,, Shyama Pada Kumar	-do-	-do-
14.	,, Bideshe Bouri	-do-	-do-
15.	,, Narayan Das	-do-	-do-
16.	,, Bhawani Karmakar	-do-	-do-
17.	,, Sohan Rajwar	-do-	-do-

2. From the terms of the reference it is clear that the only question for decision in this reference is whether the 17 concerned workmen (who are in category III and are daily-rated workers) are entitled to be placed in category IV of NCWA-II w.e.f. 1 April 1980. The colliery management, however, has raised a preliminary objection that the reference is not maintainable because all issues relating to categorisation and wage scales of the employees of the coal industry including of Ropeways of B.C.C.L. stood settled by the NCWA-II which was signed on 11-8-1979 but came into effect retrospectively from 1 January 1979 and which is still in force, not having been terminated. I will, therefore, first deal with this preliminary objection. The contention of the union is that they, namely, the Central Ropeways Employees' Union, were not parties to the said settlement and hence it was not binding on them. It is also said that the NCWA-I & II had no occasion to consider the job description of conveyor operators as there were not laid down in the report of the Central Wage Board for coal industry.

3. Mr. Murthy appearing for the management submits that as per para 12.2.1 of the said NCWA-II, no demand of the type covered by the present reference can be made by the concerned workmen. Para 12.2.1 runs as below :

> "12.2.1 During the period of operation of this agreement, no demand will be made or disputes raised in respect of matters settled by this agreement."

It is to be seen as to whether categorisation of the workmen stood settled by the NCWA-II. It is not disputed that when this dispute was raised by the union before Regional Labour Commissioner (C) Asansol by letter dated 22 October 1982 (Ext. M-5), the NCWA-II was in force. In my opinion the stand taken by the management in this respect is correct. On a perusal of NCWA-II (Ext. M-2) page 26 it is clear that categorisation and wage scales of daily-rated workers have been settled. In Ext. M-5 the letter raising industrial dispute dated 22 October 1982 sent by the union to the Regional Labour Commissioner (C) Asansol it is admited that the concerned 17 Conveyor operators are working since 1 April 1975 in the Main Bunker 'F' area in category III, NCWA II. it is further written in that letter that these Conveyor operators through a written petition addressed to the General Manager dated 14-12-81 had requested to change their present category from III to IV. It is thus an admitted position that they are in category III under NCWA-II from 1 April 1975 and for the first time they requested the management in December 1981 to change their category. Mr. Murthy is therefore right that no such demand can be made by the union in view of para 12.2.1 of NCWA-II. Sri A. D. Chowdhury appearing for the union contended that this union was not a party to NCWA-II and therefore it is not binding on them. I do not agree. As already said it is an admitted fact (see Ext. M-5 the letter raising indusrial dispute) that they were placed in category III under the National Coal Wage Agreement II and hence this point has no force.

4. It is now to be noticed that they made this demand for category IV with effect from 1 April 1980—To ramamber this date is important. These Conveyor Operators say, bucket man cum helper attendant who were below them in category II have been elevated to category III from 1 April 1980; so they also must go to higher category. That is the only reason for their demand for higher category, that is, category IV with effect from 1 April 1980 (see para 11 and 12 of their written statement dated 10-8-83). Admittedly the work which they were doing before 1 April 1980 was being done after 1-4-80, that is clear from WW-2 D. K. Mukherjee who has said at page 4 of his deposition "The Conveyor operators are doing the same job before and after 1 April 1980". The witness has also said that from 1-4-1980 JBCCI has introduced a new category of workmen named bucket man cum helper attandant in category III with job description and that the NCWA-I had placed bucketman in category II. The witness is the General Secretary of the Central Ropeways Employees Union I think that he has mentioned the above fact only for the purpose of claiming higher category for the concerned workmen. Sri A Das Chowdhury has made submissions on the nature of job of the Conveyor operators and he has contended that having regard to the nature of job the concerned workmen should be placed in category IV. WW-1 Gopal Baroui No. I has said in his evidence "A conveyor operator is to operate a motor of 200 HP capacity. A conveyor operator also operates Compressor. He also operates Bucket elevator. The helper attendant or bucket-cum-helper attendant helps the conveyor operator. Apart from operation of different motors of different capacities, we have to do greasing work, roller changing work, to check classified tank (Objected to on behalf of the management on the ground that there is no pleading) Our work is skilled work. Conveyor operator's work is more skilled work than the work of Haulage K. Khalasi". This witness however has admitted in the cerss-examination all Khalasies are operators and they are operating pumps. He further admits that he cannot say if the categories of Conveyor Operators and he Conveyor Khalasies are mentioned in the Wage Board Report. WW-2 has also spoken about the nature of job of the Conveyor operators "The nature of work of Conveyor operator is skilled, because the work reuires responsibility, sincerely, diligence and efficiency. If there is any sort of negligence there is every chance of remarkable accident. In this respect I have already submitted documents before this Tribunal. The Conveyor operators operate at a great height from the ground, say about 250' to 300' from the ground and the length of the Conveyor is upto 650'. For the said length and height they require dilligence in operating. They are also assisted in this matter by the helpers. The Conveyor operators also check their Conveyors. They also check the motors. They operate hoist motor. There is difficulty in such operation because the operation of hoist motor is very critical and if there is any wrong adjustment then the entire sand coming from the river may go out to the river bed-again. There is no such post of Conveyor Khalasi in Rope Ways. The Conveyor Khalasies in other mines do not operate such conveyors and they are also not involved in such conveyor operation." The nature of job has also been mentioned in para 3 of the written statement of the union. Sri Chowdhury submits that having regard to the nature of job they should be placed in category II. This argument is not of any help to him because WW-2 has admitted in his evidence that the same job is being done after 1-4-1980. It would not be out of place to mention here that the nature of job as alleged by the union has not been accepted as correct by the management. MW-1 H. V. Solanki in his evidence has said : "In operation of Conveyor, the Conveyor operator has to press the button like a small switch and the conveyor is started. Thereafter he continues to watch the running of convevor and in case of any slippage of belt/ break down at that time he has to stop the running by pressing button. Thus there is no mental fatigue or physical work involved in the operation of Conveyor operation. The job is more simpler compared to haulage operation Haulage operator can be in category II. IV and V depending upon the size of the haulages where in the case of Convevor which is operated by electrical help by pressing button switch for any size of motor can be of semi-skilled." He has denied

that the Conveyor operators work at a height of 250' to 300' from ground. According to this witness it is generally at the height of 20 mtrs. only. The witness has further said that the Hoist is a part of the Conveyor and that the Conveyor operator has to operate it only occasionally and that too by a similar press button." I see no reason to disbelieve him. I accept his evidence as reliable. I do not believe the witness of the union on this point.

5. As regards the question as to whether the Conveyor operators are conveyor khalasies the witness (MW-1) has deposed that in Hindi they are called khalasi but in English they are called operators. His further evidence is that the conveyor operators in other mines are in category III and the number of such persons can be in thousands. MW-1 is a very responsible officer. He is a qualified mining engineer. He has worked in the coal industry in different capacities from 1961 in different collieries including repeways. He joined the ropeways division in August 1963 under the DOCL as Deputy Chief Mining Engineer and is working as overall incharge of production of sand. He got training in East European collierits as well as in England. He worked under the mining allied machineries at Durgapur as consultant on mining office machineries, conveyors, haulages, roof supports etc. for one year. He has deposed that in Sudamdih and Monidih collieries there are conveyors and in these two collieries, the witness has worked nearly for 16 years. According to him these two mines are highly mechanised and have been constructed in collaboration with Poland. The witness has himself operated conveyor and haulage. He is thus a highly responsible officer. I accept his evidence as reliable. He has not been shaken in cross-examination. A question was put to him in cross-examination as to whether he had brought any paper to show that the conveyor operators were called operators in English but in Hindi they were called conveyor khalasies. The witness frankly answered that he had no such paper. In my opinion this is not a ground to disbelieve him. In Ext. W-3 dated 13-14 November 1980 which has marked as an exhibit at the instance of the union the conveyor khalasi conveyor operator has been shown in category III and no distinction has been made between conveyor operator and conveyor khalasy. Ext. W-3 is an office order but it has been marked as an Ext. in the instance of the union and it has thus became their own document. The statement in this office order putting the conveyor khalasies/conveyor operator in category III, I think, goes against the union. Mr. Murthy appearing for the management drew my attention to the report of the Central Wage Board for the Coal Mining Industry Volume I and II and contended that conveyor operators were conveyer khalasies. As it has not been stated therein in distinct terms that conveyor operators were conveyor khalasies, it will not be useful to discuss that report in any detail. Mr. Murthy says that at page 44 and 45 of volume II mention has been made about pump khalasi, fan khalasi, haulage khalasi etc. and that categorisation of workers has been shown at page 54 and 58 of volume I on taking into consideration their skill and hence it should be held that conveyor operators are conveyor khalasies. On the other hand Mr. A Das Chowdhury submits that in Ext. M-1 NCWA-I at page 38 conveyor khalasi has been defined as an underground workman who operates the driving car of face or rope way conveyors of the belt, shaker (jigger) or scraper types. He has also drawn my attention to NCWA-I (Ext. M-1) in which several types of operators have been mentioned as for example, Escavetor operator, Crane operator Gr. I, Drill operator Gr. I, Tractor/Dozer operators etc. and on this basis he had contended that the NCWA-I itself has made a distinction between khalasies and operators. His argument is that at some places only khalasies have been mentioned and at other places 'operators have been mentioned, that as so, but it does not mean that conveyor operators cannot be called conveyor khalasies. It is to be noticed that there is no mention of conveyor operator in the NCWA and this indicates that conveyor operators and conveyor khalasies were understood in the same sense. In the fact and circumstances of this case I would like to rely upon the evidence of MW-1 H. V. Solanki ant Ext. M-3 and would hold that the conveyor khalasies and the conveyor operators are the same persons. Mr. A Das Chowdhury conceded that if the conveyor operators are held to be conveyor khalasies then the union will have no case. I also think so. I am further of opinion that they also were considered by the National Coal Wage Agreement II and that they had been placed in category III.

6.1 I have already said that the claim of the union for placing the 17 concerned conveyor operators in category IV is based on the fact that certain bucket man cum helper attendants who were in category II were elevated to category III, this claim on the very face of it is not reasonable. Such a claim is not based on any principle of justice. Take for example, a munsif is elevated to the post of Subordinate Judge, is it open to a Subordinate Judge to claim that he must be elevated to the post of Additional District Judge or District Judge on the ground that a munshif who was below him was promoted to the rank of Subordinate Judge. In my opinion it cannot be done. I am of the opinion that the demand of the union for placing the concerned workmen in category IV does not indicate any reasonable basis for the same and it is frivolous, unfounded and fit to be rejected. Such a claim if allowed can only create unrest and uncertainty in the industrial field.

7. For the above reasons my concluded award is that the demand of the 17 conveyor operators named in the annexure to the schedule of the reference working in Bunker 'F' in Rope Ways, BCCL for placing them in category IV of NCWA-II from 1st April 1980 is not justified. It follows that the concerned workmen are not entitled to any relief. Let this award be sbmitted to the appropriate government as provided in section 15 of the Industrial Disputes Act, 1947.

Dated, Calcutta,

26th April 1984.

M. P. SINGH, Presiding Officer
[No. L-19011(42)/82-D. IV(B)]
S. S. MEHTA, Desk Officer

New Delhi, the 14th May, 1984

S.O. 1780.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 1 Dhanbad in the industrial dispute between employers in relation to the management of Bararee Coke Works of M/s. Bharat Coking Coal Ltd., Bhowra Area, PO Bhulanbararee, Distt. Dhanbad and their workmen, which was received by the Central Government on the 8th May, 1984.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1, DHANBAD

In the matter of a reference under section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947

Reference No. 68 of 1982

PARTIES.

Employers in relation to the management of Bararee Coke Works of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Bhagaband Area No. VII, Post Office Kusunda, District Dhanbad.

AND

Their Workmen.

PRESENT :

Mr. Justice Manoranjan Prasad (Retd.) Presiding Officer.

APPEARANCES :

For the Employers—Shri G. Prasad, Advocate.

For the Workmen—Shri Lalit Burman, Vice-President, United Coal Workers' Union.

STATE . Bihar. INDUSTRY : Coal.

Dhanbad, the 30th April, 1984

AWARD

By Order No. L-20012(37)/82-D.III(A) dated the 17th May/20th May, 1982, the Central Government in the Ministry of Labour, has, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the

Industrial Disputes Act, 1947, referred the following dispute to this Tribunal for adjudication .—

"Whether the demand of the workmen of Bararee Coke Works of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Bhagaband Area No. VII, Post Office Kusunda, District Dhanbad that Sarvashri Sadan Kumar Singh, Rajnarain Singh, Nandu Nag, Budhan Shaw, Ramkishun Ram and Jiroa Bahadur should be treated as departmental workers and paid wages as per National Coal Wage Agreement is justified. If so, to what relief are the workmen concerned entitled?"

2. The case of the concerned workmen is that they have been working in the canteen of the Bararee Coke Works of Messrs Bharat Coking Coal Limited in different capacties as shown below :

1. Sadan Kumar Singh	—Canteen Manager,
2. Rajnarain Singh	—Canteen Clerk,
3. Nandu Nag	—Canteen Cook,
4. Budhan Shaw	—Canteen Cook
5. Ramkishun Ram	— Canteen Boy/Salesman
6. Jiroa Bahadur	—Canteen Boy.

The canteen of the Bararee Coke Works caters to over 500 employees of the establishment and, apart from tea, snacks etc., meals are also prepared and served to the workers. Under the existing rules, the canteen should be managed and run by the management departmentally and the employees of the canteen should be on the roll of the company and should we paid wages and other emoluments according to their respective grades/categories, as per National Coal Wage Agreements, but the management has been treating the canteen workers as employees of the Canteen Managing Committee and has been depriving them of all the benefits. In this way the concerned workmen are deprived of the scales of pay as per National Coal Wage Agreements, the statutory bonus (quarterly), fixed D.A., variable D.A. and such other benefits which they are entitled to get as direct employees of the company. It may be mentioned that the canteens of the sister concerns like Loyabad Coke Plan and Lodna Coke Plant of M/s. Bharat Coking Coal Ltd., are managed departmentally and the employees of the canteens of those establishments are on the roll of the company and are given all the benefits payable to the direct employees. The sponsoring union raised the dispute before the management of Bararee Coke Works and the General Manager of Bhagaband Area No. VII but the management refused to concede to the just and legitimate demand of the workmen for departmentalisation of the canteen and the workmen employed therein. There upon the sponsoring union at first raised an industrial dispute before the Assistant Labour Commissioner, Govt. of Bihar, Dhanbad. But after the report of the failure of conciliation in the said dispute was received in the Department of Labour, Government of Bihar, the Joint Labour Commissioner, Government of Bihar informed the union that the Central Government is the appropriate Government in respect of industrial dispute concerning the Coke ovens under M/S. Bhart Coking Coal Ltd. and advised that the industrial dispute should be raised before the Regional Labour Commissioner (Central), Dhanbad. Therefore the union raised the dispute before the Assistant Labour Commissioner (Central) Dhanbad on 11-12-1981 which ended in failure leading to the present reference. The demand of the concerned workmen is that they should be treated as departmental workers and should be paid wages and other benefits as per National Coal wage Agreements with effect form their respective dates of employment.

3. The case of the management, on the other hand, is that in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 258 of the Constitution of India, the Central Govt. by a notification dated 30-4-57 had entrusted to the State Government the function of the Central Government under the Industrial Disputes Act, 1947, in so far as they relate to industrial disputes covering the industrial establishments specified therein including the Bararee Coke Works/Plant. Thus, by virtue of the aforesaid notification, the power under section 10(1) of the Industrial Disputes Act, 1947 to refer the industrial dispute in respect of the Bararee Coke Works/Plants has been conferred by the Central Govt. on the State Government. That the State Government of Bihar is the appropriate Government in respect of Bararee Coke Plants/Works has been finally decided by the Patna High Court in the case of the Manager of Bararee Coke Plant Vs. Their workmen and another reported in 1968 Lab. I.C. 512 and hence the present reference made by the Central Government is incompetent. The Central Government in the Ministry of Labour and Employment by a subsequent notification No. S.O. 3699 dated 22-11-1965 under section 83(1) of the Mines Act, 1952 has also exempted all Coke Plants in India from all the provisions of the Mines Act and hence the Bararee Coke Works is also not a mine as defined in the Act and hence on that score also the Central Government is not the appropriate Government in respect of Bararee Coke Plant to make reference of the instant dispute which is, therefore, bad in law and void abinitio. The Bararee Coke Plant/Works is a factory and is engaged in manufacturing hard coke and by-products and has been registered as such under the Factories Act, 1948 but the persons named in the order of reference are not employed/engaged in manufacturing of coke or its by-products. Under Section 46 of the Factories Act, 1948 an occupier of a Factory is required to maintain and provide a canteen in a factory wherein more than 200 workers are employed. The employer of Bararee Coke Plant has provided a canteen in accordance with the provisions of the Factories Act and has provided necessary tools, materials, equipments, free fuel, light, water, utensils, crockeries, accommodation etc. as provided under Bihar Factories Rules and also pays a sum of Rs. 1200 per month to the canteen. The said canteen is run by a duly constituted canteen managing committee consisting of the representatives, both of the employers of Bararee Coke Plant and the workers employer therein. The said canteen is run on 'no profit, no loss' basis. The persons named in the schedule to the reference are employees of the said canteen managing committee and they are not the employees of Bararee Coke Works and since they are not workers under the Factories Act, 1948 they cannot be treated at par with other workers of the factory and they cannot be treated as departmental workers. Therefore the demand of the concerned workmen that they should be treated as departmental workers is not justified. The National Coal Wage Agreements are not applicable to the concerned workmen and the concerned workmen are being paid wages as prescribed for the employees concerned under the Bihar Shops and Establishment Act, 1953. Prior to the nationalisation of the coking coal mines and the coke plants under the Coking Coal Mines (Nationalisation) Act, 1972, they were owned, controlled and managed by the erstwhile owners, and since the employees of the canteen of Loyabad Coke Plant and Lodne Colliery were on the pay rolls of the erstwhile owners they continued to be employed by the present management on the same terms and conditions as were applicable to them prior to the natioanlisation. But since the concerned workmen named in the present reference were not on the pay rolls of the erstwhile owner of Bararee Coke Plant and were treated by the erstwhile owner as employees of the Canteen Managing Committee, they have been continued to be so treated by the present management under the provisions of Coking Coal Mines (Nationalisation) Act, 1972. The demand of the concerned workmen that they should be treated as departmental workers and should be paid wages and other benefits as per National Coal Wage Agreement is, therefore, not justified, and, in any case, no retrospective effect can be given to an award for any period prior to the date on which specific demands which resulted in the industrial dispute was made, and therefore, the demand of the concerned workmen that they should be departmentalised and paid wages and other benefits with effect from their respective dates of employment is misconceived and illegal.

4. I would first like to dispose of the legal objection raised on behalf of the management regarding the competency of the Central Government to make the present reference. In this connection reliance has been placed by the management in its written statement on a decision of the Patna High Court in the case of the Management of Bararee Coke Plant Vs. Their Workmen and another (1968 Lab. I.C.512)

on which Shri G. Prasad, Advocate, appearing on behalf of the management, also heavily relied for his contention that the State Government is the "appropriate Government" under section 2 (a) of the Industrial Disputes Act, 1947 to make any reference in respect of Bararee Coke Works and not the Central Government. In that case what had happened was that on 25-6-65 the Governer of Bihar in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act had referred to the Labour Court, Ranchi, constituted by the State Government, a dispute between some of the workmen and the management of Bararee Coke Plant regarding the termination of service of workmen named in the order of reference by the management. The matter had been taken by the management of Bararee Coke Plant to the Patna High Court in a Civil Writ jurisdiction case in which an important question of jurisdiction urged on behalf of the management of Bararee Coke Plant was that as the dispute was in respect of a coal mine, the Central Government had alone jurisdiction to a reference under section 10 (1) of the Industrial Disputes Act, 1947, and the State Government had no such jurisdiction. This was, however, negatived by the High Court and it was held that it is ture that the Central Government is the appropriate Government in relation to an industrial dispute with respect to a mine within the meaning of section 2 (a) (i) of the Industrial Disputes Act, 1947 and has jurisdiction to make a reference under section 10 (1) of that act, but since as early as 30-4-57 the Central Govt. in exercise of the powers conferred by clause (1) of Art. 258 of the Constitution had entrusted to the State Government the function of the Central Government under the Act in so far as they relate to industrial disputes concerning the industrial establishments specified in the schedule the Bararee Coke Plant being one of those included in the schedule, the power under section 10 (1) to refer the industrial dispute in respect of the Bararee Coke Plant to a Labour Court was expressly conferred on the State Government by the Central Government with the former's prior consent. The reference made by the State Government to the Labour Court, Ranchi constituted by the State Govt., in respect of the dispute between the management of Bararee Coke Plant and its workmen was, therefore, held to be vaild reference. That decision of the Patna High Court is, however, only a ruling for the proposition that the State Government may also refer under section 10 (1) of the Industrial Disputes Act, 1947 any dispute between the management of Bararee Coke Plant and their workmen in exercise of its powers delegated to it by the Central Government under clause (1) of Art 258 of the Constitution but it is no ruling for the proposition that after such delegation of power the Central Government itself became functus officio or ceased to have powers to make a reference under section 10(1) of the Industrial Disputes Act, 1947 in respect of a dispute between the management of Bararee Coke Plant and its workmen. Therefore, notwithstanding such delegation of power by the Central Government to the State Government under clause (1) of Art. 258 of the Constitution of India, the Central Government also continues to have the said power inherently vested in it under section 2 (a) (i) of the Industrial Disputes Act, 1947 in respect of mine.

5. It has next been contended by Sri G. Prasad, Advocate, appearing on behalf of the management that under section 2 (1b) of the Industrial Disputes Act, 1947 "mine" has been defined to mean a mine as defined in clause (j) of sub-section (1) of section 2 of the Mines Act, 1952, and the Bararee Coke Works may come under the definition of mine under sub-clause (x) of clause (j) of sub-section (1) of section 2 of the Mines Act, 1952 which says that mines includes any premises or part thereof in or adjacent and belonging to a mine on which any process ancillary to the getting, dressing or preparation for sale of minerals or of coke is being carried on unless exempted by the Central Government by notification in the official gazette. In this connection he referred to a Notification No. S.O. 3699 dated 22-11-1965 by which the Central Government in exercise of its power conferred by sub-section (1) of section 83 of the Mines Act, 1952 has exempted all coke plants forming part of mines which have arrangements for recovery of by-products from all the provisions of the Mines Act, 1952, and, on the basis of the same, he contended that since all coke plants forming part of mines which have arrangement for recovery of by-products like Bararee Coke Works have been exempted from all the provisions of the Mines Act, 1952, the Bararee Coke Works is not a mine within the meaning of sub-clause (x) of clause (j) of sub section (i) of section 2 of the Mines Act, 1952. The argument appears to be falicious inas much as the said notification No. S.O. 3699 dated 22-11-65 had been issued by the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 83 of the Mines Act, 1952 which empowers the Central Government to exempt either absolutely or subject to any specified condition any local area or any mine or group or class of mines or any part of a mine or any class of persons from the operation of all or any of the provisions of the said Act, and the said notification was not issued by the Central Government in exercise of the powers conferred under sub-clause (x) of clause (j) of sub-section (1) of section 2 of the Mines Act, 1952 which empowers the Central Government to exempt by notification in the official gazette any premises or part thereof in or adjacent to and belonging to a mine on which any process ancillary to the getting, dressing or preparation for sale of minerals or of coke is being carried on from the definition of mine. I, therefore, see no merit in the aforesaid contention of Sri G. Prasad, Advocate, appearing on behalf of the management and I hold that the Bararee Coke Works is a mine for the purpose of the Industrial Disputes Act, 1947 as defined in sub-clause (x) of clause (j) of sub-section (1) of section 2 of the Mines Act 1952, notwithstanding the notification No. S.O. 3699 dated 22-11-65 issued by the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 83 of the Mines Act, 1952 exempting all cokes plants forming part of mines which have arrangements for recovery of by-product from all the provisions of the Mines Act, 1952. It is also significant to mention here that even after the issue of the aforesaid notification No. S.O. 3699 dated 22-11-65, it was the stand of the management of Bararee Coke Plant before the Patna High Court in the aforesaid Civil Writ jurisdiction case between the Management of Bararee Coke plant and their workmen (1968 Lab.I.C.512) decided on 11-7-67 that the dispute was in respect of a coal mine and hence the Central Government alone had jurisdiction to make a reference under section 10(1) of the Act.

6. Sri Lalit Burman appearing on behalf of the concerned workmen has urged that besides being a mine, the Bararee Coke Works is also a controlled industry within a meaning of section 2 (a) (i) of the Industrial Disputes Act, 1947 and on that ground also the appropriate Government to refer the present dispute is the Central Government. In this connection he has referred to a notification No. S.R.O. 68 dated 5-1-57 issued by the Central Government in pursuance of sub-clause (i) of clause (a) of section 2 of the Industrial Disputes Act,1947 specifying for the purpose of that sub-clause the controlled industry engaged in the manufacture or production of coal, including coke and other drivatives which has been declared as a controlled industry under section 2 of the Industrial (Development and Regulation) Act, 1951, and on the basis of the said notification he has contended that since the Bararee Coke Works is engaged in the manufacture or production of coke and other deprivaties it is a controlled industry within the meaning of section 2 (a) (i) of the Industrial Disputes Act, 1947, in respect of which the appropriate Government is the Central Government to make a reference under section 10 (1) of the Act. I agree with the aforesaid contention of Sri Lalit Burman and hold that the Bararee Coke works is a controlled industry within the meaning of section 2 (a) (i) of the Industrial Disputes Act, 1947 and on that score also the Central Government is the appropriate Government to make the present reference under section 10 (1) of the Act.

7. It is also significant to note here that before raising the present dispute before the Asstt. Labour Commissioner (C), Dhanbad, which ended in a failure report leading to the present reference by the Central Govt., the sponsoring union had also raised the dispute before the Asstt. Labour Commissioner, Govt. of Bihar, Dhanbad and it is the evidence of Sri Ram Nath Singh (WW-2), Branch Secretary of the Bararee Coke Works unit of the sponsoring union, that the Asstt. Labour Commissioner, Govt. of Bihar, Dhanbad had

referred the dispute to the Dy. Labour Commissioner, Govt. of Bihar, Bokaro Steel City, who had sent a failure report to the Joint Labour Commissioner, Govt. of Bihar, Patna. It is the further evidence of Sri Ram Nath Singh (WW-2) that thereafter he had received a written communication regarding the same from the Dy. Labour Commissioner, Govt. of Bihar, Bokaro Steel City, in his letter dated 2-1-1981 (Ext. W-1) asking him to make further correspondence in the matter with the Joint Labour Commission, Govt. of Bihar, Patna, and thereafter he had written to the Joint Labour Commissioner, Govt. of Bihar, Patna to know about the position on which he had received the letter dated 3-6-81 (Ext. W-2) from the Joint Labour Commissioner intimating him that his letter had been sent to Labour Commissioner, Govt. of Bihar, who may be contacted for further action and thereafter he received the letter dated 21-7-81 (Ext.W-3) from the Joint Labour Commissioner Govt. of Bihar intimating him that after necessary examination of the dispute it had been found that in respect of hard coke ovens like Bararee Coke Works the Central Government was the appropriate Government to refer the dispute for adjudication and hence he should contact the Regional Labour Commissioner (C), Dhanbad for the purpose. A copy of the said letter dated 27-7-81 (Ext. W-3) was also sent by the Joint Labour Commissioner, Govt. of Bihar to the Regional Labour Commissioner (C), Dhanbad. It was thereafter that the sponsoring union had raised the present dispute before the Asstt. Labour Commissioner (C), Dhanbad by its letter dated 11-12-1981 (Ext.W-4).

8. Therefore, from whatever angle the matter is looked into and examined, the Central Government is the appropriate Government under section 2(a)(i)—of the Industrial Disputes Act, 1947 to refer the present dispute to this Tribunal in respect of Bararee Coke Works of Messrs Bharat Coking Coal Limited.

9. It has, however, next been contended by Sri G. Prasad appearing on behalf of the management that even if the Central Government be the appropriate Government to make a reference under section 10(1) of the Industrial Disputes Act, 1947 in respect of any dispute concerning Bararee Coke Works, it is not the appropriate Government in respect of any dispute raised by the concerned workmen who are not the employees or workmen of the Bararee Coke Works but are the employees and workers of the Canteen Managing Committee of the Bararee Coke Works. A consideration of the validity of otherwise of the aforesaid contention of Sri G. Prasad will require the examination of oral and documentary evidence adduced by the parties on the question of constitution of the Canteen Managing Committee and the relationship inter se between the management of the Bararee Coke Works, the Canteen Managing Committee and the concerned workman and it will also require the examination of the relevant laws relating to provision of canteen and constitution of Canteen Managing Committee by the owner, agent or occupier of mine or factory under the Mines Act, 1952 and the Factories Act, 1948 and the rules framed thereunder.

10. Rule 64 of the Mines Rules, 1955 provides that at every mine wherein more than 250 persons are ordinarily employed where Chief Inspector or Inspector so required, there shall be provided within the precincts of the mine a canteen for the use of all persons employed. Rule 65 specifies the standards of canteen, rule 66 specifies the furniture and equipments required to be provided in a canteen and rule 67 provides about cleanliness of canteen. Rule 68 provides that every canteen provided under these rules shall be run by the owner, agent or manager thereof who shall appoint supervisory and other staff sufficient for the proper working of the canteen. Rule 69 provides that the owner, agent or manager shall appoint a canteen managing committee which shall be consulted from time to time, but not less than once a month, as to the management and working of the canteen and the committee shall consist of an equal number of members nominated by the owner, agent or manager and elected by the persons employed in the mine and the owner, agent or manager shall appoint either himself or his nominee as ex officio Chairman of the committee and the Chairman shall preside at every meeting of the committee and the proceeding of every meeting of the committee shall be recorded in a minute book and shall be signed by the committee. Rule 70 further provides that food, drink and other item served in a canteen shall be sold on a non-profit basis and the prices charged shall be subject to the approval of the canteen managing committee and in calculating the cost of food, drink and other items served in a canteen, expenditure on the cost of utensils including cooking vessels and utensils necessary to serve food to the workmen cost of furniture, cost of coal, fuel and electricity and the salaries of supervisory and other staff shall not be taken into account. Similar provisions regarding canteen and canteen managing committee are also to be found under section 46 of the Factories Act, 1948 and Bihar Factories Rules. The Central Coal Wage Board recommendations—Vol.-I, also provide at page 81 the revised scales of pay for the employees in the canteen which have been further revised and enhanced from time to time at page 6 of National Coal Wage Agreement I, page 26 of National Coal Wage Agreement II and page 16 of National Coal Wage Agreement III which respectively came into force with effect from 1-1-75, 1-1-79 and 1-1-83. Para 8.9.0 of National Coal Wage Agreement III at page 43 deals with improvement of canteens and it states that the management agreed that during the Agreement period there would be a canteen in each of the colleries/establishment and the same would not be run by contractors and utensils and fuel required in the canteen will be supplied by the Colliery management and the management will also give certain amount to the canteen managing committee depending upon the size and operation of the canteen to enable the canteen to supply food articles at cheaper prices. Thus, after briefly referring to the laws on the subject of canteen and canteen managing committee which clearly show that provision of a canteen within the precincts of a mine or factory and constitution of a canteen managing committee are the duties and responsibilities of the owner, agent or the manager of the mine or factory, the canteen being an integral part thereof, I shall next turn to the oral and documentary evidence adduced by the parties in this regard.

11. Sri Raj Narain Singh (WW-1) is one of the concerned workman who has deposed that in Bararee Coke Works the number of employees is about 550 to 600 and he is a salesman in the canteen of Bararee Coke Works which is run in the building of M/s. Bharat Coking Coal Ltd. within the premises of Bararee Coke Works just inside its gate. He has further deposed that the canteen runs from 7 a.m. to 1 p.m. and again from 3 p.m. to 5 p.m. and in the morning eatables for breakfast are prepared and in the mid-day meals are cooked for the workmen working in Bararee Coke Works and in the afternoon tea and snacks are served which are purchased by the workmen and staff of Bararee Coke Works. He has further deposed that when the canteen was started the management of Bararee Coke Works had given about Rs. 2000 for starting it and there is a canteen managing committee to look after the canteen of which the Supdt. of Bararee Coke Works is the Chairman and the Senior Personnel Officer is the Secretary and some representatives of the workmen are elected members of the committee. He has further deposed that materials for preparing eatable are purchased from the funds supplied by the Secretary of the managing committee who gets the fund for the purpose from the cashier of Bararee Coke Works and the sale proceeds of the canteen are deposited with the cashier of Bararee Coke Works daily and it is he who supplies further fund for purchasing further materials for running the canteen. The management has elicited in his cross-examination that the crockeries and utensiles for running the canteen are supplied by the management and water and electricity are also supplied by the management. Sri Jagdish Chandra Narula (MW-1) is the Superintendent of Bararee Coke Works since January 1974 and he is the top officer of Bararee Coke Works on the management side and there is no officer there higher in rank than himself. According to him, in 1978 the strength of the workers in Bararee Coke Works was 512 but at present the strengthis 476. He too has deposed that the management has provided a building for running the canteen which is situate inside the precincts of the Bararee Coke Works near the gate and the management has also provided furniture and utensils for the canteen and the canteen is also provided with free electric light, coal and water by the management, and, besides that, the management also gives a subsidy of Rs. 1200 per month to the canteen. He has further deposed that he as the Superintendent of Bararee Coal Works is the ex-officio Chairman of the canteen managing committee and the Personnel Officer of Bararee Coke Works is the ex-officio member Secretary of the

canteen managing committee in which there are six representatives of the workmen and the said canteen managing committee runs the canteen and it is the canteen managing committee which appoints the employees of the canteen and the member secretary grants leave etc. to them. He has further deposed that the employees of the canteen are being paid wages according to the minimum wages prescribed under the Minimum Wages Act for shops and establishments under the Bihar Shops and Establishment Act, 1953, and the canteen of Bararee Coke Works is also registered under the Bihar Shops and Establishment Act, 1953.

12. Ext. M-1 is the payment register showing monthly payments to the concerned workmen as employees of Bararee Coke Works canteen. Exts. M-2 and M-3 are leave applications submitted by Raj Narain Singh, one of the concerned workmen, to the Secretary, Bararee Coke Works canteen for grant of leave. Ext. M-4 is another application submittetd by the concerned workmen regarding their wages to the Secretary of the Canteen. Ext. M-5 is another application dated 3-2-79 submitted by the concerned workmen to the Deputy Labour Commissioner, Government of Bihar, Bokaro Steel City, Dhanbad, regarding the union of which they are members. Ext. M-6 is a photostat copy of renewal license for the calendar year 1968 granted by the Chief Inspector of Factories, Bihar to Bararee Coke Works to work the factory. Ext. M-7 is a letter dated 25-12-82 sent by the Superintendent, Bararee Coke Works to the Chief Inspector of Factories, Bihar, for renewal of factory license for the year 1983. Ext. M8 is a letter dated 30-6-78 sent by the Factory Inspector, Dhanbad to the Superintendent, Bararee Coke Works complaining that the instructions given by him regarding the factory canteen had not been followed so far. Ext. M-9 is a letter dated 27-8-82 from the Labour Superintendent and Inspector under the Bihar Shops and Establishment Act, 1953 to the Secretary, Bararee Coke Works canteen asking him to get the canteen registered under that Act. Ext. M-10 is a letter dated 12-3-79 from the Dy. Labour Commissioner, Bokaro Steel City to the Superintendent, Bararee Coke Works intimating him that he would discuss on 27-3-79 the question of payment of wages to the workers of the canteen according to the Central Coal Wage Board recommendations which had been raised by the sponsoring union. Ext. M-11 is a letter dated 28-3-81 from the Asstt. Labour Commissioner, Government of Bihar, to the Supdt., Bararee Coke Works intimating that the Supdt. Bararee Coke Works had earlier agreed in an informal discussion that the workers of the canteen shall be paid wages payable to similar workers under the Bihar Shops and Establishment Act but he had not so far paid Rs. 50.96 per month to them as dearness allowance and that arrangements for payment of the same may be made. Ext. M-12 is a photostat copy of Treasury Challan showing deposit of Rs. 2048 for registeration of the canteen under Bihar Shops and Establishment Act, 1953. Exts. M-13 and M-14 are letters of appointment issued to the concerned workmen Ram Kisan Ram and Budhan Saw by the canteen managing committee appointing them as canteen boys with effect from 31-1-74 on Rs. 5 per day. Ext. M-15 is a letter of appointment issued to the concerned workman Bandu Nag by the canteen managing committee appointing him as a cook with effect from 31-1-74 on Rs. 7 per day and Ext. M-16 is a letter of appointment issued to the concerned workman Sadan Kumar Sinha by the canteen managing committee appointing him as canteen clerk on Rs. 6 per day with effect from 2-9-1975. Ext. M-17 is a letter dated 3-9-82 from the Supdt. of Bararee Coke Works and Chairman of the canteen managing committee to the Labour Supdt., Government of Bihar intimating that he was depositing Rs. 2048 by Treasury Challan for getting the canteen registered under the Bihar Shops and Establishment Act, 1953. Ext. M-19 is a letter dated 22-1-79 sent by the Supdt. Bararee Coke Works to the Asstt. Labour Commissioner, Government of Bihar, Bokaro Steel City, Dhanbad intimating the amount of salary per month which the canteen managing committee had been paying to the concerned workmen since 1-10-78 as employees covered under the Bihar Shops and Establishment Act, 1953. Ext. M-21 is a photostat copy of an order dated 4-9-78 issued by the Personnel Manager of M/s. Bharat Coking Coal intimating that Director (P) had been pleased to sanction Rs. 1200 towards subsidy to Bararee Coke Plant for running its canteen including payment to staff, engaged therein. Ext. M-22 is the minute book of canteen managing committee.

13. From the oral and documentary evidence also, as discussed above, it would appear that the canteen of Bararee Coke Works which is situate within its precincts is almost a part of it which is being financed and run by the management of Bararee Coke Works through the canteen managing committee of which the Supdt. of the Bararee Coke Works is the ex-officio Chairman and its Personnel Officer is the ex-officio Secretary and the said canteen is being run by the management in discharge of its statutory obligations for the welfare of the workmen working in the Bararee Coke Works and hence the concerned workmen who are working in the canteen cannot be discriminated against and denied the wages to which they are entitled under the Central Coal Wage Board recommendations which have been revised and enhanced from time to time under National Coal Wage Agreements I, II and III.

44. It has, however, been contended by Sri G. Prasad, Advocate, appearing on behalf of the management that since the concerned workmen, who are working in the canteen of Bararee Coke Works, are not engaged in the manufacture or production of coal including coke and other derivatives as mentioned in notification No. S.R.O. 68 dated 5-1-57 specifying the controlled industry in pursuance of sub-clause (i) of clause (a) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947, they are not entitled to the wages prescribed under the Central Coal Wage Board recommendations as revised from time to time under National Coke Wage Agreements I, II and III. In this connection he also referred to a decision of the Supreme Court in the case of M/s. Godavari Sugar Mills Ltd. Fort, Bombay-1 Vs. D. K. Worlikar (1950—67) 1 SCLJ. 201. In that case the short question which came up for consideration was about the construction of the notification No. 1131—46 issued by the Government of Bombay on 4-10-1982 under section 2(4) of the Bombay Isdustrial Relations Act, 1947. The respondent, who was a stenographer employed by the appellant, the Godavari Sugar Mills Ltd. at its Head Office at Bombay, was dismissed by the appellant on April 22, 1955. He was charged with having committed acts of disobedience and in subordination and was found guilty of the alleged misconduct, and his services were terminated. The respondent challenged the legality and propriety of the dismissal by an appliction before the Labour Court at Bombay and he purported to make this application under section 42(4) read with section 78(1)(a) (i) and (iii) of the Bombay Industrial Relation Act, 1947. The appellant in reply challenged the competence of the application on the ground that the Act did not apply to the respondent's case and so the Labour Court had no jurisdiction to entertain it. The Labour Court held tthat the notification in question on which the respondent relied did not apply to the Head Office of the appellant at Bombay and accordingly the Labour Court dismissed the respondent's application. The respondent challenged the correctness of this decision by preferring an appeal before the Industrial Court. His appeal, however, failed since the Industrial Court agreed with the Labour Court in holding that tbte notification did not apply to the head office of the appellant. The matter was then taken by the respondent before the Labour Appellate Tribunal and this time the respondent succeeded the Labour Appellate Tribunal having held that the notification applied to the head office and that the respondent was entitled to claim the benefits of the provisions of the Act. On this finding the Labour Appellate Tribunal set aside the order passed by the courts below and remended the case to the Labour Court for disposal on merits in accordance with law. It was this order which had given rise to the appeal before the Supreme Court in which the only question which arose for decision was whether the notification in question applied to the head office of the appellant at Bombay. It was common ground that if the notification applied to the case of the respondent the application made by him to the Labour Court would be competent and would have to be considered on merit; on the other hand, if the said notification did not apply then the application was incompetent and must be dismissed in limine on that ground. Their Lordship of the Supreme Court then considered the notification which had been issued by the Government of Bombay in exercise of the powers conferred on it by section 2, subsection (4) of the Act which provides that the Government of Bombay is pleased to direct that all the provisions of the said Act shall apply to the following industry viz the manufacture of sugar and its by products including (1) the growing of sugarcane on farms belonging to or attached to concerns engaged in the said manufacture, and (2) all

agricultural and industrial operations connected with the growing of sugarcane or the said manufacture engaged in such concerns. On consideration of the said notification it was held by the Supreme Court that the notification applies not to the sugar industry as such but to the manufacture of sugar and its by-products and if the expression 'sugar industry' had been used it would have been possible to construe that expression in a broader sense having regard to the wide definition of the word "industry" prescribed in section 2(19) of the Act but the notification had deliberately adopted a different phraseology and had brought within its purview not the sugar industry as such but the manufacture of sugar and its by-products. Besides, the inclusion of the two items specified in clauses (1) and (2) is also significant. Section 2(19)(b)(i) shows that "industry" includes agriculture and agricultural operations. Now, if the manufacture of sugar and its by-products had the same meaning as the expression sugar industry, then the two items added by clauses (1) and (2) would have been included in the said expression by virtue of the definition of "industry" itself and the addition of the two clauses would have been superfluous. The fact that the two items have been included specifically clearly indicates that the first part of the notification would not have applied to them and it is with a view to extend the scope of the said clause that the inclusive words introducing the two items have been used. This fact also shows the limited interpretation which must be put on the words "the manufacture of sugar and its by-products." it was further observed by their Lordships of the Supreme Court that the factories and the offices attached to them are situated at Lakshmiwadi and Sakharwadi respectively and are separated by hundreds of miles from the head office at Bombay and in this situation it was difficult to extend the scope of the notification to the head office of the appellant. Accordingly it was held by the Supreme Court that the Labour Appellate Tribunal erred in law in holding that the case of the respondent was governed by the notification.

15. The aforesaid decision of the Supreme Court in the case of M/s. Godavari Sugar Mills Ltd., Fort Bombay-1 Vs. D. K. Worlikar has, however, no application to the facts of the present case, firstly, because the notification No. S.R.O. 68 dated 5-1-57 does not refer only to "manufacture or production of coal including coke and other derivatives" but it refers to "industry engaged is the manufacture or production of coal including coke and other derivatives", and, secondly because the canteen is situate within the very precincts of Bararee Coke Works and is almost a part of it and is not hundred miles apart from the Bararee Coke Works as was the case with the head office at Bombay from the factories of M/s. Godavari Sugar Mills Ltd. and offices attached to them in the aforesaid Supreme Court decision.

16. In the case of Saraspur Mills Co. Ltd. Vs. Ramanlal Chamanlal and others (1973) 10 SCLJ 21 the only question which required determination by the Supreme Court was whether the canteen workers employed by the Co-operative Society could be treated as employees of the appellant, the Saraspur Mills Co. Ltd., within the meaning of the relevant provisions of Bombay Industrial Relations Act, 1946 for the purpose of payment of their wages in spite of the fact that they were employees of the Co-operative Society and were being paid wages by that society. It was contended that the appellant was under a statutory obligation because of section 46 of the Factories Act and the relevant rules made therein to maintain the canteen for the workers, but the canteen was being actually run by the co-operative society and the appellant had nothing of the society who were working in the canteen. It was to do with it nor did it pay any wages to the employees of the society who were working in the canteen. It was, however, held by the Supreme Court that an employees engaged in a work or operation which was incidentally connected with the main industry was a workman if other requirements of the statute were satisfied and that the workers in order to come within the definition of an employee need not necessarily be directly connected with the main industry and since under the Factories Act it was the duty of the appellant to run and maintain the canteen for the use of its employees, the canteen employees were employees of the appellant. That decision of the Supreme Court fully applies to the facts of the present case and, accordingly, the canteen of Bararee Coke Works is held to be incidentally connected with the main industry of Bararee Coke Works and the concerned workmen of the canteen are held to be in the facts and circumstance of the case as discussed above, the employees of Bararee Coke Works of M/s. Bharat Coking Coal Ltd.

17. It is also worthwhile to mention here that it is the undisputed position that the employees of similar canteens of Loyabad Coke Plant and Lodna Coke Plant of M/s. Bharat Coking Coal Ltd. are on the pay rolls of the present management and are given all the benefits payable to the direct employees. The explanation given by the management that prior to the nationalisation of the Coking Coal Mines and the coke plants under the Coking Coal Mines (Nationalisation) Act, 1972, they were owned, controlled and managed by the erstwhile owners and since the employees of the canteen of Loyabad Coke Plant and Lodna Coke Plant were on the pay rolls of erstwhile owners they continued to be employed by the present management on the same terms and conditions as were applicable to them prior to the nationalisation, but since the concerned workmen named in the present reference were not on the pay rolls of the erstwhile owner of Bararee Coke Plant and they were treated by the erstwhile owner as employees of the canteen managing committee, they have been continued to be so treated by the present management, can hardly be accepted as a plausible explanation, as for all intends and purposes the concerned workmen are also employees of Bararee Coke Plant, the provision of canteen and constitution of canteen managing committee for the welfare of the workmen of Bararee Coke Works being the statuted duty and responsibility of the management. Moreover, it is also not correct to say that the concerned workmen were employed by the erstwhile owner of Bararee Coke Works and they continued to be employed by the present management on the same terms and conditions as were applicable to them during the time of the erstwhile owner, because the appointment letters Exts. M-13, M-14, M-15 and M-16 show that the concerned workmen Ram Kisun Ram, Budhan Saw and Nandu Nag were appointed with effect from 31-1-74 and Sadan Kumar Sinha was appointed with effect from 2-9-75 after the vesting of Bararee Coke Works in M/s. Bharat Coking Coal Ltd. with effect from 1-5-72 under Coking Coal Mines (Nationalisation) Act, 1972. In the circumstances, there seems to be no justification for making any indivious discrimination between the concerned workmen who are workers of the canteen of Bararee Coke Plant belonging to M/s. Bharat Coking Coal Ltd. and workers of similar canteens of Loyabad Coke Plant and Lodna Coke Plant of the same employer, viz., M/s. Bharat Coking Coal Ltd. who are on the rolls of the management and who are given all the benefits payable to the direct employees.

18. In view of the aforesaid findings, the concerned workmen are surely entitled to be treated as departmental workers and paid wages as per National Coal Wage Agreements. The next question which, however, arisen for consideration is as to from which date they should be departmentalised and paid wages as per National Coal Wage Agreements. The concerned workmen have claimed in their written statement that they should be treated as departmental worker and should be paid wages and other benefits as per National Coal Wage Agreements with effect from their respective dates of employment. It has, however, been held by the Supreme Court in the case of Jhagrakhand Collieries (Private) Ltd. Vs. Central Government Industrial Tribunal, Dhanbad (1950—67) 5 SCLJ 3067 that no retrospective effect can be given to an award for any period prior to the date on which the specific demands, which resulted in industrial dispute, were made. A similar view has been taken in another Supreme Court decision in the case of Cox and Kings (Agents) Ltd. Vs. Their workmen and others (1977) 14 SCLJ 207. In the present case the specific demand which resulted in the present industrial dispute was made by the sponsoring union by its letter dated 11-12-81 (Ext. M-4) addressed to the Asstt. Labour Commissioner (C), Dhanbad and as such the concerned workmen can be departmentalised and paid wages according to the National Coal Wage Agreements retrospectively with effect from the said date 11-12-81 and not from any date prior to that. It has, however, been contended by Sri Lalit Burman appearing on behalf of the concerned workmen that before that date also the sponsoring union had been agitating this matter before the Asstt. Labour Commissioner, Government of Bihar, Dhanbad, but subsequently the union was advised by the Joint Labour Commissioner, Government of Bihar in his letter dated 21-7-81 (Ext. W-3) that the Central Government was the appropriate Government to refer a

dispute under the Industrial Disputes Act, 1947 in respect of hard coke over like Bararee Coke Works and as such the union should raise the dispute before the Regional Labour Commissioner (C), Dhanbad whereafter the union had raised the dispute before the Asstt. Labour Commissioner (C), Dhanbad by the aforesaid letter dated 11-12-81 (Ext. W-4), and hence the concerned workmen should be departmentalised and paid wages as per National Coal Wage Agreements from the date the union had raised the dispute before the Asstt. Labour Commissioner, Government of Bihar, Dhanbad. I, however, do not agree with the contention of Sri Lalit Burman at the dispute which the union had raised before the Asstt. Labour Commissioner, Government of Bihar, Dhanbad, has not resulted in the present reference of the industrial dispute by the Central Government and it is only the union's letter dated 11-12-1981 (Ext. W-4) addressed to the Assistant Labour Commissioner (C), Dhanbad which has resulted in such reference of the present industrial dispute by the Central Government. Therefore, the benefit of departmentalisation and payment of wages as per National Coal Wage Agreements cannot be given to the concerned workmen from any date prior to 11-12-1981.

19. In the result, it is held that the demand of the concerned workmen, namely, S/Shri Sadan Kumar Singh, Rajnarain Singh, Nandu Nag, Budhan Sha[illegible], Ramkishun Ram and Jiroa Bahadur that they should be treated as departmental workers and paid wages as per National Coal Wage Agreements is justified, and the management is directed to treat them as departmental workers and to pay them wages and other benefits with effect from 11-12-81 including arrears as per National Coal Wage Agreements II and III. The reference is answered and the award is made accordingly. But in the circumstance of the case there will be no order as to costs.

MANORANJAN PRASAD, Presiding Officer.

[No. L-20012(37)/82-D. III (A)]

S.O. 1781.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Dhanbad in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Jamadoba Colliery of M/s. Tata Iron and Steel Company Ltd., Post Office Jamadoba, District Dhanbad, and their workmen, which was received by the Central Government on the 8th May, 1984.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD

PRESENT :

Shri I. N. Sinha, Presiding Officer.

Reference No. 50 of 1982

In the matter of an industrial dispute under S. 10(1)(d) of the I.D. Act., 1947.

PARTIES :

Employers in relation to the management of Jamadoba Colliery of Messrs. Tata Iron and Steel Company Limited, Post Office Jamadoba, District Dhanbad and their workmen.

APPEARANCES :

On behalf of the Employers.—Shri B. Lal Advocate.

On behalf of the workmen.—Shri B. N. Sharma, Joint General Secretary, Janata Mazdoor Sangh.

STATE : Bihar. INDUSTRY : Coal.

Dhanbad, the 1st May, 1984

AWARD

The Government of India in the Ministry of Labour, in exercise of the powers conferred on them under section 10(1)(d) of the I.D. Act., 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication under Order No. L-20012(85)/82-D. III(A), dated the 17th/20th May, 1982.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Jamadoba Colliery of Messrs Tata Iron and Steel Company Limited, Post Office Jamadoba, District Dhanbad in not regularising Shri Bijoy Bahadur as Coal Transport Worker in Category-V is justified : If not to what relief is the said workman entitled ?"

The case of the management is that Janta Mazdoor Sangh is neither the recognised nor representative union functioning in Jamadoba Colliery. The management is not also aware if the concerned workman is a member of the said union. The case of the management, further, is that the concerned workman Shri Bijoy Bahadur was appointed as Category I Mazdoor w.e.f. 15-4-75. He was promoted as Category Timber Mazdoor from 21-9-1977 and is still working as Timber Mazdoor in Jamadoba Colliery. The concerned workman was sometimes deputed as Trammer in Category II during the leave and sick vacancy in the year 1976 and was paid difference of wages. He was also sometimes deputed to act as Coal Transport Worker during the leave and sick vacancies intermittently in different sections of Jamadoba Colliery from September, 1978 to March, 1979 and again from June, 1979 to September, 1981 and the difference in wages for acting as Coal Transport Worker was paid to the concerned workman. The substantive post of the concerned workman remained that of a Timber Mazdoor. He never worked as permanent Coal Transport Worker continuously for about three years. In 1975 the management introduced a scrapper mining system which continued upto 1982 in 16A Seam of Jamadoba Colliery of M/s. Tisco. The purpose was to mechanise the winning and transport of coal and in order to suit this specific system of mine, the management introduced three distinct categories of workers, viz multi skilled miners, electro mechanics and coal transport workers. Since the area got exhausted in 16A Seam of Jamadoba Colliery and the management had no other area to introduce scrapper mining system, the scrapper mining system was stopped in 1982. The coal Transport Workers were responsible for running of the Conveyors and their maintenance. After the scrapper mining system was stopped in two shifts of 16A Seam of Jamadoba Colliery, Coal Transport Workers working in the two shifts became surplus and they were deputed to work in leave and sick vacancies of the remaining one shift. The concerned workman was sent back to his substantive post of Timber Mazdoor. After the stoppage of work in two shifts of Jamadoba Colliery there was no requirement for even temporary deputation as Coal Transport worker of the concerned workman in preference to the permanent Coal Transport Workers who were previously working in the two shifts. As such there was no question of regularising the concerned workman as Coal Transport Worker in Category V. There was no reason for the management for being vindictive against the concerned workman, on the contrary, whenever job of a higher category was temporarily available, the concerned workman was given a chance and was paid the difference of wages of the higher category. The management was never provocated because a dispute was raised by the concerned workman. After the stoppage of the Scrapper mining system the concerned workman was never given to work as Coal Transport Worker. On the above facts it is submitted on behalf of the management that the Award be delivered in favour of the management that the action of the management in not regularising Shri Bijoy Bahadur as Coal Transport Worker in Category V is justified.

The case of the concerned workman is that he was employed as a Category I Mazdoor w.e.f. 16-9-74 in Jamadoba Colliery of M/s. Tisco. and subsequently he was made permanent w.e.f. 15-4-75 as Category I Mazdoor. The work entrusted to him was that of stowing mazdoor and he worked as such for about one year. Although his designation as Category I Mazdoor remained in the record of the management, he was actually working as a Trammer from 16-5-76 to August 1978. He was up graded as Timber Mazdoor from 1978 but he did not ever work as Timber Mazdoor. His actual job performance was of Coal Transport Worker (for the sake of brevety Coal Transport Worker will be referred as CTW) from 23-9-78 to 24-6-81 which is the work of Category-V of National Coal Wage Agreement No. II. The concerned workman was paid the difference of

.. for these periods but he was not confirmed as Category V workman. After having worked in permanent post as C.T.W. in Category V for about three years, the concerned workman demanded that his fictitious designation should be changed and he should be confirmed as Category V workman. The management became revengeful and vindictive and did not confirm him in that post. The management ousted the concerned workman from his job deliberately in calculated manner for a short duration in order to prevent him of his confirmation as Category V workman. The management took work from the junior hands of Category I Mazdoor after ousting the concerned workman from the job of C.T.W. The concerned workman did not work in sick or leave vacancy as C.T.W. The concerned workman submitted several applications demanding his confirmation in Category V workman but his demand was turned down unreasonably by the management and an industrial dispute was raised before the ALC(C), Dhanbad. The action of the concerned workman provocated the management and thereafter the management forced the concerned workman to work elsewhere and the workmen who were temporary and junior to the concerned workman were given the work of C.T.W. in his place. When the matter in dispute ended in failure before the ALC(C), Dhanbad the concerned workman was given to work as C.T.W. in Category V but the difference of wages was not paid. The demand of the workmen is that as he had been working in permanent post as Category V workman, he should be made permanent in his post as Category V with retrospective effect from 23-9-78 and should be paid difference of wages from April, 1982 onwards. Shri Anil Kumar, Blal, Ram Bilas, Jogi, and Lala who were junior and incompetent to the concerned workman in all respects were up-graded from Category I to Category V but the concerned workman was singled out for victimisation. It is, further, stated on behalf of the workman that before temporary closure of 16A Seam the work of 14 Seam started. The contention of the management of surplus C.T.W. to requirement was totally false. In 16A Seam of Jamadoba Colliery four C.T.W. were employed in each shift during the year 1981. After suspension of work of 16A Seam all C.T.Ws. were transferred to 14 Seam where in each shift number of C.T.Ws increased by three times more and in all the three shifts 36 C.T.Ws were required in seam No. 14 in place of only 12 C.T.Ws. of 16A Seam. The concerned workman was victimised and his services were not taken as C.T.W. because he had raised an industrial dispute. If the work of C.T.Ws in Seam No. 16A and 14 is carefully examined it will transpire that there is sufficient justification for regularisation of the concerned workman in Category V as a C.T.W. The change of designation as C.T.W. in Category V is directly linked with the conditions of service of the concerned workman and as a part and parcel of the terms of employment. The action of the management is not justified and the concerned workman is entitled to be placed in Category V as C.T.W.

The only question for determination in this case is whether the management was justified in not regularising the concerned workman as C.T.W. in Category V.

The management has examined two witnesses in support of their case. The concerned workman has examined four witnesses including himself in support of his case. Besides, the parties have aduced and exhibited certain documents.

It is the admitted case of the parties that the concerned workman was a permanent Category I mazdoor since 15-4-75 and that he was promoted to Category II as Timber Mazdoor. It is also admitted that the concerned workman was given the job of trammer in Category III for sometime. It is also admitted that he had worked as C.T.W. for sometime prior to the closure of 16A Seam of Jamadoba Colliery. In para-3 of the W.S. of the workman it is admitted that the difference of wages for the period he worked as C.T.W. was paid to him. It is further stated in para-3 of the W.S. of the concerned workman that from 23-9-78 to 24-6-81 he had worked as C.T.W. but he was not confirmed as Category V workman. Ext. M-2 is the Service Card of the concerned workmen which shows that he was employed from 15-4-75 as Category I Mazdoor in Jamadoba Colliery and that on 21-9-77 he was promoted as Timber Mazdoor Category II. There is no other entry in the Service Card Ext. M-2 to show that the concerned workman was promoted to Category V. From the service card it will appear that the concerned workman was in the substantive rank of timber mazdoor in Category II.

In para-5 of the W.S. of the management it is stated that the concerned workman was sometime deputed to act as CTW during leave and sick vacancies intermittently in different section of Jamadoba Colliery from September, 1978 to March 1979 and again from June 1979 to September, 1981 and was paid the difference in wages for acting as C.T.W. Thus, it will appear that the concerned workman had worked as C.T.W. from September, 1978 to September, 1981 except a gap of two months during the month of April and May, 1979. It will thus appear that the concerned workman had worked for sufficiently long period as C.T.W.

The question is whether the concerned workman could be regularised in Category V as C.T.W. It will appear from the evidence of MW-1 Shri S. K. Tripathy who is a Personnel Officer and MW-2 Shri R. S. Singh who is Manager of Jamadoba Colliery of Tisco that in 1974 the management with the help of French Consultants introduced scrapper mining system in 16A Seam of Jamadoba Colliery with the purpose to mechanise the winning and transport of Coal. MW-2 has stated that three distinct categories of workers were introduced to work the said specific system of scrapper mining. The three categories were multi skilled miners, electro mechanics and C.T.W. He has stated that in 1982 the scrapper mining system was stopped since the area got exhausted and the mangement did not have any area to introduced scrapper mining system. MW-1 has stated that multi skilled miners were appointed and trained to run this system and they were to do all the jobs of production of coal at the worksite and that in order to transport the heavy prodnction of coal the management employed C.T.W. who were posted in Jamadoba Colliery in the scrapper mining system only. MW-1 has further stated that 40 C.T.Ws were appointed and when the jobs of C.T.Ws were stopped in 1982 they were allotted another jobs. MW-1 has specifically stated that after the work of C.T.W. were stopped in 1982 the concerned workmen did not work, as C.T.W. and now he cannot be regularised as C.T.W. as the work of C.T.W. which was introduced in the scrapper mining system in 16A Seam was stopped. MW-1 has denied the suggestion made on behalf of the concerned workman that all the C.T.Ws who were working before, are still working as C.T.W. MW-2 has also stated that C.T.Ws were responsible for running of the conveyors and their maintenance and that the management have no job of C.T.W. after the stoppage of the Scrapper mining system. MW-2 has further stated that since the requirement of C.T.W. does not exist, it is now no longer possible to regularise him as C.T.W. He has stated that since March, 1981 the concerned workman has not worked as C.T.W. In cross-examination MW-2 has stated that at the time when scrapper mining system was stopped, there were about 42 C.T.Ws in Category V and they were provided in inferior jobs protecting their wages after the system was stopped and they were generally given the work of belt khalasi and chain khalasi.

WW-1 is the concerned workman. He has admitted in his cross-examination that the scrapper mining system started working in 1975 in Seam No. 16A and C.T.Ws were also working since that period. He has stated that at first training was given to the persons who were employed as C.T.W., multi skilled miners and electro mechanics when the scrapper mining system was introduced but he was not given any training of C.T.W. It is clear, therefore, that he was not originally selected for the job of C.T.W. when the scrapper mining system was introduced and that his services were requisitioned during stop gap arrangement. He has admitted that he had been paid for the work done by him as C.T.W. till before March, 1981. He has clearly admitted that the work of raising coal in Seam No. 16A has been stopped since September, 1982. He has further stated that after the work of 16A Seam was stopped the multi skilled workers were being paid on the time rated basis and that no new appointments were made as C.T.W. since 1982. He has stated that although he was always working as C.T.W., intermittently be was not paid for the work of C.T.W. but he did not make any claim in this Court of the non payment of wages of C.T.W. when intermittently it was not paid.

This statement of his is falsified from his earlier statement in cross-examination and his case in para 3 of his W.S. He has also admitted that he has no personal quarrel with any officer of the management and as such there does not appear to be any reason as to why the management would be against him. WW-2 is a loader. He has stated that when the work of 16A Seam was finished, the workers were employed in Seam No. 14 He has further stated that the concerned workman was presently working as C.T.W. in Seam No. 14. He has stated that the C.T.Ws designation has been changed as belt khalasi but they are doing the same job of C.T.W. It will be clear from his evidence that no workman is employed as C.T.W. in Seam No. 14 and that those workers who were working as C.T.W. in 16A Seam were working as belt khalasi in Seam No. 14. The case of the management is that when the scrapper mining system was stopped in 16A Seam, all the workmen of 16A Seam were given alternative job in Seam No. 14 and as there was no work of C.T.W. after the stopping of the system of scrapper mining system, they were given the alternative jobs protecting their wages. The said case of the management finds support from the evidence of WW-2 that those workers who were working as C.T.W. in Seam No. 16A were given the job of belt khalasi in Seam No. 14. In cross-examination WW-2 has stated that he does not know if any timber mazdoor junior in service to the concerned workman has been regularised as C.T.W. He has also no knowledge that any workman has been regularised as C.T.W. since 1981. WW-3 Shri Jhaman Das is working as Pump Khalasi. He has stated that he had worked in 16A Seam as C.T.W. for about four years. He has no doubt stated that the work of C.T.W. which was being taken in 16A Seam is still continuing in 14 Seam. But it will appear from his evidence in cross-examination that after the work of 16A Seam was closed he was provided the work of Pump Khalasi in 14 Seam. He has also stated that there was no special reason for sending him to work as Pump Khalasi from the work of C.T.W. It is clear from this evidence of his that the work of C.T.W. which was in 16A Seam was not required in 14 Seam and as such after the stoppage of 16A Seam he was given the job of Pump Khalasi in 14 Seam. He has in cross-examination stated that no C.T.W. has been regularised after the closure of 16A Seam. He has also stated that the management has paid the wages of C.T.W. to those persons who had worked as C.T.W. from the lower categories. It appears from his evidence that he also filed a case for being regularised as C.T.W. which is still pending and as such he has come to support the case of the concerned workman as perhaps he was thinking that the success of his case depends much on the success of the case of the concerned workman.

WW-4 Shri Munilal is a coal cutter. He has stated that when Seam No. 16 was closed the development work was taken up in 14 Seam and more C.T.Ws were engaged to work in Seam No. 14. He has stated that the concerned workman was a regular C.T.W. and was not temporarily working in leave and sick vacancy. According to him the concerned workman is still working as C.T.W. in Seam No. 14. Ht has stated that no new appointment has been made since 1982 and that the work of C.T.W. is taken from him and others. As discussed above his evidence does not appear to be reliable on the fact that the concerned workman is still working as C.T.W. in view of the fact that the job of C.T.W. was introduced in the Scrapper Mining System by M/s. Tisco. Ltd. in only 16A Seam of Jamadoba Colliery.

On reference to the Coal Wage Board Recommendations it will appear that there is no job description of a C.T.W. in it. According to the admitted evidence it will appear that the job of C.T.W. was introduced by M/s. Tisco. Ltd. in 16A Seam of Jamadoba Colliery and for the working of the said system the job of C.T.W., Electro Mechanic and multi skilled miner was introduced. Admittedly, the said scheme of scrapper mining system was stopped and the said scheme was not introduced in other seam of the management and as such it is evident that there could be no job of the description of the C.T.W. It has come in the evidence of the parties that all the workmen who were working in the Scrapper Mining system of 16A Seam were employed in Seam No. 14 and were given alternative job of belt khalasi, Pump Khalasi but the higher wages of Category V of those regular workmen were protected.

We have seen from the evidence discussed above that the post of C.T.W. ended with the stoppage of the scrapper mining system in 1982 but the concerned workman is claiming be C.T.W. even after the system of scrapper mining was stopped in which there was the job of C.T.W. It will further appear from the evidence that the concerned workman held the substantive post of Timber Mazdoor in Category II and that he used to work as C.T.W. as a stop gap arrangement. He could not have been regularised as C.T.W. even if the scrapper mining system existed because admittedly he had not received training as C.T.W. which had been imparted to all the workers whose services were requisitioned to work in the scrapper mining system.

Ext. M-1 is the memo of settlement dated 8-10-82 arrived at between the management and the representative of the RCMS. It will appear from this settlement that the scrapper districts of 16A Seam of Jamadoba Colliery could not be introduced in any other collieries of the management in the depillering sections. The job of the multi skilled miners were to be deployed after the stoppage of the scrapper mining system. Finally the settlement was arrived at between the management and the union's representative of the multi skilled miners and the multi skilled miners were put in the basic salary in the time rated grade which was to be the grade personnel to them. The work of multi skilled miners was piece rated one in the scrapper mining system and by this settlement their pay was made time rated. It will appear from the evidence of MW-2 that since the multi skilled miners were piece rated workers the management entered into an agreement with the recognised union to settle their fresh service conditions and Ext. M-1 is the said settlement. He has further stated that no settlement was made in respect of C.T.W. and electro mechanics as they were already time rated workers and there was no change in their service conditions and they were put on alternative jobs with protection of their jobs of the permanent C.T.W.S. He has further stated that now C.T.Ws are doing the job of belt khalasi in Category III. I have taken into consideration Ext. M-1 only for the purpose of showing that the scrapper mining system in 16A Seam was stopped since 1982 and that the workmen who were working in Seam No. 16A were given alternative jobs. So far the concerned workman is concerned, admittedly he was not a permanent C.T.W. and after the scrapper mining system was stopped the concerned workman whose services were no longer required as C.T.W. reverted back to his substantive post of Category II. In my opinion the concerned workman cannot be regularized as C.T.W. in Category V as he was neither a regular C.T.W. nor the post of C.T.W. now exists with the management. The concerned workman has raised a point that the workmen junior to him have been regularised as C.T.W. in Category V. On careful consideration of all the documents and the evidence of the W.Ws themselves, it will appear that no workman junior to the concerned workman has been promoted in Category V as CTW.

In view of the facts, evidence and circumstances discussed above, I hold that the action of the management of Jamadoba Colliery of M/s. Tisco. Ltd. in not regularising the concerned workman Shri Bijoy Bahadur in C.T.W. in Cat. V is justified and as such he is not entitled to any relief.

This is my Award.

Dated : 1-5-84

I. N. SINGA, Presiding Officer

[No. L-20012(35)/82-D. II(A)]

A. V. S. SARMA, Desk Officer

नई दिल्ली, 21 मई, 1984

का० आ० 1782.—केन्द्रीय सरकार ने, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 27 की अपेक्षानुसार उक्त अधिनियम की अनुसूची केभाग 1 में रेल, माल शेड, डाक और पत्तनों पर लदाई और उतराई और रेल के राख गर्त की सफाई के संबंध में कतिपय रोजगार जोड़े हैं ।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रेल, माल शेड, डाक और पत्तनों पर लदाई और उतराई और रेल, के राख पर्त, की सफाई के संबंध में रोजगारों के लिए मजदूरी की न्यूनतम दर नियत करने की बाबत जांच करने और केंद्रीय सरकार को सलाह देने के लिए एक समिति नियुक्त करती है जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:—

1. श्री सी० टी० दिघे, — अध्यक्ष
109, "शलाका",
महर्षि कर्वे रोड
को-आपरेज के सामने
मुम्बई 400021।

2. श्री राखाल दास गुप्त — कर्मचारियोंकी प्रतिनिधि
ज्येष्ठ लिपिक,
मंडल विद्युत इंजीनियर
का कार्यालय, बनगाईगाव
कर्मशाला, डाक घर बनगाईगाव, असम

3. श्री सी० एच० शशिभूषण राव — कर्मचारियों के प्रतिनिधि
संयुक्त महासचिव,
एन० एफ० आई० आर०
मार्फत-साउथ ईस्टर्न रेलवे मेन्स
कांग्रेस, ब्लाक 112/6, यूनिट 2,
गार्डन रीच,
कलकत्ता -43।

4. श्री आर० सी० शर्मा, — कर्मचारियों के प्रतिनिधि
संयुक्त निदेशक,
वाणिज्यिक यातायात (जी) 2
रेल बोर्ड, नई दिल्ली।

5. श्री जे०एस० आजाद, — कर्मचारियों के प्रतिनिधि
संयुक्त निदेशक
यांत्रिक इंजीनियर (ईंधन)
रेल बोर्ड, नई दिल्ली।

मुख्य श्रम आयुक्त के कार्यालय के श्री एच० जी० भावे, उप मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) समिति के सचिव होंगे।

समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

[फा० सं० एस-32019/4/83-डब्लू सी (एम डब्लू)]
आर० के० ए० सुब्रह्मण्यम, अपर सचिव

New Delhi, the 21st May, 1984

S.O. 1782.—Whereas the Central Government having added certain employments in loading and unloading in railways, goods sheds, docks and ports, and Ash pit cleaning on Railways to Part-I of the Schedule to the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948), as required by Section 27 of the said Act.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 5 of the said Act, the Central Government hereby appoints a committee consisting of the following members to hold enquiries and advise the Central Government in respect of fixation of minimum rates of wages for employments in loading and unloading in railways goods sheds, docks and ports and Ash pit cleaning on Railways, namely:—

(1) Shri C. T. Dighe, — *Chairman*
109, Shalaka,
Maharshi Karve Road,
Opp. Co-operage,
Bombay-400021.

(2) Shri Rakhal Das Gupta, — Employees' representative
Senior Clerk,
Office of the Divisional Electrical Engineer,
Bongaigaon Workshops,
P. O. Bongaigaon (Assam)

(3) Shri C. H. Seshibhushana Rao, — Employees' representative
Joint General Secretary,
N. F. I. R.
C/o South Eastern Railwaymens Congress,
Block 112/6, Unit 2,
Garden Reach,
Calcutta-43

(4) Shri R. C. Sharma, — Employees' representative
Joint Director,
Traffic Commercial (G) II,
Railway Board,
New Delhi.

(5) Shri I. S. Azad, — Employees' representative
Joint Director,
Mechanical Engineer (Fuel),
Railway Board,
New Delhi.

Shri H. G. Bhave, Deputy Chief Labour Commissioner (Central) in the office of the Chief Labour Commissioner (Central) shall be the Secretary of the Committee.

The headquarters of the Committee shall be at New Delhi.

[F. No. S-32019/4/83—W.C.(M.W.)]
R. K. A. SUBRAHAMANYA, Addl. Secy.

New Delhi, the 23rd May, 1984

S.O. 1783.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Delhi in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Punjab National Bank and their workmen which was received by the Central Government on the 8th May, 1984.

BEFORE SHRI O. P. SINGLA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL, NEW DELHI

I. D. No. 36/80

In the matter of dispute between :
Phool Chand

Versus

Punjab National Bank, Delhi.

PRESENT :

Shri R. K. Kadam with workman Phool Chand.
Shri A. K. Jethy for the Management.

AWARD

The Central Government, Ministry of Labour vide Order No. 12012/90/79-D.II. A dated 24th May, 1980 referred the following dispute to this Tribunal for adjudication:—

"Whether the management of Punjab National Bank in relation to their Paharganj Branch, New Delhi is justified in not giving chance to Shri Phool Chand, Cashier to officiate as Head Clerk in leave vacancy, in preference to other clerical staff, who did not work in cash section of the Branch ? If not, to what relief is the workman concerned entitled ? "

2. Today the workman made a statement that he was no longer interested in pursuing the matter under reference and believed that the Management in the absence of the pendency of the reference would deal with him fairly and understandably and as such withdraw from the reference and so did the Punjab National Bank Workers' Organization.

3. Under the circumstances, the reference is not proceeded with any further and a 'No Dispute' Award is made.

Further ordered that the requisite number of copies of this Award be forwarded to the Central Government for necessary action at their end.

April 30, 1984.

O. P. SINGLA, Presiding Officer

[No. L—12012/90/79/D—II (A)|D. IV (A)|

S.O. 1784.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, New Delhi, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of New Bank of India Limited, New Delhi and their workmen which was received by the Central Government on the 8th May, 1984.

BEFORE SHRI O. P. SINGLA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, NEW DELHI

I.D. No. 198/77

In the matter of dispute between :
Shri K. K. Bajaj,
Through New Bank of India Employees Union,
C/o New Bank of India,
Janpath, New Delhi.

Versus

New Bank of India Limited,
New Delhi.

APPEARANCES :

Shri N. C. Sikri—for the Management of New Bank of India.

R. C. Pathak—for the workman.

AWARD

Central Government, Ministry of Labour vide Order No. L-12012/92/77-D.II.A dated 13th October, 1977 referred the following dispute to this Tribunal for adjudication :—

> "Whether action of the New Bank of India Limited, New Delhi in terminating services of Shri K. K. Bajaj, Clerk-cum-Typist on probation is legal and justified. If not to what relief Shri Bajaj is entitled to ?"

2. Mr. K. K. Bajaj was appointed as a Clerk-cum-Typist on probation in the New Bank of India Limited, New Delhi vide order dated 15th November, 1975. In para 2 of the appointment letter it was specifically stated that he was being appointed on probation for a period of six months commencing from the date he reported for duty. It was clarified that "unless the period of probation is extended and a letter of confirmation given to you, your services shall automatically come to an end and the relationship of employer and employee between the Bank and yourself shall cease on the expiry of the said probation period without any further notice". His services were terminated by order dated 19th May, 1976 from the close of the day on 21st May, 1976.

3. The main cause for the action taken by the Bank is the alleged attempt to cheat the Bank by submitting false and frivolous bill in respect of his inspection at Nawashahar Doaba Branch, in which bill he claimed payment for being outside Delhi, while factually he was in Delhi on these days, and he certified that he was out station and he claimed money from the bank on that basis

4. The workman in his statement of claim has asserted that termination of his services was illegal because no notice-pay or notice was given to him before termination of service and there was breach of para 522(1) of the Sastry Award. Further, it was pleaded that he never misconducted himself during his employment in the Management. The action of the Management in not extending the period of probation if it thought that the services were not satisfactory during probation indicated foul play on the part of the Management in terminating the services.

5. The Management of the Bank contested the claim made by the workman and explained that his services were terminated in accordance with the service conditions read with appointment letter dated 15th November, 1975. The action was said to be bona fide. Mr. Bajaj was said to have submitted a T.A. bill, in which he falsely claimed amounts to which he was entitled and that was an attempt at illegal gain. The Management was not required to hold an enquiry and action was taken by way of not confirming him and ending the services with the period of probation.

6. The details were furnished that Mr. Bajaj was attached with Mr. A. K. Garyali, Inspector in the Audit and Inspection Department, and they were entrusted with the inspection of Nawashahar Doaba Branch on 7th April, 1976. The inspection was started on 8th April, 1976. During the course of inspection on 10th April, 1976 both A. K. Garyali and K. K. Bajaj left the place of inspection viz. Nawashahar Doaba, without prior approval and without intimation to the Head Office Authorities. Mr. Bajaj reached back at Navashahar Doaba on 14th April, 1976, after the unauthorised absence of four days, but claimed that he was at Nawashahar and submitted T.A. bill on that basis. The sincerety of the workman towards the bank was, thus, doubtful, and this financial institution did not think it necessary to retain him in service by confirmation. A reference is made to his admission made by him in the letter dated 5th May, 1976 which is in the following words:—

> "I beg to state that I alongwith Shri A. K. Garyali, left B|O Nawashahar on 10th April, 1976 at 3.30 P.M for Delhi on urgent call from my home. I want to bring to your kind notice that again I alone left Delhi on Tuesday evening on 13th April, 1976 and reached B/O Nawashahar on 14th April, 1976 at 9.30 a.m.
>
> I sincerely regret for my mistake and assure you Sir, that I will never be repeated in future, as it was all not known to me because my appointment is new and I do not know the Rules and regulation of the Bank.
>
> I hope you will look into the matter with a sympathetic consideration".

7. The matter in reference has been examined and the evidence of the parties has been recorded. The arguments of the Ld. representatives of the parties have been examined.

8. State Bank of India Vs. N. C. Jain—1964(1) LLJ 392 is the authority that larger notice includes a smaller notice. When the appointment letter itself clearly indicated that, unless the period of probation is extended or letter of confirmation issue, his services would automatically come to an end at the end of six months of his joining, no notice was necessary of termination of service on completion of probation period of six months.

9. Even otherwise the bona fides of the Management are clear that they intended to make payment of notice-pay to the workman. They asked the workman to indicate about the advances, if any, that he had taken from the various branches so as to enable the bank to settle his claim but instead of complying with the Bank's request, Mr. Bajaj by letter dated 4th February, 1977 asked for the rule under which he was being asked to indicate such details. Under the circumstances, the Bank sought information its own and, ultimately, issued him a cheque for Rs. 870.92 p. by memorandum dated 5th December, 1977 which the workman did not encash. The delay in payment to the workman seems to have been occasioned by the workman's own refusal to give details to the Management. In any case, the order of the Management terminating his services during period of probation is not invalid on ground of lack of notice, because the notice was explicit in the appointment letter itself.

10. The New Bank of India is a Financial Institution and it cannot be compelled to continue in-service people who lack integrity and can certify that they have been outside Head Quarters, while they are in fact at the Head Quarters and not at the place of inspection. The Management of New Bank of India did not think it proper to extend probation of the workman or to confirm the workman, when the workman clearly was guilty of seeking to make illegal gain by claiming D.A. for the days on which he was not at Nawashahar, and certified in D.A., T.A. bill that he was at Nawashahar while he was in Delhi,

11. Under the circumstances aforesaid, the action of the Management of New Bank of India in terminating the services of Mr. K. K. Bajaj appears to be legal and justified and the workman is not entitled to any relief. The Award is made accordingly.

Further ordered that the requisite number of copies of this award be forwarded to the Central Government for necessary action at their end.

O. P. SINGLA, Presiding Officer
[No. L-12012/92/77/D-II(A)/D-IV(A)]

S.O. 1785.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal New Delhi in the industrial dispute between the employers in relation to the Reserve Bank of India, New Delhi and their workmen, which was received by the Central Government on the 8th May, 1984.

BEFORE SHRI O. P. SINGLA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, NEW DELHI

I.D. No. 63 of 1981

In the matter of dispute between :
Chanda Singh
Versus
Reserve Bank of India

APPEARANCES :

Shri S. C. Gupta—for Reserve Bank of India.
Shri J. M. Wij and G. C. Kapur—for the workman.

AWARD

The Central Government, Ministry of Labour vide No. L-12012/126/80-D.II.A dated 4th June, 1981 referred the following dispute to this Tribunal for adjudication :

"Whether the action of the management of Reserve Bank of India, New Delhi in denying Shri Chanda Singh, Assistant Caretaker, the promotion to the post of Caretaker Grade II and instead promoting Shri P. N. Behl, Clerk Grade I is justified. If not, to what relief is the workman concerned (Shri Chanda Singh) entitled ?"

2. The Reserve Bank of India from Central Office issued a D.O. Letter No. 9994/51F-75/76 dated 9th March, 1976 mentioning that, for the post of caretakers Grade II at Bombay a panel was prepared from eligible staff candidates namely Assistant caretakers, Electricians-cum-Caretaker etc. attached to the office and staff quarters. It was also mentioned that vacancies were notified to the approved bodies like Regional Employment Exchange etc. for sponsoring a few suitable ex-servicemen candidates, and then the staff as well as out-side candidates were interviewed, and the names of successful candidates were placed in the panel. Similar procedure was required to be adopted in other offices.

3. In response to this office circular, the New Delhi Office issued a circular dated 15th March, 1979 stating that it had been decided to prepare a panel of Assistant Caretakers/Electricians-cum-Caretakers attached to New Delhi Office including staff-quarters for the post of Caretaker Grade II and intending candidates were required to send their applications through respective department.

4. However, ultimately, not only Assistant Caretakers and Electricians-cum-Caretakers were considered, but Mr. P. N. Behl, Clerk Grade I was also considered for the said post, on the ground that he had worked as Assistant Caretaker (for broken-periods total one year and 7 months) as Assistant Caretaker during the years 1963 to 1969, and he was placed 1st in the panel, whereas Chanda Singh was placed at No. 3.

5. There were only two posts, and the result was that Chanda Singh was not appointed as Assistant Caretaker, and the two posts went to Mr. P. N. Behl and Parbhi Kesar Singh Ghura. Presently, however, Chanda Singh is working as Caretaker since November, 1982 and Mr. P. N. Behl has been working as Assistant Security Officer since 1983.

6. The case of Chanda Singh is that the Security Staff like Assistant Caretaker and Electricians-cum-Caretaker are not eligible for promotion in the offices of the nature available to clerical staff, and it was unfair and improper to take P. N. Behl from the clerical cadre for the post of Caretaker, and he himself should have been promoted because he was in the panel at No. 3, and P. N. Behl should not have been put in the panel at all. He claimed promotion by upsetting the promotion of Mr. P. N. Behl and monetary benefits on that basis.

7. The Management of Reserve Bank of India contested the claim and raised preliminary objections. The first objection raised was that the dispute was not an 'Industrial Dispute' because the espousal was by Reserve Bank Workers' Organisation, which did not have a worthwhile following among class III employees. The second preliminary objection was that the Reserve Bank of India Staff Regulation 1948 provide that all promotions will be made at the discretion of the bank and there is no right to promotion to any particular post or grade. The third objection taken was that Chanda Singh was not a 'workman'. On merits, it was pleaded that the promotion of Mr. P. N. Behl was valid because he had worked as 'Assistant Caretaker' and could not be ignored and there was no mala fide involved in his promotion. The evidence led by the parties have been recorded and I have heard the representatives of the parties.

8. It is in evidence that this Union, which has espoused the cause of the workman has the membership of 457, and at the end of 1981, it had 184 class III employees as members. The espousal by such Union cannot be said to be worthless and the objection is over-ruled.

9. The promotion may be one in the discretion of the bank, but, if wrong persons not entitled to be included in the zone of promotion are considered, the workman, who is entitled to be considered for promotion, has a right to raise his grievance and an Industrial dispute is the means by which he can get the grievance redressed. The objection is over-ruled.

10. The duty list of Assistant Caretaker at the bank's building is given in Annexure IV to the affidavit filed by the bank, and the duties mentioned there are as under :—

ANNEXURE IV

Duty list of Assistant Caretaker at the Bank's building

	Duty hours	
	Week days	Saturdays
'A'	11.00 A.M. to 6.00 P.M. (with 1/2 hour lunch recess)	11.00 A.M. to 2.30 P.M.

(1) To keep watch and maintain proper account of dead stock articles of Central Office Wing, Security Officer's Office/Dining rooms and V.O.Ps./Manager's flats.

(2) To check petrol consumption of the Bank's care and verification of their bills.

(3) Distribution of work/duty amongst the maintenance staff in the second shift.

(4) To attend to liaison type of work i.e. to collect information from various Ministries as directed by the office/Central Office from time to time.

(5) To assist the Security Officer in handling routine office matters.

(6) To assist the Security Officer in maintaining the accounts of various sundry items and also for the purchase of rail/air tickets etc.

(7) To issue Tell-Tale clocks dials daily to Durwans and to examine and to ensure that they are punched properly. To keep their proper record.

(8) To ensure the periodical cleaning of incinerator.

(9) Preparation of bills—of cars and allied Institutions and also for the private use of the cars by the Bank's officers. Preparation of quarterly statement—use of petrol etc. for onward transmission to Central Office.

(10) To arrange for the priority seats both Rail and Air for the Bank's officials.

(11) To assist the Security Officer in receiving and seeing off of the Senior Executives of the Bank when required.

(12) Any other duty allotted to him by the Security Officer/Manager.

(13) To assist the Security Officer in all emergency matters irrespective of the duties allotted to him.

Duty list of Assistant Caretaker at the Bank's Staff Quarters 'B'

(1) To take and hand over the possession of the staff quarters and to ensure in connection therewith that all the fittings etc. to the staff quarters are in order and also to take care of the premises as to their proper upkeep.

(2) To ensure that the complaints regarding electrical installation, sanitary, wood and masionary work, etc. are properly and promptly attended to.

(3) To supervise over the work charge staff viz. plumber, wireman, carpenter-cum-mason, mazdoors, sweepers, etc. and to pay frequent visits to the colony to ensure that the staff is performing their duties in a satisfactory manner and to guide the staff from time to time.

(4) To restore necessary material purchased against indents under orders of the main office and to keep proper record thereof in connection with the maintenance of the staff quarters.

(5) To Look after the contractor's work relating white washing, colour washing, painting, additions and alterations and other miscellaneous work entrusted to them from time to time in connection with complaints received from the occupants for properly coordinating the work.

(6) To keep proper record and to attend to all the correspondence emanating from/to the main office, regarding occupation, vacation reports, submission of the indents for the required material after preparing the estimates thereof, monthy statistics of the work done by the staff, and to maintain proper inventiories of the fittings provided in the staff quarters conducting confidential enquiries regarding complaints filed by the staff against their fellow residents, and to pursue the matters with the other local concerns.

(7) To keep a proper account of petty cash as and when received from the main office in connection with the postage of the letters despatched to the main office and purchase of petty materials etc.

(8) To receive and despatch the dak of Dispensary from and to the main office.

(9) To arrange the purchase cleaning material for Dispensary etc. and to keep a proper record thereof.

(10) To make arrangements for washing of clothes, linon, uniforms of the staff etc. attached to the staff-quarters.

(11) To supervise the work of Sweepers i.e. scanvening of staircases, roads and open swaures etc.

(12) To ensure about the proper running of pumps and also to ensure about the regular water supply to the residents.

(13) To keep a proper record and keys of meter chains and terraces and to issue them to the staff as and when required.

(14) To keep monthly proper record of meter readings and pump-house enquiry office dispensary and stairness etc. for which the bills are paid by the Bank.

It is the case of the Management that these duties show the Assistant Caretaker to be a Supervisory Officer, drawing emoluments more than Rs. 500 per mensem.

11. It is not understood how the Assistant Caretaker can be said to be a Supervisory Officer, when he does not have any disciplinary powers when he himself is controlled by the Caretaker and the Assistant Security Officer, and himself has to work manually. It is the Security Officer or Assistant Security Officer, who can be said to be the Supervisory Officer of the caretaking staff. At the most, a Caretaker may also be included in that category, but the Assistant Caretaker cannot at all be included in the category of Supervisory Staff. His grade is low, and he is a minor functionary, subject to control of Caretaker, Assistant Security Officer and Security Officer. The objection is over-ruled.

12. It is not understood how the workman, Assistant Caretaker can be said to be not a workman as the term is defined in section 2(s) of the Industrial Disputes Act, 1947. His is a technical job and as a technical worker, he could be included in the Supervisory staff. The claim is maintainable and has to be investigated.

13. The matter has to be examined in the manner of channels of promotion. The clerks have their promotion in one channel and the Assistant Caretaker and Electricians-cum-Caretaker have their promotion to the most of Caretaker and Assistant Security Officer. The manner in which the Management of Reserve Bank has acted is to open two promotion channels for P. N. Behl. The question is whether the same is correct, when no such two channels of promotion are available to the workman Chanda Singh, Assistant Caretaker.

14. In case Mr. P. N. Behl was working as Assistant Caretaker at the time the names were to be considered, but happened to be in the clerical cadre, there could have been no objection to his being considered for the post of caretaker. Again there would have been no objection to his being considered, if he had worked for a major portion of service as Assistant Caretaker. He has merely worked on leave vacancies for a short period of one year and some months as Assistant Caretaker in a total service of 30 years in the bank from 1949 to 1979. In this situation, P. N. Behl was essentially not in the Caretaking-staff, but was in the clerical cadre of the Bank, and if the exigencies of the work required him to work as Assistant Caretaker for short periods, that would not allow him to take away the promotion chances available to the Caretaking staff.

15. I am of the clear opinion that the Management was ill-advised to consider Mr. P. N. Behl for the post of Caretaker, under the circulars mentioned earlier, and Chanda Singh ostensibly put at No. 3 should have been found at No. 2 and being promoted as Caretaker w.e.f. 6-7-79, the date from which Bakshi Kesar Singh Ghura was promoted as Caretaker Gr. II. Chanda Singh shall be allowed back wages and advantages on that basis. The Award is made accordingly with no orders as to costs.

Further ordered that the requisite number of copies of this award be forwarded to the Central Government for necessary action at their end.

O. P. SINGLA, Presiding Officer

May 2, 1984.

[No. L-12012/126/80-D.II(A)]

S.O. 1786.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal Jaipur in the industrial dispute between the employers in relation to the United Commercial Bank, Jaipur and their workmen, which was received by the Central Government on the 11th May, 1984.

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर

केस नं० सी०आई०टी० 1/82

केन्द्र सरकार श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या :
एल० 12012/257/80-डी० II (ए) दिनांक 19-12-81

सैक्रेटरी, राजस्थान बैंक एम्पलाईज यूनियन, अजमेर—यूनियन पक्ष

बनाम

डिवीजन मैनेजर, यूनाईटेड कामर्शियल बैंक, जयपुर—जयपुर

उपस्थिति :

यूनियन पक्ष की ओर से : कोई उपस्थित नहीं
नियोजक पक्ष की ओर से : श्री एम०पी० माथुर
दिनांक अवार्ड : 12-5-83

अवार्ड

केन्द्र सरकार ने निम्न लिखित विवाद इस न्यायाधिकरण को वास्ते निपटारा अपनी अधिसूचना संख्या : एल 12012/257/80-डी 11(ए) दिनांक 19-12-81 के द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 10(1) के अन्तर्गत भेजा है।

Whether the action of the management of the United Commercial Bank in relation to its Branch at Purani Mandi, Ajmer in warning Sh. C. L. Shalley, Assistant Head Cashier by way of punishment in their letter dated August 4; 1979 is justified ? if not, to what relief is the workman concerned entitled ? "

2. उक्त विवाद श्री सी०एल० शैले सहायक हैड कैशियर को ताड़ना (वार्निंग) के दंड से संबंधित है। इस न्यायाधिकरण को उस दंड की वैधता को निर्णीत करना है।

3. इससे पूर्व कि हम तथ्य अंकित करें यह कहना आवश्यक है कि श्री एम०पी०माथुर ने बहस के लिए समय चाहा। राजस्थान औद्योगिक विवाद रूल्स के रूल्स 10(बी) (3) के परन्तुक में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि साधारणतया मुकदमें की सुनवाई दिन प्रतिदिन की जायेगी एवं जिस दिन साक्ष्य बंद होगी उसके तुरन्त बाद बहस समाप्त की जायेगी। अतः सामान्य तथा औद्योगिक विवाद शीघ्र से शीघ्र निपटाये जाने चाहिएं। यह विवाद दिनांक 5-1-82 से लम्बित है एवं अधिवक्ताओं की उचित प्रार्थनाएं हमेशा स्वीकार की जाती हैं। यदि किसी मामले में कोई कानूनी या तथ्यों की पेचीदगियां हों तो न्याय हेतु बहस के लिए समय दिया जाना उचित होगा एवं दिया भी जाता है। परन्तु यह मामला एक छोटा मामला है, जिसमें विभागीय जांच अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई साक्ष्य पर यह निर्णीत किया जाना है कि उस साक्ष्य से आरोप सिद्ध है या नहीं। अतः श्री माथुर की प्रार्थना है कि उन्हें बहस के लिए एक सप्ताह का समय दिया जाय, इस मामले की प्रकृति एवं तथ्यों को देखते हुए अनुचित प्रतीत होता है। तत्पश्चात श्री माथुर ने हमारे समक्षविभागीय जांच अधिकारी के समक्ष हुए गवाहों के कथनों को शब्दोशब्द पढ़ा एवं उनका कहना है कि आरोप साक्ष्य से सिद्ध है।

4. इससे पूर्व कि हम अपना निर्णय विवाद पर दें कुछ तथ्य अंकित किये जाने आवश्यक है जो निम्न प्रकार हैं।

5. श्री सी०एल० शैले यूनाईटेड कामर्शियल बैंक अजमेर पुरानी मंडी शाखा में सहायक हैड कैशियर के पद पर कार्यरत था। उस बैंक में चीफ कैशियर का एक स्थाई पद था एवं उस पद पर कार्य कर रहे चीफ कैशियर का स्थानान्तरण हो गया था क्योंकि श्री शैले वरिष्ठ सहायक हैड कैशियर थे अतः उन्हें चीफ कैशियर का कार्य करने के लिए कार्यवाहक रूप से काम करने का आदेश दिया गया एवं उन्हें मासिक अलाउन्स मिलता था। श्री शैले के अनुसार वह यूनियन में सक्रिय था एवं समय-समय पर कर्मचारियों की कठिनाईयों को बैंक मैनेजर के समक्ष प्रस्तुत करते रहते थे, जिनके कारण बैंक मैनेजर उससे नाराज था एवं तत्कालीन बैंक मैनेजर श्री भार्गव ने उन्हें चीफ कैशियर के पद के कार्यवाहक अलाउन्स से वंचित करने के लिए एक अन्य व्यक्ति को अन्य शाखा से स्थानान्तरित करा लिया। ऐसा किया जाना द्विपक्षीय समझौता दिनांक 19-10-66 के विरुद्ध था।

6. यूनियन का आगे कहना है कि श्री शैले एक अन्य व्यक्ति खूबचंद के साथ 13 जुलाई सन् 76 को लगभग 7 बजकर 10 मिनट पर बैंक की शाखा में गये जहां श्री भार्गव मैनेजर मौजूद थे एवं उन्होंने उनसे श्री शैले को कार्यवाहक अलाउन्स से वंचित करने के कारण जानने के लिए कहा। इस पर श्री भार्गव नाराज हो गये और उन्होंने एक मनगढ़न्त झूठा आरोप पत्र दिया एवं जांच अधिकारी नियुक्त किया जाकर जांच कराई गई। जांच अधिकारी ने उन्हें उनके द्वारा शराब में धुत होने का आरोप एवं दुर्व्यवहार का आरोप नहीं माना एवं केवल जोर से बोलने का आरोप सिद्ध माना। परन्तु सक्षम अधिकारी ने उनके विरुद्ध यह आरोप भी सिद्ध माना एवं उन्हें वार्निंग का दंड दिया।

7. हमने पत्रावली का अवलोकन किया, जिसके अवलोकन से यह कहा जा सकता है कि विभागीय जांच विधीवत की गई थी एवं उसमें पूर्णतः नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों का पालन किया गया है। अब प्रश्न यह है कि क्या कोई साक्ष्य उपलब्ध है जिसके आधार पर तथाकथित आरोप सिद्ध माना जा सकता है।

8. जो आरोप श्री शैले के विरुद्ध दिनांक 17-7-76 को लगाया गया उसका सारांश यह है कि दिनांक 13 जुलाई 76 को लगभग 7 बजकर 40 मिनिट शाम श्री शैले खूबचंद के साथ शराब में धुत होकर बैंक में आये एवं श्री भार्गव मैनेजर के साथ दुर्व्यवहार किया। उन्होंने मैनेजर से कहा कि उनका (शैले) का, कार्यवाहक हैड कैशियर की हैसियत से कार्य करना बंद कर दिया गया है और जब श्री शैले को सूचित किया गया कि यह एक प्रशासनिक मामला है एवं उन्हें इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए तो उन्होंने दुर्व्यवहार करना प्रारम्भ किया एवं अनात्मक या हिंसात्मक आचरण किया एवं यह कृत्य द्विपक्षीय समझौता 1966 की धारा 19.5 (सी) के अन्तर्गत दुराचरण है।

9. श्री शैले ने अपने उत्तर में आरोप अस्वीकार किये एवं जांच अधिकारी के समक्ष जांच कार्यवाही दिनांक 11-1-78 से प्रारम्भ हुई। जांच अधिकारी के समक्ष आरोप सिद्ध करने के लिए श्री गहलोत श्री वर्मा एवं श्री तुलसीराम के ब्यान कराये गये। एवं श्री शैले ने केवल अपना ब्यान कराया। जांच अधिकारी ने उनके जांच प्रतिवेदन में यह निर्णय किया कि शराब में धुत होने का आरोप श्री शैले के विरुद्ध सिद्ध नहीं है। उन्होंने कहा कि आरोप सं० 1 सिद्ध नहीं है। परन्तु जांच अधिकारी के विचार में श्री शैले द्वारा जोर से बोलना सिद्ध है। सक्षम अधिकारी ने जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर दिनांक 25 मई 1979 को यह अंकित किया एवं श्री शैले को सूचित किया कि जांच अधिकारी की रिपोर्ट से यह सिद्ध है कि श्री शैले शराब में धुत होकर बैंक शाखा में आये। जब शैले ने सक्षम अधिकारी का ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि जांच अधिकारी ने तो यह आरोप सिद्ध नहीं माना है एवं जांच अधिकारी की रिपोर्ट का कुछ अंश उस संबंध में अपने पत्र में अंकित किये गये तो सक्षम अधिकारी ने श्री गहलोत एवं वर्मा के कथन, जो कि जांच अधिकारी के समक्ष हुए थे, का हवाला देते हुए यह कहा कि उन्होंने अपने कथनों में कहा है कि श्री शैले शराब के नशे में थे एवं उनसे यह आरोप सिद्ध है। एवं उन्होंने वार्निंग का दंड दिया।

10. हमने श्री माथुर की मदद से विभागीय जांच अधिकारी के समक्ष हुए कथनों को शब्दशब्द पढ़ा। इससे पूर्व की हम साक्ष्य का विश्लेषन करके यह बतायें कि आरोप सिद्ध नहीं है यह कहना आवश्यक है कि श्री भार्गव ब्राच मैनेजर जिनके साथ दुर्व्यवहार किया जाना कहा जाता है, को साक्ष्य में विभागीय जांच अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया था। वही ऐसे व्यक्ति हो सकते थे जो यह कह सकते थे कि उनके साथ क्या दुर्व्यवहार किया गया। श्री गहलोत ने अपने कथन में कहा है कि श्री शैले ने भार्गव को कोई गाली नहीं दी एवं वह केवल ऊंची आवाज

में बोल रहे थे उन्होंने यह भी कहा है कि यह दोनों मानि शैले और खूबचंद ऐसे लगते थे कि वह शराब पिये हुए थे

"It appeared that they were under some intoxication"

अतः वह यह कहीं नहीं कहते कि श्री शैले दारु पिये हुए था। यह कहने में कि ऐसा प्रतीत होता है कि कोई व्यक्ति किसी नशे में था एवं यह कहने में कि एक व्यक्ति दारु पिये हुए था काफी अंतर है। अतः सक्षम अधिकारी ने जांच अधिकारी से भिन्न मत इस संबंध में व्यक्त साक्ष्य पर नहीं किये हैं क्योंकि श्री गहलोत ने कहीं भी ऐसा नहीं कहा है कि श्री शैले नशे में थे जबकि सक्षम अधिकारी ने उनके कथन से ऐसा पढ़ लिया है। अब यदि वर्मा के कथन को देखें तो उन्होंने भी अपने मुख्य कथन में कहा है कि

"It appeared they were drunk which we could smell"

वह भी यह स्वीकार करते हैं कि श्री शैले न तो गाली दे रहे थे न ही अपशब्द कह रहे थे। प्रतिपरीक्षण में उन्होंने पुनः कहा कि वह नशे में थे। तीसरा साक्षी श्री तुलसीराम है जो यह नहीं कहता कि श्री शैले शराब पिये हुए थे एवं नशे में थे। हम कह चुके हैं कि श्री भार्गव शाखा मैनेजर को उपस्थित नहीं किया गया है जिनके साथ घटना घटित कही जाती है एवं जिनके साथ हुई घटना के संबंध में आरोप पत्र दिया गया था। शैले ने अपने कथन में कहा है कि उन्होंने अपने जीवन में कभी भी शराब नहीं पी एवं न ही कभी किसी के साथ गलत व्यवहार किया है। तुलसीराम जो कि विभाग की ओर से प्रस्तुत किये गये थे कहते हैं कि शैले जोर से बोलने के आदी हैं और उस रोज भी वह आम दिनों की तरह बोल रहे थे अतः केवल इसी कारण कि शैले जो स्वभावतः जोर से बोलने के आदि हैं, जोर से श्री भार्गव से बोले जिस संबंध में कि श्री भार्गव को ही कहना चाहिए था यह नहीं कहा जा सकता कि शैले द्वारा कोई दुराचरण किया गया, अतः न तो यह आरोप सिद्ध है कि श्री शैले शराब के नशे में भार्गव के कमरे में बैंक में 7 बजकर 40 मिनिट पर शाम को गये एवं उन्होंने दुर्व्यवहार किया एवं न ही उनके विरुद्ध यह सिद्ध कि उन्होंने इस प्रकार जोर से बोला कि जो कि अवैध व्यवहार की परिधि में आता हो।

11 अतः यह घोषित करता है कि यूनाईटेड कामर्शियल बैंक के व्यवस्थापकों द्वारा मो०एल० शैले सहायक हैड कैशियर को वार्निग का दंड देना अनुचित है। श्री शैले के विरुद्ध आरोप सिद्ध नहीं है। अतः इस प्रकार का अवार्ड पारित किया जाता है। यह अवार्ड केन्द्र सरकार को वास्ते प्रकाशनार्थ अन्तर्गत धारा 17(1) अधिनियम भेजा जाये।

महेन्द्र भूषण शर्मा, न्यायाधीश

[संख्या एल-12012/257/80-डी II(ए०)]

S. S. PRASHER, Desk Officer

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984